

नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त

नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त

पहला भाग

ओम्प्रकाश मिहल एम० ए०
महेन्द्र कालेज, पटियाला

१९५६

एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी
दिल्ली - जालंधर - लखनऊ

पंजाबी संस्करण भी प्राप्य हे

एस० चन्द्र० एण्ड कम्पनी

दिल्ली—फव्वारा

लखनऊ—छात्र बाग

जालन्धर—मार्ड हीरा गेट



मूल्य ३॥) रुपये

प्रकाशक : श्रीरोसाकर शर्मा, एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी, फव्वारा, दिल्ली ।

मुद्रक : श्रीनिवास प्रेस, भीरोनेट, दिल्ली ।

भूमिका

यह पुस्तक इंटरमीडियेट के विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए लिखी गयी है। यह नागरिक शास्त्र की बोर्ड पुस्तक तक ही अपना अग्रे मतलब पूरा कर सकती है यदि वह राष्ट्र के नौजवान एडवो और एडविका में भीष डग में गोबने, बायीषी में दुनिया की देखने और ईमानदारी में व्यवहार करने की आदत डालने में मदद दे, ऊंचे उठने की इच्छा और इमान के लिए मुन्मन पैदा करे, और हम रोज नग करने वाली गमम्प्राओं को मुल्गाने का होमला उनय बडाए। हम पुस्तक में वाद-विवाद, दलील, और काम करने के, दलिक स्वय जीवन के पय-प्रदर्शन के, कुछ नियम मिलेंगे।

इस वास्ते हम पुस्तक में कुछ ऐसी सामाजिक गमम्प्राए भीषे हम में पैदा करने की कोशिश की गयी है, जो पडाई के बाद विद्यार्थी के सामने जरूर आयेंगे। भारत के नागरिकों पर अब जो नयी जिम्मेदारियाँ आ पडी ह उन्हें देखते हुए यह पुस्तक अच्छी नागरिकता का सारना बनानी है।

महेश्वर कालेज, पटियाला।
१५ जून, १९५६।

श्रीमन्मोक्ष सिंहल -
१९७३

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	नागरिक शास्त्र (Civics) किसे कहते हैं	१
2	नागरिक शास्त्र की परिभारा, क्षेत्र, शिक्षा और उपयोगिता	६
3	नागरिक शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध	१४
4	प्रमुख और समाज	१९
5	साहचर्य या गण	२६
6	समुदाय—गाव और नगर	३९
7	सामाजिक समस्या (सम्पत्ति जाति और धर्म)	४६
8	राज्य और हमारे घटक तत्व	५८
9	राज्य का उद्गम और प्रवृत्ति	६८
10	राज्य के भाग और लक्ष्य	७७
11	शिक्षा	९१
12	नागरिक और नागरिकता	९९
13	नागरिक के अधिकार और कर्तव्य	११०
14	विधि, स्वाधीनता और समता-अपराध और दण्ड	१२२
15	सरकार—विधानाग कार्य, न्यायाग	१३९
16	सरकार के रूप—राजतन्त्र कुलीनतन्त्र लोकतन्त्र और अधिनायकतन्त्र	१५७
17	शासन के रूप (कमाल)	१६६
18	निर्वाचन मंडल जाति, और राजनैतिक दल का कार्य	१८१
19	संस्कृति और सम्प्रदाय अवकाश और मनोरंजन	२०१
20	राष्ट्रवाद और अन्तरराष्ट्रवाद गणतन्त्रराष्ट्र सभ	२१२

अध्याय :: १

विषय-प्रवेश

नागरिक शास्त्र (Civics) किसे कहते हैं ?

नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य को, नागरिक के रूप में, अध्ययन करता है, और इस बात पर विचार करता है कि समाज और राज्य के मदस्य रूप में मनुष्य के जीवन-जीवन से अधिचार और कर्तव्य है। इस प्रकार, नागरिक शास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन के एक पहलू पर विचार करता है और वह है उनका नागरिक पहलू। अन्य सामाजिक विज्ञान उसके सामाजिक जीवन के दूसरे पहलुओं पर विचार करते हैं। इतिहास मनुष्य के गुजरे हुए सामाजिक जीवन की तस्वीर बनाना है, अर्थशास्त्र मनुष्य के राजी बनाने की कोशिशों पर विचार करता है, आचार शास्त्र (Ethics) मनुष्य के कामों के नैतिक पहलू, अच्चार्य-दुर्ग, पर गौर करता है, राजनीति विज्ञान राजनैतिक कामों की चर्चा करता है, इत्यादि। अमल बात यह है कि मनुष्य समाज बनाकर रहने वाला प्राणी है। अपने स्वभाव और अपनी आवश्यकता, दोनों से वह एक सामाजिक प्राणी है। कोई आदमी अपने सच काम खुद नहीं कर सकता। हर सामाजिक विज्ञान अस्तु के इस समूह कथन की सचाई का मानता है कि जो आदमी सामाजिक नहीं है, वह या तो देवता होगा या पशु। मनुष्य के सामाजिक कार्यों के बहुत से रूप हैं, अर्थात् आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक। इन सब कामों में उमे परिवार, जालि, गांव, गहर, मजहब, राज्य, फंडरी, और कलब जैसे कई साहचर्य या मध^१, समुदाय या बिरादरी^२ और मस्था^३ बनानी पडनी है।

पर नागरिक शास्त्र में हम गता सारे सामाजिक जीवन पर विचार करते हैं, और न मध सधा, बिरादरिया और मस्थाओं पर। नागरिक शास्त्र में हम सामाजिक जीवन के सिर्फ एक पहलू पर विचार करते हैं और वह यह है कि नागरिक के रूप में मनुष्य का क्या काम है, और हम सिर्फ उन साहचर्यों या मधों, बिरादरियों और मस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जो नागरिक के तौर पर मनुष्य के जीवन और कार्यों पर गहरा असर

१ साहचर्य या मध (Association) एक एकतर रखने वाले लोगों के संगठित समूह का कहते हैं।

२ समुदाय या बिरादरी उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनके कुछ मछे मिले हों और इन मछे मिलने के कारण जिनसे एकता की शक्ति हो।

३ मस्था उन सम्बन्ध का नाम है जो बिना समूह के सदस्यों के बीच होता है।

झांसी है और उन पर भी उसी हद तक विचार करने है। जहाँ तक वे ऐसा असर डालती हैं। मियाल के तौर पर, बहुत से साहबों या मधों में से हम उनके परिवार और राज्य पर विचार करते हैं। परिवार पर हम इसलिए गौर करते हैं क्योंकि नागरिक की शुरु की शिक्षा, आदमी, और लाठी पर इसका बड़ा असर पड़ता है। नागरिक को अपने परिवार में ही सबसे पहले बच्चे के रूप में नागरिकता का पहला सबक मिलता है। जो आज बच्चा है, वही कल नागरिक हो जायेगा, और बच्चा पैदा हो जयेगा, जैसा उसका परिवार उसे बनायेगा। हम राज्य पर इसलिए विचार करते हैं क्योंकि राज्य के बिना कोई नागरिक नहीं हो सकता। नागरिक हमेशा किसी राज्य का नागरिक होगा। जहाँ राज्य नहीं, वहाँ नागरिक भी नहीं। इसके अलावा, नागरिक के अधिकार और कर्तव्य उसे राज्य की सहायता से प्राप्त होने हैं। नागरिक शास्त्र मुख्य रूप से नागरिक के इन अधिकारों और कर्तव्यों पर ही शोध-विचार करता है। यह मत है कि अधिकारों का उन्मूलन राज्य नहीं है, पर उनका आगम में और मूलतः तौर पर फासला उठाने के लिये यह विस्तृत शोध है कि राज्य उन अधिकारों की सहायता हो, और उनकी शिक्षा करना हो। सामाजिक शिक्षा हमेशा दूसरों के साथ में संश्लेषण करने की शिक्षा है। हमें समाज के और लोगों को देखते हुए अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि आगम में कोई उद्वेग या शक्यता पैदा न हो। इनका मत यह हुआ कि मुझे सिद्ध कर देना चाहिए कि मैं पर दूसरे लोग ऐश्वर्य न करे। इसी तरह, दूसरों को भी आपन में ऐसा ही मनुष्य बनना चाहिए। इस तरह अधिकार का मन्त्र यह हो जाता है कि उन्हें सिद्ध में सब जाया है, जिनका आगम में सब कर दिया गया है, और राज्य अपनी ताकत के ओर से उन अधिकारों को, दूसरों को दखलाने से, रक्षा मान करता है।

नागरिक शास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं ?

इस प्रकार नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिये राज्य का अध्ययन विस्तृत शोध ही है। राज्य का अध्ययन करते हुए हमें इसके जन्म, वृद्धि, बाधा, मरठन और लक्ष्यों का भी अध्ययन करना होगा। राज्य का नागरिक में सम्बन्ध एक भूमिका समझना है क्योंकि एक ओर तो राज्य की सवने बढी और गौणतः गति है और दूसरी ओर आदमी की आजादी है। राज्य को कबसे उची और अनौचित गति को सर्वोच्चता या प्रभुता (Sovereignty), कहते हैं। राज्य इन शक्ति के जेने के कारण ही कानून बनाता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के विचार के लिये सर्वोच्चता, कानून, आजादी, सहायता और अधिकारों की समझना बड़ी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

राज्य के अध्ययन में सरकार पर भी विचार करना पड़ता है। सरकार के बिना राज्य अपना काम नहीं कर सकता। राज्य एक विचार मात्र है। हम राज्य की कल्पना ही कर सकते हैं, उसे महसूस नहीं कर सकते और न छु या देख ही सकते हैं। सरकार में मंत्री, मन्त्र, उच्च न्यायालय और नेता आदि हैं, और इन सब चीजों को हम देख सकते हैं। राज्य लोगों में कानून और व्यवस्था बनाने रखने के लिये होता है। इस

नाम को यह सरकार के जरिये करता है ।

इस तरह नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिये सरकार पर बारीकी से विचार करना जरूरी हो जाता है । इसलिये हम सरकार के रूपों, इसके समझन और कामों पर विचार करते हैं । हर एक सरकार की तीन शाखाएँ होती हैं । (१) विधायिका (Legislature), (२) कार्यपालिका (Executive) और (३) न्यायपालिका (Judiciary) । सदन और विधान सभाएँ विधायिका का रूप हैं । राष्ट्रपति, राज्यपाल और सभी कार्यपालिका को सूचित करते हैं । न्यायालय न्यायपालिका के रूप में है । सरकार का अध्ययन करते हुए हम राजनैतिक दलों का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विधान सभाओं और सदन के चुनावों में उनका बहुत अहम हिस्सा होता है । सभी भी किसी न किसी राजनैतिक दल के ही सदस्य होने हैं ।

हम ऊपर बता चुके हैं कि सभों में से निर्णय परिवार और राज्य पर हम विस्तार से विचार करते हैं । इसी प्रकार, समुदायों में गाँव का और नगर का अध्ययन नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिये बहुत जरूरी है । परिवार के बाद नागरिक के कामों का केन्द्र गाँव और नगर होते हैं । परिवार की तरह गाँव और नगर भी नागरिकता की मिथा देते हैं । किसी नागरिक को लोकतन्त्र का पहला पाठ गाँव-पंचायतों और नगर-पालिकाओं में ही मिलता है ।

साहचर्य या सभ्य और समुदायों के अलावा हम जाति, सम्पत्ति और धर्म आदि कुछ समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं । हमारे मुल्क में जाति बहुत पुरानी समस्या है और इसने लोगों की जिन्दगी में अच्छा और बुरा, दोनों तरह का असर डाला है । भाजवर्ग इसे सब जगह बुरी चीज समझा जाता है, क्योंकि इसके कारण हमारी जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ा रहा । इसी प्रकार धर्म का भी किसी नागरिक के जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा होता है । इसका भी अच्छा और बुरा, दोनों तरह का असर होता है । धर्म के बहुत ज्यादा असर ने हमें भाग्यवादी और निरकारपरस्त बनाया है । फिरके-दाराणा सगडे समाज के शान्त जीवन को अनाश कर देने हैं—नागरिक शास्त्र शांति जीवन का निर्माण करना चाहता है । पर धर्म कुछ अच्छी बातें भी सिखाता है जो मनुष्य को नागरिक बनाने में बड़ी सहायक हो सकती हैं । यह हम सहनशीलता, हृमदवी, दया, भाईचारे और प्रेम का पाठ पढ़ाता है । इस प्रकार, नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी को नागरिक के जीवन पर धर्म के अच्छे और बुरे प्रभावों पर भी गौर करना चाहिये । सम्पत्ति भी नागरिक के जीवन पर गहरा असर डालती है । कुछ न-कुछ सम्पत्ति के बिना आदमी पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता । पर सब सम्पत्ति की अममानता से गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएँ पैदा होती हैं । गरीब और बेरोजगार नागरिक समाज पर बोझा है ।

नागरिक शास्त्र में हम नागरिक के जीवन पर असर डालने वाले साहचर्य या सभ्य, समुदायों और समस्याओं पर ही विचार नहीं करते, बल्कि उन बातों पर भी विचार करते हैं, जिनसे कोई आदमी अच्छा नागरिक बनता है । नागरिक शास्त्र सामाजिक इंजीनियरिंग का विज्ञान भी है । इस दृष्टि से नागरिक शास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान

है। इसका मकसद है अच्छे नागरिक तैयार करना और साथ ही शान्तिमय, सुगमाल तथा बेझिम्झप वाला सामाजिक और नागरिक जीवन बनाना। उदाहरण के लिए, शिक्षा अच्छा नागरिक बनाने में मदद करती है। बिना शिक्षा के आदमी जानवर जैसा रहता है। बिना तालीम पाये किसी नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ठीक-ठीक ख्याल नहीं पंदा हो सकता, और मुनी सामाजिक जीवन के लिये यह बिलकुल लाजमी है कि आदमी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सही ख्याल हो। बिना ठीक तालीम के कोई नागरिक सामाजिक जीवन में अपना पूरा योगदान भी नहीं कर सकता।

आन्विकी दल यह है कि नागरिक शास्त्र में हम नागरिक के इसी रूप पर विचार नहीं करते कि वह एक राज्य का अंग है, बल्कि इस रूप पर भी विचार करते हैं कि वह सारी मनुष्य जाति का एक हिस्सा है। मारा ससार एक बड़ी विरादरी है। अगर इस बड़ी विरादरी की प्रिन्दगी में हलचल मची हुई हो तो किसी राज्य में शानि नहीं हो सकती। इसलिए हमें नागरिक के जीवन के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू पर भी विचार करना होगा। हम राष्ट्रवादिता (nationalism) और अन्तर्राष्ट्रीयता के फायदे और नुकसान भी मोचने होंगे। राष्ट्रवादिता का अर्थ है अपने देश से प्रेम, अन्तर्राष्ट्रीयता का मतलब है अन्य राष्ट्रों से भी मुहल्लन। सयुक्त राष्ट्र सय (United Nations Organisation) जैसी सरसण जाति कायम रखने और दुनिया को लड़ाई की सरबाबी से बचाने के लिये बनी हुई है। इसलिए सयुक्त राष्ट्र सय के लक्ष्य, सणठन और कानों का अध्पन भी नागरिक शास्त्र में लिया जाना है।

सारास

नागरिक शास्त्र किते कहते हैं—नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह नागरिक के रूप में मनुष्य का और उसके अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्पन करता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है और उन्हीं की तरह यह मनुष्य के समाजगत जीवन से निकल एक पहलू का अध्पन करता है।

नागरिक शास्त्र में हम क्या अध्पन करते हैं?—नागरिक शास्त्र के अध्पन का केन्द्रबिन्दु नागरिक है। प्रथम तो, हम नागरिक का, उसके अधिकारों और कर्तव्यों का और उन अनेक प्रभावों का अध्पन करने हैं जो उसे अच्छा या बुरा नागरिक बनाने हैं, उदाहरण के लिये, हम उस पर परिवार, शिक्षा, समृद्धि, सम्पत्ता और कुरसान या अवकाश के प्रभावों का अध्पन करते हैं। इसलिए नागरिक शास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान है।

दूसरे, हम कुछ ऐसे माहल्लवों या सयों, समुदायों और सरसणों का अध्पन करते हैं, जिनका नागरिक के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है। माहल्लवों में से हम परिवार और राज्य का, समुदायों में से गाव आर सहर का, तथा सरसणों में से सम्पत्ति, धर्म, जाति या वर्ण का अध्पन करते हैं।

तीसरे, हम राज्य और उसके उद्गम (Origin), वृद्धि, कायों, और

प्रयोजन या मतभेद का अध्ययन करने है। राज्य का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना कोई आदर्श नागरिक नहीं बन सकता। हम उन सब समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं जिनका राज्य और नागरिक के बीच सम्बन्ध है, अर्थात् कानून, सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता, अधिकारों और समानता की समस्याएँ।

चौथे, राज्य के अध्ययन में सरकार और इसके रूपों, भावों और इसके संगठन का अध्ययन भी करना पड़ता है। आज के जमाने में जबकि राज्य लाक्षणिक हैं, सरकार को चलाने में नागरिक का जो हिस्सा है उसका अध्ययन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कारण, हम राजनैतिक दलों और लोकमत का भी अध्ययन करते हैं।

अन्त में, नागरिक साम्प्रदायिक अध्ययन की, राज्य के एक सदस्य के रूप में मनुष्य का जो कार्य है, उसके अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहता। यह उमरा, अधिक धनी विरादरी, अर्थात् मानव विरादरी, के सदस्य के रूप में भी अध्ययन करता है। इस निदर्शित में हम मनुष्य राष्ट्र मध्य जंम संगठनों का अध्ययन करते हैं।

नागरिक शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, विधियां और उपयोगिता

नागरिक शास्त्र की परिभाषा

नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन होता है। 'सिविक' शब्द लैटिन के 'सिविटस' और 'निबिस' शब्दों से निकला है। पहले शब्द का अर्थ है 'नगर' और पिछले शब्द का अर्थ है 'नागरिक'। उन अर्थ में, यह कहा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र मनुष्य का नगर के मध्य के रूप में अध्ययन है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि प्राचीन ग्रीक और रोम में आम तौर पर नगर-राज्य (City-State) हुआ करते थे। समय के बदलने के साथ राज्यों का आकार बढ़ता गया, यहां तक कि आब्र. अम, चीन और भारत के समान बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्य बन गये हैं। राज्य का आकार बढ़ जाने के साथ नागरिक शब्द का अर्थ भी विस्तृत हो गया है। आज नागरिक मियं नगर का मध्य नहीं है, बल्कि वह एक लम्बे-चौड़े और बड़े राजनैतिक संगठन, अर्थात् राज्य, का भी मध्य है, पर नागरिक शास्त्र के क्षेत्र की दृष्टि में इतना भी बांधी है। प्रत्येक नागरिक राज्य का मध्य होने के अनिश्चित मानी मनुष्य विरादगी का भी एक हिस्सा है। अब भारी मनुष्य ज्ञान का लाभ प्रत्येक अच्छे नागरिक को चिन्ता का विषय समझा जाना है। इसमें नागरिक शास्त्र का सहन्य बहुत विस्तृत हो जाना है। इसलिए अब नागरिक शास्त्र को मनुष्य के साम-पड़ोस की बातों का ही अध्ययन, अर्थात् उनके परिवार, गांव या नगर का ही अध्ययन, न समझना चाहिए, बल्कि कुछ समय पहले तक समझा जाता था, अब इस नागरिक और राज्य को सब समस्याओं का, चाहे वे स्थानीय हों, राष्ट्रीय हों, या अन्तराष्ट्रीय हों, अध्ययन मानना चाहिए।

नागरिक शास्त्र का क्षेत्र—इस पुस्तक के विषय-प्रवेश में हमने नागरिक शास्त्र के क्षेत्र और विषयवस्तु का काफ़ी परिचय दिया है। यहां हम उन सबका मध्य में उल्लेख करने विनये ये बातें स्पष्ट रूप से विद्यादिशे के सामने आ जाएं। नागरिक शास्त्र के क्षेत्र में एक बार तो नागरिक के रूप में मनुष्य के भय काभी का अध्ययन शामिल है, और दूसरे ओर, उन सब बातों का अध्ययन इसमें शामिल है जिनमें उनके अच्छा नागरिक बनने में मदद या रुकावट होती है। हर नागरिक किसी समाज का और किसी राज्य का अंग होता है। समाज में अनेक सारथियों या मध्य, मनुष्य और

सत्पाए होती हैं। उन्हें मनुष्य ने अपनी तरह-तरह की जरूरतें पूरी करने के लिये और अपने फायदे के लिये बनाया है। परिवार, गाँव, नगर और राज्य और दूसरे अनेक समूह नागरिक के काम करने की जगह हैं और इन सबका उसके जीवन के ऊपर गहरा असर पड़ता है। जाति, सम्पत्ति और धर्म जैसी अनेक सत्पाए भी उस पर अच्छा या बुरा असर डालती हैं, पर नागरिक किमी राज्य का सदस्य अवश्य होता है। इसलिए नागरिकता का अध्ययन करते हुए राज्य का, इसके जन्म, प्रवृत्ति, कामों और प्रयोजन का अध्ययन भी जरूरी हो जाता है। मनुष्य के साथ राज्य का सम्बन्ध सर्वोच्चता या प्रभुगता, नानून, आजादी, समानता और अधिकारों के मसले पैदा करता है। नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी को, इन शब्दों का अर्थ और इनका आपसी सम्बन्ध साफ-साफ समझ लेना चाहिए। फिर राज्य अपने अभिवृत्तियों, सरकार, के जरिये काम करता है। इसलिए सरकार के रूप, संगठन और कार्यप्रणाली भी नागरिक शास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। नागरिक शास्त्र सामाजिक इंजीनियरिंग का विज्ञान है। इस नाते इसका काम है अच्छे नागरिक पैदा करना और समाज में शान्ति और तालमेल कायम करना। शिक्षा, छुट्टी, मनोरंजन, सस्वृति और सम्यता से अच्छे और उपयोगी नागरिक पैदा करने में मदद मिलती है। दूसरी ओर, गरीबी, अनपठन, सराब तन्दुरुस्ती, बुरी सामाजिक प्रथाएँ, बुरी मस्याएँ और बुरे कानून अच्छी नागरिकता के दुश्मन हैं। इसलिए, नागरिक शास्त्र के गर्भधार विद्यार्थी का यह पता होना चाहिए कि नागरिक के जीवन के लिए अच्छी बातें कैसे अच्छी हैं, और बुरी बातें कैसे बुरी हैं। फिर, अच्छे नागरिक को अपनी निष्ठा सही जगह रखनी चाहिए। उसे न केवल अपने मूल्य के प्रति सच्चा होना चाहिए, बल्कि उसे मनुष्य मात्र से भी उतना ही प्रेम रखना चाहिए। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीयता और मधुवनराष्ट्र राष आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मस्याओं का अध्ययन भी नागरिक शास्त्र में आता है।

नागरिक शास्त्र विज्ञान भी है और कला भी—जिन विषयों में मनुष्य और उसके कामों का अध्ययन होता है वे सामाजिक विज्ञान कहलाती हैं। उनमें से एक नागरिक शास्त्र है। पर यह भौतिकी और रसायन की तरह यथार्थ विज्ञान (exact science) नहीं है। अतिवृत्तियों और रसायन में निष्कर्ष यथार्थ और सुनिश्चित होते हैं। उनके परिणामों में कोई हेर-फेर नहीं हो सकता। यदि कोई हेर-फेर हो तो प्रयोग द्वारा उनका कारण बताया जा सकता है। नागरिक शास्त्र में यह नहीं हो सकता। मनुष्य और उसकी मस्याओं पर प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, भौतिकी और रसायन में जिन वस्तुओं का वर्णन है, उनकी प्रवृत्ति और आचरण बदलना नहीं, पर मनुष्य का आचरण बदलता रहता है। यदि हम उनके आचरण के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालें तो संभव है कि कुछ समय बाद वे बिल्कुल बदल जायें। फिर, एक ही आदमी अलग-अलग वातावरण में अलग-अलग आचरण करता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र को यथार्थ विज्ञान नहीं कहा जा सकता।

इसलिए यह सुझाया गया है कि नागरिक शास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं। यदि विज्ञान शब्द का अर्थ एक हमरे से सम्बन्धित बहुत समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन है तो नागरिक विज्ञान को विज्ञान माना जाना चाहिए। नागरिक विज्ञान का विद्यार्थी अपने विषय को, समस्याओं पर वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने को सीखा जाता है। यह इतिहास पढ़कर सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी और तथ्य हासिल करता है, उनके अगर देखता है और अन्त में कुछ नतीजे निकालता है। इन सब बातों में नागरिक शास्त्र का विज्ञान चहुँपने का दावा करना साबित हो जाता है।

पर नागरिक विज्ञान का एक यही नाम नहीं। इसका मतलब इतना है कि पूरा विश्लेषण करता और उसे एक आदर्श नागरिक बनाना है। यह यह भी लक्ष्य करता है कि किस अवस्थाओं में सामाजिक जीवन सुखी और मेल-मिलाप वाला हो सकता है। इस जगह नागरिक विज्ञान एक कला बन जाता है। इसका एक क्रियात्मक मतलब होता है।

गणेश में, यह कहा जा सकता है कि नागरिक विज्ञान विज्ञान भी है और कला भी।

नागरिक विज्ञान के अध्ययन की विधियाँ

नागरिक विज्ञान का अध्ययन उन्हीं विधियों से होता है जिनसे अन्य सामाजिक विज्ञानों का।

(१) प्रायोगिक विधि

हम मनुष्य और उसकी समस्याओं में उस तरह प्रयोग नहीं कर सकते, जिस तरह नीतिकी और रसायन द्रव्य में करते हैं। पर मनुष्य के प्रयोगों के लिये मारा मसाला एक प्रयोगशाला है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि मनुष्य के अनुभवों के अनुसार व्यवहारों और समस्याओं के रूप बदलते रहते हैं। हर अनुभव मनुष्य को अधिक बुद्धिमान बना देता है, और वह तत्पक्षी की ओर बढ़ता जाता है। परीक्षण या प्रयोग की विधि नागरिकता की प्रयोगशाला में बड़ी महत्वपूर्ण होती है।

(२) प्रेक्षण (Observation) की विधियाँ

प्रयोग की विधि असल में प्रेक्षण या अच्छी तरह देखने पर आधारित है। हम अपनी सामाजिक संस्थाओं की काम करने हुए देखते हैं, उनके प्रभावों का विश्लेषण करते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। हम दूसरे देशों में हम प्रकार की समस्याओं की कार्यप्रणाली देखते हैं और उनकी-मुल्यता अपनी समस्याओं से करते हैं।

तब तब कोई इशारा हासिल नहीं होता जब तक हम जाच-पड़ताल की और विधियों का भी उपयोग न करें।

(३) तुलनात्मक विधि (Comparative Method)

अमल में प्रेक्षण की विधि है। तुलना के लिए जाच करन बाग्य सामग्रो जमा करता है, उसे व्यवस्थित करता है और जगों में बाँटता है और तुलना तथा छटाई (selection) द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मस्याआ के आदर्श रूपो का पता लगाना है।

(४) ऐतिहासिक विधि

तुलनात्मक विधि तब तक उपयोगी नहीं हो सकती जब तक हमका कोई ऐतिहासिक आधार न हो। सामाजिक मस्याआ को भूतकाल क ज्ञान के द्वारा हा अच्छी तरह समझा जा सकता है और इन मस्याआ के जन्म और विकास की परिस्थितिया को जानकर तथा इस बात की ध्यानाचना करके कि आज उनका होना कहा तक उचित है हम भविष्य के लिये कुछ भील सकते हैं।

(५) दार्शनिक विधि

नागरिक विज्ञान यह भी बताता है कि नागरिक कैसा होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी को कल्पना की दुनिया में घुसना पडता है। यह मनुष्य की प्रकृति के बारे में कुछ व्यापक सिद्धान्तो के आधार पर अपने निष्कर्ष निकारता है और सामाजिक मस्याआओ से उनका सम्बन्ध जोडता है।

पर यह एक चेतावनी देना उचित होगा। हमारी कल्पना बहुत उडन वाली न होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, यह बात जहा तक हो सके इस बात में प्रल खानी चाहिए कि कैसा हुआ जा सकता है। इस प्रकार कल्पना करत समय हमें उन सामाजिक परिस्थितियों में, जिनमें कोई नागरिक रहना है, बिल्कुल अलग ध्यान न हो जाना चाहिए। इन सब बातो को ध्यान में रखने हुए आदर्श नागरिक पैदा करने के लिए सज्जार्ड में यत्न करना चाहिए।

नागरिक शास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है? इसकी उपयोगिता

नागरिक विज्ञान के अध्ययन के व्यावहारिक फायदे बहुत अधिक हैं और उनसे निम्नलिखित लाभ होने हैं —

(१) पहली बात तो यह है कि नागरिक विज्ञान सामाजिक इमोनियरिज्म का विनाश है। यह हमें मिलकर रहने का ठोक तरीका सिखाता है। यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सही विचार देता है और इस तरह हमारे अन्दर नागरिक बुद्धि पैदा करता है। यदि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही पता हो तो समाज के संपर्क बहुत कम हो जाते हैं, नागरिकों में अधिक मतभेद और शक्ति रहती है, और मात्र समाज अच्छी तरह तरकी करता है। लोग में अधिक सहयोग और प्रेम होता है। अधिकारों के बारे में मिथ्या भावनाओं पर होने वाली लडाइयों पर जो ताकत बरबाद होती है, उसे खराब तन्दुलम्ती, अनपढ़पन, गरीबी, बुरी प्रथाओं

और अन्य सामाजिक दुरादृशों को हटाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

सारारगतता हम सब लोगों में यह संघ है कि हम अपने अधिकारों पर तो जोर देते हैं, पर साथ ही अपने कर्तव्यों की नहीं पहचानते। नागरिक विज्ञान हमें यह सिखाता है कि अधिकार और कर्तव्य एकट्ठे चलते हैं। जहाँ कर्तव्य नहीं, वहाँ अधिकार भी नहीं। इसी प्रकार यह हमें सिखाता है कि हमें हर बात के लिये हमेशा राज्य और सरकार का ही सह न देखना चाहिए। हमें, कम से कम, अपनी ही महत्त्वता बरके राज्य की मदद करना चाहिए। नागरिकों की महत्त्वता के बिना राज्य का कुछ भी काम नहीं चल सकता।

(२) दूसरी बात यह है कि नागरिक विज्ञान हमारे द्वारा-उत्तर बड़ी हुई निष्ठाओं (loyalties) को समझना हमें करता है—यह सामाजिक आवश्यकता का मान-दंड वापस करता है और मनुष्य को यह समझने लायक बनाता है कि उसे अपने परिवार अपने पड़ोसियों, अपने गांव या नगर अपने राज्य, और अन्ततः, मनुष्य मात्र से कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमारे परती निष्ठा मदा बड़े समूह के लिये होना चाहिए और हमें सामाजिक लाभ के लिये छोटे स्वार्थों को छोड़ना सीखना चाहिए।

(३) तीसरी बात यह है कि नागरिक विज्ञान समाज तथा सरकार को मरतना, संगठन और कार्य प्रणाली के बारे में हमारे दृष्टिकोण और ज्ञान को विस्तृत करता है। हम यह जानने लगते हैं कि आज का समाज रितना जटिल हुआ है। हमें यह पता चलता है कि हमने हमारा स्थान कहाँ और हमके अनेक अर्थों में हमारा क्या सम्बन्ध है। इस ज्ञान से नागरिक को अपने रोजाना के कामों में बड़ी मदद मिलती है। इनसे उसका अपना काम अच्छी तरह करने का हीमना बढ़ता है। इसके बिना नागरिक समाज और सरकार का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकेगा, म यह स्वयं समाज के लिये बहुत कुछ कर सकेगा।

(४) चौथी बात यह है कि लोकतन्त्र के नागरिकों के लिये मान कर नागरिक विज्ञान अध्ययन बहुत आवश्यक और लाभदायक है। लोकतन्त्र की लाक्षणिक परिभाषा यह है कि 'जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिये शासन।' इस प्रणाली में किसी अच्छी, या बुरी, सरकार की चुनने की अधिकार जिम्मेदारी और सशक्तता रहकर इन नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी नागरिकों के कंधों पर पड़ती है। इस प्रकार, यदि किसी लोकतन्त्र के नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अहसास नहीं, तो उनके लोकतन्त्रीय सरकार ठीक तरह काम नहीं कर सकती। हर नागरिक को अपना बंट का अधिकार समझना और ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। बंट के अधिकार का समझना ही इस्तेमाल करने के लिये सामाजिक और राजनीतिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी जरूरी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नागरिक विज्ञान से नागरिक को यह जानकारी हासिल होने में मदद मिलती है। आजकल अधिकतर देशों में लोकतन्त्रीय सरकारें हैं, इसलिए आज के जनता में नागरिक विज्ञान के अध्ययन का और भी अधिक महत्त्व हो गया है।

(५) पाचवीं बात यह है कि नागरिक विज्ञान के अध्ययन का छात्रों के लिये बड़ा महत्व है। आज के छात्र ही कल के नागरिक होंगे। नागरिक विज्ञान की जानकारी उन्हें ठीक तरह का नागरिक बनने में मदद देनी है। नौजवान ही किसी राष्ट्र की माना होते हैं। कुछ वर्ष बाद वे ही नागरिक बनकर इसके भाग्य विधाता होंगे। राष्ट्र की शक्ति उनके चरित्र और मिथा पर निर्भर है। इसलिए नौजवानों को अपने शरीरों को शिक्षित करना, अपने दिमाग को योग्य बनाना और अपने चरित्र का विकास करना जरूरी शुरू कर देना चाहिए जिससे वे देश के सामने आने वाले अनेक समस्याओं को हल कर सकें। नागरिक विज्ञान उनके सामने नागरिकता और मुसीबतमाज, इन दोनों के जरूरी आदर्श पेश करता है।

हमारे देशवासियों के लिये नागरिक विज्ञान का महत्व

यद्यपि भारत का आकार, जावादी और मापन बहुत बड़े हैं, तो भी यदि उसकी गुलना अमरीका, रूस और इंग्लैंड जैसे आगे बढ़े हुए मुल्कों में की जाये तो वह बहुत पिछड़ा हुआ है। उसके पिछड़े होने का एक कारण यह है कि उसने सदियों की मुसामी के बाद अभी हाल में आजादी हासिल की है। पर माय ही हम अपनी समाज की गहरी बुराइयों से बाख़े नहीं मोच सकते। हमारे अन्दर नागरिक बृद्धि की बहुत कमी है। साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, जहालत, गरीबी और कराव तन्दुर्गती हमारी कुछ मोटी बुराइयों में से हैं। जाति प्रथा, छुआछूत, स्त्री-दुष्प का भेदभाव और बहज प्रथा जैसी बुराइयाँ हमारे देश में आज भी फैली हुई हैं। हमारे अन्दर वह चरित्र नहीं जो स्वतन्त्र लोकतन्त्रीय देश के नागरिकों में हुआ करता है। खुदगर्बी, काहिली, बड़ो का हुकूमत मानना, आगे बड़ने से भय और जिम्मेदारी को भावना की कमी, हमारे चरित्र की कुछ मोटी विशेषताएँ हैं। अगर हमारा धम चले तो हम टंकम ठा अदा करने ही नहीं और बेसा न करने पर फरः भी करने हैं। हम रोज सरकार का गाली देने हैं कि उसने अबतक रामराम्य नहीं बनाया और स्वयं उसके लिये कोई कारिना नहीं करने।

यदि ऊपर कही गई सब बृद्धियों को चलने दिया जाए तो इसने हमारी नयी आजादी को लगरा पेश हो जाएगा। यदि हमने अपनी कमियों को महसूस नहीं किया तो लाकतन्त्र का प्रयोग अमफल हो जायेगा। हमें अच्छे नागरिक बनने की कोशिना करनी चाहिए और नागरिक विज्ञान का अध्ययन हमारी समस्याएँ हल करने में बहुत मदद करेगा।

सारांश

नागरिक शास्त्र की परिभाषा

मिचिक्म टाट्ट लेटिन के 'मिचिटम' और 'मिचिम' शब्दों से निकला है, जिनका अर्थ क्रमशः 'नगर' और 'नागरिक' है। इसका यह अर्थ नहीं है कि नागरिक शास्त्र मनुष्य का सिर्फ नगर के महसूस के रंग में अध्ययन करता है। आज राज्य नगर में बहुत बड़ी चीज है और इसलिए नागरिक शास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र भी बड़ा गया है। नागरिक न केवल राज्य का सदस्य है बल्कि वह शारी मानव विरादरी का भी एक सदस्य है। इस

प्रकार, नागरिक शास्त्र की भी परिभाषा यह की जा सकती है कि 'नागरिक का और राज्य का उसकी स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सब प्रकार की समस्याओं की दृष्टि में अध्ययन करना।'

क्षेत्र—नागरिक शास्त्र के अध्ययन में निम्नलिखित क्षेत्र आती हैं —

(१) नागरिक का और उसके अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन; (२) महत्वपूर्ण साहचर्यों—जैसे परिवार और राज्य का, नगर और राज्ज जैसे समुदायों का, सम्पत्ति, जाति और धर्म जैसे मस्यारों का अध्ययन, (३) उन अनेक तरह के प्रभावों का अध्ययन जो नागरिक को अच्छा या बुरा बनाते हैं, जैसे परिवार, सम्पत्ति, जाति या धर्म, शिक्षा, अवकाश या छुट्टी, मनोरंजन, गश्कृति, और सम्पत्ता, (४) राज्य का, और अलग-अलग नागरिक के साथ उसके सम्बन्ध का, अध्ययन, इसमें राज्य के उद्गम, प्रकृति, कार्यों, प्रयोजन या मकसद का और प्रभुमत्ता, कानून, अधिकार, स्वतन्त्रता और समानता आदि समस्याओं का अध्ययन भी शामिल है, (५) राज्य के अधिकर्ता, सरकार, का अध्ययन, जिसमें सरकार के कार्यों का, और तीन अर्थों, अर्थात् विधानाय, कार्य और व्यापार, के रूप में उसके संगठन का अध्ययन भी शामिल है; (६) जनता के कार्य का अध्ययन जिसमें राजनैतिक दलों और लोकमत का अध्ययन भी शामिल है, (७) समुक्त राष्ट्र मण जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन।

नागरिक शास्त्र विज्ञान भी है और कला भी

नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। प्रणालीबद्ध ज्ञान के तौर पर यह एक विज्ञान है, पर यह नैतिकी और रणायन की तरह यथार्थ विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसे मनुष्य का अध्ययन करना होगा है, जिसका व्यवहार समय और वातावरण के बदलने पर बदल जाता है।

नागरिक शास्त्र एक कला भी है, क्योंकि इसका लक्ष्य अच्छे नागरिक पैदा करना और सुखी तथा भेल-मिलाप का सामाजिक जीवन बनाना है।

नागरिक शास्त्र की विधियाँ

नागरिक शास्त्र के ही विधियाँ इस्तेमाल करना है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों में इस्तेमाल होती हैं। प्रयोगात्मक विधि इस कारण उपयोगी है, क्योंकि मानवीय अनुभव से मानवीय मस्याएँ बदल जाती हैं, और हर तजुबों के बाद इन्मान अधिक अकल्पमन्द हो जाता है। प्रेक्षण (observation) की विधि इसलिए उपयोगी है क्योंकि दुनिया भर में मौजूद अनेक मानवीय मस्याओं के काम से तरीकों को अच्छी तरह देखे बिना नागरिक शास्त्र में सही निष्कर्षों पर पहुँचना कठिन है। तुलनात्मक विधि हमें अलग-अलग मस्याओं के काम की तुलना करने में मदद देती है। ऐतिहासिक विधि द्वारा हमें विभिन्न मस्याओं के मनीव के अध्ययन से उन्हें गहरी रूप में समझने का मौका मिलता है। दार्शनिक विधि से हम, जो होना चाहिए उसका, जो हो सकता है उससे साथ में विचारना सीखते हैं।

नागरिक शास्त्र की उपयोगिता

नागरिक शास्त्र के अध्ययन में निम्नलिखित लाभ होते हैं —

(१) यह हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही रूप बताकर जीने की सही विधि सिखाता है ।

(२) यह हम बताता है कि हमारी पहली निष्ठा सबसे बड़े समुदाय के प्रति होती चाहिए और हम तरह-तरह हमारी विभाजित निष्ठा का हल करने की वासिधा करना है, और हमें स्वार्थभाव छोड़ने में सहायता देता है ।

(३) यह हमें सामाजिक ढांचे और सरकारों के पक्षी-दमियाँ और काम करने का तरीका बताकर हमारे दृष्टिकोण का बड़ा करता है ।

(४) लोकतन्त्र के नागरिकों के लिए नागरिक शास्त्र का अध्ययन उपयोगी और आवश्यक है ।

(५) छात्रों के लिये यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बल उन्हें ही नागरिक बनना है ।

(६) हम भारतवासियों के लिए नागरिक शास्त्र का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन में पार फुटिका है ।

प्रश्न

QUESTIONS

- १ नागरिक विज्ञान की परिभाषा लिखो और इसका क्षेत्र बताओ ।
- 1 Define Civics and give its scope
- २ नागरिक विज्ञान का क्षेत्र और उपयोगिता बताओ ? (५ वि. सितम्बर, १९५०)
- 2 Indicate the scope and utility of Civics (P U Sept 1950)
- ३ नागरिक विज्ञान के अध्ययन के क्या लाभ हैं ? (५ वि. अप्रैल, १९४८)
- 3 What are the advantages of the study of Civics (P U April, 1949)
- ४ नागरिक विज्ञान की परिभाषा लिखो । यह एक विज्ञान है या कला ?
- 4 Define Civics Is it a science or an art ?
- ५ नागरिक शास्त्र की परिभाषा करो और सामाजिक विज्ञान के रूप में इसका स्थान बताओ ? (५ वि. अप्रैल १९५०)
- 5 Define Civics and indicate its place in the social sciences. (P. U April, 1950)

नागरिक शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों में संबंध

जो विज्ञान मनुष्यों और उनके कार्यों का वर्णन करते हैं, वे सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं। नागरिक शास्त्र, इतिहास, अपराधशास्त्र, राजनीति विज्ञान, आचारशास्त्र (Ethics), समाजविज्ञान (Sociology) और मनोविज्ञान (Psychology) — ये सब सामाजिक विज्ञान हैं, क्योंकि उनके अध्ययन का विषय मनुष्य-जीवन का कोई पहलू है। नागरिक विज्ञान नागरिकों के रूप में मनुष्य का अध्ययन करता है। मनुष्य का व्यक्तित्व एक 'अखंड संपूर्ण' (integrated whole) है और इसके एक पहलू को दूसरे पहलुओं में अलग नहीं किया जा सकता। उसके एक तरह के कामों का अध्ययन दूसरे कामों को बिलकुल छोड़कर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, बही आदमी, एक ही समय, एक परिवार का सदस्य होता है, एक राज्य का सदस्य होता है, किसी का कर्मचारी होता है, इत्यादि। दूरी प्रचार, छात्र के रूप में तुम्हारे जो काम हैं, अर्थात् तुम्हारा पढ़ना और खेलना, उन पर तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति और उसकी अन्य अवस्थाओं का प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहरा सम्बन्ध है, वैसे ही इन पहलुओं का अध्ययन करने वाले अनेक सामाजिक विज्ञान भी एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह सम्बन्धित हैं।

नागरिक शास्त्र और समाज विज्ञान दोनों में अन्तर

(१) समाज विज्ञान सब सामाजिक विज्ञानों का जन्मदाता विज्ञान है। इसमें समाज के तारे रूप पर विचार होता है और इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह सामाजिक जीवन के सब पहलुओं, अर्थात् आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। इस रूप में यह हर एक बात पर विस्तार में विचार नहीं कर सकता। दूरगामी और, नागरिक शास्त्र सामाजिक जीवन के सिर्फ एक पहलू का विशेष अध्ययन करता है, अर्थात् नागरिक और अन्य व्यक्तियों तथा समूहों की दृष्टि से उसके अधिकार और कर्तव्य। अन्त में, समाज विज्ञान माना है और नागरिक शास्त्र सिर्फ पुत्री है। समाज विज्ञान में नागरिक शास्त्र भी आ जाता है।

(२) नागरिक शास्त्र यह मानकर चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज विज्ञान इस समस्या पर गहराई से विचार करता है कि मनुष्य क्यों और कैसे सामाजिक प्राणी है।

नागरिक शास्त्र परिवार, गांव, नगर और राज्य जैसी कई सामाजिक समस्यओं के जन्म और वृद्धि के बारे में सही जानकारी समाज विज्ञान से ही हासिल करता है। समाज विज्ञान से हम निजी सम्पत्ति और समाज में प्रचलित कई अन्य प्रथाओं के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं।

नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान सम्बन्ध

(१) राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन होता है और नागरिक शास्त्र में नागरिकता का, और इन दोनों का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। राज्य के बिना नागरिक नहीं हो सकता। राज्य और नागरिकता का अध्ययन इन दोनों विज्ञानों में होता है। फर्क सिर्फ जोर देने का है। नागरिक शास्त्र में नागरिकता और उसमें तान्त्रिक रखने वाली समस्यओं के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए राज्य के अध्ययन का कम महत्व है। दूसरी ओर, राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः राज्य का अध्ययन है और नागरिकता की चर्चा उसमें कहीं प्रथम से ही आती है।

दोनों में अन्तर—

(१) जैसा ऊपर कहा जा चुका है, दोनों विज्ञानों के अध्ययन का क्षेत्र अलग-अलग है। इसके अलावा, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र नागरिक शास्त्र के क्षेत्र के अपेक्षा बहुत बड़ा है। राजनीतिक विज्ञान राज्य की समस्याओं तथा राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मवालों की गहराई में जाना है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन नागरिक के वातावरण तक ही सीमित रहता है।

(२) राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अधिकतर विचारान्मक और दार्शनिक है। नागरिक शास्त्र अधिकतर एक प्रायोगिक विज्ञान है। नागरिक शास्त्र का मतभेद है सर्वोत्तम नागरिक पैदा करना।

नागरिक शास्त्र और इतिहास का सम्बन्ध

इतिहास समाज के गुजरे हुए सामाजिक, राजनैतिक, जायिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की अवस्थाओं और विकास की तस्वीर होता है। जो मस्याएँ आज नागरिक के जीवन पर इतना गहरा असर डाल रही हैं, उनकी मौजूदा कार्यप्रणाली को पूरी तरह समझने के लिये हम उनके जन्म और वृद्धि का भी अध्ययन करना होगा। यह ज्ञान हमें इतिहास से ही मिल सकता है। उदाहरण के लिये, जाति प्रथा, अविभक्त परिवार, छुआछूत, जमींदारी और उत्तराधिकार के कानून आदि नागरिक के जीवन पर इतना गहरे रूप से असर डाले हैं, पर उन्हें उनका इतिहास बिना देखे ठीक तरह समझा नहीं जा सकता। इसी प्रकार नागरिक का राज्य में बड़ा सम्बन्ध है। राज्य की सही प्रवृत्ति और प्रयोजन को समझने के लिये नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी को इसके जन्म और वृद्धि पर अवश्य विचार करना चाहिए।

जोनों में अन्तर

(१) पर उनकी विषय-वस्तु भिन्न है। एक तो आचार व नियमों का विज्ञान है और दूसरा नागरिकता का, (२) आचार शास्त्र का मध्य काम के भौतिक (प्रेरक और आराध) तथा बाह्य (स्वयं काम) दोनों भागों से है। नागरिक शास्त्र निरंक मनुष्य के बाह्य व्यवहार से संबन्ध रखता है।

नागरिक शास्त्र और मनोविज्ञान

मनोविज्ञान में मन का अध्ययन होता है। यह भावनाया मन्त्रना, जन्मना, सृष्ट्यवृत्तिया, भावा, भावावेशो, और बुद्धि का अध्ययन करता है। इनमें ही मानवीय व्यवहार प्रेरित होता है। नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह मनुष्यों के रूप में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। स्वभाव मनुष्य के नाशों के प्रत्यक्ष भावा की जानकारी, अर्थात् यह जानना कि वे मनुष्य एक स्वाम तरह में कैय और कयो व्यवहार करने हैं, नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए उपयोगी होता।

सारांश

नागरिक शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि सब सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का विषय एक, अर्थात् मनुष्य, है।

नागरिक शास्त्र और समाज विज्ञान

समाज विज्ञान जनक विज्ञान है और इन रूप में यह माना है तथा नागरिक शास्त्र इनका पुत्र है। समाज विज्ञान का क्षेत्र नागरिक विज्ञान के क्षेत्र की अपेक्षा बहुत विस्तृत है। समाज विज्ञान सारे सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, पर नागरिक शास्त्र निरंक एक पट्टी का, अर्थात् मनुष्य के नागरिक रूप का अध्ययन करता है। तो भी, परिवार, नगर और राज्य जैसी कई सामाजिक समस्याओं के उद्गम और वृद्धि की सही जानकारी के लिये नागरिक शास्त्र समाज विज्ञान पर निर्भर है।

नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान

नागरिक का और राज्य का अध्ययन दोनों में एकलमान है, पर राजनीति विज्ञान मुख्यतः राज्य का अध्ययन है और नागरिकता पर वह निरंक प्रसंगत विचार करता है। दूसरे ओर, नागरिक शास्त्र नागरिकता के अध्ययन पर ध्यान देता है और राज्य का अध्ययन नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए गौण महत्व का है।

नागरिक शास्त्र और इतिहास

इतिहास नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी का नागरिक के जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा लेने वाला, अनेक सामाजिक समस्याओं के उद्गम, वृद्धि, प्रवृत्ति और मौजूदा कार्यप्रणाली को सही रूप में समझने में सहायता देता है। तो भी, इतिहास का अधिकांश नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए अप्रामाणिक है। दूसरे, इतिहास अधिकतर स्यात्मक और घटनाक्रम के रूप में होता है, पर नागरिक शास्त्र आदर्शिक (Normative) तथा क्रियात्मक विज्ञान है।

नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र

नागरिकशास्त्र का अर्थशास्त्र से भी सम्बन्ध है क्योंकि नागरिक और समाज का गुण सम्पत्ति के उत्पादन और उचित वितरण पर निर्भर है। गरीबों और बेकारी जल्दी नागरिकता के बड़े धनु है। इन समस्याओं को अर्थशास्त्र से हल किया जाता है। तो भी नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र एक-दूसरे से अलग दो सामाजिक विज्ञान है।

नागरिक शास्त्र और आचार-शास्त्र

आचार शास्त्र आचार सम्बन्धी विज्ञान है। यह गुण और दोष में भेद करता है। अच्छे नागरिक को गुण प्राप्त करने चाहिए और दोषों से बचना चाहिए। इन गुणों और दोषों का ज्ञान, और मनुष्य तथा समाज पर इनके प्रभावों का ज्ञान आचार शास्त्र में ही हो सकता है। इसलिए नागरिक-शास्त्र और आचार शास्त्र में सम्बन्ध है पर दोनों विज्ञानों में भेद भी है। आचार शास्त्र सारी क्रिया का अध्ययन करता है और नागरिक शास्त्र क्रिया के सिर्फ बाहरी भाग का अध्ययन करता है।

नागरिक शास्त्र और मनोविज्ञान

नागरिक शास्त्र मन का अध्ययन करता है और मनुष्य के व्यवहार के विभिन्न प्रकार की बातों के बारे में ज्ञान देता है। चूंकि नागरिक शास्त्र सामाजिक निर्माण का विज्ञान है, इसलिए उसे यह जानना ज़रूरी है कि आदमी एक स्थान से दूसरे में कैसे और क्यों व्यवहार करता है।

प्रश्न

QUESTIONS

- १ नागरिक शास्त्र की परिभाषा करो। नागरिक शास्त्र का राजनीति, अर्थशास्त्र, और आचार शास्त्र से किस प्रकार सम्बन्ध ? (ए वि सितम्बर १९५३)
- 1 Define Civics How is Civics related to Politics, Economics and Ethics ? (P U. Sep 1953)
- २ स्पष्ट रूप से बताइये कि नागरिक शास्त्र समाज विज्ञान, आचार शास्त्र और इतिहास से किस तरह सम्बन्धित है।
- 2 Explain clearly how Civics is related to Sociology, Ethics and History

अध्याय : : ४

मनुष्य और समाज

मनुष्य की सामाजिक प्रकृति

मनुष्य की प्रकृति दो भागों में बर्ती है जिनमें से एक पार्श्विक है और दूसरा बौद्धिक (animal and rational) । पशु के नाते उसमें कुछ सहज प्रवृत्तियाँ हैं, जो उसे सामाजिक होने के लिये मजबूर करती हैं । पहली बात तो यह है कि जोर पशुओं की तरह मनुष्य में प्रबल मूषचारी (gregarious) वृत्ति होती है । जैसे पशु झुण्ड बनाकर चलते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य भी हमेशा समूहों में रहना हुआ पाया जाता है । कहीं कोई आदमी एकांत जीवन बिताता हुआ नहीं दिखाई देता । जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले सापुओं और फकीरों का उदाहरण देकर प्रायः यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि मनुष्य बिना समाज के रह सकता है पर हमें यह याद रखना चाहिए कि इन लोगों का भी समाज में वाक्यादा मजबूत बना रहता है । उनकी पाम कुछ शिष्यमंडली रहती है और गहर से भक्त मंडली उनके पाम आनी-जानी रहती है ।

दूसरी बात यह है कि दो और सहज प्रवृत्तियाँ हैं जो मनुष्य को सामाजिक बनाती हैं, अर्थात् जनकीय प्रकृति (parental instincts) और लैंग प्रकृति (Sex instinct) । ये दोनों प्रवृत्तियाँ पारिवारिक जीवन का मूल हैं । परिवार मनुष्य जाति में एक प्राकृतिक समूह है ।

पशु होने के अलावा, मनुष्य बुद्धियुक्त (rational) भी है । इस गुण में वह सामाजिक बनने के लिये और भी अधिक मजबूर हो जाता है । हर मनुष्य को मरणाप के लिये और जरा देर रहने के लिये साथी चाहिए । वह दूसरों के विचार सुनकर या अपने विचार उन्हें बताकर अपना निरह्ला वर लेना चाहता है । इसी लक्ष्य से यह बात स्पष्ट होती है कि बहुत दिनों तकलाई की कैद की सजा भुगतने वाले लोग क्यों पागल हो जाते हैं । तनलाई कैद सबसे अधिक बुरी सजाओं में मानी जाती है । इसी प्रकार, हर आदमी का अपनी गुप्त बातें करने के लिये या सलाह लेने के लिये दोस्त चाहिए । फिर, यश प्राप्त करने, बुवाई करने, कृतज्ञता, प्रेम, और आदर प्राप्त करने की इच्छाएँ दूसरों के साथ के बिना पूरी नहीं की जा सकती । इसीलिए अरस्तू ने कहा था कि 'जो आदमी सामाजिक नहीं है वह या तो पशु है या देवता ?' इस प्रकार समाज मनुष्य के लिये बिल्कुल स्वाभाविक है ।

मनुष्य अपनी आवश्यकता के कारण भी सामाजिक है । बहुत सी बातें उसे

दुसरों के साथ रहने के लिये मजबूर बनता है। वे धार्मिक मान्यताएँ दी जाती हैं —

शारीरिक कमजोरी—शारीरिक दृष्टि से मनुष्य इतना मजबूत नहीं कि अकेला प्रकृति का सामना कर सके। बर्षा और सूकान, गर्मी और सर्दी, पहाड़ और नदियाँ, जंगल पशु और रोग तथा दुर्घटनाएँ आदि दुसरों की सहायता से ही जीने के लिए एक अकेला आदमी उठ पाए नहीं कर सकता। इन सब सतहों में अपने जीवन की सफलता के लिए मनुष्यों को सहयोग करना होगा। मिर्माजुली बोधिग ने मनुष्य के कुदरत को जीत लिया है।

आर्थिक जरूरतें—मनुष्य की जरूरतें बहुत मारो हैं। वह उन सबको अकेला पूरा नहीं कर सकता। किसी अकेले आदमी के लिये अपना भोजन बनाना, अपना भनाज उगाना, और अपने कपड़े तैयार कर सकता बिल्कुल असंभव है। इनके अलावा, आदमी को और भी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। इन्हें लिए लोग, धर्म विभाजन के समूह पर काम करने हैं और इन तरह अपनी जरूरतें पूरा करते हैं।

यौन प्रकृति और जनकीय प्रकृति—ये दोनों प्रकृतियाँ उसे सामाजिक होने के लिये मजबूर करती हैं। नर और नारी का सम्मिलन यौन प्रकृति के कारण ही है। यह सम्बन्ध आदम और इत्सा के जमाने में बना जाया है। हर इन्सान बालक में आदमी बनता है। अगर बच्चे न हो तो मनुष्य जाति खत्म हो जायगा। फिर, कोई बच्चा अपनी देवनाल मुद नहीं कर सकता। इसलिए कुदरत ने इन्सान में जनकीय प्रकृति रख दी है और इस तरह उसे परिवारों में अपने बच्चों का पालन करने के लिये मजबूर कर दिया है।

घोलने की ताकत—मनुष्य की बोलने की ताकत भी इन्हीं बजहों से है कि वह सामाजिक प्राणी है। यदि किसी बच्चे से कोई भी न बोलें तो वह बोलना नहीं सीख सकता।

अच्छा जीवन—इन्सान सिर्फ रोटी में नहीं जीता। उसे समाज की जरूरतें सिर्फ अपनी प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरा करने के लिये ही नहीं हैं बल्कि अच्छे जीवन के लिये भी है। अच्छे जीवन में सम्मति और सम्मति भी आती हैं। अन्ततः के आतिथ्य, दसन और कर्म तथा माहित्य की चीजें अपनी कर्म और विचारों की अपनी बदल-बदल का नतीजा है। अगर समाज न हो तो न खाली मरना होगा और न कोई विचारों की बदल-बदल होगी।

समाज किसे कहते हैं—इस देश चुके हैं कि हर आदमी को दूसरे आदमी का साथ जरूर शामिल करना पड़ता है। जब लोग एक उद्देश्य रखकर आपस में मिलते हैं या कुछ माले हितों के कारण वे इकट्ठे हो जाते हैं तब उनका एक समाज बन जाता है। मिर्माजुली बोधिग ने समाज के बारे में स्पष्ट विचार बन जायगा —

(१) समाज एक व्यापक शब्द है और इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। समाज शब्द १० व्यक्तियों के समूह के लिये भी बोला जा सकता है, और नारी, मनुष्य जाति के लिये भी। किसी परिवार को भी छोटे तौर से समाज कहा जा सकता है। अलग-अलग तरह के समूहों के लिये अलग-अलग शब्द हैं।

(२) समाज जम्पायी भी हो सकता है और स्थायी भी। रेल के टिकटों में गफर करने वाले मुद्राधिकारी भी एक समाज बना लेते हैं, यद्यपि वह जम्पायी ढंग का होता है। दूसरी ओर, राज्य एक स्थायी ढंग का समाज है।

(३) समाज शब्द के अन्दर संगठित और असंगठित दोनों तरह के समूह आते हैं। कोई परिवार फालेज या कल्प संगठित समूहों के उदाहरण है। बाजार में जादू या खेल देखने जाने लोगों की भीड़ असंगठित समूह का उदाहरण है।

(४) समाज की कोई प्रादेशिक सीमा भी नहीं होती। एक अर्थ में भूमण्डल पर रहने वाली सारी मनुष्य जाति ही एक समाज है।

समाज का गठन—समाज की संरचना बड़ी जटिल होती है। इसमें अनेक साहचर्य, समुदाय और संस्थाएँ शामिल होती हैं।

साहचर्य या सघ (Association)—साहचर्य या सघ उन समूहों का नाम है जिनमें कई व्यक्ति एक साझे उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपने आपको संगठित कर लेते हैं।

समुदाय—समुदाय उन लोगों के समूहों को कहते हैं जिनमें कुछ साझे हितों के कारण एकता की भावना हो। कभी-कभी लोगों में एक भूगोल पर निवास के कारण कुछ साझे हित पैदा हो जाते हैं। इसी अर्थ में मैकाइवर ने गाँवों और नगरों को समुदाय कहा। अन्यथा समुदाय के लिये प्रदेश का होना लाजमी नहीं। उदाहरण के लिये, जब हम छात्र समुदाय कहते हैं, तब समुदाय शब्द से हमारा मतलब किसी प्रदेश से नहीं होता। इसी प्रकार धर्म के साझे हित के कारण हम लोगों को हिन्दू, सिख, मुस्लिम और ईसाई समुदायों में रखते हैं। ईसाई समुदाय सारी दुनिया में फँसा हुआ है। समुदाय के सदस्यों के लिए सघ की तरह संगठित होना जरूरी नहीं। समुदाय सघ से बड़ा भी होता है। सघ तो यह है कि एक समुदाय में कई सघ हो सकते हैं।

संस्था—उन नियमों या प्रथाओं और वानुओं को संस्था कहते हैं जो किसी समूह के सदस्यों के आपसी सम्बन्ध निर्दिष्ट करते हैं। जाति-प्रथा, विवाह, तलाक और अविभक्त परिवार प्रणाली, ये सब संस्थाएँ हैं।

समाज का जन्म और विकास—कोई नहीं कह सकता कि मनुष्य ने समाज में रहना सबसे शुरू किया। समाज उतना ही पुराना होगा जितना आदमी, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य के जीवन के विलुप्त शुरु में वह सामाजिक है। समाज की वृद्धि मरल में जटिल की ओर हुई है। आज समाज का ढांचा बड़ा जटिल है। समाज या विकास इन अवस्थाओं से हुआ होगा —

परिवार—सबसे पुराना और सबसे मरल मानव समाज ऐसा परिवार होगा जिसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे होंगे।

गोत्र (Clan)—जबान छटकें सारी के बाद अपने अलग परिवार बनाने से, पर वे अब भी उर्म, बुजुर्ग की बात मानकर चलने थे। इस तरह एक जगह से शुरू होने वाले परिवारों का समूह गोत्र कहलाने लगा।

गण या जनजाति या कबीला (Tribe)—कई गोत्र मिलकर एक गण हो गए।

गण की अदम्या में एक सम्बन्ध बमजोर हो गया और सत्ता सून की दृष्टि में सबसे बड़े सभ्य से हटकर सबसे अधिकगामी सभ्य के पास पहुँच गई जो लडाई के समय बर्बाने की रक्षा कर सकता था। यह आदर्श बर्बाने का सरदार बहाना बना। बर्बाने का सरदार धरि-धरि राजा हो गया।

राज्य—जब किसी साम्र प्रदेश में रहने वाले बर्बानों ने कानून और व्यवस्था के लिये किसी राजा के मान्यता करने जाकरा सगठित करना कुछ विद्या गव राज्य का जन्म हुआ। तभी से मानव समाज कई राज्यों में बटा हुआ है।

समाज का प्रयोजन—जब हमें समाज का प्रयोजन स्पष्ट हो गया होगा। मनुष्य स्वभाव में और जावग्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही अर्थात् अनेक तरह की जरूरतों पूर्ण कर सकता है। समाज की बंदीलन वह न केवल जी सकता है, बल्कि अच्छे तरह भी जी सकता है। अच्छा जीवन वही है जो समाज के अन्दर जीवन है। समाज के बिना मनुष्य पूर्ण तरह सुख नहीं हो सकता। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि समाज में सब मनुष्यों की बराबरी बराबर है। हर एक आदर्श का आत्म-सम्मान और व्यक्तिव एक सा कीर्ति है। इसलिए समाज सब आदर्शों की शिष्ट और सुखी जीवन बिलाने का बराबर मोटा दवा है।

मनुष्य और समाज—जब समाज मनुष्य के लिए इतना कीमती है तो स्वभावतः यह पूछा जा सकता है कि मनुष्य और समाज में क्या सम्बन्ध होना चाहिए। इन दोनों का सम्बन्ध इतना नजदीकी है कि इनमें से कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता और जब ये दोनों एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं तो स्वभावतः यह सवाल पैदा होता है कि मनुष्य का अधिक महत्व है या समाज का। इस सवाल पर लोगों की राय अलग-अलग है और दो जगह (extreme) विचार ये हैं—

(१) मनुष्य का अधिक महत्व है—कुछ विचारक जिन्हें व्यक्तिवादी (individualist) कहते हैं, यह मानते हैं कि मनुष्य को समाज की बहुत जरूरत नहीं। समाज की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि वह बर्बानों की गारदी से बमजोर को बचा सके। और किसी बाल के लिये मनुष्य को समाज की जरूरत नहीं। मनुष्य खुद इतना अकल्प्य है कि वह अपने फायदे के लिए काम कर सके और इस काम में उसे समाज की सहायता की जरूरत नहीं। बल्कि व्यक्तिवादी तो यही तक मानते हैं कि समाज की दखलान्दगी से मनुष्य को कर्म भी करना नहीं पड़ना। इसलिए समाज को उस विस्तृत आजाद रहने देना चाहिए। समाज की दखलान्दगी मनुष्य के व्यक्तिव के विकास में बाधक होती है और उसमें चरित्र को पनपने नहीं देती। इसलिए वे कहते हैं कि मनुष्य को, जहाँ तक हो सके, अलग से अलग आजादी देनी चाहिए और यह मानते हैं कि मनुष्य समाज के लिए बिल्कुल रक्षक है और ला ही फल-फूल सकता है।

समाज का अधिक महत्व है—कुछ और विचारक, जो आदर्शवादी (idealist) कहलाते हैं, समाज का अधिक महत्व मानते हैं। उनका कहना है कि समाज के बिना मनुष्य का कोई अर्थ या सार्थकता नहीं। उसका महत्व सजीव समष्टि (organic whole)

अर्थात् समाज, के एक भाग के रूप में ही है। मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं। मनुष्य का समाज, कपड़े, बोलने की शक्ति, ज्ञान और अमल में तो उसका माग और हृद्दिश्य भी समाज की ही है, और उसने समाज में ही शामिल की है। वे कहते हैं कि मनुष्य का काम इसी में है कि वह अपने-आपको पूरी तरह समाज में अरौन कर दे। उसे समाज के ही लिये जीना और मरना चाहिए।

असली स्थिति—पर मनुष्य और समाज के आपसी सम्बन्ध के धारों में सचाई इन दोनों चरम विचारों के बही बीच में है। कोई भी आदमी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हम पहले ही यह चूके हैं कि समाज मनुष्य के लिये स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। उसे इसकी न केवल जिन्दगी के लिये, बल्कि अच्छी जिन्दगी के लिये जरूरत है। अच्छी जिन्दगी में भौतिक और नैतिक तरकी भी शामिल है। सम्पत्ता और संस्कृति समाज से ही पैदा होनी है। समाज के बिना आदमी पशु जैसा हो जाएगा। मनुष्य में जो बुद्धि का जग है, जो उममें और पशुओं में भिन्नता करता है, बहुतमी विवर्धित होता है, जब वह समाज में रहे।

पर इस मन्थने हमें यह न समझने लगना चाहिए कि समाज मनुष्य में अधिक ऊँचा या अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार, समाज है क्या? यह मनुष्यों का एक जमाव ही है। बिना मनुष्यों के समाज नहीं हो सकता। समाज का जपना मगल इसकी व्यष्टियों के मगल पर ही निर्भर है। अगर व्यष्टि पिछड़ी हुई है तो समाज आगे बढ़ा हुआ नहीं हो सकता। इसलिए समाज के अपने फायदे के लिये यह जरूरी है कि यह ऐसी परिस्थितियाँ और परिभाषण पेश करे, जिसमें व्यष्टि अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।

इस प्रकार, अन्त में हम यह बत मक्ने हैं कि मनुष्य और समाज के आपेभिक महत्व के धारे में सारो बहम समतलब हैं। कोई भी दूररे में अधिक महत्व का नहीं है, न उनके हिन एक दूररे के बिरोधी हैं। दोनों का एक सा महत्व है और पारस्परिक सहयोग से ही दोनों को लाभ है।

सारांश

मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता के कारण सामाजिक है। उसकी सामाजिक प्रकृति इन तथ्यों में सिद्ध होनी है —

१. मनुष्य सदा अपूहो में रहता हुआ दिसाई देता है। वह वही भी जकेला जीवन विताना हुआ नहीं बीखता।

२. मनुष्य को गपशर और हँसने-हँसाने के लिये समाज की आवश्यकता है। वह किसी के साथ विचार-विनिमय करना चाहता है। कंद तनहाई या एकाकी परिराध सबसे बठोर मजाओं में से है।

३. कुछ इच्छाएँ, जैसे दम की, इच्छा, त्याग की इच्छा, वृत्तजना प्राप्त करने की इच्छा, प्रेम और सम्मान पाने की इच्छा, दूररे की मयति के बिना नहीं पूरी की जा सकती।

मनुष्य अपनी आवश्यकता के कारण भी सामाजिक है—

१ मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का सामना नहीं कर सकता। सामंजस्य प्रदान द्वारा मनुष्य प्रकृति का सामाजिक बन गया है।

२ मनुष्य का अपनी व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों से सहयोग करना आवश्यक है।

३ मान प्रकृति और अनवीर्य प्रकृति एवं सामाजिक होने को मजबूर करती है।

४ मनुष्य की बोधने की शक्ति मानव ने ही पैदा हुई है।

५ समाज के बिना जलवा प्रबंध आवश्यक है।

समाज क्यों बहते हैं—यह सभी मनुष्य किन्हीं मामलों में एक ही दिशा के लिए साथ मिलकर चलते हैं, या कुछ मामलों में ही के कारण एकट्ठे मिल जाते हैं, यह के एक मानव बताते हैं। समाज व्यापक अपने द्वारा बहते हैं। यह किन्हीं छोटे समूह के किन्हीं की प्रयोग या सम्बन्धों और गारं मानव बस के किन्हीं भी। समाज मनुष्य के अन्दर सामाजिक जीवन आवश्यक दोनों मनुष्य धारण है।

समाज का संप्रदान—समाज की आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। इसमें जलवा सामाजिक या मनुष्य, मनुष्य और मनुष्य सामिल है।

समाज का उद्भव और वृद्धि—समाज उत्पन्न ही प्रकृति है जिन्हीं पुराना मनुष्य। यह मनुष्य रूप में बदलकर मनुष्य हो गया है। परिवार सबसे पुराना और सबसे सरल सामाजिक समाज है। इसमें बाँट गीत आता है, जो सभी रक्त के बंधु परिवारों का समूह था। कई गोत्र मिलकर कबीला या दल या जनजाति (tribe) बनाते थे। जब किन्हीं क्षय मनुष्य पर रहने वाले कबीलों ने किन्हीं राजा के अधीन कानून और व्यवस्था के किन्हीं अपने आदेशों को लागू करना शुरू किया, तब राज्य पैदा हुआ। सबसे मनुष्य समाज कई राज्या में बँटा हुआ है।

समाज का प्रयोजन—समाज मनुष्य को न केवल जीने के, बल्कि अच्छी तरह जीने के योग्य बनाता है। बिना समाज के मनुष्य अधिकांश सुखी नहीं हो सकता।

मनुष्य और समाज के आंगणिक महत्व के बारे में हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के किन्हीं समाज रूप में महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्तिवर्दी यह कहते हैं कि समाज मनुष्य के अभाव के किन्हीं हैं, वे व्यक्ति की अनुचित महत्व देते हैं। इसी प्रकार, जातीय-वादी समाज का अनुचित महत्व देते हैं। अतः में व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध एक दूसरे पर इतना अधिक आधिन है कि दोनों को आपसी सहयोग में काम करना जरूरी है। दोनों का सम्बन्ध समान रूप में महत्वपूर्ण है।

प्रश्न

QUESTIONS

१ इस कथन को स्पष्ट कीजिए, कि "मनुष्य सामाजिक प्राणी है।"

(५ वि अंश १९४८, और दिसम्बर १९५०)।

1. Explain the proposition that, "man is a social animal."
(P. U. April 1948 and Sep 1950)

- २ "मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है"—स्पष्ट कीजिये।
(प वि सितम्बर १९५२)।
- ३ "Man is by nature a social animal" Explain (P U. Sep 1952)
- ३ "मनुष्य स्वभाव से और आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है।" दुष्टांत देकर स्पष्ट कीजिए।
(प वि १९४०)
- ३ "Man is by nature and necessity a social animal Explain clearly, giving illustrations. (U P 1940)
- ४ "समाज" शब्द से आप क्या समझते हैं? यह सहज्य, समुदाय और सत्वा से किम तरह भिन्न है?
(पू वा १९३८)
- 4 What do you understand by the term "society? How does it differ from an association, community and institution? (U P 1939)
- ५ मनुष्य समाज पर कौंधे निर्भर है? समाज एवं सत्य है या सत्यन? —
(प वि अप्रैल १९५४)
- 6 Explain the dependence of the individual on society. Is society an end or a means? (P U April, 1954)
- ६ मनुष्य और समाज का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये। क्या उनके हित एक दूसरे के विरोधी है?
- 6 Explain clearly the relation between the individual and society. Do they have conflicting interests?

अध्याय : : ५

साहचर्य या संघ

(Associations)

परिभाषा—साहचर्य या संघ लोगों के उस समूह को कह सकते हैं जो किसी काम नाम या प्रयोजन के लिये अभिव्यक्त रूप में संगठित किया गया हो।

सब साहचर्यों में पाए जाने वाले लक्षण—ऊपर की गई परिभाषा में साहचर्य या संघ के निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होंगे —

(१) साहचर्य या संघ एक संगठित समूह है। इसकी यह विशेषता इसे असंगठित समूहों में अलग करती है। भंडा साहचर्य नहीं हो सकती क्योंकि इसमें संगठन नहीं होता। इसी तरह रेलगाड़ी के हिस्से में गकर करने वाले मुसाफिर, या बाजार में जाड़ का खेल देखने वाले लोग साहचर्य नहीं होते। साहचर्य क्योंकि संगठित समूह होता है, इसलिए उसके सदस्यों के साथ इसके सम्बन्धों को नियमित करने के लिये कानून या केलिखे नियम जरूर होने चाहिए।

(२) साहचर्य किसी काम प्रयोजन की पूर्ति के लिये बनाया जाता है। हर एक संघ का मनसब कोई न कोई लक्ष्य हासिल करना होता है। कोई एक साहचर्य आदमी की सब जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। इस तरह, जिनकी अनेक जरूरतों को पूरा करने के लिये आदमी बहुत से साहचर्यों में शामिल होता है और उन साहचर्यों की सहायता उनकी सवनी है जिनकी मनुष्य की जरूरतें।

(३) साहचर्य शब्द सिर्फ कुछ लोगों को निर्दिष्ट करता है और यह किसी प्रदेश को निर्दिष्ट नहीं करता। यह प्रादेशिक संगठन नहीं है। राज्य के अन्तर्गत और किसी साहचर्य का प्रदेश नहीं होता। अंगु में किसी साहचर्य के सदस्य कई राज्यों में फैले हो सकते हैं। रंड काम समाजकार्या साहचर्य है।

साहचर्य में भेद—साहचर्य, आकार, संगठन, प्रकृति, अवधि और कार्यों की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार, ये आकार में छोटे-बड़े हो सकते हैं। खेलने के लिये बनाया गया कंड खेल किराया काम नगर तक सीमित हो सकता है और रंडकाम समाजकार्या साहचर्य है। किसी साहचर्य का संगठन उसके आकार और कार्यों के अनुसार सरल व अटिल होता है। कुछ साहचर्य, जैसे परिवार और राज्य, स्थानाधिक, अनिवार्य और स्थायी होते हैं। अन्य साहचर्य मापारणकता स्वेच्छा में बनाये गये और कम देर रहने वाले होते हैं। साहचर्यों के काम भी अलग-अलग होते हैं जल्द ही, क्योंकि उनके उद्देश्य अलग-अलग होते हैं।

साहचर्यों के प्रकार—साहचर्यों को उनकी प्रकृति, अवधि और कार्यों के आधार

पर इन वर्गों में बाटा जा सकता है —

(१) स्वाभाविक और ऐच्छिक।

(२) स्थायी और अस्थायी।

(३) नामों की दृष्टि में साहचर्य जैविकीय (Biological), आर्थिक, राजनैतिक, मनोरंजनत्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक और परोपकारी हो सकते हैं।

स्वाभाविक और ऐच्छिक—राज्य और परिवार मनुष्य के लिये स्वाभाविक हैं। आदमी जन्म में ही इन दोनों का सदस्य होता है। इनका सदस्य होना या न होना मनुष्य की इच्छा पर नहीं है। उसे इनका सदस्य बनना पड़ता है। एसा कोई आदमी नहीं होगा, जिसका जन्म और पालन किसी परिवार में न हुआ हो। इसी प्रकार, अपिन्तर मनुष्य जाति राज्यों में मगठित होकर रहता है।

स्थायी और अस्थायी—फिर, राज्य और परिवार दोनों अस्थायी भी हैं। वे न मालूम कब में मौजूद हैं। और आगे भी बने रहेंगे। और साहचर्य ऐच्छिक तथा धोरे बहुत अस्थायी होते हैं। मनुष्य को उनमें शामिल होने या उनमें अलग हो जाने की आजादी होती है। ये साहचर्य अपना प्रयोजन पूरा होने ही सतत हो जाते हैं।

जैविकीय साहचर्य का मन्वद सन्तान उत्पन्न करना और मनुष्य जाति को बनाये रखना है। परिवार एक जैविकीय साहचर्य है।

आर्थिक—आर्थिक साहचर्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों, वृद्धि और रक्षा के लिये बनाये जाते हैं। ट्रेड यूनियन या मजदूर मण मजदूरों का मालिकों के मुकाबले में अपने हित आगे बढ़ाने और उनका रक्षा करने के लिये बनाया हुआ साहचर्य होता है। फिर, किसी वृत्ति, व्यापार या उपजीविका में लगे हुए लोगों का साहचर्य हो सकता है। अध्यापक मण, अनाज व्यापारी मण, बपडा व्यापारी मण, बलक मण, ऐसे साहचर्यों के उदाहरण हैं।

राजनैतिक—राज्य और मण्डलराष्ट्र मण राजनैतिक साहचर्य हैं, जिनका लक्ष्य समाज में कानून और व्यवस्था को बनाये रखना है। यह राजनैतिक दल, जिनका लक्ष्य राज्य में राजनैतिक मता ह्रासित करना है, इसी श्रेणी में आता है।

मनोरंजनत्मक—खाने वाली शारीरिक और बौद्धिक मेहनत के बाद आदमी को अपने को तरो-ताजा करने के लिये कुछ मनोरंजन की आवश्यकता होती है। गायक, संगीत और खेल मण मण मनोरंजनत्मक साहचर्यों के उदाहरण हैं।

सांस्कृतिक—स्कूल, कालेज, विनविद्यालय, वाद-विवाद सभाएं, अध्ययन केन्द्र, रोटीरी सर्कल, संगीत और नाटक क्लब, पेंटिंग और अन्य ललित कलाओं के म्बूक, ये सब सांस्कृतिक साहचर्य हैं। इनका लक्ष्य वृद्धि का पैना करना, ज्ञान की तरक्की करना और मोक्ष का परिष्कार तथा उसे ममजना है।

धार्मिक—पक्का धर्म आत्मा का भोजन है। मन्दिर, गुड्डारे मस्जिद और विराज-घर ऐसे स्थान हैं, जहाँ लोग भोतर, धार्मिक और मुण की सोझ में जाते हैं। जिन साहचर्यों का लक्ष्य धर्म और समाज की बुराइयों में सुधार करना होता है, वे सुधारक मण कहलाते हैं। आर्यसमाज और ब्राह्मणमाज इन प्रकृ के उदाहरण हैं।

परोपकारी—मनुष्य सदा स्वार्थी नहीं होता। बहुत बार हम देखते हैं कि वह गरीब लाचार और पद्दलिन लोगों में सहानुभूति और उदारता दिखाता है। समाज सेवा की प्रेरणा में बनाये गये साहचर्य परोपकारी मग्न कहलाते हैं। अनाथालय विधवाश्रमों, अममर्ष व्यक्तियों और कोठियों के आश्रम, हस्पताल और औषधालय इस प्ररूप के साहचर्य हैं।

साहचर्य की उपजोपिता और महत्व

नागरिक की साहचर्य में निर्मार्गमित लाभ होने हैं —

(१) कोई आदमी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होता। उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये दूसरों में सहयोग करना होगा। इस प्रकार साहचर्य मनुष्य की तरह-तरह की जरूरतें पूरी करने के लिये आवश्यक है।

(२) साहचर्य में कठिन से कठिन कार्य की निधि के लिये मनुष्य और सगठित कोशिश का सम्मेलन बनता है।

(३) आदमी के सर्वनीयता विकास के लिये साहचर्य जरूरी है। अलग-अलग साहचर्य मनुष्य के व्यक्तिगत के अलग-अलग पहलुओं के विकास में सहायक होने हैं। तरह-तरह के लोगों से मिलने में उसका अनुभव और ज्ञान बहुत बढ़ जाता है।

(४) एका में ही शक्ति है। किसी साहचर्य के सदस्य के रूप में आदमी अपने हितों की अधिक आसानी से रक्षा कर सकते हैं, और अपने अधिकारों के लिये अधिक आसानी से लड़ सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिये, ट्रेड यूनियन बनाकर।

(५) बहुत में साहचर्य का सदस्य बनकर ही आदमी अपने मित्रों और परिचितों का क्षेत्र बड़ा सकता है। कोई आदमी जितने अधिक साहचर्य में जाता है, उसकी जान-पहचान उतनी ही अधिक होने की सम्भावना है।

साहचर्य और समुदाय में भेद

इन दोनों में भेद करने वाले बातें ये हैं —

(१) समुदाय में गश्त गगहन नहीं होता पर साहचर्य में गगहन अवश्य होता है।

(२) समुदाय के सदस्यों की ओरने वाली चीज कुछ मात्रा में ही होनी हैं। उनका कोई एक ही लक्ष्य या उद्देश्य होना जरूरी नहीं, पर साहचर्य में कोई निश्चित प्रयोजन या लक्ष्य अवश्य होना चाहिए।

(३) समुदाय साहचर्य की अपेक्षा बड़ा समूह है। इसमें कई साहचर्य हो सकते हैं। किसी नगर में, जो एक समुदाय है, कई साहचर्य हो सकते हैं। इसी प्रकार, एक समुदाय कई साहचर्य में संगठित हो सकते हैं। किसी साहचर्य में भी विभिन्न समुदायों के लोग हो सकते हैं।

(४) जब हम किसी गाँव या शहर को समुदाय कहते हैं, तब समुदाय शब्द प्रादेशिक अर्थ भी रखता है। राज्य की छोड़कर और कोई साहचर्य प्रादेशिक अर्थ नहीं रखता।

साहचर्य और सत्या में भेद

बोलचाल में ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह प्रयुक्त कर दिये जाते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से साहचर्य और सत्या का अन्तर भाषा तौर से समझ में आ जायगा। कालेज उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रयोजन के लिये छात्रों का साहचर्य है, सैवचर, एजिटी, प्रिंसिपल की आज्ञाएँ और परीक्षाएँ इन साहचर्य की सत्या हैं। इसी प्रकार, राज्य कानून और व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजन के लिये एक साहचर्य है। इसका भविष्य और इसके कानून इस साहचर्य की सत्याएँ हैं। इस प्रकार, साहचर्य किसी विशेष प्रयोजन के लिये समष्टि लोगों का समूह है, पर सत्या उन नियमों, प्रथाओं परम्पराओं और रुढ़ियों को कहते हैं जो किसी साहचर्य के सदस्यों के आचरण और व्यवहार से सम्बन्ध रखती हैं। (अपूर्ण)

अध्याय : : ५ (तेपाया)

परिवार

अनेक साहचर्यों में से दो साहचर्यों, परिवार और राज्य, का सागरिक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हम परिवार के हिस्से पर विचार करेंगे।

परिवार कितने कहते हैं—

परिवार उम स्वामाविक साहचर्य को कह सकते हैं, जो पति, पत्नी और बच्चों का होता है, और जिसमें कुछ नियम और धार्मिक कृत्य होने हैं, तथा जो सतान पैदा करने, और उनके पालन-पोषण के लिये बनाया जाता है।

इसकी भेदक विशेषताएँ—

परिवार की निम्नलिखित विशेषताएँ और सब समूहों में इसे भिन्न करती है

(१) यह राज्य की तरह एक स्वामाविक साहचर्य है। हर आदमी जन्म से किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। उनका जीवन ही परिवार पर निर्भर होता है। परिवार उसके व्यक्तित्व के विकास में भी बड़ा हिस्सा लेता है। इन कारणों से यह सबसे महत्वपूर्ण मानवीय समूह है।

(२) प्राकृतिक होने के अलावा, यह सबसे अधिक सार्वत्रिक साहचर्य भी है। मनुष्य जति में यह सारे समूहों में होता है। यह चिड़ियों और पशुओं में भी मौजूद है।

(३) किसी परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से बांधने वाले बंधन सबसे तबदीकी होते हैं। मनुष्य जति के और किसी समूह में एकता के सम्बन्ध इतने प्रबल नहीं होते। परिवार का आधार रक्त का सम्बन्ध है।

(४) समय के लिहाज से परिवार प्राचीनतम समूह है।

सब परिवारों की सामाजिक विशेषताएँ

निम्नलिखित विशेषताएँ सब मानवीय परिवारों में होती हैं —

(१) पति और पत्नी के मध्य दौन और प्रेम सम्बन्ध सब मानवीय परिवारों की पहली विशेषता है।

(२) विवाह दूसरी विशेषता है। दौन सम्बन्ध के अलावा पति-पत्नी किसी तरह के विवाह से बंधे हुए होते हैं।

(३) सारी दुनिया में, परिवार ने ही मनुष्य का बस जाना जाना है।

(४) बच्चा सब मानवीय परिवारों का केन्द्र है। बच्चे का पालन-पोषण सब मानवीय परिवारों का ध्येय है।

(५) परिवार के सब सदस्यों का एक साझा निवास-स्थान होता है जिसे घर कहते हैं।

नाशान्वित बच्चे हों। ऐसे परिवारों को जल्दसे परिवार कहते हैं। हमारे देश में प्रायः परिवारों में बड़े और विवाहित पुत्र, बूढ़ बादा-दादी, विधवा बहिन और पावित्र्य आदि भी होती हैं। इन परिवारों को अविभक्त परिवार कहते हैं।

अविभक्त परिवार प्रणाली

अविभक्त परिवार के कामों का प्रबन्ध सबसे बड़ा नर सदस्य करता है जो बर्ता कहलाता है। परिवार की सम्पत्ति के सब भोग स्थानी होते हैं और बर्ता इसका अनिच्छक होता है। सब सदस्यों की कमाई इनटूटी कर ली जाती है और वे मिलकर उसे बांट लेते हैं। अविभक्त परिवार प्रणाली छोटे पैमाने पर समाजवादी परीक्षण है। परिवार का हर एक सदस्य अपने मामलों के अनुसार काम करता और कमाता है और उससे बढ़ते में, उनकी जरूरत के अनुसार उसे दिया जाता है।

अविभक्त परिवार के लाभ

(१) अविभक्त परिवार प्रणाली वेगन सहयोगिता का एक महान प्रयोग है। यह मिलकर रहने और मिलकर काम करने का पाठ पढ़ाता है। यह परिवार के सदस्यों के मन में आदर, आजागलन, अनुनामन, त्याग और सहनशीलता की भावनाएँ पैदा करती है। इन गुणों में युक्त आदमी अच्छा नागरिक बन जाता है।

(२) पर इसका मुख्य लाभ यह है कि प्रत्येक को जीविका मिलनी निश्चय हो जाती है। अविभक्त परिवार अनाथों, गैरियों, बूढ़ों और विधवाओं के लिये, जिनके पास जीविका का और कोई साधन नहीं है, सुरक्षित आश्रय स्थान है।

(३) अविभक्त परिवार प्रणाली धर्म के विनाश का भी बहुत अच्छा तमूना है। परिवार के सब सदस्यों को घर के किसी न किसी काम में जमा दिया जाता है और इसलिए वह काम करता है जिसके लिये वह अधिक से अधिक योग्य है। इनटूटे रहने और माने में सब में भी बचत होती है।

(४) अन्तिम बात यह है कि अविभक्त परिवार परिवार की सम्पत्ति और अधिकता अमठी पीढ़ी को पहुँचाने का सर्वोत्तम माध्यम है। बच्चों को बचपन में परिवार की परम्पराओं और प्रथाओं का पाठन करना सिखाया जाता है।

अविभक्त परिवार की हानियाँ

(१) पर अविभक्त परिवार प्रणाली मरती हुई मर्यादा है और इसकी उपबोधिना के बारे में बड़ा संदेह होता जाता है। इसकी मुख्य हानि यह है कि यह आदमी के व्यक्तित्व के विकास के लिये सुझा और पूरा मौका नहीं देती। आदमी अपनी मूल-बुद्धि में कुछ नहीं कर सकता। उसे परिवार की रक्षिकानुगीत परम्पराएँ माननी पड़ती हैं। फिर, हो सकता है कोई एक व्यक्ति जोशिम लेने को तैयार हो और परिवार के अन्य समाने वाले लोग यह जोशिम उठाना पसन्द न करें।

(२) अविभक्त परिवार प्रणाली की दुसरी हानि यह है कि यह अपने सब 'सदस्यों' को एक निश्चित दायरे में बालती है। सबकी मर्यादा में परिवार की परम्पराओं का पाठन करना होता। जवान लड़की-लड़कियों को, शादी, लग करने का काम भी

पर के बंधो का है। इन तरह विगी के लिये नई बात गोपने या नया राल्ना बनाने की मुजाहद नहीं। यह प्रवृत्ति स्वस्थ नागरिक जीवन के लिये बड़ी हातिवारक है।

(३) अविभक्त परिवार में अलग-अलग पनप, आदती और स्वभावी के लोग होते हैं। उनकी उम्रों और दृष्टिकोणों में बड़ी समानता नहीं होती और पर म हागरे पेशा हा जाते हैं जिनमें गुण और हाति नाट हो जाती है।

अविभक्त परिवार का भविष्य

अविभक्त परिवार प्रगती अर अरती मीन नर रही है। औद्योगिक समाज पैदा हो जाने, बहूत तरह के धर्य हो जाने, तागीम के पैँक मान आर जान-बाद के गोपन बड जाने में भी पुराने अविभक्त परिवार का टुटने म मदर मिला। नयी पाई आन लिय एक मार, पर अलग, पर बनाना बनती है जती यह अपर, इच्छा री गुद मानिा हो। परिषामन विगी परिवार के मरम्य अरती आमरने, व मुनाबिक रान-गहन का मुष भागो के लिये अरने, इच्छा में अलग हा जान है।

पर हमारा देग कृपि प्रधान दग है और इन रूप म अविभक्त परिवार हमारी जरूरता के लिय बडा ठंन बेंडगा है। अविभक्त परिवार क टुटन में जान छाटी रह जाएगी और इनग जो धुराइयां हाती हैं व यर हाय। इगणि यदि हम मिन्बर एर ही मकान म नती रर गवते मा भी जती तब जर्मन क म्नामाव और पैदा का खवाल है, बती तब हमें मिन्बर ररना चाहिये।

परिवार के कार्य

एक मातृमर्य के रूप में परिवार बहून म महत्वपूर्ण कार्य करता है।

मनोबैज्ञानिक

मनुष्य और स्त्री का विकास व, स्व गुन रीतिग सम्मिलन मीन प्रकृति को मनुष्ट करी का मवन अधिा वैगिक राल्ना है।

जैविकीय (Biological)

परिवार का जैविकीय काम है मानव जाँत के तनु को बड़ाने जाना। इसमें ममान उन्पन्न करना और उनकी रखा करना, ये दानो बाव शामिल हैं। मन्तान उन्पन्न करने का अर्थ है बच्चे पैदा करने मानव जाति को जारी रमना। पर बच्चा का पैदा हो जाना है। काफी नहीं, इनका पालन-पोषण और जिनारा में रखा भी करनी हागी। जनकीय प्रकृति माना-निदान का अर्थ बच्चे को दबमाड करने की प्ररणा देना है। बच्चो का पालन-पोषण बडा कठिन काम है। माता-पिता के अलावा और कोई बच्चा के गिा गुनी में आते गुन की सुबती नहीं कर तपना। बच्चे माता पिता में जो प्रेम और आदर दिगलाते हैं, उनमें माता-निदान अपना मर तबलीका का भूल जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार के द्वारा प्रकृति मन्तान पैदा करने और उनकी रखा करने की अनरी, याजना को अधिा में अधिा अच्छ, रति में पूरा करती है।

परिवार एक जाविक इबाई भी है। परिवार के मरम्य कर्तव्यों का आनन में बाट लेते हैं और आपसी सहयोग में रहते हैं। इनका नतीजा यह होता है कि परिवार

भी कामदानी और लक्ष अधिक से अधिक अच्छे तरीके से मभल जाते हैं। प्रत्येक सदस्य नवद धन द्वारा या अपने काम द्वारा परिवार को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का भरमक यत्न करता है। लक्ष में भी बरबादी से बचने के लिये सब तरह की सावधानी बरती जाती है।

दूसरी बात यह है कि परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम होने के कारण हर सदस्य बीमारी और बेरोजगारी में दूसरों की महानता पर भरोसा कर सकता है। बड़े और धनमय्य माना-पिता अपने बरत-पोषण के लिये अपने जवान लड़कों पर भरोसा कर सकते हैं। इस अर्थ में परिवार एक बॉमा कम्पनी का काम करता है।

तीसरे, पुराने जमाने में, जब पिता का हुनर लड़का सीखता था, परिवार एक शिक्षालय का काम भी करता था।

शिक्षात्मक, सांस्कृतिक और नैतिक

बच्चा परिवार में अपने माता-पिता की निगरानी में जन्म लेता है। वह हर चीज के लिये उन पर निर्भर है। माता-पिता उसे बोलना, अच्छा भोजन करना और बपड़े पहनना सिखाते हैं। बच्चे पर बहुत अच्छी नजर पड़ता है, और उगमें नकल की प्रवृत्ति होती है। अनेक चीजों के बारे में उसका ज्ञान और गम तथा उसकी आदों बचनन्द, तीर-तरीखा और विश्वास, अधिकतर उसके माता-पिता से पाये हुए होते हैं। इस प्रकार शिक्षात्मक के अलावा परिवार का सामूहिक महत्व भी है।

इसका नैतिक कार्य भी है। परिवार में ही बच्चे के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। विशेष रूप से इस दिना में मान्य बहुत कुछ कर सकते हैं। शिवाजी की महतिना का अधिकतर श्रेय उनकी माया को ही था।

नागरिक कर्तव्य

घर में ही आदमी गवने पढ़के नागरिक कर्तव्य सीखता है। हम पहले देन चुके हैं कि व्यक्ति के जीवन में परिवार का क्या स्थान है? उसके चरित्र और व्यक्तित्व की नींव परिवार में ही पड़ती है। उनके व्यवहार और गम्हति इसी से उनके मिलते हैं। बचपन में पैदा हुए गुण और दोष आदर्शों में बड़े होकर पर भी दबे रहते हैं। अनुशासन और आज्ञापालन, जो नागरिकता के लिये इतनी जरूरी चीजें हैं, बच्चा पहले परिवार में ही सीखता है। इस अर्थ में परिवार एक छोटा सा राज्य है।

हर मनुष्य के जीवन में जीरी के अनुकूल बनकर चलना पड़ता है। बच्चे को परिवार के जीवन से अपने-आपको अनुकूल बनाना पड़ता है। कुर्बानी, महिगुना और महयोग आदि गुणों के बिना अनुकूलन सम्भव नहीं। माता-पिता अपने बच्चों की निम्नार्थ सेवा द्वारा उनके सामने कुर्बानी का बहुत अच्छा उदाहरण देग करते हैं। इस तरह बच्चा स्वयं को उद्योग करनेवाला सीखता है। अनुभव में ही बच्चे यह सीखते हैं कि परिवार में अपने अधिकार पर जोर देने के साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों की पूर्ति भी करनी चाहिए। इसी तरह उन्हें बहन-भाइयों से मतभेद होने पर उनका दृष्टिकोण भी मानना चाहिए और ब्रह्म में नागरिक गुणों, जैसे सचाई, ईमानदारी, समद-व्यवस्था,

वस्तुमय की भावना और जिम्मेवारी, जो नागरिक जीवन के लिये बड़े महत्व के हैं, भी आदमी पहले परिवार में ही नीतना है। इस प्रकार नागरिक जीवन में परिवार बड़ा उपयोगी काम करता है।

परिवार का भविष्य

पिछले १०० सालों में आधुनिक मन्थना जिस तेजी से आगे बढ़ी है, उसमें परिवार का महत्व कम हो रहा मानस पठना है। एल्डम टक्कले जैसे लेखकों का विचार है कि शायद किसी दिन परिवार विलुक्त मरम हो जाये क्योंकि इसके मय महत्वपूर्ण कार्य समाज के अन्य साहचर्य अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। कहा जाता है कि दिन कल्याण केन्द्र और बाल मदन परिवार की बच्चे पालने के काम में छुटकारा दे देते हैं। सब उम्रों के बच्चों के लिये स्कूल गोनर राज्य में शिक्षा का काम अपने ऊपर ले लिया है। विडर-गार्टन स्कूल बच्चों की गानुल उम्र में उन्हें ताम्रम और शिक्षा देने का काम करते हैं। अधिर दृष्टि में लोगों में बाजार में बनी-बनाई वस्तुएँ खरीदने की प्रवृत्ति है। हंस्टिंग और रैस्टोरेंट हर पगन्द की चीज देने हैं और इस तरह पर में रमोई की जगह नहीं रहता। स्त्रियों में बढ़ती हुई पुरुषों में बराबरी और स्वतन्त्रता की भावना ने परिवार की नींव हिला दी है। त्रिया पर में बड़े रहन की संसार नहीं। पुरुषों की तरह ये भी नोवरी उड़ते हैं और स्वतन्त्र बनाने करना चाहते हैं। ये भी समाज में घूमना-फिरना चाहते हैं। तलान ने विवाह-ग्रन्थन का तोड़ना आसन्न कर दिया है। इन सब बातों को देखने हुए, जामनीर से कहा जाता है कि परिवार की इबाई टटने की ओर बढ़ रही है।

पर हमें याद रखना चाहिए कि परिवार का भविष्य ऐसा निराशाजनक नहीं है। यह ठीक है कि परिवार की रचना और कामों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। इन सबके बावजूद इस बात का याई सबूत नहीं कि परिवार टूट रहा है। अधिक से अधिक आगे बढ़े हुए देशों में भी परिवार मौजूद है। आदमी की जिविकीय और सामाजिक आवश्यकताओं के लिये इसे अब भी जरूरी समझा जाता है। स्त्रियों की पुरुषों के साथ बराबरी ने पारिवारिक जीवन में अधिक तालमेल की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में अपनी प्रेम, विश्वास, सहयोग और सहानुभूति का जो वातावरण होता है वह किसी और समूह में नहीं हो सकता।

सारांश

साहचर्य या मय लोगों का यह मगठिन समूह है जो किसी काम सामे प्रयोजन की सिद्धि के लिये बनाया जाता है।

साहचर्यों के प्ररूप—साहचर्य स्वाभाविक या स्वेच्छया बनाये हुए, स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं, और उनमें उनके कार्यों की प्ररुति के अनुसार भी भेद हो सकता है।

साहचर्यों की उपयोगिता—(१) मनुष्य की अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साहचर्य की आवश्यकता है। (२) साहचर्य कठिन में कठिन उद्देश्य की

निष्ठि के लिये शक्ति की व्यवस्था करने हे। (३) साहचर्य लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के योग्य बनाने हे। (४) बिना साहचर्यों के, मनुष्य के व्यक्तित्व का अनुभूती विकास सम्भव नहीं। (५) साहचर्यों द्वारा हम अपने मित्रों और परिचितों का दायरा बढ़ाने हे।

साहचर्य और समुदाय—(१) समुदाय का समन्वित होना आवश्यक नहीं। साहचर्य एक समन्वित समूह है। (२) समुदाय के सदस्यों को बांधने वाली धीज शांति है। साहचर्य के सदस्यों का उद्देश्य या लक्ष्य सामा होता है। (३) समुदाय साहचर्य की अपेक्षा अधिक बड़ा समूह है। (४) गाँव या शहर के अर्थ में समुदाय क्षेत्र को भी सूचित करता है। साहचर्यों में के सिर्फ राज्य में ही क्षेत्र होता है।

साहचर्य और सम्बन्ध—लोगों के समन्वित समूह को साहचर्य कहते हैं। बिना समन्वित समूह के सदस्यों के बीच के सम्बन्ध को निर्दिष्ट करने वाले, लिये या बेलिसे नियमों के समूह को सम्बन्ध कहते हैं। कानि एक साहचर्य है, पर भाषण, परीक्षाएँ और आचार्य के आदेश एक साहचर्य की सम्बन्ध है।

परिवार

परिवार पति, उसकी पत्नी और बच्चों, के उम प्राकृतिक साहचर्य को कहते हैं जो मतानुबंध करने और बच्चों के पालन-पोषण के लिये होता है और जिनके साथ कुछ नियम तथा कर्मकांड जुड़े रहते हैं।

इसकी विशेषताएँ—(१) यह प्राकृतिक और मार्बनिक है। (२) इसके सदस्य पतिपुत्रम बंधनों से बंधे होते हैं। (३) पति और पत्नी का योन सम्बन्ध विवाह पर आधारित है। (४) यमत्रम परिवार के अरिये होता है। (५) सब सदस्यों की रहने की जगह एक होती है जो घर कहलाती है।

परिवार का उद्गम और आधार—यह ज्ञान इतिहास के काल से पहले पैदा हुआ। एक अर्थ में यह मनुष्य में भी पहले का है। परिवार दो बलों, अर्थात् योन बल और सुधा की पारम्परिक क्रिया का परिणाम है।

परिवार के प्रभय—(१) यमत्रम के आधार पर परिवार या तो पँनूक होने हे या मानूक अर्थात् या तो पिता के जम में बना देला जाता है, या माता के जम से। (२) विवाह के रूप के आधार पर, परिवार एकपत्नीय बहुपत्नीय या बहुपति हो सकता है। (३) इसकी बनापट के आधार पर परिवार अकेला या अविभक्त हो सकता है। अकेले परिवार में पति-पत्नी और उनके मावालिग बच्चे होते हैं। अविभक्त परिवार में बड़े और विवाहित पुत्र, बड़े दादा-दादी, विधवा बहनें और चाचिया भी शामिल होती हैं। अविभक्त परिवार का मुखिया कर्ता कहलाता है। अविभक्त परिवार में सम्पत्ति सबकी इच्छती होती है और कमाई को इच्छता कर लिया जाता है और सब मिलकर उमका उपभोग करते हैं।

अविभक्त परिवार की अच्छादियाँ—यह सहकारिता का एक महान् परीक्षण है और यम के विभाजन का एक अच्छा उदाहरण है। (२) इसमें हरेक की जीविका

- ५ "नागरिक जीवन घर में शुरू होता है" । इस कथन को स्पष्ट कीजिए ।
(५० वि० सत्र १९५०)
- ६ Elucidate the statement that civic life begins at home.
(P U April 1950)
- ६ "घर नागरिक गुणों का पहला विद्यालय है", इसे स्पष्ट करो और इसकी विवेचना करो ।
(५० वि० सितम्बर १९५३)
- ६ "The home is the primary school of civic virtues". Explain and discuss
(P U Sep 1953)
- ७ सभ्य में परिवार के काम गिनाइये और बताइये कि नागरिक के जीवन में इसका क्या महत्व है ?
- ७ Briefly enumerate the functions of family and also give its importance in the life of a citizen
- ८ राष्ट्रधर्म के रूप में परिवार का भविष्य क्या है ? क्या बिन्दुम इसके बिना काम चल सकता है ?
- ८ Discuss the future of family as an association. Is it possible to do without it ?

अध्याय : : ६

समुदाय—गांव और नगर गांव

परिभाषा—गांव समाज की सबसे छोटी इकाई है। जब कई परिवार किसी निश्चित जमीन पर घेती और उससे सम्बन्धित और पेशे के लिये बस जाते हैं तो गांव बन जाता है। भारत में गांव बच्चे मवानों का वह समूह होता है, जिसमें नहीं कोई पवरा मकर हो और जिनके चारा और लेती की जमीनें हो।

उद्गम—गांव की परिभाषा में हम देख चुके हैं कि गांव समाज की एक प्रादेशिक इकाई है। इसका अर्थ यह है कि गांव तब पैदा हुए जब आदमी निश्चित प्रदेश पर स्थायी रूप से रहने लगा था। मानव समाज के विकास की पहली दो अवस्थाओं, अर्थात् शिकारी अवस्था और पशुपालक अवस्थाओं में मनुष्य बजारों का जीवन बिताता था। वह अपने लिये और अपने समुहों के लिये भोजन खोजता हुआ एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहता था। जब धीरे धीरे आदमी ने खेती करना सीख लिया, तब किसी खास जमीन में दिलचस्पी हो जाने से वह वहां स्थायी रूप से रहने को मजबूर हो गया होगा। जब उस जमीन पर खेती के लिए कई परिवार बस गये, तब गांव का जन्म हुआ।

एक बार पैदा हो जाने के बाद गांव के बचने में आमपास के परिवारों की दिलचस्पी बढ जाने से और प्रतिरक्षा, पानी, सफाई और निष्ठा आदि मिली-जुली समस्याओं से मदद मिली। ये समस्याएँ हट करने के लिये गांव वालों की इकट्ठी बौद्धिक और सहयोग की जरूरत थी। आदमी की रोजाना की जरूरतें पूरी करने के लिये भी सहयोग और धन का विभाजन जरूरी हो गया। कोई भी परिवार अपने लिये काफी अनाज, कपड़ा और अन्य वस्तुएँ नहीं बना सकता था। आत्मनिर्भरता गांव की एक पहचान हो गई।

पुराने और नये गांव—पुराने जमाने में गांव का जीवन आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से आत्मनिर्भर हुआ करता था। आर्थिक दृष्टि से गांव वाले आपसी धन-विभाजन द्वारा अपनी सब जरूरतें पूरी किया करते थे। किसान जमीन जोतता था और सारे गांव के लिये काफी अनाज और अन्य वस्तु सामान पैदा करता था। उसे गांव में इकट्ठी की स्थिति हासिल थी और लोग उसके अनाज में हिस्सा पाते थे और अलग-अलग तरह उसकी सेवा करते थे। लोहार और दहई उसका हल, बेलगाड़ी और खेती के अन्य औजार बनाते और मुधारते थे। जुलाहा घरों में औरतों द्वारा बाँते हुए सूत से कपड़ा बनाता था, चमार जूते बनाता था, इत्यादि।

राजनीतिक दृष्टि से भी पुराने जमाने के गांव अंगल में आत्मनिर्भर हुआ

करते थे। वे गांव पचासती द्वारा अपना नाम-नाम कमालसे थे और अपने सगरे तप करते थे। नाम के लिए बंधक शब्द किसी राज्य का हिस्सा होना पर कमल में राज्य की राजधानी की सरकार उनको जिवन्तो में कोई दण्ड न रखती थी।

पर वाजकल गांव आत्मनिर्भर नहीं रहे। तेज सवारों और सवार साधनों ने उनकी आत्मनिर्भरता सतम कर दी। उनका पास के कस्बों और शहरों से सम्बन्ध जुड़ गया। शहर की फंटेटी में बनी वस्तुएं गांवों में पहुँचने लगी। बाज ह्म गांव के आदमी को मित्र में बने बपड़े और जूते पहने देखते हैं। घालु के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, माट्टिक और रेडियो जैसे विद्युत-वस्तुएं आकरल गांवों में आमतौर से पायी जाती हैं। गांव वाला अपने बच्चों को शालीन के लिये शहरों के स्कूलों में भेजता है। राज-नैतिक दृष्टि ने भी पचासती को सना खत्म हो जाने के कारण गांवों के शहरे शहरों की अज्ञान में तप होने लगे।

नागरिक जीवन में गांव का महत्व—गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनीय और राजनैतिक इकाई है।

सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व—प्रथम तो, गांव मनुष्य के सामाजिक जीवन की उन्नत अवस्था को सूचित करता है। हमने पहले-पहल गांव में ही उन लोगों के साथ सहयोग करना और शान्तिपूर्वक रहना सीखा होगा जो उसके रक्त-सम्बन्धी नहीं थे।

दूसरी बात यह है कि गांव के जीवन में मनुष्य की उन प्रवृत्तियों को पूरा होने का मौका मिलता है जिसकी पूर्ति परिवार में नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मित्रमत्तनी चाहिए जिसके साथ वह बातचीत कर सके और हँसो-मजाक कर सके। गांव में यह इच्छा आसानी से पूरी हो सकती है, क्योंकि सब गांव वाले उनके रक्त-सम्बन्धी नहीं हो सकते।

तीसरे, नाटक, खेल, संगीत सम्मेलन और लोकनृत्य आदि मनोरंजन काम ने कम गांव के ही स्तर पर हो सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों की शालीन के लिये स्कूल भी सब गांव वालों के सहयोग से ही बनाए जा सकते हैं।

आर्थिक दृष्टि से गांव किसी देश में उत्पादन की महत्वपूर्ण इकाई है। हम अनाज और बहुत से उद्योगों के लिये बच्चा सामान गांवों से ही हासिल करते हैं। गांव के खेतों की माट्टुजारी या भूराज्य राज्य की आसानी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है।

प्रशासनीय और राजनैतिक महत्व—किसी देश के प्रशासनतन्त्र में गांव के अधिकारी, जैसे पटवारी और मुंसिफ, महत्वपूर्ण बड़ी होते हैं। दूसरे, गांव पंचायत के काम में गांव वालों को जो अवकाश मिलता है, वह लोकतन्त्रीय शासन को सफल बनाने में बड़ी मदद करता है। पंचायतों में गांव वाले अपने मामलों की देखभाल और प्रबन्ध खुद करना सीखते हैं। परिवार के बाद गांव ही लोकतन्त्र के नागरिक का असली शिक्षागार्य है।

तीसरे, गांव वाले आम तौर से रुढ़िप्रेमी दृष्टिकोण रखते हैं, जिससे देश के राज-नैतिक जीवन में आकस्मिक परिवर्तन नहीं हो पाते।

चौथे, सतुष्ट, सरल और वानून-पालक गाँव समुदाय सरकार की शक्ति और रीढ़ की हड्डी का काम भी देता है।

पाँचव, गाव वाले देश की रक्षा में बड़ा योग देते हैं। स्वस्थ और मेहनती गाँव वाले अच्छे सिपाही बनते हैं।

नगर

नगर गाव से बड़ी और अधिक आबारी वाली इकाई है। नगरो और महानगरो का जीवन गावों के जीवन की अपेक्षा अधिक समृद्ध और रगविरमा होता है। गाव तो मुख्यतः कृषिजीवी होता है, पर नगरनिवासी अधिकतर उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और नौकरी में लगे रहते हैं।

नगरो का उद्गम और वृद्धि—नगर मनुष्य के सामाजिक जीवन के विकास में अगली सीढ़ी है। जब तब मनुष्य की जरूरतें सादी थी, तब तब वे गाव में पूरी की जा सकती थी। पर सम्पत्ता के बढ़ने और मनुष्य की जरूरतों के बढ़ जाने पर मनुष्य बाहरी दुनिया से वस्तुओं की बदला-बदली करने लगा। व्यापार और वाणिज्य बढ़ गये और महत्वपूर्ण सड़क और बाजार नगरों के रूप में बदल गये। कभी-कभी उन जगहों पर फँटरिया बनने से भी, जहाँ कच्चा सामान और शक्ति प्राप्त हो सकती थी, अनेक नगर और महानगर बन गए। बहुत से नगर कई गावों के मिलने से बन गये हैं। तीर्थयात्राओं और भेड़ों के स्थान, पार्थिव नदियों के किनारे, वैश्विक महत्व की जगह और सरकारों की राजधानियाँ भी धीरे धीरे समृद्ध नगर बन गयीं।

नगरों का महत्व—नगरों का देश के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

आर्थिक—गाव तो कृषि की इकाई है, पर नगर और महानगर उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के बड़े केन्द्र हैं। बड़ी-बड़ी फँटरियाँ, जो हमारी राज की चीजों की सैबडो जरूरतें पूरी करती हैं, सिर्फ नगरों और महानगरों में होती हैं। इन फँटरियों में देश के लाखों आदमियों को रोजगार मिलता है। देश के अन्दर और बाहर सब तरह की वस्तुएँ बेचने और खरीदने के लिए घोक बाजार और बड़े-बड़े बैंक और कपनियाँ नगरों और महानगरों में ही होती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय सम्पत्ति के उत्पादन में नगरों का भी उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सामाजिक—मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को नगर में होने वाले अनेक तरह के साहचर्यों में अधिक सतोप प्राप्त होता है। नगर और महानगर विनोद और मनोरंजन के भी महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। सिनेमा, नाचघर, खेल के मैदान, पार्क, व्यायाम-घाटाएँ, शोडगण और मद्रहालय ऐसी जगहें हैं, जहाँ नगर-निवासी जा सकते हैं और लाभदायक मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं।

सांस्कृतिक—उपयुक्त सब स्थान तथा विद्वत्विद्यालय, कलेज, स्कूल, पुस्तकालय, कला और दर्शन के विशालय, वादविवाद मण्डल, नाटक, संगीत और रोस्टरी समाज, नगरों में राष्ट्रीय सस्कृति फैलाती है। सिप्टाकार और फँड भी नगरों

और महानगरों में शुरू होते हैं ।

राजनैतिक—नगरों और महानगरों के निवासियों का दृष्टिकोण प्रगतिशील होता है । परिवर्तन के लिये महत्त्वपूर्ण आन्दोलन नगरों में ही चलते हैं । दलीय प्रचार आंदोलन, सम्मेलन, जलूम और सांख्यिक सभाएँ नगरों में रोजाना हुआ करती हैं । इसी कारण नगर-निवासियों को राजनैतिक शिक्षा भी अधिक अच्छी मिल जाती है, उसे देग में होनेवाली हर बात की पूरी जानकारी रहती है । सरकारों की राजधानियाँ भी नगरों में होने के कारण इन स्थानों के निवासियों को सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में अधिक अच्छी जानकारी मिल जाती है । राजनैतिक दलों के दफ्तर भी नगरों में होते हैं । इन प्रकार नगर राजनैतिक हलचल के बड़े केंद्र बने रहते हैं । हर नगर में अपना प्रबन्ध व्यव करने वाली कोई शस्था होती है, जैसे नगरपालिका, जो शिक्षा, सफाई, डाक्टरी मदद, नालियों, बिजली और मकान, आदि सब नगरनिवासियों के हित की चीजों का प्रबन्ध करती है ।

प्रान्त

प्रांत किसी देश के प्रदेश के बड़े टुकड़े को कहते हैं, जिसमें अनेक नगर और महानगर होते हैं । सामन की सुविधा के लिये देश को आमतौर से कई प्रान्तों में बांट दिया जाता है । इसलिए प्रांत मुख्यतः प्रशासनीय और राजनैतिक इकाई है । कभी-कभी देश में शक्ति के बाद पहले वाले राज्यों को नए राज्यों के प्रान्त बनाकर रख दिया जाता है । प्रान्तों की सीमा रेखा मस्कृति और भाषा के आधार पर भी खींची जा सकती है । प्रान्त में सार्वजनिक जीवन और समाज की शिक्षा के लिये और भी बड़ा क्षेत्र मिलता है ।

देश—देश शब्द भौगोलिक अर्थ का सूचक है । भौगोलिक दृष्टि से दुनिया कई प्राकृतिक खंडों में बटी हुई है और प्रत्येक खंड समुद्र, पहाड़ों या नदियों द्वारा दूसरे से अलग है । ऐसी प्राकृतिक एकाइयों में दो खंडों के बीच आया-जाता घटित हो जाता है । इसलिए अलग-अलग भूखंडों के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन का विकास अलग-अलग रूप में होता है । एक भूखंड के अन्दर लोगों के रहन-सहन का तरीका, भावनाएँ और विचार स्वार्थ और समस्याएँ एक में होते हैं । देश शब्द का प्रयोग जब राजनैतिक दृष्टि से होता है तब यह उसी अर्थ का वाचक होता है जिसका वाचक राष्ट्र शब्द है । देश के सदस्य के माने आदमी का अधिक विस्तृत दृष्टिकोण होना चाहिए । उसे अपने भित्री और स्थानीय हितों के मुकाबले में सारे देश के अधिक ऊँचे हितों का महत्त्व देना चाहिए ।

कभी ऐसा हो सकता है, कि अनेक समूहों के प्रति उसकी निष्ठाओं में विरोध हो जाए। उदाहरण के लिये, उसका अपना हित उसके परिवार के हित का विरोधी हो, या उसके परिवार का हित उसके गांव के हित का विरोधी हो, इत्यादि। तो फिर आदमी अपनी निष्ठाओं को कैसे काम में लाये ?

अपनी निष्ठाओं के प्रयोग की बात सोचने हुए आदमी को यह ऐसना चाहिए कि कौन सा दावरा उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं को अधिक पूरा करता है। उदाहरण के लिए, उसकी निष्ठा पर प्रात, गांव या परिवार का जिनना दावा हो सकता है, उसमें अधिक दावा देना है। देश अस्पताल सोलकर उसकी स्वास्थ्य रक्षा अधिन अच्छी तरह कर सकता है, स्कूल और कालेज खोलकर उसकी बुद्धि को तीव्र और उसके दृष्टिकोण को विस्तृत कर सकता है, और सार्वजनिक उपयोगिता को वस्तुए बनाकर उसके जीवन को आरामदेह और सुखी बना सकता है। देश आदमी के जीवन को भीतरी अराजकता और बाहरी हमलों से बचाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण मानवता, देश, प्रात, जिले, गांव या नगर, और परिवार का इसी क्रम से उसके ऊपर पहले अधिकार होगा। व्यक्ति का अपना हित या अपने ऊपर व्यक्ति का दावा सबसे अन्त में आएगा। आदर्श नागरिक यह है जिसकी निष्ठाएँ उचित रीति से प्रयोग में आती हैं और जो अपनी अनेक निष्ठाओं में विरोध नहीं पैदा होने देता।

पर निष्ठाओं की सही व्यवस्था का यह अर्थ नहीं कि किसी एक सामाजिक इकाई के दावों को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया जाए। आदमी का प्रत्येक इकाई की आर उचित ध्यान देना चाहिए। उसे अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी अनेक निष्ठाओं के मध्य विरोध के सीके कम से कम रह जाए। पर वास्तविक व्यवहार में निष्ठाओं की व्यवस्था बहुत दूर तक आदमी के चरित्र पर निर्भर है। बहुत बार हम देखते हैं कि आदमी के लिए अपने गांव, प्रात या देश के हित में अपने या अपने परिवार के स्वार्थों की कुर्बानी करना कठिन हो जाता है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन आदमी को यह शिक्षा देकर कि उसे बड़े समूह के हितों के सामने अपने हितों को गौण कर लेना चाहिए, सही नागरिक बुद्धि का विकास करता है।

सारान

गांव—गांव एक क्षेत्रीय समुदाय है जिसके सदस्यों का रुचि और सम्बन्धित धर्मों में सामान्य हित होना है।

इस प्रकार, क्षेत्र गांव की परमाधन्यक विशेषता है। यह तब ही अस्तित्व में आ गया होगा जब मनुष्य ने खेती की कला सीखी।

पुराने जमाने में गांव आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों में आत्मनिर्भर हुआ करता था, और आज के जमाने में सभार के अधिक तेज साधनों के आविष्कार ने इस आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया है।

गांव का महत्व—(१) सामाजिक दृष्टि से गांव मनुष्य के सामाजिक जीवन में एक उन्नत सीढ़ी का सूचक है। गांव में ही उसने पहले बार उन लोगों से महयोग

करना सीमा जो उसके सगे सम्बन्धी नहीं थे । गांव में मनुष्य की मित्रों के साथ रहने की इच्छा की भी पूर्ति हीं सक्ती है । (२) सामूहिक दृष्टि से कुछ मनोरञ्जन, जैसे नाटक और नाच, बन ने कम गांव के स्तर पर हो सकते हैं । (३) आर्थिक दृष्टि से गांव उत्पादन की एक महत्वपूर्ण इकाई है । हमें अनाज और उद्योगों के लिये कच्चा सामान गावों से ही मिलता है । (४) राजनैतिक दृष्टि से गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है । गांव पञ्चायत लोगों को लोकतन्त्र की शिक्षा देता है । गांव वालों की रुचिप्रियता से शान्तियां होने में बड़ी इकावट रहती है ।

नगर—नगर गांव की अपेक्षा बड़ा और अधिक आबादी वाला होता है । इसके लोग अधिकतर उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और नौकरी में लगे रहते हैं ।

शहर गावों के बाद बने । लोगों की चक्री हुई जरूरतों ने उन्हें बाहर की दुनिया को अपनी वस्तुएं देने और उनकी वस्तुएं लेने को मजबूर किया । साधारणतया नगर महत्वपूर्ण सड़कों के मिलने की जगह, मंडियों में, तीर्थयात्रा-और मेले के स्थानों पर, सामाजिक महत्वों के स्थानों पर और सरकार के अधिकार पर बने ।

नगरी का महत्व—आर्थिक दृष्टि से नगर और महानगर उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के महत्वपूर्ण केन्द्र होते हैं । फैक्टरियां, बैंक और बड़े बाजार अधिकतर नगरों और महानगरों में होते हैं । सामाजिक दृष्टि से नगरों में होने वाले अनेक तरह के माह-सभों में सामाजिक भावना की पूर्ति के लिये अधिक बड़ा क्षेत्र मिल जाता है । सांस्कृतिक दृष्टि से महानगरों के विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, बाला विद्यालय, नाटक और संगीत गण्टियां, ये सब सांस्कृतिक हृदय के केन्द्र होते हैं । राजनैतिक दृष्टि से नगर-निवासियों का दृष्टिकोण प्रगतिशील होता है । आन्दोलन, सम्मेलन और सार्वजनिक सम्मेलन नगरों में होती रहती हैं । राजनैतिक दली के दफ्तर नगरों में होते हैं । सरकार की राजधानी भी महानगरों में होती है ।

प्रान्त—प्रान्त प्रथम एक प्रशासनीय और राजनीतिक इकाई है । प्रत्येक राज्य या देश को प्रशासनीय प्रयोजनों के लिये प्रान्तों में बाटा जाता है । प्रान्त में सैकड़ों गांव और नगर होते हैं ।

देश—नगर के उस भौगोलिक विभाजन को देश कहते हैं जो प्राकृतिक सीमाओं द्वारा ऐसे ही अन्य विभाजनों से वृत्त कर दिया जाता है ।

निष्ठाओं की ठीक क्रम देना—आदमी अनेक दायरों अर्थात् परिवार, गांव या शहर, प्रान्त, देश और सारी दुनिया का सदस्य होता है । ये सब दायरे उसे लगभग पृथक् होते हैं, और इसलिए उसकी निष्ठा मांगते हैं । कभी-कभी उसकी एक दायरे के प्रति निष्ठा उसकी दूसरे दायरे के प्रति निष्ठा की विरोधी हो सकती है । तो, आदमी को अपनी निष्ठाओं को कैसे क्रमबद्ध करना चाहिए ? उसकी निष्ठा सदा अधिक बड़े दायरे के प्रति अधिक बड़ी होनी चाहिए क्योंकि दायरा जितना बड़ा होगा, वह उतना ही उसकी व्यक्तित्व की आवश्यकताओं को अधिक पूरा करने वाला होगा । तो भी उसे किसी भी सामाजिक इकाई के दावे की पूरी तरह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए । सब तो यह

है कि उसे अपना वाचरण ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी अनेक निष्ठाओं में कोई विरोध पैदा न हो सके ।

प्रश्न

Questions

१. गाव और नगरों का राष्ट्रीय जीवन में क्या स्थान है ? (पू० वि० १९३१)
1. What important part do villages and towns play in national life ?
(U P 1931)
२. गांव किसे कहते हैं ? किसी राष्ट्र के नागरिक जीवन में इसके कार्य और महत्व बताइये ।
2. What is a village ? Describe its functions and importance in the civic life of a nation.
३. निष्ठाओं के सही प्रयोग से आप क्या समझते हैं ? किसी नागरिक को अपनी निष्ठाओं का कैसे प्रयोग करना चाहिए और क्यों ?
3. What do you understand by 'right ordering of loyalties' ? How should a citizen order his loyalties and why ?
४. बताइये कि कहीं तक नागरिकता का अर्थ निष्ठाओं का सही प्रयोग है ।
(प० वि० असेस, १९५१)
4. Show how far citizenship means the right ordering of loyalties.
(P U. 1951)

अध्याय : : ७

सामाजिक संस्थाएं

सम्पत्ति, जाति और धर्म

सम्पत्ति

सम्पत्ति का अर्थ—सब आदमों और आदमियों के समूह भौतिक और अर्भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने हैं, अर्थात् उन पर सम्पत्ति के अधिकार भागने हैं। सम्पत्ति शब्द में जमीन, फैक्टरी, मकान, पत्नी, परेलू सामान, और धन आदि भौतिक वस्तुएं शामिल हैं। इसमें पेटेंट या एक्स्त्र, प्रतिलिप्यधिकार या ब्रांडींगडिट और किसी कारखाने या फर्म की स्थिति या नाम (Goodwill) जैसे अर्भौतिक वस्तुएं भी शामिल हैं। किसी समय लोग पुण्या और स्थिया के भी स्वामी होने थे और ये उम समय गुणम कटलाने थे।

सम्पत्ति का महत्व—सम्पत्ति मनुष्य और समाज दोनों के लिये महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिये यह हम कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि उसे सम्पत्ति रखने की ज़रूरत है तो उसकी काम करने की इच्छा बढ़ जाती है। बट्टा हम मनुष्य की योग्यता को उसकी निजी सम्पत्ति की मात्रा से नापने है क्योंकि हम समझते हैं कि योग्य आदमी अधिक कामना है और अधिक बचता है। सम्पत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बड़ी आवश्यक है। समाज के लिये सम्पत्ति का महत्व इस बात से प्रकट होता है कि सामाजिक जीवन के अधिकतर अंगों में इन पर ही विचार होगा है। निजी सम्पत्ति की प्रणाली में धन की विभक्ता पैदा होती है और इनके साथ गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं आती हैं, जो लोगों में कई तरह के अपराध और दुर्गुण पैदा करती है। राज्य भी, जो सामाजिक समूह का सर्वम उच्च रूप है, लोगों की सम्पत्ति की रक्षा के लिये बना था। बहुत बार सम्पत्ति के पीछे ही राष्ट्रों में युद्ध होने हैं। इसके अलावा, सम्पत्ति का महत्व इस बात से भी पता चलता कि मानव सम्पत्ता मनुष्य की सम्पत्ति बढ़ने के कारण ही आगे बढ़ सकी है। भिकारी जमाने में मनुष्य के पास कोई साम सम्पत्ति नहीं होगी थी, पर आजकल उसकी सम्पत्ति में अलग वस्तुएं हैं। मच तो यह है कि अगर आज की सम्यता में ये सम्पत्ति की संस्था को निकाश दिया जाए तो सम्यता का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा।

सम्पत्ति का उद्गम और वृद्धि—सम्पत्ति की मूल्य पहले निकाली बच्चों में पैदा हुईं। पहले पत्थर के औजार और हथियार जैसी चीजें वस्तुएं भी सम्पत्ति होती थीं, और ये उसकी ही होती थीं जिसका इन पर अमल में बर्खा होता और जो इनका प्रयोग करता। सेनी की जमाने और मकानों के रूप में अर्चक सम्पत्ति सेनी के साथ आई। कृषि की आरम्भिक अवस्था में जमीन उसकी होती थी, जो उस पर पहले दमल कर ले। उद्योग का विकास होने पर सम्पत्ति सम्बन्धी विचार बढ़ गये। अब यह भी महसूस

किया जाने लगा कि जिम चीज में आदमी अपनी मेहनत लगाए, वही उसकी सम्पत्ति है।

पर आजकल कोई भी इस बात पर पडताल में नहीं पडता कि शुरू में सम्पत्ति का जन्म कैसे हुआ। हम सब लोग सम्पत्ति की मग्ना को एक मस्यूपित तथ्य के रूप में ममजते हैं। आजकल इसकी मान्यता कुछ तो प्रथा में और कुछ कानून में है। अधिकतर देशों के कानून आजकल निजी सम्पत्ति के अधिकार को गारण्टी करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी इस अधिकार को मानता है।

निजी सम्पत्ति का अधिकार निरुपाधि अधिकार (absolute right) नहीं, पर यह याद रखना चाहिए कि अन्य सब अधिकारों की तरह सम्पत्ति का अधिकार भी सीमित किया जा सकता है। स्वामित्व के "नैसर्गिक अधिकार" (natural right) या सम्पत्ति के निरुपाधि अधिकार जैसी कोई चीज नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में बल ही एकमात्र अधिकार था। व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति पर अधिकार धीरे-धीरे ही माना जाना शुरू हुआ। पहले यह प्रथा पर आपारित था, और फिर कानून द्वारा माना जाने लगा। सम्पत्ति पर अधिकार तब तक माना जाना रहेगा, जब तक यह आदमी और समाज, दोनों के लिये उपयोगी और आमस्यव समझा जाता है। समाजवादी विचारधारा ने असीमित निजी सम्पत्ति के अधिकार का समाज के लिये अहितकर बताया है। इस विचारधारा के प्रभाव में बहुत से देशों में निजी सम्पत्ति के अधिकार पर पाबन्धियाँ लगा दी गई हैं, और ल्पार्द जा रही हैं।

समाजोत्तरण या राष्ट्रीयकरण—इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। इनका अर्थ है सम्पत्ति पर राज्य का स्वामित्व। राष्ट्रीयकरण का विचार समाजवादी विचारधारा का परिणाम है। गणतंत्रवादियों का कहना है कि फँटरियों और उत्पादन के अन्य मापनों के रूप में निजी सम्पत्ति सौंघही सम्पत्ति को बहुत बड़ा विषमता पैदा कर देती है। धन ही शक्ति है इसलिए असीमित निजी सम्पत्ति न केवल आर्थिक विषमताएँ पैदा करती है, बल्कि सामाजिक और राजनैतिक विषमताओं को भी जन्म देती है। इस प्रकार धन का असीमित मच्चय अलोकतन्त्रीय समझा जाता है। यह इसलिए भी समाज के लिए हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि इसमें धनी आदमी दूसरों के बल पर और अधिक धनी हो जाता है और दूसरे ज्यादा और ज्यादा गरीब होने जाते हैं। इस कारण समाजवादी उत्पादन के सब मापनों, अर्थात् भूमि, फँटरियों और वंकों, पर राज्य का स्वामित्व कर देने के हामी हैं। वे सारी निजी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते, बल्कि इसके सिर्फ उम हिस्से का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं जिसमें और धन पैदा होता है। समाजवाद में फँटरियों का नफा राजकोष में जाएगा, और वहाँ से वह राज्य के सब लोगों के लिये खर्च किया जाएगा। समाजवादी शान्तिपूर्ण और क्रमिक उपायों में तथा मुआवजा देकर राष्ट्रीयकरण करने को पक्षपाती हैं, पर कम्युनिस्ट या साम्यवादी क्रान्तिकारी और हिंसक उपायों से तथा बिना मुआवजा दिये ही राष्ट्रीयकरण करने को पक्षपाती हैं।

दूसरी बात यह है कि आदमी की सम्पत्ति के उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्से का

समाजीकरण करने के लिये कहा जाता है। कहा जाता है कि जो सम्पत्ति व्यक्ति को अपने पुरखों में मिलती है उसके लिए वह स्वयं क्रॉडिंग या मुंबानी नहीं करता। इसलिए उत्तराधिकार में निजी सम्पत्ति निकम्मे लोगों का एक बड़ा पैदा कर देती है और इसलिए यह समाज के लिए हानिकारक समझा जाता है। इसे अदर एकदम नहीं तो थोड़ा-थोड़ा करके राज्य की सम्पत्ति बना लेना चाहिए। बहुत से उन्नत देशों में उत्तराधिकार में निजी सम्पत्ति थोड़ी-थोड़ी करके समाज के अधिकार में लेने के लिये मृत्यु और उत्तराधिकार मृतक लगाने जाते हैं।

निजी सम्पत्ति के पास और विपन्न में सुनिश्चिता—(१) निजी सम्पत्ति अर्वाणि (acquisition) की प्रवृत्ति पर आधारित है, जो मनुष्य में बड़ी प्रबल होती है। इसलिए निजी सम्पत्ति बनें ही नैतिक है जैसे परिवार, जो धर्म और जनकीय प्रवृत्तियों के आधार पर बनता है। यह आदमी के मान के लिये परिवार के ही समाज परमरी भी है। कोई भी आदमी, चाहे वह कितना भी सुनसुत और बुद्धिमान हो, सम्पत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति में छापी नहीं है। हम सोच सकते हैं कि निजी सम्पत्ति में मनुष्य का अनुराग और इससे मिलने वाला आनन्द सामंजसिक सम्पत्ति के समान और आनन्द में कहीं अधिक होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि सम्पत्ति एक नैतिक सत्ता है।

(२) सम्पत्ति होने से इनके स्वामी को कुछ सुरक्षा अनुभव होती है। अगर निजी सम्पत्ति न हो तो मिनी के पास भविष्य के लिये कोई व्यवस्था न होगी और इसलिए सुरक्षा की भावना भी नहीं होगी। मनुष्य तभी उन्नति कर सकता है जब उसे निश्चिन्तता हो।

(३) सम्पत्ति से इनके स्वामी को कुछ आशंसी की भावना भी मिलती है। जिस आदमी के पास जीवन-भारण के लिये कुछ साधन हैं, उसे अरबी पसन्द न आने वाला काम स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी रचि के अनुसार अपनी सोचता का उनको कर सकता है। सम्पत्ति की उन्नति तभी होती है जब प्रत्येक व्यक्ति यह काम करे जिसके लिये वह सबसे अधिक उपयुक्त है।

(४) सम्पत्ति रखने का अधिकार मनुष्य को इच्छापूर्वक और अच्छी तरह काम करने के लिये आह्वान करता है। इस प्रकार, निजी सम्पत्ति उत्पादन के लिये बड़ी प्रेरणा होती है।

(५) सम्पत्ति रखने के अधिकार से धन बचाने की चेष्टा मिलता है और इसके न होने पर आदमी धन बर्बाद कर देता है। अनेक तरह के उत्पादन कामों में स्वामी के लिये धन बचाना बहुत जरूरी है। अगर बचत न होती तो लोग बड़ी-बड़ी ऐकस्मिका सम्पत्तियां जोड़ कर खारूत न मने कर पाते।

सहारा मिलता है जिनकी जीविका उत्तराधिकार में प्राप्त और संचित निजी सम्पत्ति पर होती है। अगर हर आदमी को अपनी जीविका बमाना पड़े और उसके पान कोई सालो समय न हो तो ये विज्ञान और कलाएँ खत्म हो जाएगी।

विपक्ष में युक्तिवा—समाजवादी और कम्युनिस्ट निजी सम्पत्ति को विपक्ष में युक्तिवा देते हैं। वे इस पर निम्नलिखित कारणों से आपत्ति उठाने हैं —

(१) निजी सम्पत्ति की प्रणाली मनुष्य को लोभी और स्वार्थी बना देती है और आम तौर पर समाज में झगड़ों का कारण होती है।

(२) इनमें धन की विपमता पैदा होती है। अधिक विपमता ने सामाजिक और राजनैतिक विपमता का जन्म होता है। इसलिए निजी सम्पत्ति आलोकनशील है।

(३) निजी सम्पत्ति की प्रणाली अदल लोभों का जीने और फलने फूलने का अनुचित रूप से मौका देती है। दूसरी ओर, उन लोगों को जो योग्य और दक्ष हैं, और सम्पत्ति से हीन हैं, प्रायः जीवन को आरम्भिक सुविधाएँ भी नहीं मिलती।

(४) सम्पत्ति होने से मनुष्य को सुरक्षा और जाबादी की भावना तो मित्त सतती है, पर यह उसे निकम्मा और किञ्चलक्ष्म भी बनाती है। वह अपना समय और नकल उत्पादक कार्यों में लगाने के बजाय निरर्थक कामों में लगा सकता है।

(५) मनुष्य सदा निजी धन-लाभ की प्रेरणा से ही काम नहीं करता। बड़े-छोटे लोग समाज में यश और सम्मान पाने के लिये काम करते हैं और काम करने के लिये प्रेरित किये जा सकते हैं।

(६) कला, विज्ञान और साहित्य की उन्नति के लिये निजी सम्पत्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह काम विद्वविद्यालयों और अन्य निगमित निवाया (corporate bodies) द्वारा, जिनमें राज्य भी है, अधिक सरलता और दक्षता से किया जा सकता है। राज्य द्वारा कला, विज्ञान और साहित्य के संरक्षण के उदाहरण भूतकाल के भी हैं और वर्तमान काल के भी।

(७) अन्त में यह कहा जाता है कि निजी सम्पत्ति तभी उचित ठहराई जा सकती है, जब यह समाज के लिये उपयोगी या हितकर हो। अगर निजी सम्पत्ति में ये ही सुराइया पैदा होती हैं जिनसे समाज काफ़ी उठा रहा है तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं और इसे खत्म कर देना चाहिए।

निष्कर्ष—हम मानते हैं कि निजी सम्पत्ति का कोई निरपराध अधिकार नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी अधिकार सामाजिक दृष्टि से उचित होना चाहिए। तो भी, आदमी को रोजाना की जरूरतों में आने वाली कुछ वस्तुओं पर निजी स्वामित्व में न केवल उसकी उतनी दक्षता बढ जाती है, बल्कि सामाजिक जीवन में मददगी भी रक जाती है। जमीन और भारी मशीनों का, जिनमें और सम्पत्ति पैदा होती है, निजी स्वामित्व राज्य को सौंपा जा सकता है, पर ऐसा होने से पहले इसके स्वामी को उचित मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए। असल बात यह है कि यह तय करना बड़ा कठिन है कि किस मोमा तक सम्पत्ति का निजी या सार्वजनिक रहने दिया जाए।

जाति या वर्ण

हर एक समाज के सदस्यों में कोई न कोई भेदभाव आमनोर में पाया जाता है। ये भेदभाव, चाहे ये जन्म के आधार पर हो या धन सम्पत्ति के, समाज को कई समूहों में बांट देते हैं, जो श्रेणिया या वर्ण कहलाते हैं। पुराने जमाने में जन्म या कुलीनता, खास तौर से इन्डो-यूरोपीय भाषा बोलने वाले लोगों में, विशेषता प्रकट करने वाली महत्वपूर्ण बात रही है। आज के जमाने में जन्म का इतना महत्व नहीं है जितना धन का।

जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था अनेक देशों में फैली हुई है पर तीन दृष्टियों से यह भारत की खास चीज है —

(१) भारत में ही जातियों की संख्या हजारों में है और कहीं ऐसा नहीं है।

(२) जातियों की प्रणाली और योजना जितनी बारीकी से भारत में बनाई गयी है उतनी और किसी देश में नहीं है।

(३) और कहीं स्पृश्य और अस्पृश्य का भेदभाव नहीं है।

जाति प्रथा की कुछ विशेषताएँ—यद्यपि जाति की अनेक परिभाषाएँ हैं, फिर भी ऐसी कोई व्यापक असली परिभाषा नहीं है, जिसमें जाति प्रथा की सब विशेषताएँ आ जाय। असल में, जाति प्रथा इतनी जटिल चीज है कि इसकी परिभाषा करना कठिन है। ज्यादा से ज्यादा हम इसकी कुछ विशेषताएँ बता सकते हैं। जाति की कुछ विशेषताएँ ये हैं —

(१) हर जाति का एक नाम है जिससे उसके सदस्य पुकारे जाते हैं।

(२) पुराने जमाने में सब जातियों की पचासवें होनी थी, जो अपने सदस्यों पर अर्धसर्वोच्च सत्ता (semi-sovereign authority) का प्रयोग करती थीं। पचासवें का मुख्य काम फैसले करना होना था।

(३) जाति प्रथा की एक खास विशेषता यह थी कि एक जाति के सदस्य कुछ जातियों के लोगों के हाथ का भोजन नहीं करते थे। नये जमाने के साथ यह बान तेजी से खत्म होनी जा रही है।

(४) एक और महत्वपूर्ण रीति, जो अब भी बहुत कुछ जगहों में जारी है, अपनी जाति से बाहर शादी करने के बारे में थी।

(५) जाति की सदस्यता जन्म से होती थी। व्यक्ति के गुणों का उसमें कोई दखल न था।

(६) उंची जातियों के लोगों को नीची जातियों के लोगों के मुकाबले में समाज में कुछ विशेष मुक्तिपाएँ हासिल थीं। नीची जाति वाले लोगों को शिक्षा, पूजा और सेवा बदलने के मामलों में बड़ी रूपायतें थीं।

जाति प्रथा का उद्गम और वृद्धि—भारत में जाति का सबसे पुराना उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। आर्यों ने जाति प्रथा प्रथम तो द्रविडों से, जिनका रूप थाला था, अपने रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए, और दूगरे, दूध में कुम्हनों के मुकाबिले में अपनी दशना बढाने के लिये शुरू की थी। चार जातियों में धर्म के

विभाजन या वामो के बटवारे से उनके लिए लड़ते रहना और साथ ही साथ अपनी दूसरी जरूरतें पूरी करने रहना सम्भव हो गया। गुरु के जमाने में जाति प्रथा कठोर नहीं थी। पैसा बदला जा सकता था। दूसरी जाति में भोजन और विवाह करने की पाबन्दी भी इतनी सख्त नहीं थी। धीरे धीरे जाति प्रथा कठोर हो गयी और आदमी जन्म में ही किसी जाति का सदस्य होने लगा। निम्नलिखित कारणों के प्रभाव से जानियों की सख्या भी बढ़ने लगी —

(१) काम-धर्मों की वृद्धि—योग के आश्रित जीवन में तरफकी के साथ काम-धर्मों की सख्या बढ़ गई। अलग-अलग पेरो और धर्म करने वाला लोग ने अपनी अलग जाति बना ली, यद्यपि गुरु म के किसी एक ही जाति के रहे हाने।

(२) पूजा की रीति—अलग-अलग देवताओं की पूजा से भी जातियों में भेद पैदा हो गया।

(३) निवास और भाषा—एक ही जाति के लोग देश के अलग-अलग भाषा और संस्कृति वाले अलग-अलग भागों में निवास करने लगे। इस कारण भी अलग जातियां बन गईं।

(४) विदेशी आक्रमण का प्रभाव—विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से भी जातियों की सख्या बढ़ गई। ग्रीक, हूण, बुगान आदि गुरु के आक्रान्ता हिंदू जाति में विलीन हो गए। पर उन्होंने अपनी अलग जातियां बना लीं विदेशी आक्रमणों ने भी जाति प्रथा का कठोर बना दिया।

जाति प्रथा के लाभ—किसी समय जाति ने बड़ा उपयोगी काम किया

(१) जाति प्रथा के कारण आर्य लोग अपनी रक्त की शुद्धता कायम रख सके।

(२) जाति प्रथा द्वारा अम के विभाजन ने उनकी द्रविडों से लड़ने की शक्ति बढ़ा दी।

(३) पैसा बदलने के बारे में पाबन्दी लगा दी गई। जाति प्रथा ने विभिन्न संस्कारियों में कौशल और ज्ञान की विशेष योग्यता पैदा की। धर्म का कौशल पिता ने पुत्र को प्राप्त हो जाता था।

(४) सदस्यों की बन्धुता और सहयोग की भावना बढिनाई के समय काम आती थी।

(५) जाति प्रथा की कठोरता ने हिन्दू समाज को विनाश से बचाया है। इस प्रथा ने विदेशियों को इसमें विलीन होने में सहायता दी। जो आक्रान्ता, जैसे मुसलमान, हिन्दू समाज में विलीन नहीं हो सके, वे जाति से बाहर खाने और जाति से बाहर सारी करने के बारे में कठोरता के कारण, जो जाति प्रथा की विशेषताएँ थीं, हिन्दू धर्म को नष्ट नहीं कर सके।

जाति प्रथा की हानियाँ—(१) जाति प्रथा जन्म को अनावश्यक महत्त्व देती है और योग्यता की कौशल कम लगानी है।

(२) इसने तरक्की को रोका, क्योंकि किसी को अपना पैसा या बुद्धा बर्तों की इजाजत नहीं थी। विरोध रूप से नीची जातियों को बड़ी निर्बलता (disabilities) भोगनी पट्टी थी और उन्हें तरक्की करने का मौका नहीं था।

(३) मेना का काम सिर्फ क्षत्रियों के जिम्मे था। इसलिए अन्य वर्ण दुग्मन का मुनाबन्ग करने से उदासिन हो गये और उन्होंने देश को मुसोवत के समय भी हार पाव हिलाने की जम्मत नहीं समझी। इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था ने विदेशियों के मुनाबने के समय देश को कमजोर रखा।

(४) जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था ने समाज को विलुप्त अलग विभागों में बांट दिया है, और यह देश की फुट का बहुत बडा कारण है। इसने राष्ट्रीयता और देश प्रेम को बढ़ने से रोका।

जातिप्रथा या वर्ण व्यवस्था का भविष्य—यद्यपि वर्ण व्यवस्था अब भी हमारे समाज की बहुत बडी विघेपना है, तो भी समय गुजरने के साथ उसकी पुरानी शक्ति बहुत कुछ नष्ट हो गई है। मौजूदा जमाने में इसकी बढोला तेजी से खत्म होनी जा रही है। शिक्षा के प्रकार और विज्ञान ने हम दिशा में बडा काम किया है। वर्ण की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। और अगर हमें एक शक्तिशाली संगठन और लोकनन्वीय राष्ट्र बनाना है तो इसे छोडना ही होगा। गांधी जी ने छुआडूत विरोधी आन्दोलन ने वर्ण की व्यवस्था सिद्ध करने में बडा काम किया है। अब तक हमारा समाज लोकनन्वीय न हो, जिनमें सब लोग बराबरी के आधार पर सडे हो, सब एक लोकनन्वीय सामन भी नहीं होनवता। भारतीय गणराज्य के संविधान ने छुआडूत को खत्म कर दिया है।

धर्म

धर्म किसे कहने है—मनुष्य स्वभाव से कमजोर और टरपोक है। वह अपूर्ण है और कई कामों में अशक्त है। बडिनाई जाने पर वह मदद के लिए किसी अधिक बलवान ताकत की ओर देखता है। आदिकालीन जमाने में लोग अपने मूल भूतबों की सहायता के लिये बुधने थे, और उन्हें मुश करने के लिये भेड चड्ढा करने थे। इसके बाद वे प्रकृति के बलों की पूजा करने लगे। हर प्राकृतिक प्रतीति का, उदाहरण के लिये, आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और वर्षा को, एक देवता माना जाता था। बाद में इन्होंने एक सर्वोच्च सत्ता, अर्थात् ईश्वर का विचार विचरिन किया और सब प्राकृतिक प्रतीतिया उस ईश्वर की शक्ति का रूप मानी जाने लगीं। इस प्रकार, धर्म की यह परिभाषा की जा सकती है कि आदमी का अधिमानवीय शक्ति में विश्वास धर्म है जो मनुष्य के भाग्य को गण्डा या बुरा बनाने में मयथ है। "धर्म मनुष्य की उस व्यक्ति से की गई अर्पण है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वह वे काम कर सकता है जो आदमी खुद नहीं कर सकता।" धार्मिक व्यवहार आदि उन दूसरे व्यवहारों की तरह ही है जिनमें वह अपने से ऊंची किसी सत्ता से कृपा की माचना करता है। किसी की कृपा मानने हुए आदमी उसकी प्रणामा करता है। धर्म में प्रार्थना यही प्रयोजन पूरा करनी है।

धर्म की आवश्यकता—बुद्धि की दृष्टि से आदमी आसानी से कह सकता है कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपुनिक पुनर्तर्क का युग है और इसी कारण आज का आदमी अधिक धर्महीन है, पर धर्म विश्वास की वस्तु है, तर्क की नहीं। यह हृदय को छूता है। मनुष्य का मस्तिष्क अपने बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण कठोर हो सकता है, पर ऐसा बहुत कम मिलेगा कि किसी का दिल इतना कठोर हो कि उसे धर्म की आवश्यकता न रहे। आदमी अपने रोजाना के जीवन में, जब वह किसी मूसीबत में नहीं है, धर्महीन हो सकता है, पर कष्टाई के समय प्रायः हर आदमी किसी अतिमानवीय शक्ति का सहारा चाहता है। इन्सान अभी धर्म की आवश्यकता की मजिल से आगे नहीं पहुंचा। हो सकता है कि जब मनुष्य विज्ञान की सहायता से प्रकृति को पूरी तरह जीत ले तब धर्म की आवश्यकता न रहे।

धर्म और सम्प्रदाय—धर्म आदमी का विलुप्त वैयक्तिक और निजी मामला है। ठीक ठीक कहे तो यह मनुष्य और उसके आराध्यदेव या ईश्वर के बीच वैयक्तिक सम्बन्ध को सूचित करता है। इस सम्बन्ध को प्रकट करने के लिये किसी बाहरी चिन्ह की जरूरत नहीं। इस अर्थ में एक आदमी का धर्म दूसरे को प्रभावित नहीं करता और न इसे दूसरे को प्रभावित करना चाहिए। यह आपसी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा नहीं पैदा कर सकता। धर्म के कारण जो अनेक ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धाएं हैं, वे असल में अनेक सम्प्रदायों के कारण हैं। सम्प्रदाय उन व्यक्तियों के सामाजिक संगठन को कहते हैं जिनका विश्वास, पूजा की रीति, धार्मिक कृत्य और ममारोह एक-से हो और यह उस विश्वास की रक्षा, वृद्धि और प्रचार के लिये बनाया जाता है। सम्प्रदाय के कुछ मुनिरचित सिद्धान्त और नियम होते हैं इसका एक संगठन, पुरोहित मंडल, पूजा और सम्मेलन की जगह तथा कोई प्रार्थना-मुस्तक होती है। मन्त्र धर्म को इनमें से किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है। वह तो हमारे अन्नकरण का विषय है और अगर हमारा हृदय और आत्मा ईश्वर के साथ पूर्ण एकात्मता रखते हैं तो उसे किसी बाहरी चिन्ह या दिखावे की जरूरत नहीं। जब लोग अपने आपको सम्प्रदायों में संगठित कर लेते हैं और एक विश्वास की धूमरे विश्वास में धोखेगा सिद्ध करने लगते हैं, तब समाज में गड़बड़ी पैदा होती है।

धर्म और सामाजिक प्रथाएं—जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, धर्म भवन और उसके आराध्यदेव के बीच निजी मामला है। इसका प्रयाओ से कोई सम्बन्ध नहीं। प्रथाएं वे पुराने आचार हैं जिन्हें किसी जनसमूह ने उनकी उपयोगिता के कारण अपना लिया था, और अब वे या तो आशुन के कारण या भय के कारण चली आती हैं। वर्ण व्यवस्था, विवाह, पर्दा और दहेज, ये सब सामाजिक प्रथाओं के उदाहरण हैं। धर्म का उनमें कोई वास्ता नहीं। अधिक से अधिक यह ही सत्यता है कि सम्प्रदाय इन्हें लोगों पर लागू कर दे।

धर्म और नैतिकता—नैतिकता मनुष्य के अनुभव और उसके अच्छे और बुरे परिणाम से पैदा होती है। अगर आदमी ईमानदार और सच्चा है तो इसका कारण

यह है कि वह देखता है कि बेईमानी और झूठ से वह मुसीबत में फँस जाएगा। इस प्रकार ठीक-ठीक बड़े तो नैतिकता और धर्म एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं। पर धर्म ने नैतिकता को फैलाने में बड़ा काम किया है। जब यह बड़ा जाना है कि अनैतिक काम करने से ईश्वर नाराज होगा तो आदमी उन्हें करते हुए डरता है।

धर्म के अच्छे परिणाम— (१) धर्म हमारी इन्द्रियो को अनुशासित करता है। यह हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं, भावों और वासनाओं का नियन्त्रण करना सिखाता है। यह हमें लोभ, कामुकता, अहंकार और नफरत से बचाना है। यह नैतिक शक्ति देता है, और बड़बुदाइयों का मुकाबला करने का साहस पैदा करता है। धर्म आदमी की आन्तरिक शक्ति के लिए, जहाँ मन और आत्मा की सगुण्टि के लिये, आवश्यक है।

(२) धर्म हमें ईश्वर के रूप में एक पूर्ण सत्ता का विचार देता है और हमें उस पूर्णता का रास्ता दिखाता है। यह हमें बनाता है कि ईश्वर मनुष्य के भीतर है। आदमी को सिर्फ यह करना है कि वह ईश्वर को पहिचाने और उसका साक्षात्कार करे।

(३) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, धर्म आदमी को आत्म-नियन्त्रण, मान-वीथना, प्रेम, दया नष्टता और सहनशीलता आदि कई नैतिक गुण पैदा करने में सहायता देता है। यह जीवन के सम्मान की शिक्षा देता है और ईश्वर की नज़रों में सब आदमियों की समानता का उपदेश करता है। इसके द्वारा मनुष्य के पापविक गुण, यर्थात् अभिमान, अहंकार, लोभ, स्वार्थ और प्रीध नियन्त्रण में रखे जा सकते हैं।

(४) मनुष्य धर्म मनुष्यों में प्रतिस्पर्धा, पूणा और युद्ध के स्थान पर शांति, सामंजस्य और सहानुभूति पैदा करता है। पुराने समाजों में धर्म लोगों को कानून पालक बनाने में बड़ा सहायक होता था। तथाकथित धर्मयुद्ध असल में सम्प्रदायों के मध्य हुए युद्ध हैं। धर्म अपने आप में कभी लोगों को लड़ने के लिए प्रेरणा नहीं देता।

धर्म के विरुद्ध कुछ बातें— (१) धर्म समाज में परिवर्तन-विरोधी बल के रूप में काम करता रहा है। यह दुनियाँ की बस्तुओं के प्रति उदासीनता का उपदेश करता है। इन तरह हमने समाज की भौतिक उन्नति को रोका है। दूसरी बात यह कि धर्म के अधिष्ठाताओं ने प्रायः समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ढांचे में परिवर्तन करने के महान आन्दोलनों की बुराई की है। सच तो यह है कि धार्मिक सगठन समाज के घनी वर्गों के सदा सहयोगी रहे हैं, जो इन परिवर्तनों के विरोधी होते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति धार्मिक सगठनों का रुख न केवल उदासीनता का, बल्कि बाधापदा उत्पन्न का रहा है।

(२) जहाँ तक धर्म भय से पैदा होता है, वहाँ तक यह मनुष्य की गरिमा को कम करता है।

(३) धर्म भौत के बाद के परलोक जीवन को महत्त्व देता है और इस लोक में जीवन के दुःखों और कष्टों को शीघ्र बसाटा है। ईसाई धर्म के अनुसार यरीबी और रोग सिर्फ इस लोक के जीवन में हैं। जीवन का ऐसा अवधारण उन्नति को रोक्ता है।

(४) धर्म प्रायः लोगों का आत्मविश्वास नष्ट कर देता है। वे अपनी बढि-नाइसों और मुसीबतों को जीतने के लिये कुछ यत्न नहीं करते। वे भाग्यवादी हो जाते हैं और अपने दुःखों का कारण भाग्य को बताते हैं जो उनके काबू से बाहर है। वे अपनी मुसीबतों दूर करने के लिये ईश्वर का सहारा देखते हैं और पूरी तरह उस पर ही निर्भर होते हैं।

(५) यह भी कहा जाता है कि धर्म बौद्धिक योग्यता को हीन मानता है, क्योंकि इसे थडालू लोगों की जरूरत है, तर्कशील लोगों की नहीं।

भारत

सम्पत्ति—सम्पत्ति शब्द में वे सब भौतिक और अभौतिक वस्तुएं शामिल हैं जिन पर मनुष्य का स्वामित्व होता है। सम्पत्ति मनुष्य और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह आदमी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसी के कारण लोगों में झगड़े और राष्ट्रों में युद्ध होने हैं। यह आदमी की योग्यता और समाज की प्रगति आपने की बगैरे है।

सम्पत्ति का उद्गम चाहे जो रहा हो, पर आज इसका आधार रुद्धि और कानून की मजूरी है।

सम्पत्ति का अधिकार कोई निर्याधि (absolute) अधिकार नहीं है। सारे समाज की भलाई को देखते हुए सम्पत्ति के अधिकार का सीमित किया जा सकता है और निया जाता है।

सम्पत्ति के सार्वजनिक या राज्य द्वारा स्वामित्व को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। सम्पत्ति का सीमाहीन लक्ष्य न्याय के विरुद्ध भी माना जाता है और लोकतंत्र के विरुद्ध भी। राष्ट्रीयकरण सम्पत्ति का समान और उचित वितरण कर देता है।

निजी सम्पत्ति के पक्ष में युक्तियां—(१) अवाप्ति की महत्व वृत्ति (instinct of acquisition) पर आधारित होने से यह प्राकृतिक है। (२) यह काम करने के लिए प्रेरणा देती है। (३) इसके द्वारा आदमी अपने भविष्य की रक्षा कर लेता है। (४) यह अपने स्वामी की स्वतंत्रता की भावना देती है। (५) इसने विज्ञान, कला और साहित्य की उन्नति में भी सहायता दी।

निजी सम्पत्ति के विरुद्ध युक्तियां—(१) यह आदमी को लोभी और स्वार्थी बनाती है। (२) यह असमानताएं पैदा करती है। (३) यह निवृत्त और फिजूलखर्ची को बढ़ावा देती है। (४) यह अरुण को फलने-फूलने में सहायता देती है। (५) मनुष्य में सदा निजी आर्थिक लाभ की भावना ही नहीं रहती। (६) यह विज्ञान और कला की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं।

जाति या वर्ण (Caste)—जाति या वर्ण की परिभाषा करना बढिन है। सो भी, जाति-अथा या वर्ण-व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं ये हैं —

(१) प्रत्येक जाति का कोई नाम होता है।

(२) पहले सब जातियों की पचापने होनी थी।

(३) ज्ञानि प्रथा का ध्वनितार्थ यह है कि यह दो जातियों में परस्पर मोहन और विराह पर पावन्दी लगायी है।

(४) ज्ञानि की मदम्यता जन्म में होती है।

भाग्य में रक्त की शुद्धता और धर्म के विभाजन के विचारों ने वैदिक काल में ज्ञानि प्रथा को जन्म और बढ़ावा दिया। इनके बढ़ने में धर्मों की बुद्धि, पूजा की गिनतियाँ रहन-महन की व्यवस्थाओं और विदेशी आक्रमणों में भी मदद मिली।

इसकी अच्छाईयाँ—जिसी जमाने में ज्ञानि या वन बड़ा उपयोगी था:

(१) इसने आर्यों की रक्त की शुद्धता बनाये रखी। (२) धर्म के विभाजन ने उनकी दृष्टता बड़ा दी। (३) इससे काम-धर्म, दम्भकारी और व्यापार में शुद्धता पैदा हुई। (४) हिन्दू धर्म को नष्ट शक्ति में बचाया।

दुराईयाँ—(१) इसने योग्यता को गौण कर दिया। (२) इसने समाज की प्रगति को रोक दिया। (३) इसके कारण मष्टवाद और देश-धर्म की नृष्टि न हो सकी। (४) इसने विदेशियों के मुकाबले में हमारी प्रतिरक्षा को कमजोर कर दिया। (५) इसने बड़ी सामाजिक असमानताएँ पैदा कर दीं।

धर्म—मनुष्य स्वभाव में कमजोर और दरगोत्र है। यदिवाक्य में वह अनेक प्रतियोगियों और बलों की पूजा करता आता है, जिन्हें वह अपने में अपित प्रबल मानता रहा। इसलिए "धर्म" जैसे व्यक्ति में मनुष्य की प्रार्थना है जिसमें धर्म में यह माना जाता है कि वह वे काम कर सकता है जो मनुष्य खुद नहीं कर सकता। वह प्रार्थना द्वारा इन बलों में महायत्ना मागता है।

किमी आदमी का मन इतना मन्त्र हो सकता है कि उसे धर्म को बलवत् अनुभव न हो। पर ऐसा बहुत कम होता है कि उसका दिल भी इतना ही मन्त्र हो। मुनोवत के समय प्रायः हर कोई अति मानवीय शक्ति को सहायता के लिए पुकारता है।

धर्म आदमी का वैयक्तिक और निजी माधन्य है। यह भक्त और उसके आगम्य-देव या ईश्वर के मध्य वैयक्तिक सम्बन्ध को सूचित करता है। धर्म के लिए किमी बाहरी चिन्त की आवश्यकता नहीं। धर्म के नाम पर जो ईर्ष्या और विरोध योग्य जाता है वह अन्त में धार्मिक सपत्नों द्वारा पैदा किया जाता है।

धर्म के अच्छे प्रभाव—(१) यह हमारी दृष्टियों को अनुशासित करता है। (२) यह धार्मिक शांति के लिए जरूरी है। (३) यह हमें सिखाता है कि ईश्वर मनुष्य में है, और कि मनुष्य भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। (४) यह मनुष्य में नैतिक गुण पैदा करके उसके नैतिक बल का प्रयोग में लाता है। (५) यह सामाजिक सम्बन्धों में शांति लाता है।

धर्म के दुष्परिणाम—(१) इसने समाज की भौतिक दृष्टि में रखावट डाली है। (२) यह हम जीवन के दुःखों को कम करके दिनाता है और मनुष्य को भाग्यवादी बना देता है। (३) यह धर्म को बवाकर धडा को बढ़ावा देता है।

प्रश्न

QUESTION

- १ 'सम्पत्ति' शब्द से आप क्या समझते हैं। इसका किसी नागरिक के जीवन में क्या स्थान है ?
- 1 What do you understand by the term Property ? What part does it play in the life of a citizen ?
- २ निजी सम्पत्ति के पक्ष और विपक्ष में युक्तियों दीजिये।
(१० वि० अप्रैल १९५२)
- 2 Make out a case for and against private property
(P U April 1952)
- ३ सम्पत्ति कहां तक निजी रहने दी जानी चाहिए और कहां तक इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये ? दोनों बातों का उत्तर युक्तियों सहित दीजिये।
- 3: To what extent property may be allowed to be private and to what extent should it be nationalised ? Support your answer with arguments in both the cases
- ४ धर्म किसे कहते हैं ? किसी नागरिक के जीवन में इसका क्या महत्व है ?
- 4 What is 'Religion' ? What is its importance in the life of a citizen ?
- ५ नागरिक जीवन पर धर्म के अच्छे और बुरे प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
- 5 Estimate the good and bad effects of religion on civic life
- ६ वर्ण या जाति किसे कहते हैं ? वर्ण या जाति अच्छे नागरिक जीवन में कैसे बाधा डालती है ?
- 6 What is 'caste' ? How is caste a hinderance to good civic life ?
- ७ वर्ण या जाति किसे कहते हैं ? इसके गुण और दोष बताइये।
- 7 What is caste ? What are its merits and demerits ?

अध्याय : : =

राज्य और इसके घटक तत्त्व

राज्य शब्द का गलत प्रयोग—मादाएण बोडवान् में राज्य शब्द का प्राम. गलत प्रयोग किया जाता है। इसका राष्ट्र, समाज, सरकार और देश जैसे शब्दों के स्थान में प्रयोग करना और सम में डालने वाला है। उदाहरण के लिये, जब हम अनाज पर राज्य के नियंत्रण या सिकके डालने पर राज्य के गुणाधिकार की बात कहते हैं, तब व्यसल में हमारा मतलब सरकार के नियंत्रण और सरकार के एकाधिकार से होता है। किसी सघान या फेडरेशन की इकाइयों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग भी गलत है। वेम्पू और पञ्जाब भारतीय मण की इकाइया हैं। इस शब्द के ठीक अर्थ की दृष्टि से वे राज्य नहीं हैं, क्योंकि उनमें राज्य के एक परमावस्था गुण, अर्थात् सर्वोच्चता, का अभाव है।

नागरिक शास्त्र में राज्य शब्द का एक मुनिश्चित अर्थ है। यह राजनैतिक रूप से सङ्गठित और स्वतन्त्र किसी प्रादेशिक समाज के लिये प्रयुक्त होता है। राज्य आज एक समाज के विकास की सबसे ऊँची सीढ़ी को निरूपित करता है। राज्य एक सामान्य उद्देश्य की सिद्धि के लिए सङ्गठित मनुष्यों का साहचर्य भी है। परन्तु एक दोन्नीय साहचर्य है। यह सब साहचर्यों में अधिक महत्वपूर्ण भी है।

नागरिक शास्त्र के विचारों के रूप में हमें राज्य का गहराई से अध्ययन करना होगा क्योंकि नागरिक और उसके अधिकारों और कर्तव्यों के अध्ययन में हमारी गहरी दिलचस्पी है। यदि राज्य न हो तो कोई नागरिक भी न होगा और उसके कोई अधिकार और कर्तव्य भी नहीं हो सकते।

राज्य की परिभाषा—आज तक समय-समय पर राज्य की असंख्य परिभाषायें की गई हैं। वेम्पू ने राज्य की यह परिभाषा की थी कि राज्य 'उन परिवारों और गावों का साहचर्य है जिनका उद्देश्य पूरा और आनन्दपूर्ण जीवन है।' ग्रीकनी सतान्त्री में बोडिन ने राज्य की यह परिभाषा की कि 'बहु परिवारों और उनकी सामी सम्पत्तियों का ऐसा साहचर्य है जो सर्वोच्च शक्ति और तर्क में शामिल होता है।' पर ये परिभाषायें अब विलकृत पुरानी हो गई हैं। वे परिवार को राज्य की इकाई मानकर चलती हैं, व्यक्ति को नहीं।

आज के जमाने में हालैण्ड ने राज्य की यह परिभाषा की कि 'मनुष्यों का बहुत-सा समुदाय जो साधारणतया किसी प्रदेश पर रहता है और जिसमें बहुमत की या किसी निश्चित वर्ग की दृष्टि, ऐसे बहुमत या वर्ग की शक्ति से, उनके मुखावले में, जो इनका विरोध करते हैं, प्रभावी बनाई जाती है।' राज्य की सबसे अच्छी और सबसे स्पष्ट परि-

माया गार्नर ने दी है। उसके अनुसार राज्य "उन व्यक्तियों का एक समुदाय है, जिनकी सख्या कहीं कम कहीं अधिक होती है, और जो किसी निश्चित राज्य क्षेत्र पर स्थायी रूप से रहते हैं—यह समुदाय बाह्य नियंत्रण से स्वतन्त्र या एग्रेग्रेट स्वतन्त्र होता है, और इसमें एक संगठित सरकार होती है जिसकी आज्ञाओं का अधिकतर नागरिक आदतन पालन करते हैं।" बुढ़रे विलमन की परिभाषा छोटी और तथ्यसूचक है। वह कहता है, "राज्य वह जनसमुदाय है जो किसी मुनिश्चित राज्यक्षेत्र में कानून के लिये संगठित है।"

राज्य के घटक तत्त्व—गार्नर की उपर्युक्त परिभाषा में यह स्पष्ट होगा कि राज्य के गठन में चार परमावश्यक तत्त्व होते हैं। वे हैं—(१) आबादी, (२) क्षेत्र, (३) सर्वोच्चता, और (४) सरकार। ये चारो तत्त्व मिलकर राज्य बनाते हैं। राज्य का अर्थ न तो जन-समुदाय है और न वह राज्यक्षेत्र है, जिस पर वह रहता है, और न वह सरकार है जिसके द्वारा राज्य अपना कार्य करता है।

अब हम राज्य के विभिन्न तत्त्वों के महत्त्व पर एक एक करके विचार करेंगे।

आबादी—आबादी राज्य का पहला परमावश्यक तत्त्व है। बिना लोगों के राज्य नहीं हो सकता। राज्य का जन्म तब ही होता है जब मनुष्य जाति का एक भाग राजनैतिक दृष्टि से संगठित हो जाता है। पर राज्य के मदस्यों की कोई अधिकतम या न्यूनतम सख्या निश्चित नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि उनकी सख्या बहुत होनी चाहिए और दस-बीस आदमी, चाहे वे स्वतन्त्र और संगठित भी हों, राज्य का निर्माण नहीं करते। गार्नर के अनुसार आबादी सख्या में इतनी काफ़ी होनी चाहिए कि वह राज्य के संगठन को बनाए रख सके। वह राज्य के क्षेत्रफल और साधनों के अनुपात में बहुत अधिक भी न होनी चाहिए। जब किसी राज्य की आबादी उसके साधनों की तुलना में बहुत अधिक होती है, तब इसका मतलब होता है कि गरीब राज्य की गरीब आबादी।

राज्य क्षेत्र—जन समुदाय के पास राज्य बनने में पहले एक मुनिश्चित राज्य-क्षेत्र होना चाहिए। कोई घूमने फिरने वाला कबोला राज्य का निर्माण नहीं करता, यद्यपि तब तबस्य उसके एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। मुनिश्चित राज्य-क्षेत्र का होना राज्य को मनुष्यों के और सब साहज्यों से भिन्न करता है।

पर राज्य-क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं है। प्राचीन ग्रीस में एक नगर ही राज्य हुआ करता था। आजकल बहुत बड़े-बड़े राज्य भी हैं, जैसे रूस, चीन और भारत, तथा बहुत छोटे-छोटे राज्य भी हैं जैसे लाजमदग और अल्बानिया। इसके अलावा, किसी राज्य का क्षेत्र सारा दृग्दृष्ट या बड़ा हुआ और भौगोलिक दृष्टि में अलग-अलग भी हो सकता है। पान्किवान का राज्य क्षेत्र इन्ट्रॉ नहीं है।

सरकार—आवश्यक नहीं कि किसी मुनिश्चित क्षेत्र में रहने वाले जनसमुदाय राज्य का निर्माण करना ही हो। उसे राजनैतिक रूप से संगठित और सामूहिक कार्यवाही करने में समर्थ होना चाहिए। गार्नर के अनुसार "सरकार वह अभिकरण या तंत्र है जिसके जरिये साक्षी नीतियाँ तय की जाती हैं और जो साक्षे मामलों को नियमित करता

अधिकृतता और साहचर्य पर एक समान लागू होती है। इस नियम का अन्वय अपवाद अन्य राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधि है। यह अपवाद सिर्फ मौज्ज्य (courtesy) है और सर्वोच्च प्रभु द्वारा वापिस लिया जा सकता है।

सर्वोच्चता अविभाज्य होती है—सर्वोच्चता विभाजित नहीं की जा सकती। जैसे यह कहना निरर्थक है कि आपा बर्गे, उगी तरह आपी सर्वोच्चता भी कोई चीज नहीं है। सर्वोच्चता अखण्ड होती है। यदि सर्वोच्चता को विभाजित कर दिया जाए तो राज्य के अनेक विभाग होंगे, उसमें उतने ही सर्वोच्च प्रभु या राज्य पैदा हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, जब भारत की सर्वोच्चता विभाजित की गई तब भारत और पाकिस्तान में दो सर्वोच्च राज्य पैदा हो गए। निस्सन्देह सर्वोच्चता की सन्धियों का प्रयोग एक से अधिक अंग द्वारा किया जा सकता है। किंगो सधान या फेडरेशन में सर्वोच्चता सन्धियों में रहती है पर इसका प्रयोग कुछ अंगों में केन्द्रीय सरकार के जरिये और कुछ अंगों में स्थान करने वाली इकाइयों के जरिये होता है।

सर्वोच्चता अमर्याद (inalienable) होती है—सर्वोच्चता राज्य का जीवन है। जैसे कोई आदमी अपना जीवन किसी दूसरे का नहीं दे सकता उसी प्रकार कोई राज्य अपनी सर्वोच्चता अस्थायी या स्थायी रूप से किसी दूसरे को नहीं दे सकता। राज्य सरकार को राज्य में प्रत्याखोजित प्राधिकार (delegated authority) प्राप्त होता है, पर राज्य का सर्वोच्च अधिकार हट नहीं जाता।

सर्वोच्चता स्थायी होती है—हम देख चुके हैं कि राज्य और सर्वोच्चता को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। राज्य की तरह सर्वोच्चता भी स्थायी है। सर्वोच्चता तब तक बनी रहती है, जब तक राज्य मौजूद है। सरकार में होने वाले परिवर्तनों से सर्वोच्चता पर बने ही कोई अमर नहीं पड़ता, जैसे राज्य पर।

सर्वोच्चता के प्रकार—सर्वोच्चता के प्रकारों की बात करना अवैज्ञानिक है। सर्वोच्चता जम्न (abstract) होती है। यह राज्य के सर्वोच्च प्राधिकार को दिया गया नाम है जो सब अलग एक सा होता है। राज्य में यह किस अंग है, इस बारे में बहिसर्ग पैदा होती है। इसलिए सर्वोच्चता के स्थान के बारे में कई विचार प्रचलित हैं।

तथ्य और विधि (De facto and De jure)—विधि सर्वोच्च प्रभु वह है जिसे कानून की दृष्टि में लोगो में आज्ञा पालन कराने का हक है पर अभी अभी यह होता है कि लोग बिना अथ प्राधिकारी की आज्ञा मानने लगे हैं। इसलिए तथ्य सर्वोच्च प्रभु वह है जो वास्तविक व्यवहार में बल द्वारा या सम्पत्ति द्वारा लोगों में आज्ञापालन करा ले। प्रायः विधि प्रभु तथ्य प्रभु भी होता है, यद्यपि उनका हमेशा ऐसा होना आवश्यक नहीं।

वैधि सर्वोच्चता (Legal sovereignty)—कानून बनाना या विधिनियम प्रभु का सबसे महत्वपूर्ण काम है। मैटेल के अनुसार 'विधि प्रभु वह प्राधिकारी है जो राज्य के सर्वोच्च समाधान को विधि के रूप में अभिव्यक्त

(५) राज्य मुख्यतः लोगों के राज-नीतिक जीवन में सम्बन्ध रखता है।

समाज के लिये लोगों के सब कार्य, चाहे वे राजनीतिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों, या सांस्कृतिक हों, बराबर महत्त्व के हैं।

(६) राज्य मनुष्य के अस्तित्व के लिये सर्वथा अनिवार्य नहीं है।

पर समाज के बिना मनुष्य का जीना कठिन हो जाएगा।

राज्य और साहचर्य — राज्य भी एक साहचर्य है। हर एक साहचर्य की तरह राज्य का भी एक सगठन, एक लक्ष्य या प्रयोजन होता है। अपने आकार, सदस्य संख्या और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से राज्य सबसे बड़ा और अधिक सर्वांगीण साहचर्य है। यह सबसे अधिक शक्तिशाली साहचर्य भी है। राज्य अपने क्षेत्र में अन्य सब साहचर्यों के कार्यों को अपनी हिदायत के अनुसार चलाता है और उन पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण राज्य को साहचर्यों का साहचर्य कहते हैं। राज्य और साहचर्य में बर्क बरने वाली मुख्य बातें ये हैं —

राज्य

(१) क्षेत्र राज्य का आवश्यक गुण है।

साहचर्य

साहचर्य के लिये क्षेत्र आवश्यक नहीं। क्षेत्र से युक्त साहचर्य सिर्फ राज्य है और किसी साहचर्य के पास क्षेत्र नहीं होता। असंलियत यह है कि किसी साहचर्य के सदस्य दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहते हो सकते हैं।

(२) एक आदमी एक समय में एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है।

एक आदमी एक ही समय में अपनी उन आवश्यकताओं के अनुसार, जिन्हें वह पूरा करना चाहता है, चाहे जितने साहचर्यों का सदस्य हो सकता है। साहचर्यों की सदस्यता स्वेच्छया होती है। आदमी जब चाहे तब साहचर्य का सदस्य बन सकता है और जब चाहे तब अपनी सदस्यता छोड़ सकता है।

(३) राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। मनुष्य अपने जन्म से राज्य का सदस्य होता है, अपने मृत्यु से नहीं। उसे इसके अधिकारियों का आदेश मानना पड़ता है, और वह जब चाहे तब इसकी सदस्यता से पृथक् नहीं हो सकता।

(४) राज्य सर्वोच्च है। इसके आदेशों का पालन करना होगा अन्यथा दंड मिलेगा। राज्य किसी व्यक्ति का जीवन भी ले सकता है।

साहचर्यों को कोई सर्वोच्च प्राधिकार नहीं होता। वे अपने आदेशों को मानने वाले सदस्यों को शारीरिक दण्ड नहीं दे सकते। वे, अधिक से अधिक, किसी सदस्य को अपनी सदस्यता से अलग कर सकते हैं।

(५) राज्य का क्षेत्र बड़ा विस्तृत और

हर एक साहचर्य का एक सास

स्थापक है और इसके भीतर इसके राज्य-क्षेत्र में विद्यमान अनेक साहचर्यों के लक्ष्य शामिल हैं।

(६) राज्य स्थायी साहचर्य है।

(९) राज्य परिवार की तरह एक नैसर्गिक साहचर्य है।

राज्य और सरकार—राज्य और सरकार को प्रायः एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में वे एक दूसरे में बहुत भिन्न अवधारण हैं। इन दोनों में फर्क तब तक नहीं है जब तक कि राष्ट्रीय शासन की कुछ बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में बड़ा आम धारणा होने की संभावना है। सरकार राज्य के चार घटक तत्वों में से सिर्फ एक है। जैसे किसी कंपनी का मन्बालव महत्व ही कंपनी नहीं होता, वैसे ही सरकार राज्य नहीं हो सकती। यह तो राज्य की एक एजेंट मात्र है। इन दोनों में मुख्य भेद ये है —

राज्य

(१) राज्य अमूर्त है। हम इसे देख या छू नहीं सकते। हम राज्य का सिर्फ एक विचार बना सकते हैं।

१ १ १

(२) राज्य में सर्वोच्चता होती है और इसका प्राधिकार इसका अपना है। वह और किसी में पैदा नहीं होता।

(३) राज्य स्थायी होता है। सरकार का परिवर्तन होने पर भी यह बना रहता है।

(४) राज्य के किसी निश्चित क्षेत्र के लिये लोग इसके सदस्य होते हैं। हम सब भारत राज्य के सदस्य हैं।

लक्ष्य या उद्देश्य होता है।

राज्य और परिवार को छोड़कर और कोई साहचर्य स्थायी नहीं। अन्य साहचर्य अपने उद्देश्य पूरे होने ही भंग हो जाते हैं।

राज्य और परिवार को छोड़कर और सब साहचर्य कृत्रिम हैं। वे किसी काम उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं।

सरकार

दूसरी ओर, सरकार एक मूर्त वस्तु है। हम राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, अन्य मंत्रियों, मन्बाल और नई दिल्ली के मन्बि-वालय के रूप में भारत सरकार को देख सकते हैं।

सरकार सर्वोच्च नहीं होती। इसका प्राधिकार अपना नहीं है। वह राज्य में पैदा होता है। राज्य जब चाहे तब सरकार के प्राधिकार को बड़ा, घटा, या छोटा सकता है।

सरकारें अस्थायी और छोटे दिन की होती हैं। हम देखते हैं कि देश में आम चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। एक राजा की मृत्यु और दूसरे के गद्दी पर बैठने से सिर्फ सरकार में परिवर्तन होता है।

सब लोग सरकार के सदस्य नहीं होते। बहुत छोटे में लोग सरकार गठित करते हैं।

(५) हम अपने राज्य को कभी नष्ट नहीं करना चाहते। हम सब भारत राज्य के प्रति निष्ठा रमते हैं। पर हम एक सरकार की जगह दूसरी सरकार लाने की बात गभीरता से सोचते हो मक्ते हैं। हमारा सबका सरकार के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक नहीं।

राज्य, राष्ट्र और जाति (State, nation and people) — राज्य में राष्ट्र और जाति से भी अंतर करना चाहिए। राज्य एक राजनैतिक अवधारण है। इसलिए यह मनुष्य जाति के एक अंश की राजनैतिक एकता या समूह को ही मुख्यतः सूचित करता है। दूसरी ओर जाति और राष्ट्र जैसे अवधारणा से जो एकता सूचित होती है, वह अति गहरी है। जाति अधिकतर एक मूलवर्गीय (racial or ethnic) अवधारणा है। राष्ट्र राज्य तथा राष्ट्रियता (nationality) का समूह है। राष्ट्रियता मूलवर्गीय सम्बन्ध के अलावा और बहुत सारे सम्बन्ध सूचित करती है।

सारांश

"राज्य उन व्यक्तियों का एक समुदाय है जिसकी सहायता नहीं मग और नहीं अधिक होती है और जो किसी निश्चित राज्यक्षेत्र पर स्थायी रूप से रहते हैं—यह समुदाय बाह्य नियंत्रण से स्वतन्त्र या लगभग स्वतन्त्र होता है और इसमें एक संगठित सरकार होती है जिसकी आज्ञाओं का अधिकतर नागरिक पालन करते हैं"—गार्नर। इस प्रकार राज्य के ये चार आवश्यक तत्व हैं (१) आबादी, (२) राज्य क्षेत्र, (३) सरकार (४) सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता।

इन सब तत्वों में से सर्वोच्चता सब से अधिक आवश्यक और विभेदकारी तत्व है।

सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता—आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्चता राज्य के सर्वोच्च प्राधिकार का नाम है जो उसे अपने क्षेत्र में रहने वाले सब व्यक्तियों और समुदायों पर प्राप्त होता है। बाहरी दृष्टि में सर्वोच्चता राज्य की किसी अन्य बाहरी शक्ति के नियंत्रण से स्वतन्त्रता को ध्वजित करती है।

सर्वोच्चता निरपेक्ष (absolute) असीमित, सार्वभौमिक, अविभाज्य अमर्याद और स्थायी होती है।

सर्वोच्चता के प्रकार—सर्वोच्चता के प्रकारों की बात करना अर्थशास्त्रिक है। शास्त्र में के सर्वोच्चता के स्थान के बारे में दृष्टिकोण है।

- (१) संप्रत्य—जो संप्रत्य सर्वोच्च प्राधिकार रखता है।
- (२) विधित—जिसे विधि द्वारा सर्वोच्च शक्ति का अधिकार प्राप्त है।
- (३) विधिगत सर्वोच्चता—राज्य में विधि बनाने का प्राधिकार।
- (४) राजनैतिक सर्वोच्चता—इसमें उन विभिन्न प्रभावा का समावेश है जो विधिगत प्रभु के पीछे नाम करते हैं।

(५) जनता की सर्वोच्चता—सर्वोच्च प्राधिकार जनता को होता है।

राज्य और समाज—(१) राज्य क्षेत्र और सर्वोच्चता राज्य के होते हैं, समाज के नहीं। (२) राज्य का संगठन होता है, और समाज में अंगगठित समूह भी समाविष्ट हैं। (३) राज्य दण्ड दे सकता है पर समाज ऐसा नहीं कर सकता। (४) राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, समाज की नहीं। (५) राज्य मनुष्य के जीवन के लिए परमावश्यक नहीं, पर समाज के बिना मनुष्य का जीवन कठिन हो जाता है।

राज्य और साहचर्य—(१) क्षेत्र और सर्वोच्चता राज्य की विशेषताएँ हैं, साहचर्य की नहीं, (२) एक आदर्श अनेक साहचर्यों का सदस्य हो सकता है, पर अनेक राज्यों का नहीं हो सकता। (३) राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, साहचर्य की नहीं। (४) राज्य का क्षेत्र साहचर्य के क्षेत्र की अपेक्षा बहुत विस्तृत है। राज्य के अन्दर हजारों साहचर्य समाविष्ट हैं। (५) राज्य स्थायी होता है और साहचर्य प्रायः अस्थायी होता है।

राज्य और सरकार—(१) राज्य अमूर्त होता है, सरकार मूर्त होती है। (२) राज्य सर्वोच्चता धारण करता है और उसकी मता मौज्जि होती है। सरकार सर्वोच्च नहीं होती और इसका प्राधिकार लिमा हुआ होता है। (३) राज्य स्थायी होता है, सरकारें बदलती रहती हैं। जब लोग राज्य में सदस्य होते हैं, सरकार के नहीं। (४) हम सब राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, सरकार के प्रति नहीं।

प्रश्न

QUESTIONS

१. राज्य की परिभाषा करो। इसके जीवन-जीवन से गुण हैं ?

(५० वि० अंश, १९४८)

1. Define 'state'? What are its attributes? (P. U. April, 1948)

या

सावधानी से राज्य के सारकून गुणों का वर्णन करो।

(५० वि० अंश, १९५०)

Describe carefully the essential attributes of the state.

(P. U. April, 1950)

२. राज्य का क्या अर्थ है ? राज्य और सरकार में अंतर करो ?

(५० वि० अंश, १९५०)

2. What is meant by the state? Distinguish between state and government (P. U. April, 1950)

३. समाज, राज्य और सरकार में अंतर करो।

(५० वि० अंश, १९५१ व अंश, १९५२)

3. Distinguish between society, state and government.

(P. U. Sep. 1951, and Apr., 1950)

- ४ राज्य और साहचर्य की परिभाषा करो । इन दोनों का अंतर बतलाओ ।
(प० वि० अप्रैल, १९५४)
- 4 Define the state and an association Distinguish between them
(P U April 1954)
- ५ 'सर्वोच्चता' शब्द से आप क्या समझते हैं । इसके आवश्यक लक्षण क्या हैं ?
(प० वि० अप्रैल, १९५३)
- 5 What do you understand by the term Sovereignty ? What are its essential characteristics ?
(P U April 1953)
६. सर्वोच्चता के कौन से अनेक प्रकार हैं ?
- 6 What are the various kinds of sovereignty ?

राज्य का उद्गम और भ्रूति

(Origin and Nature of the State)

राज्य का उद्गम—राज्य समाज में से उत्पन्न और विकसित हुआ है। इसका उद्गम प्रागैतिहासिक काल में है। इसी कारण यह अनिश्चित है। इस बात का कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य कैसे और कब आरम्भ हुआ। इसी कारण विद्वानों में राज्य के उद्गम के बारे में बड़ा मतभेद है। इस प्रसंग में हम पाँच महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर शोध में विचार करेंगे।

- (१) दैवगम सिद्धान्त (Theory of Divine Origin)।
- (२) समाज सन्धि सिद्धान्त (Social Contract Theory)
- (३) बल सिद्धान्त (Force Theory)
- (४) वैज्ञानिक और मानव सिद्धान्त
- (५) ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धान्त।

दैवगम सिद्धांत—राज्य के उद्गम के बारे में पुराना विचार यह है कि यह ईश्वर की वृत्ति है। ईश्वर ने केवल राज्य का सूत्रन करता है, बल्कि किसी अभि-कर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस पर शासन भी करता है। राजा ईश्वर के स्थानापन्न के रूप में राज्य पर शासन करता है। यह सिद्धान्त सब धर्मों की धार्मिक पुस्तकों में पाया जाता है और मोहूर्वा मदी तक यह आम तौर पर माना जाता था, पर आज की दुनिया में यह नहीं माना जाता। इसके न माने जाने के ये अनेक कारण हैं—

(१) राजाओं के दैवी अधिकार का सिद्धान्त इसी सिद्धान्त से पैदा हुआ था। इस सिद्धान्त के अनुसार राजा अपने आपकी सिर्फ ईश्वर के सामने जवाबदेह बनाता था, जनता के सामने नहीं। इस तरह के विचार ने उसे बिल्कुल निरंकुश बना दिया और उसके गद्दत नामों के विषे उसमें पूछनाछ करने का जनता के पास कोई अधिकार नहीं छोड़ा। इसलिए जनता की ओर से राजाओं के दैवी सिद्धान्त के अधिकार का मुकाबिला करने के विषे समाज सन्धि सिद्धान्त रखा गया। इस सिद्धान्त के अनुसार, राजा अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है, और राज्य शासक अ.र. शासित के बीच सन्धि हाने से उत्पन्न हुआ है। समाज सन्धि सिद्धान्त बड़ा तर्कपूर्ण था, और इसने सीधे ही दैवगम सिद्धान्त को मैदान से हटा दिया।

(२) दैवगम सिद्धान्त तब तक चला रहा जब तक धर्म में अंधविश्वास मनुष्य समाज में जमा हुआ था। जब धर्म के सिद्धान्तों की समीक्षा होने लगी, तब यह

क्षत्रम हो गया। यह शासक अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। इसलिए कोई आदमी तर्क-संगत रूप से यह नहीं मीच सकता था कि ईश्वर लोगों पर बुरे राजा से शासन कराने की इच्छा रख सकता है। इसलिए राज्य ईश्वरजनित नहीं हो सकता।

तो भी देवागम मिथ्या ने गुरु के समय में अधिवारियों ने प्रति सम्मान पैदा किया।

समाज सविदा सिद्धान्त—यह सिद्धान्त सविदा द्वारा राज्य का उद्गम बताना है। समाज सविदा के पक्षपाती प्रमुख लेखक तीन हैं, अर्थात् हॉब्स, लॉक और रूसो। ये सब अपने सिद्धान्त की नैसर्गिक अवस्था (state of nature) से शुरु करते हैं। नैसर्गिक अवस्था में उनका मतलब उस दशा से है जिसमें मनुष्य समाज और राज्य के बनने से पहले रहते थे। इन लेखकों के अनुसार लोगों ने आपस में सविदा या समझौता करके समाज और राज्य का निर्माण किया।

हॉब्स का सिद्धान्त—हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अराजकता की थी। इसमें हर आदमी अलग रहता था, बड़ी स्वार्थबुद्धि से काम करना था और दूसरे के मुल की परवाह न करके अपने लिये अधिवनम मुख हासिल करने की कोशिश करता था, ऐसी अवस्था में किसी का जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं हो सकती थी और हर आदमी दूसरे में डरता और उस पर मदेह करता था। इस अवस्था को देखकर ही लोगों ने आपस में सविदा करने का करार किया। इस सविदा द्वारा हॉब्स के अनुसार लोगों ने अपनी सत्ता एक तीसरे व्यक्ति को सौंप दी, जो शासक या प्रभु कहलाया, पर प्रभु स्वयं इन सविदा में शामिल नहीं था। इसके बाद सविदा द्वारा लोग वानूनन और नैतिक दृष्टि से प्रभु द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करने के लिए बंध गए। उन्हें प्रभु द्वारा दी गई आजादी और अधिकारों के अलावा और कोई आजादी और अधिकार नहीं रहे। इस प्रकार हॉब्स ने परम शक्तिवाद (Absolutism) को अनुचित ठहराने के लिये सविदा सिद्धान्त का प्रयोग किया।

पर हॉब्स समाज सविदा सिद्धान्त का प्राकृतिक लेखक नहीं है। यद्यपि सामाजिक-सविदा सिद्धान्त में दो सविदाएँ होनी आवश्यक हैं। एक समाज के निर्माण के लिये जो सामाजिक सविदा कहलाएगी और दूसरी सरकार स्थापित करने के लिये जो सरकार सम्बन्धी सविदा कहलाएगी। परा भी सामाजिक सविदा सिद्धान्त का वास्तविक प्रयोजन राजाओं के देवी अधिकार या निरंकुशता का मुकाबिला करना था। इस सिद्धान्त के द्वारा व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार, जो वह नैसर्गिक अवस्था से लाया था, समाज और राज्य की सत्ता पर सदा एक रोक बने रहते थे।

लॉक का सिद्धान्त—लॉक समाज सविदा सिद्धान्त का एक प्राकृतिक लेखक है। उपर्युक्त सब विचार उसके सिद्धान्त में आ जाते हैं। वह हॉब्स के प्रतिकूल बातें मानता है। उसने विराम के अनुसार, नैसर्गिक अवस्था शान्तिपूर्ण थी जिसमें सब व्यक्ति एक दूसरे में तर्कसंगत रीति से व्यवहार करते थे। दो भी लॉक का यह विश्वास था कि सम्पत्ति का विचार आ जाने पर लोगों ने समझना शुरु कर दिया। उन्हें नैसर्गिक अवस्था

के स्थान पर सविदा द्वारा एक जनपद समाज (Civil society) स्थापित करने पडी । लोक के अनुसार समाज सविदा द्वारा आदमी ने अपना मिर्क एक अधिकार समाज को दिया, अर्थात् अन्य आदमियों के साथ उगता सम्बन्ध रख करने का अधिकार । शेष अधिकार, जैसे जीवन, स्वतन्त्रता, और सम्पत्ति का अधिकार, जिन्हे लोक नैसर्गिक अधिकार कहता है, व्यक्ति ने अपने पास रखे । समाज उसे इन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता था । बाद में समाज ने उन्हीं शर्तों पर सरकार सम्बन्धी सविदा द्वारा एक सरकार या शासन स्थापित किया । लोक के अनुसार शासन ने तब तक सत्ताग्रह रहना था जब तक वह लोगों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे और जनता के हित की दृष्टि में शासन करे । यदि यह संघा नहीं करता तो जनता को शक्ति द्वारा उसे बदल देने का और उसके स्थान पर दूसरा शासन बना देने का अधिकार था ।

रुमो का सिद्धान्त—रुमो की नैसर्गिक अवस्था लोक की अवस्था में भी अधिक आनन्दमय है । पर लोक के अननुभव, वह मिर्क एक सविदा का उल्लेख करता है, जिसमें सब लोग मिलकर अपने सब प्राधिकार एक साधारण इच्छा (General will) को सौंप देते हैं । और प्रत्येक आदमी इस इच्छा का एक भाग बन जाता है । इस प्रकार रुमो के अनुसार प्राधिकार किसी एक आदमी को नहीं सौंपा जाता, जैसा कि हॉब्स की सामाजिक सविदा में होता था, बल्कि सब लोगों को मिलाकर सौंपा जाता है । रुमो का साधारण इच्छा का सिद्धान्त बाद में जनता की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का आधार बन गया । यद्यपि रुमो नैसर्गिक अधिकारों में विचार नहीं करता था, तो भी वह सम्पत्ति द्वारा शासन का पक्ष समर्थक था । वह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का हामी है जिसमें सब आदमी गना में बैठेंगे और कानून बनायेंगे ।

समाज सविदा सिद्धान्त की आलोचना—इस सिद्धान्त पर मुख्य आपत्तियाँ ये हैं —

(१) समाज सविदा का मतलब यह हो जाना है कि लोगों ने विचार-विमर्श करके राज्य बनाया । तथ्य यह है कि ऐसी कोसिस का राज्य के विचार में बहुत छोटा हाव रहा है । मुख्यतः राज्य समाज में से स्वभाविक रीति से बिना जानबूझकर कोसिस किये पैदा हुआ है ।

(२) समाज सविदा इतिहास में सात नहीं है । इतिहास में सरकार सम्बन्धी सविदा के उदाहरण तो मिलते हैं, पर सविदा द्वारा समाज पैदा होने का कोई उदाहरण नहीं मिलता ।

(३) यह विचार भी इतिहासमग्न नहीं है कि आदमी नैसर्गिक अवस्था में अलग-अलग जीवन बिताते थे । आदमी सभी इस तरह नहीं रहता था । बहुत आदिवासी लोग का अध्ययन करने से भी हमें यही पता चला है कि मनुष्य सदा समूहों में रहता रहा है ।

(४) शान्ति दृष्टि से सविदा सिर्फ सविदाकारी पक्षों पर ही बचनकारी होती

चाहिए । समाज सविदा के पक्षपाती लेखक यह कैसे मान लेंगे हैं कि जिन्होंने शुरु में सविदा की थी, उनके बेटों-पोतों पर भी वह बधनकारी होगी ।

(५) यह कहकर कि समाज सविदा के अधीन लोग अपना शासन बदल सकते हैं, यह सिद्धान्त प्राधिकार की इज्जत न बरने की सलाह देता है । यह लोगों को सुच्छ बाती पर विद्रोह बर देने के लिये बड़ावा देता है ।

(६) इस सिद्धान्त में अधिकारों के बारे में गलत विचार पैदा होगा है । नैतिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं होती । आदमी को समाज और राज्य पर कोई अधिकार नहीं मिल सकता ।

इस सिद्धान्त की कुछ अच्छाइयाँ भाँ हैं —

(१) यह राज्य के उद्गम के बारे में अधिक अच्छी व्याख्या पेश करता है । इसके अनुसार राज्य मनुष्य का बनाया हुआ है, ईश्वर का नहीं ।

(२) इस सिद्धान्त में सम्मति द्वारा शासन का जो उमूल है, यह आपुनिक लोकतन्त्र का आधार बना है ।

(३) इस सिद्धान्त ने सबसे पहले ठीक तरह से व्यष्टि का महत्व बनाया ।

बल का सिद्धान्त—यह सिद्धान्त यह कहता है कि राज्य बल द्वारा पैदा होता है और बल द्वारा ही यह कायम रखा जाता है । इसके समर्थक कहते हैं कि आदमी स्वभाव से झगडालू है । उसमें ताकत की चाह भी है । इसलिए समाज के शुरु के दिनों में आदमी आदमी के अधिकार ताकतवर था, उसने अपने पड़ोस के कमजोर लोगों पर अधिकार कर लिया होगा और उन्हें गुलाम बना लिया होगा । धीरे धीरे हमने बल के जोर से अपने साथियों की सख्या बढ़ा ली और वह कबीले का सरदार बन गया । जब एक कबीले ने अपने सरदार के नेतृत्व में बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण बर लिया और वह उस पर स्थायी रूप से रहने लगा, तब राज्य का जन्म हुआ ।

इसके अलावा, बल के सिद्धान्त के पक्षपातियों का यह भी कहना है कि बल सिर्फ राज्य के मुज्तम के लिये आवश्यक नहीं, बल्कि इसे कायम रखने के लिये भी लाजमी है । आदमी के स्वभाव से झगडालू होने के कारण, राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था तथा बाहरी आक्रमणों से बचाव बल द्वारा ही किया जा सकता है ।

बल के सिद्धान्त की आलोचना—यह सिद्धान्त राज्य के उद्गम की पूरी व्याख्या नहीं करता । इसका यह कहना भी गलत है कि राज्य के पैदा करने और कायम रखने में बल ही एकमात्र कारण है । हम मानते हैं कि राज्य के उद्गम और विकास में बल ने महत्वपूर्ण कार्य किया है । हम यह भी मानते हैं कि राज्य को बनाये रखने के लिए बल आवश्यक है । राज्य के भीतर राज्य को इस वास्ते बल की आवश्यकता है जिससे लोग इसके कानूनों का पालन करें । बाहरी दृष्टि में किसी विदेशी शक्ति के आक्रमण को विफल करने के लिए बल आवश्यक है । पर हमें यह याद रखना चाहिए कि राज्य के उद्गम और उसके नपारण, दोनों, में बल सिर्फ एक कारण रहा है । यह न

के स्थान पर सविदा द्वारा एक जानपद समाज (Civil society) स्थापित करनी पड़ी । लोक के अनुसार समाज सविदा द्वारा आदमी ने अपना सिर्फ एक अधिकार समाज को दिया, अर्थात् अन्य आदमियों के साथ उसका सम्बन्ध तब करने का अधिकार । शेष अधिकार, जैसे जीवन, स्वतन्त्रता, और सम्पत्ति का अधिकार, जिन्हें लोक नैसर्गिक अधिकार कहता है, व्यक्ति ने अपने पास रखे । समाज उसे इन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता था । बाद में समाज ने उन्हीं शर्तों पर सरकार सम्बन्धी सविदा द्वारा एक सरकार या शासन स्थापित किया । लोक के अनुसार शासन ने तब तक सत्तास्थ रहना था जब तक वह लोगों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे और जनता के हित की दृष्टि से शासन करे । यदि वह ऐसा नहीं करता तो जनता को शान्ति द्वारा उसे बदल देने का और उसके स्थान पर दूसरा शासन बना देने का अधिकार था ।

रूमो का सिद्धान्त—रूमो की नैसर्गिक अवस्था लोक की अवस्था से भी अधिक आनन्दमय है । पर लोक के अमर्त्य, वह सिर्फ एक सविदा का उल्लेख करता है, जिसमें सब लोग मिलकर अपने सब प्राधिकार एक साधारण इच्छा (General will) को सौंप देते हैं । और प्रत्येक आदमी इस इच्छा का एक भाग बन जाता है । इस प्रकार रूमो के अनुसार प्राधिकार किसी एक आदमी को नहीं सौंपा जाता, जैसा कि हाब्स की सामाजिक सविदा में होता था, बल्कि सब लोगों को मिलाकर सौंपा जाता है । रूमो का साधारण इच्छा का सिद्धान्त बाद में जनता की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का आधार बन गया । यद्यपि रूमो नैसर्गिक अधिकारों में विश्वास नहीं करता था, तो भी वह सम्पत्ति द्वारा शासन का पक्का समर्थक था । वह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का हामी है जिसमें सब आदमी समान में बैठेंगे और कानून बनायेंगे ।

समाज सविदा सिद्धान्त की आलोचना—दूसरे सिद्धान्त पर मुख्य आश्रयिया ये हैं —

(१) समाज सविदा का मतलब यह हो जाता है कि लोगों ने विचार-विमर्श करके राज्य बनाया । तथ्य यह है कि रोमी रोमिश का राज्य के विकास में बहुत झोडा हाक रहा है । मुख्यतः राज्य समाज में से स्वाभाविक रीति से बिना जानबूझकर रोमिश रिये पैदा हुआ है ।

(२) समाज सविदा इतिहास से सगत नहीं है । इतिहास में सरकार सम्बन्धी सविदा के उदाहरण तो मिलते हैं, पर सविदा द्वारा समाज पैदा होने का कोई उदाहरण नहीं मिलता ।

(३) यह विचार भी इतिहासमगत नहीं है कि आदमी नैसर्गिक अवस्था में खलम-अज्ञ जीवन बिताने से । आदमी कभी इस तरह नहीं रहता था । बहुत आदिवासी लोग लोग का अध्ययन करने से भी हमें यही पता चलता है कि मनुष्य मनुष्य समूहों में रहता रहा है ।

(४) कानूनी दृष्टि से सविदा सिर्फ सविदाकारी पक्षों पर ही बंधनकारी होती

चाहिए । समाज सविदा के पक्षपाती लेखक यह कर्ने मान लेने हैं कि जिन्होंने शुरू में सविदा की थी, उनके बेटे-पोते पर भी वह बधनकारी होगी ।

(५) यह कहकर कि समाज सविदा के अधीन लोग अपना सामन बदल सकते हैं, यह सिद्धान्त प्राधिकार की इज्जत न बनने की सलाह देता है । यह लोगों की कुछ बातों पर विश्रोह कर देने के लिये बहावा देता है ।

(६) इस सिद्धान्त में अधिकारों के बारे में गलत विचार पैदा होता है । नैसर्गिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं होती । आदमी को समाज और राज्य पर कोई अधिकार नहीं मिल सकता ।

इस सिद्धान्त की कुछ अच्छाइया भी हैं —

(१) यह राज्य के उद्गम के बारे में अधिक अच्छी व्याख्या पेश करता है । इसके अनुसार राज्य मनुष्य का बनाया हुआ है, ईश्वर का नहीं ।

(२) इस सिद्धान्त में सम्मति द्वारा शासन का जो उमूल है, वह आधुनिक लोकतन्त्र का आधार बना है ।

(३) इस सिद्धान्त में सबसे पहले ठीक तरह से ब्यक्ति का महत्व बताया ।

बल का सिद्धान्त—यह सिद्धान्त यह कहता है कि राज्य बल द्वारा पैदा होता है और बल द्वारा ही यह कायम रखा जाता है । इसके समर्थक कहते हैं कि आदमी स्वभाव से झगडालू है । उसमें ताकत की चाह भी है । इसलिए समाज के शुरू के दिनों में जो आदमी औरों में अधिक ताकतवर था, उसने अपने पड़ोस के कमजोर लोगों पर अधिकार कर लिया होगा और उन्हें गुलाम बना लिया होगा । धीरे-धीरे इसने बल के जोर में अपने साथियों की सख्या बढ़ा ली और वह कबीले का सरदार बन गया । जब एक कबीले ने अपने सरदार के नेतृत्व में बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया और वह उस पर स्यापी रूप से रहने लगा, तब राज्य का जन्म हुआ ।

इसके अलावा, बल के सिद्धान्त के पक्षपातियों का यह भी कहना है कि बल सिर्फ राज्य के सुजन के लिये आवश्यक नहीं, बल्कि इसे कायम रखने के लिये भी लाजमी है । आदमी के स्वभाव में झगडालू होने के कारण, राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था तथा बाहरी आक्रमणों से बचाव बल द्वारा ही किया जा सकता है ।

बल के सिद्धान्त की आलोचना—यह सिद्धान्त राज्य के उद्गम की पूरी व्याख्या नहीं करता । इसका यह कहना भी गलत है कि राज्य के पैदा करने और कायम रखने में बल ही एकमात्र कारण है । हम मानते हैं कि राज्य के उद्गम और विकास में बल ने महत्वपूर्ण कार्य किया है । हम यह भी मानते हैं कि राज्य को कायम रखने के लिए बल आवश्यक है । राज्य के भीतर राज्य को इन वास्तविक बल की आवश्यकता है जिससे लोग इसके कानूनों का पालन करें । बाहरी दृष्टि से किसी विदेशी शक्ति के आक्रमण को विफल करने के लिए बल आवश्यक है । पर हमें यह याद रखना चाहिए कि राज्य के उद्गम और उसके सधारण, दोनों, में बल सिर्फ एक कारक रहा है । यह न

हो एक मान बाराक रहा हूँ, और न सबसे महत्वपूर्ण बाराक। राज्य का आधार बल नहीं है। लोगों को एक सत्ता के अधीन रखने के लिए कोई और ही चीज आवश्यक है। लोगों को डम मना की जायोगिता का विस्वास करना होगा और उनका विश्वास जीना होगा। इसलिए राज्य का वास्तविक आधार 'इच्छा' (will) है, बल नहीं। निरा बल विनी चीज को मिलाकर नहीं रख सकता। निरे बल में हम विनी जानवर को भी अपने बाबू में नहीं रख सकते। हमें माय-माय उनका प्रेम में प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार, राज्य सभी म्यापी हो सकता है, जब लोग स्वेच्छा से उसकी आज्ञा का पालन करें। बल पर आधारित राज्य अधिक दिन नहीं टिक सकता।

पंक्त और मानक सिद्धान्त—दोन सिद्धान्तों में से एक को भी राज्य के उद्गम के बारे में सही तौर से कोई सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता। वे अलग में राजनीतिक सिद्धान्त होने के बजाए समाज शास्त्रीय सिद्धान्त हैं, जो मानव समाज के आरम्भ और इसके परिवर्तन के प्रक्रम की व्याख्या करने का बल करने हैं। उन सिद्धान्तों का मूल दृष्ट प्रश्न है कि पहले पंक्त परिवार हुआ, या मानक। इस प्रकार के राज्य के उद्गम की उनकी व्याख्या नहीं करते, बिलनी परिवार के उद्गम की। हम यह भी निश्चित रूप से जानते हैं कि राज्य परिवार में से विकसित नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों अपनी प्रकृति, मगडन, बायीं और लक्ष्यों में एक दूसरे से भिन्न हैं।

ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धान्त—यह सिद्धान्त राज्य के उद्गम की मयने अच्छी और गबछे सही म्याख्या करना हैं। इसके अनुसार राज्य की बह इतिहास में है, और वह क्रमिक और अदृश्य रीति से समाज में से विकसित हुआ है। इस रूप में हम यह टीक-टीक नहीं यह सकते कि समाज कब राजनीतिक रूप से मगडित हुआ या राज्य का जन्म कब हुआ। यह बात भी नहीं है कि राज्य सब जगह एक साथ प्रादुर्भूत हुआ है। पानिस्तान के उत्तर-पश्चिम के पठान कबायली क्षेत्रों में राज्य का विकास अब तक नहीं हुआ।

समाज से राज्य का विकास होने में निम्नलिखित बाबें मूलभूत रही होंगी -

- १ रक्त सम्बन्ध।
- २ धर्म।
- ३ राजनीतिक चेतना।

रक्त सम्बन्ध—रक्त सम्बन्ध एकरत का पहला बन्धन रहा होगा। गर परिवार पहला सामाजिक समूह रहा होगा। परिवार में रक्त सम्बन्ध के कारण पिता की आज्ञा का परिवार के अन्य सदस्य पालन करते होंगे। जब परिवार गोत्रों के रूप में जा गये और गोत्र बढकर कबीलों के रूप में हो गये, तब भी रक्त सम्बन्ध बना रहा, यद्यपि यह बहुत कमजोर होता गया। सब लोग सबसे बड़े जीवित पुरुष सदस्य की आज्ञा का पालन करने से। इस प्रकार गुरु के समाजों में रक्त-सम्बन्ध ने प्राधिकार की वृद्धि में बहुत कुछ सहायता की और यह प्राधिकार ही राज्य का आधार है।

धर्म—धर्म ने इन प्राधिकार का बल और बढ़ाया। आरम्भिक अवस्था में मृत पूर्वजों की पूजा अप्रत्यक्ष रूप में सबसे बड़े जीवित पुरुष सदस्य के प्राधिकार को साबित देती थी। बाद में, जब प्रकृति के देवताओं की पूजा होने लगी, तब कबीले का नेता सारे कबीले के निमित्त उन्हें भेंट चढ़ाता था। स्वभावतः कबीले के अन्य लोग उनके देवताओं का प्यारा समझने लगे और उसकी आज्ञा भग करने से डरने लगे। इस प्रकार धर्म शासक के प्राधिकार को बलवान बनाने में और लोगो को बान्धन पालक बनाने में बड़ा महायन्त्र हुआ।

राजनैतिक चेतना—राजनैतिक चेतना आदिम जीवन की बढ़ासारी में पैदा हुई थी। आदिम दृष्टि से समाज तिकार, पशुपालन, और खेती की अवस्थाओं में मनुजों का जीवन किताने में। पर मृत्ति ने उन्हें एक निश्चित क्षेत्र में बसने को मजबूर कर दिया। इसी तरह समाज के विकास की प्रत्येक अवस्था में निजी सम्पत्ति बढ गई, और कबीलों में युद्ध अधिक होने लगे। युद्ध ने राजनैतिक चेतना पैदा की और कबीले एक दूसरे के हमला से जीवन और सम्पत्ति की रक्षा की आवश्यकता अनुभव करने लगे। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि रक्त सम्बन्ध की दृष्टि से जो सदस्य सबसे बड़ा है, वह युद्ध में उनका नेतृत्व नहीं कर सकता। परिणामतः, हर कबीले ने ऐसी आदमी को अपना युद्ध नेता बना लिया, जिसमें युद्ध सम्बन्धी गुण सबसे अधिक थे। धीरे-धीरे युद्ध-नेता की प्रतिष्ठा और महत्त्व बढ़ते गये और वह राजा कहलाने लगा। उसका प्राधिकार एक विवेक क्षेत्र के सब लोगों पर होता था और उसका विभी रक्त विरोध के लोगों में कोई सम्बन्ध नहीं था। जब समाज के विकास में ऐसी अवस्था आ गई तब राज्य का जन्म हुआ।

राज्य की प्रकृति

हम देख चुके हैं कि मनुष्य स्वभाव में सामाजिक प्राणी है। आज के समाज में जो अनेक सभ और संस्थाएँ हैं, वे मनुष्य के इसी सामाजिक स्वभाव का परिणाम हैं। इसलिये राज्य भी, जो एक सभ या साहचर्य ही है, स्वाभाविक है, पर एक बात याद रखनी चाहिए। अनेक साहचर्यों और संस्थाओं का विराग पूरी तरह स्वाभाविक मार्ग से नहीं होता। मनुष्य द्वारा जान-बूझ कर किया गया प्रयास भी इसके रूप को बनाने में बहुत हिस्सा लेता है। इसलिये राज्य को अलग स्वाभाविक और अलग सभैत प्रयत्न का परिणाम कहा जा सकता है। स्वाभाविक प्रकृति और सभैत प्रयत्न राज्य के निर्माण में ऐसी मूढमत्ता से मिल गये हैं कि लोगों में राज्य की प्रकृति के बारे में अलग-अलग विचार पैदा हो गये हैं।

कुछ लोगों की दृष्टि में राज्य विलुप्त बनाई हुई चीज है और इसमें जो एवता है वह सविदा आदि कृत्रिम साधनों का परिणाम है। कुछ लोग राज्य को एक जीवविण्ड (Organism) समझते हैं और इसकी एकता को वैसी ही एवता समझते हैं जैसे किसी जीवविण्ड के अनेक भागों में होती है। अब हम राज्य की प्रकृति के बारे में इन दोनों दृष्टिकोणों पर सशेष में विचार करेंगे।

सविदा सिद्धान्त—इस सिद्धान्त पर राज्य के उदगम के मिलसिले में भी विचार कर चुके हैं। राज्य की प्रवृत्ति के बारे में भी यह एक सिद्धान्त है। इसके अनुसार, समाज और राज्य सविदा या आपसी और स्वेच्छा विधे गये कसर का परिणाम है। इन सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि राज्य की आधारभूत एकता बनाई हुई एकता है, स्वाभाविक नहीं। यह सिद्धान्त राज्य की सत्तापजनक व्याख्या नहीं करता। यह राज्य के निर्माण में मनुष्यों के गोचे-विचारे और जानबूझकर किये गये प्रयास पर अनुचित बल देता है। यह मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति की उपेक्षा करता है जो राज्य में अधीन लोगों को इकट्ठा करने में मूल प्रेरक है।

जीवविशेष सिद्धान्त (Organismic Theory)—इस सिद्धान्त के लेखक राज्य की प्रवृत्ति की व्याख्या किसी जीवविशेष से इसकी तुलना द्वारा करते हैं। हर्बर्ट स्पेन्सर तो राज्य और मानव शरीर को विच्छिन्न एक ही बताता है। उसके अनुसार ये दोनों अपनी बुद्धि, संरचना और कार्यों में एक जैसे होते हैं। राज्य का मूल रूप में मकुल रूप में विकसित होना किसी जीवविशेष की एक-कोशिकीय पिण्ड से बहुकोशिकीय पिण्ड के रूप में बुद्धि में निम्नता-उत्पत्ता है। राज्य के विभिन्न अंगों का सहयोग वैसे ही है जैसे मानव शरीर के विभिन्न भागों का अपने कार्य करने हुए आपसी सहयोग। राज्य और मानव शरीर की संरचना के विषय में स्पेन्सर ने निम्नलिखित समानताएँ प्रस्तुत की हैं :

१ राज्य के लिए सरकार उसी रूप में है जिस रूप में मानव शरीर के लिए मस्तिष्क है।

२ रेल, सड़क और तार राज्य के लिए वैसे ही हैं जैसे शरीर के लिए घमनिया और शिराएँ।

३ पेट और आँत्र शरीर को पोषण देती हैं—मैनुफ़ैक्चरिंग और इति कार्य राज्य को जीवित रखते हैं।

जैसा कि स्पष्ट है, स्पेन्सर ने राज्य और मानव शरीर के बीच समानता बहुत दूर तक दिखाई है। राज्य को जीवविशेष कहना गलत है। यह कुछ दृष्टियों में निकट जीवविशेष जैसा है। राज्य बहुत बातों में जीवविशेष से भिन्न भी होता है। जीवविशेष के भागों का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होना। उदाहरण के लिए, हाथ शरीर में स्वतन्त्र रूप से नहीं रह सकता। दृष्टि अपने अंग में एक पूर्ण सन्निधि है और वह राज्य के बिना भी जीवित रह सकता है। दूसरे, मनुष्य प्राणियों में एक जीवविशेष दुबारे में से पैदा होता है। राज्य के मामले में यह बात नहीं।

सारांश

राज्य का उद्गम—राज्य का उद्गम अज्ञात अतीत में हुआ था। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि राज्य कब और कैसे आरम्भ हुआ। हम इसके उद्गम का अनुमान ही कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कई विचार पेश किये गये हैं —

दैवी उद्गम का सिद्धांत—राज्य के उद्गम के बारे में सबसे पुराना विचार यह है कि इसे ईश्वर ने बनाया। यह सब धर्मों की पुस्तकों में मिलता है। इस विचार से राजा के दैवी अधिकार का सिद्धान्त पैदा हुआ। इस विचार का असली आधार धार्मिक पुस्तकों में था। यह सर्व की बसोटी पर सरा न उतरने के कारण खतम हो गया।

समाज सविदा का सिद्धांत—इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का जन्म सविदा के द्वारा हुआ। हॉब्स, लॉक तथा रुसो समाज सविदा के तीन महत्वपूर्ण लेखक थे। यद्यपि हॉब्स ने इस सिद्धान्त द्वारा परमशक्तिवाद (Absolutism) को उचित ठहराया था तो भी इस सिद्धान्त का असली प्रयोजन, जैसा कि लॉक ने बताया था, दैवी अधिकार के सिद्धान्त के मुकाबिले में जनता के अधिकारों पर बल देना था। शासक को अपनी जनता के साथ की गई सविदा द्वारा सत्ता मिलनी है। इस प्रकार इस सिद्धान्त ने लोकतन्त्र के बलों को जन्म दिया। पर राज्य प्राकृतिक है और विभी सविदा का परिणाम नहीं। सामाजिक सविदा अपोल-वल्फित, इतिहास के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध है। इसी प्रकार, इस सिद्धान्त की कुछ बुनियादी अवधारणाएँ, अर्थात् प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार सर्वथा अवास्तविक हैं।

बल का सिद्धांत—इस सिद्धान्त का कहना है कि राज्य का जन्म सिर्फ बल से हुआ और बल ने ही जोर पर यह कायम है। इस प्रकार यह बल को अनुचित महत्व देता है। राज्य के सृजन और संरक्षण में बल सिर्फ एक कारक है। यह अधिक महत्वपूर्ण घटक भी नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण घटक 'इच्छा' है, बल नहीं।

ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत—इसके अनुसार राज्य समाज में विवास के क्रमिक और अनजाने प्रक्रम का परिणाम है। इसका उद्गम ऐतिहासिक ढंग से खोजना चाहिए। समाज से राज्य का विकास होने में रक्त सम्बन्ध, धर्म और राजनैतिक चेतना में मदद मिली। रक्त-सम्बन्ध एकता का पहला कारण था। इसने लोगों को पहले परिवार में और इसके बाद गोत्र तथा कबीले में रक्त की दृष्टि से प्येष्ठ के अधीन मगठित किया। धर्म ने सत्ता के प्रति आदर पैदा किया। जब समाज धिन्धार की अवस्था में सेतों की अवस्था में पहुँच गया, तब सम्पत्ति बढ़ जाने से राजनैतिक चेतना पैदा हुई। सम्पत्ति में वृद्धि हो जाने पर युद्ध अधिक होने लगे और युद्ध ने राजा को जन्म दिया। इस प्रकार जब एक राजा की सत्ता विभी निश्चित क्षेत्र के लोगों के ऊपर कायम हुई, तब राज्य का जन्म हुआ। राज्य के उद्गम के बारे में यह व्याख्या सबसे अधिक सर्वसम्मत है।

सविदा सिद्धान्त—हम इस सिद्धान्त पर राज्य के उदयम के सिलसिले में भी विचार का चुके हैं। राज्य की प्रवृत्ति के बारे में भी यह एक सिद्धान्त है। इसके अनुसार, समाज और राज्य सविदा या आपसी और स्वेच्छा किये गये करार का परिणाम है। इस सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि राज्य की आधारभूत एकता बनाई हुई एकता है, स्वामाजिक नहीं। यह सिद्धान्त राज्य की सतोपजनक व्याख्या नहीं करना। यह राज्य के निर्माण में मनुष्यों के मोक्ष-विचारे और जानबूझकर किये गये प्रयास पर अनुचित बल देता है। यह मनुष्य की सामाजिक प्रकृति की उपेक्षा करना है जो राज्य से व्यर्थान लोगो को इच्छा करने में मूल प्रेरक है।

जैवविज्ञान सिद्धान्त (Organismic Theory)—इस सिद्धान्त के लेखक राज्य की प्रकृति की व्याख्या किमी जीवपिण्ड से इसकी तुलना द्वारा करते हैं। हर्बर्ट स्पेन्सर तो राज्य और मानव शरीर को बिलकुल एक ही बताता है। उसके अनुसार ये दोनों अपनी वृद्धि, मरचना और कार्यो में एक जैसे होने हैं। राज्य का गरल रूप से मनुष्य रूप में विकसित होना किमी जीवपिण्ड की एक-जीविकीय पिण्ड संयुक्तजीविकीय पिण्ड के रूप में वृद्धि से मिलता-जुलता है। राज्य के विभिन्न अंगों का महयोग बेसा ही है जैसे मानव शरीर के विभिन्न भागों का अपने कार्य करते हुए आपसी महयोग। राज्य और मानव शरीर की मरचना के विषय में स्पेन्सर ने निम्न-लिखित समानताएँ प्रस्तुत की हैं :

१. राज्य के लिए सरकार उसी रूप में है जिस रूप में मानव शरीर के लिए मस्तिष्क है।

२. रेशे, शब्द और तार राज्य के लिए धने ही है जैसे शरीर के लिए धमनिया और गिराए।

३. पेट और आनें शरीर को पोषण देती हैं—मनुष्यकेचरित्र और कृपि कार्य राज्य का जीवन रखने हैं।

जैसा कि स्पष्ट है, स्पेन्सर ने राज्य और मानव शरीर के बीच समानता बहुत दूर तक दिखाई है। राज्य को जीवपिण्ड कहना गलत है। यह कुछ दृष्टियों से सिर्फ जीवपिण्ड जैसा है। राज्य बहुत भागो में जीवपिण्ड से भिन्न भी होता है। जीवपिण्ड के भागो का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। उदाहरण के लिए, हाथ शरीर से स्वतन्त्र रूप से नहीं रह सकता। ध्यष्टि अपने आप में एक पूर्ण समष्टि है और वह राज्य के बिना भी जीवन रह सकता है। हमारे, मनुष्य प्राणियों में एक जीवपिण्ड हमारे में से पैदा होता है। राज्य के मामले में यह बात नहीं।

इस सिद्धान्त में सत्य का अंश—राज्य के भाग अपने कल्याण के लिए उसी तरह परस्पर आश्रित होने हैं जैसे किमी जीवपिण्ड के भाग। समाज और राज्य की एकता लवटियों की गद्दी की एकता के समान नहीं है। यह सजीव एकता है। जैसे कोई तैल-वित्र तैल की बूदो और रसो का सम्यग्भाव नहीं होता उसी प्रकार राज्य ध्यष्टियों का समूहमान नहीं है।

सारांश

राज्य का उद्गम—राज्य का उद्गम अज्ञान अतीत में हुआ था। हम निर्दिष्ट रूप से यह नहीं कह सकते कि राज्य कब और कैसे आरम्भ हुआ। हम इसके उद्गम का अनुमान ही कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कई विचार पेश किये गये हैं —

ईशो उद्गम का सिद्धान्त—राज्य के उद्गम के बारे में सबसे पुराना विचार यह है कि इसे ईश्वर ने बनाया। यह सब धर्मों की पुस्तकों में मिलता है। इस विचार से राजा को देवी अधिकार का सिद्धान्त पैदा हुआ। इस विचार का असली आधार पश्चिम पुस्तकों में थड़ा था। यह तर्क की पत्तीटी पर खरा न उतरने के कारण खतम हो गया।

समाज सविदा का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का जन्म सविदा के द्वारा हुआ। हॉब्स, लॉक तथा रुमा समाज सविदा के तीन महत्वपूर्ण लेखक हैं। यद्यपि हॉब्स ने इस सिद्धान्त द्वारा परमशक्तिवाद (Absolutism) को उचित ठहराया था तो भी इस सिद्धान्त का असली प्रयोजन, जैसा कि लॉक ने बताया था, देवी अधिकार के सिद्धान्त के मुकाबिले में जनता के अधिकारों पर बल देना था। शासक का अपनी जनता के साथ की गई सविदा द्वारा सत्ता मिलती है। इस प्रकार इस सिद्धान्त ने लोकतन्त्र के बलों को जन्म दिया। पर राज्य प्राकृतिक है और किसी गविदा का परिणाम नहीं। सामाजिक सविदा कपोल-कल्पित, इतिहास के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध है। इसी प्रकार, इस सिद्धान्त की कुछ बुनियादी अवधारणाएँ, अर्थात् प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार सर्वथा अवास्तविक हैं।

बल का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त का कहना है कि राज्य का जन्म बल से हुआ और बल के ही अधीन यह कायम है। इस प्रकार यह बल को अनुचित महत्व देता है। राज्य के सृजन और सुरक्षण में बल सिर्फ एक कारक है। यह अधिक महत्वपूर्ण घटक भी नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण घटक 'इच्छा' है, बल नहीं।

ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धान्त—इसके अनुसार राज्य समाज से विकास के क्रमिक और अनजाने प्रक्रम का परिणाम है। इसका उद्गम ऐतिहासिक ढंग से खोजना चाहिए। समाज से राज्य का विकास होने में रक्त सम्बन्ध, धर्म और राजनैतिक चेतना से मदद मिली। रक्त-सम्बन्ध एकता का पहला बन्धन था। इसने लोगों को पहले परिवार में और इसके बाद गोन तथा बड़ोले में रक्त की दृष्टि से ज्येष्ठ के अधीन संगठित किया। धर्म ने सत्ता के प्रति आदर पैदा किया। जब समाज तितार की अवस्था से सैती की अवस्था में पहुँच गया, तब सम्पत्ति बढ़ जाने से राजनैतिक चेतना पैदा हुई। सम्पत्ति में वृद्धि हो जाने पर युद्ध अधिक होने लगे और युद्ध ने राजा को जन्म दिया। इस प्रकार जब एक राजा की सत्ता किसी निश्चित क्षेत्र के लोगों के ऊपर कायम हुई, तब राज्य का जन्म हुआ। राज्य के उद्गम के बारे में यह व्याख्या सबसे अधिक तर्कमग्न है।

राज्य की प्रकृति—राज्य अथवा प्राकृतिक और असात सचेत प्रयत्न का परिणाम है। राज्य की इस प्रकृति के कारण इसकी प्रकृति के बारे में अनेक विचार पैदा हो गए हैं।

संविदात्मिक सिद्धान्त के लेखकों के अनुसार, राज्य एक सर्वथा नयाई हुई चीज है और इसकी आधारभूत एकता संविदा जैसे कृत्रिम साधनों का परिणाम है। पर ये मनुष्य की सामाजिक प्रकृति को भूल जाते हैं जो लोगों को राज्य के अर्थात् इकट्ठा होने में मूल्य रूप से प्रेरणा देती है।

जोसफ़िटीय सिद्धान्त के लेखक राज्य की नुस्खा जोसफ़िटीय से बगने है। हर्बर्ट स्पेन्सर ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि राज्य एक जीवविज्ञ है, पर यह बात गलत है। जबकि ये अविश्व हम इनका यह मानने है कि राज्य की एकता एक जीवविज्ञ के समान है।

प्रश्न

QUESTIONS

- १ राज्य के इसी उद्गम के सिद्धांत की आलोचना करो।
- 1 Critically examine the theory of Divine Origin of the state
- २ राज्य के उद्गम के बारे में समाज संविदा सिद्धांत का संक्षेप में उल्लेख करो। इस सिद्धांत में क्या दोष है ?
- 2 State briefly the Social Contract Theory regarding the origin of the state. What is wrong with this theory ?
- ३ आप राज्य का सही उद्गम क्या समझते हैं ?
- 3 What do you think to be the correct origin of the state ?

Or

राज्य के उद्गम के बारे में ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत का संक्षेप में उल्लेख कीजिए ?

Briefly state the Historical and Evolutionary theory regarding the origin of the state

- ४ राज्य की प्रकृति क्या है ? इस प्रश्न में जोसफ़िटीय सिद्धांत का संक्षेप में विवेचन कीजिए।
- 4 What is the nature of the state. Briefly examine the organic theory in this connection

अध्याय : : १० राज्य के कार्य और लक्ष्य राज्य के कार्य

आजकल का कोई प्रारूपिक राज्य, जो अनेक कार्य करता है, उनका उल्लेख करने से पहले हम इस मिलमिले में दो चरम विचारों की चर्चा करेंगे। वे हैं व्यक्तिवादी (Individualistic) और समाजवाद विचार। व्यक्तिवादी लोग राज्य के कार्य कम से कम रखने के पक्ष में हैं। दूसरी ओर, समाजवादी राज्य को अधिक से अधिक कार्य सौंपना चाहते हैं।

व्यक्तिवादी विचार—व्यक्तिवादी लोग राज्य को एक बुराई समझते हैं जिसे मनुष्य की स्वार्थी और क्षयशील प्रकृति के कारण रखना पड़ता है। यदि भीतरी अराजकता और बाहरी हमलों से व्यक्ति की रक्षा की जरूरत न हो तो व्यक्तिवादी राज्य को बर्तई रखना पसन्द न करे। उनकी राय में, राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता का दुश्मन है। वे राज्य को अच्छाई पैदा करने का साधन नहीं मानते। व्यक्ति को अपने हितों की देखभाल करने के लिए आजाद छोड़ देना चाहिए। राज्य का दखल तभी उचित है, जब एक व्यक्ति की आजादी दूसरी व्यक्ति की इसी प्रकार की आजादी में टकराती है। अन्यथा, जैसा कि जे० एम० मिल ने कहा था 'अपने ऊपर अपने निज के शरीर और मन पर व्यक्ति गर्वोच्च प्रभुत्व रखता है।' व्यक्तिवादी के अनुसार, जहाँ तक व्यक्ति को अपने कल्याण का मवाल है, उसे वह जैसे तैसे प्राप्त करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि व्यक्ति स्वयं अपना भला-बुरा समझने की बुद्धि रखती है। इस प्रकार, औसत व्यक्तिवादी राज्य को निरंक निम्नलिखित कार्य देने को तैयार होता है —

- १ बाहरी हमलों से व्यक्ति की रक्षा।
- २ व्यक्तियों की एक दूसरे में रक्षा। इसमें उनकी सम्पत्ति की चोरी, डकैती या हानि से रक्षा भी शामिल है।
- ३ व्यक्तियों की मिथ्या सविदाओं, या सविदाओं के भग से रक्षा।
- ४ निरराधेह, व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति के महत्व पर बल देकर और व्यक्ति के दैनिक जीवन में सरकार के अनावश्यक दखल को बिलाफ आवाज उठाकर, उपयुक्त सेवा की है। पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता के उल्लाह में वे राज्य द्वारा व्यक्ति के संकल के लिये किये जाने वाले काम की कम कीमत लगाने हैं।

आलोचना—राज्य के कामों के बारे में व्यष्टिवादी सिद्धान्त की आलोचना करने के लिए से की गई है —

१ व्यष्टिवादी अर्थात् व्यष्टि की योग्यता के बारे में अनुचित रूप से अधिक आशावादी है। वास्तव में, अधिकतर लोग अपने भले को नहीं समझते और उन्हें मार्ग दिखाना पड़ता है। अनपढ़ आदमी शिक्षा का मूल्य नहीं समझ सकता।

२ यह समझना गलत है कि राज्य व्यष्टि की स्वतन्त्रता का दुश्मन है। यह तो उल्टा मत है अर्थात् मित्र है। राज्य उसकी अवाञ्छनीय (अराजकतावादी) स्वतन्त्रता का ही शत्रु है। नागरिक स्वतन्त्रता, जो व्यष्टि के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है, राज्य ही की देन है।

३ व्यष्टिवादी व्यापार और उद्योग में राज्य की हस्तक्षेप नहीं होने की जो मांग करते हैं, वह मांग नहीं जा सकती। मालिक और उसके मजदूरों में सुली प्रति-योगिता होने पर मजदूरों को निश्चित रूप में हानि उठानी होगी। राज्य की अपनी आवादी के अधिक दृष्टि से दुर्बल भाग की, घनियों के शोषण से, रक्षा करनी होगी।

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि व्यष्टिवाद आज की दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ चुका है। इसे धनता पहुंचाने में समाजवाद के आगमन का बड़ा हाथ रहा है।

समाजवादी विचार—समाजवाद व्यष्टिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, और ये दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध चीजों पर हैं। व्यष्टिवाद ने वैयक्तिक दिशा में बाली समाजवाद की निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं —

१. समाजवादी सिद्धान्त में राज्य को मुनिश्चित अच्छाई का अभिवर्ता माना जाता है। इसे व्यष्टि का उत्तम मित्र, हितकर्ता, और मार्गदर्शक माना जाता है।

२ समाजवादी राज्य को अधिक से अधिक काम सौंपना चाहता है।

३ व्यष्टिवादी मनुष्य के स्वामी स्वभाव पर बल देते हैं। दूसरी ओर, समाजवादी मानव प्रकृति पर आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, और उसे सारत एक सामाजिक प्राणी मानते हैं।

४ व्यष्टिवादी यह चाहते हैं कि व्यष्टि का अधिक से अधिक लाभ मुनिश्चित रूप से हो सके। समाजवाद का लक्ष्य है सारे समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त करना। समाजवाद के अनुसार, समाज का भला होने पर व्यष्टि का भला तो ही होता है।

५ व्यष्टिवाद में, उद्योगों का स्वामित्व व्यष्टियों के हाथ में होता है पर, समाजवाद उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थक है, या उन पर राज्य का स्वामित्व चाहता है।

६ व्यष्टिवाद (जिसे आर्थिक अर्थ में पूंजीवाद कह सकते हैं) में समाज का धन उन योही ही व्यष्टियों के हाथों में जमा हो जाता है, जो उत्पादन के साधनों की स्वामी होती हैं। समाजवाद का लक्ष्य समाज के सब सदस्यों में धन का समान वितरण है। उद्योग और व्यापार में होने वाले लाभ अन्त में मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य-सुविधाओं,

अच्छी सड़को और ऐसी ही अन्य सामाजिक सेवाओं पर खर्च किये जाए। इस प्रकार समाजवाद का लक्ष्य अधिक न्याय प्राप्त कराना है।

७ समाजवाद का लक्ष्य न केवल अर्थ-व्यवस्था को लोकतन्त्रीय बनाना है, बल्कि समाज को और राज्य का भी लोकतन्त्रीय बनाना है। इसका अर्थ यह है कि हर आदमी को राष्ट्रीय धन में हिस्सा पाने का समान अवसर होगा और जिस राज्य में वह रहते हैं, वह बराबरी वालों की साझेदारी होगा। उनमें कोई एक शासक वर्ग और दूसरे शामिल लोग नहीं होंगे। यह बराबरी वाला का समाज होगा।

आलोचना—थाय कहा जाता है कि समाजवाद सिद्धान्त में बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है पर व्यवहार में इसमें कुछ कमियाँ भी होंगी —

१ कहा जाता है कि यदि राज्य व्यष्टि के लिए सब कुछ कर दे तो व्यष्टि की स्वयं काम करने की प्रवृत्ति और निर्णय की स्वतन्त्रता खत्म हो जाएगी। राज्य लाड-प्यार करने वाले माता पिता की तरह व्यष्टि के व्यक्तित्व की वृद्धि में रुकावट ही जाएगा।

२ यदि राज्य पर इतने सारे काम लाद दिये गये तो चारों तरफ अक्षमता ही जाएगी। राज्य बहुत से काम छोटे-थोड़े करेगा और पूरी तरह कोई भी काम न कर सकेगा।

३ यह भी कहा जा सकता है कि उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होने पर वस्तुओं की ख़ालिती में वृद्धि और उत्पादन की लागत में कमी सम्भव नहीं। मजदूर राज्य के नौकर होंगे और इसलिए उन्हें बर्खास्त किये जान की चिन्ता न होगी और इस प्रकार उनमें काम से बचने की प्रवृत्ति होगी और उद्योग के प्रबन्धन भी बहुत सावधान नहीं होंगे, क्योंकि हानि होने में उनका अपना कुछ नुक़सान नहीं।

इसलिए राज्य के कार्यों के बारे में सही रास्ता इन दोनों सिद्धान्तों के बीच में है।

आधुनिक काल में राज्य के कार्य—ज्यों-ज्यों राज्य का संगठन जटिल होता जाता है, त्यों-त्यों इसके कार्यों की किस्म और मर्यादा भी बढ़ती जाती है। १५० साल पहले राज्य मुख्यतः पुलिस राज्य होता था और इसके कार्य नकारात्मक ढंग के थे। उसका काम आंतरिक कानून और व्यवस्था तथा बाहरी प्रतिरक्षा तक सीमित था। पर लोकतन्त्र होने पर मग़ज़वारी राज्य का विचार पैदा हुआ। लोगों की पशुमुर्खी उन्नति करता राज्य की जिम्मेदारी मानी जाने लगी। राज्य को अपने नागरिकों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक बर्थाण की वृद्धि करनी चाहिए। आज के जमाने में राज्य अब लोगों का मालिक नहीं रहा। अब यह उनका सबसे बफ़ादार और विश्वस्त नौकर हो गया है।

कोई प्रारूपिक आधुनिक राज्य जो कार्य करता है या जिन कार्यों के करने की ज़रूरत आता की जाती है, उनका वर्गीकरण निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है —

(क) अनिश्चित कार्य

(१) आंतरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना।

(२) बाहरी आक्रमण से प्रतिरक्षा ।

ये कार्य करना प्रत्येक राज्य के लिये जरूरी है । इन कार्यों को राज्य पुलिस और सेना के द्वारा करता है ।

(ख) ऐच्छिक या वैकल्पिक कार्य .

(१) आर्थिक सुख-सुविधाएँ बढ़ाना ।

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता करना ।

(३) शिक्षा देना ।

(४) सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुएँ बनाना ।

(५) सामाजिक जीवन में सुधार करना ।

(६) सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के जरिये रोग, बुढ़ापे और बेरोजगारी से लोगों को निश्चिन्त करना ।

राज्य चाहे तो इन कार्यों को करे, और न चाहे तो न करे । इनके बारे में राज्य की आवश्यकताओं और साधनों के अनुसार अलग-अलग राज्य में अलग-अलग स्थिति है । तो भी आवश्यक औषत मंगलकारी राज्य इनमें से जितने कार्य करना सम्भव हो, उतने कार्य करना अपना नैतिक वर्तव्य समझता है ।

अब हम इन कार्यों का एक-एक करके संक्षेप में वर्णन करेंगे ।

आन्तरिक व्यवस्था—राज्य बनाने के जो प्रमुख कारण थे, उनमें से एक था कानून और व्यवस्था की आवश्यकता । इस प्रकार प्रत्येक राज्य को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर लोगों को आपस में लड़ने से रोककर पूर्ण शान्ति रखनी चाहिए । अपराधियों और अन्य बदमाशों को सजा देनी चाहिए । राज्य के कानून एक दृष्टि के और दूसरे दृष्टि के तथा राज्य और व्यक्ति के सम्बन्धों को स्पष्ट रूप से बनाने वाले होने चाहिए । राज्य को दस पुलिस दल और निरपेक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायालय बनाना चाहिए जिसमें कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जा सके । उन पर मुकदमे चलाए जाएँ और उन्हें दण्डित किया जा सके ।

प्रतिरक्षा—राज्य बनाने का एक और मुख्य कारण था बाहरी हमलों से प्रतिरक्षा की आवश्यकता । इन काम के लिए राज्य के पास गुणगठित, दक्ष और ताज सामान से लैस स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना होंनी चाहिए । इसे राजनयिक प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान द्वारा अन्य राज्यों के साथ मैत्री सम्बन्ध भी रखने चाहिए ।

आर्थिक कार्य—राज्य निम्नलिखित कार्यों द्वारा आर्थिक सुख को बढ़ाता है —

(क) मिट्टाई, खेती और खाद देने के अधिक अच्छे तरीकों द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाना ।

(ख) उद्योग और व्यापार की वृद्धि को बढ़ावा देना ।

(ग) बैंकिंग और बीमा की वृद्धि को बढ़ावा देना ।

(घ) रेलवे, सड़कें, वायु मार्ग, तार, टेलीफोन और बेलार आदि संचार तथा परिवहन के अधिक तेज साधनों को बनाना ।

सूती के क्षेत्र में राज्य जमींदारी खत्म करने, चक्कन्दी कराने और नियामों के कर्जे खत्म कराने के लिए कानून बनाता है । यह अपनी गवेषणा संस्थाओं में नये प्रकार के बीजों और खादों का प्रयोग करता है और उनके परिणाम लोगों को बताता है ।

औद्योगिक क्षेत्र में, राज्य विदेशी प्रतिযোগिता के मुकाबले में नये उद्योगों को अधिक सहायता या सुरक्षण देकर बढ़ावा देता है । यह मालिकों और मजदूरों के सम्बन्धों को नियमित करने के लिए फैक्ट्री कानून बनाता है और इस प्रकार मजदूरों को काम करने की अच्छी अवस्था प्राप्त कराता है । राज्य औद्योगिक झगड़ों को निबटाने के लिए भी व्यवस्था करता है । राष्ट्रीयकरण द्वारा राज्य स्वयं उत्पादक बन जाता है ।

अपने चलायं यानी मुद्रा और अन्य देशों की मुद्राओं के विनिमय को नियन्त्रित करके राज्य-व्यापार को विनियमित करता है । संचार के अधिक तेज साधन बनाकर और बैंकिंग तथा बीमा कम्पनियों को बढ़ावा देकर राज्य उद्योग तथा वाणिज्य दोनों को बढ़ावा देता है । राज्य कीमतनियंत्रण और राशनिंग की प्रणाली द्वारा वृषि-वस्तुओं और उद्योग वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण को नियंत्रित और विनियमित कर सकता है ।

राज्य के समाज सेवा के कार्य—राज्य के वे काम जो इसकी जनता के जीवन को सुख तथा सुविधाजनक बनाने के लिए किये जाते हैं सामाजिक सेवा या सामाजिक-सेवा कार्य कहलाते हैं । सामाजिक सेवा का लक्ष्य है अज्ञान, बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को समाज से दूर करना । किसी देश की सभ्यता और संस्कृति का स्तर इसकी सामाजिक सेवाओं के विस्तार और दक्षता से निर्धारित होता है । उनका विस्तार और दक्षता हर राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार अलग-अलग होते हैं । अमेरिका जैसा धनी राज्य उन सबकी जिम्मेदारी आसानी से उठा सकता है । सामाजिक सेवाएँ पूर्णतः राज्य के सम्मिलित और प्रबन्ध में चलने वाली या अक्षत स्वेच्छित और अगत राज्य की सहायता से या राज्य के नियंत्रण में चलने वाली हो सकती हैं ।

सामाजिक सेवा की आवश्यकता—मुस्लिम राज्य का अर्थ आरक्षण मात्र है और उसकी जिम्मेदारी लेने वाले राज्य में सामाजिक सेवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता । पर औद्योगीकरण और जनसंख्या के तेजी से बढ़ने पर सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव की गई । गरीबों के उपबोध और फैक्ट्रियों की स्थापना ने नये नगर और महानगर बना दिये । औद्योगिक नगरों और फैक्ट्रियों में सफाई की हालत बड़ी खराब थी । मालिक लोग मजदूरों को बड़ी मुश्किल से निर्वाह-मजदूरी देते थे । राज्य की कुल आबादी का अधिकांश मजदूर होने थे । मजदूरों की गरीबी, बीमारी और निरक्षरता को और ध्यान दिचना स्वाभाविक था । खासकर

तब जब राज्य लोचनयोगी हो। कई बानूनों और बहुत सी सामाजिक नेत्रियों द्वारा व्यवस्था की धीरे-धीरे सुधारने लगी। इस प्रकार भी राज्य की 'सामाजिक सेवा राज्य' का मौजूदा नाम हासिल हुआ।

राज्य के सामाजिक सेवा कार्यों में निम्नलिखित ऐच्छिक कार्य भी शामिल हैं—

१. सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा।
२. शिक्षा।
३. सामाजिक सुधार।
४. लोकोपयोगी निर्माण कार्य।
५. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा—सामाजिक सेवा राज्य के विचार से पहले, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा का व्यवस्था राज्य के कार्यों में शामिल नहीं थी। हर आदमी स्वास्थ्य के लिए मुक्त जिम्मेदार था। महाभारत का पैदा होने से रोहने के लिए लोग कोई सामूहिक प्रयत्न नहीं करते थे। अगर प्लेग, चेचक, हैजा और इन्फ्लू-एंजा जैसी महाभारतिया शुरू होती थी, तो वे हजारों आदमियों के प्राण ले जाती थीं। लोग इनका कारण ईश्वरीय शक्ति की बदले से जोर इस तरह अपने को समझते देते थे। लोगों के इलाज के लिए लोग शास्त्र-युक्त करने वाले हस्तीयों और वैद्यों के पास जाते थे। नगरों में कहीं-कहीं विभिन्न मन्त्रियों या पण्डितों की तरफ से मुफ्त औषधालय भी होते थे, पर चिकित्सा की दृष्टि से व्यवस्था सब लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए नाकामी थी, मान करके महाभारतियों के दिनों में।

आज के जमाने में राज्य के स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों को दो भागों में बाटा जा सकता है—

१. रोग के निवारण में सम्बन्ध रखने वाले कार्य।
२. रोग हो जाने के बाद उसके इलाज में सम्बन्ध रखने वाले कार्य।

पहले प्रकार के कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य कहलाते हैं। निम्नलिखित व्यवस्था इस वर्ग में आते हैं

- (१) चेचक, हैजा, टाइफाइड या मालेरिया और टी० बी० के टीके लगाता।
- (२) नाशिया बनाना।
- (३) नगरों में पौधों के लिए फ्लोरोसिन-युक्त पानी पहुंचाना। इस काम के लिए राज्य नगरों को पूर्ण मुक्त करता है और जलाशय बनवाना है।

(४) सफाई निरीक्षकों का काम यह देखना है कि मलकों पर शास्त्र लगाई जाए और नाशिया गाए की जाए। नगर का गंद नगर से काफी दूर फेंका जाता है।

(५) गंदी बगिया साफ की जाती है और उनके स्थान पर हवादार तथा खुले मकान बनाये जाते हैं।

(६) नगरोंमें खाने-पीने की मिलावटी और सड़ी वस्तुओं की बिक्री रोकी जाती है।

(७) बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए छूट के हस्पताल बनाये जाते हैं, जहाँ छूट के रोगियों को बाकी लोगों से अलग रखा जाता है।

राज्य के चिकित्सा कार्य निम्नलिखित हैं।

(१) आजकल राज्य हस्पताल और औपचारिक बनवाता है। उनमें नये से नये उपकरण और दवाइयाँ रखी जाती हैं। रोगों के निदान करने, नुस्खे लिखने और दवाइयाँ देने के लिए अर्हता-प्राप्त डाक्टर, नर्स और कम्पाउण्डर रखे जाते हैं। सरकारी हस्पतालों में डाक्टर को वार्षिक वेतन देना पड़ती और दवाइयों की कीमत भी नहीं ली जाती।

(२) चिकित्सा और शल्य विद्या यानी सर्जरी का ज्ञान देने के लिए और डाक्टरों तथा नर्सों को शिक्षा देने के लिए डाक्टरों स्कूल और कॉलेज खोले जाते हैं।

(३) राज्य की गवेषणालयों में नई दवाइयों के बारे में गवेषणाएँ करती हैं।

शिक्षा—राज्य डाक्टर ही नहीं शिक्षक भी हैं। शिक्षक के रूप में यह अपने सब नागरिकों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी लेता है। कोई भी लोकतन्त्रीय राज्य अपनी जनता को उचित शिक्षा दूएँ बिना दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। इसलिए राज्य को अपने मालिकों तथा नागरिकों को शिक्षा देना जरूरी है। आज के जमाने में सब उन्नत राज्य अपने गृह के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने हैं। वे इस काम के लिए स्कूल और कॉलेज खोलते हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेशविद्यालय स्थापित करते हैं।

सामाजिक सुधार—अपनी जनता के शारीरिक और बौद्धिक बल्याण के अलावा राज्य पर उनकी नैतिक प्रगति की भी जिम्मेदारी है। इस प्रकार राज्य अपनी जनता का डाक्टर और शिक्षक होने के अलावा जनता नैतिक पथ-प्रदर्शक भी है। हर समाज में कुछ अनैतिक और अनुचित प्रथाएँ होती हैं। सर्वा प्रथा, बाल हत्या, बाल विवाह, दहेज, छुआछूत, बेगार, गुलामी, शराब पीना और जुआ खेलना—ये सब सामाजिक बुराइयाँ हैं। राज्य को इन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि इनमें स्वास्थ्य और सुखी सामाजिक जीवन बनने में बाधा पड़ती है। भारत में ब्रिटिश शासन के दिनों में सती प्रथा, बाल-हत्या, दाम प्रथा और बाल विवाहों के विरुद्ध कानून बनाए गए थे। भारतीय गणराज्य के संविधान ने बेमार और छुआछूत को गैर कानूनी घोषित कर दिया है पर यह शर्त रखता है कि राज्य अकेले सामाजिक सुधार नहीं कर सकता, यद्यपि उसे जागे-जागे चलना पड़ेगा। सामाजिक सुधारों की बहुत कुछ सफलता लोगों द्वारा अपने-आप बनाये गये ऐच्छिक साहचर्यों पर निर्भर है।

सामाजिक सुरक्षा—सच्चे मंगलकारी राज्य में नागरिकों को शरीरी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और दुर्घटनाओं से होने वाली निर्याम्यता से भी सुरक्षा प्रदान

करनी होगी । सामाजिक बीमा योजनाओं की प्रणाली द्वारा राज्य इन सब क्षेत्रों में अपने ऊपर बहुत बिलीय बोझ बिना डाले लोगों को मजबूर पड़ना सक्ता है । अब उभरत राज्यों में सामाजिक बीमा प्रणाली मौजूद है । इंग्लैण्ड में रोग और बेकारी से बचाव करने के लिए १९११ में अनिवार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अधिनियम पार किया गया था । प्रत्येक मजदूर को कानूनन अपनी मजदूरी का एक हिस्सा एक तिथि में जमा कराना होगा । मालिक और राज्य भी इसमें रकमा डालने हें । बेकारी या बेकारी होने पर मजदूर का इन रकमों में से सहायता दी जाती है । इसी प्रकार दुर्घटनाओं की अवस्था में दुर्घटना बीमा की प्रणाली बनाई गई है । बृहद आदमियों को सहायता देने की प्रणाली पहले स्कूलांलैण्ड में शुरू हुई । १९०८ में ब्रिटिश संसद ने भी बुढ़ापा बंधन कानून पास कर दिया । इस कानून के अधीन ७० वर्षों या इसमें अधिक के सब ब्रिटिश प्रवाशनों को वित्तीय आनंदनी २१। पौंड से कम होने पर ८ सिप्लिग प्रति सप्ताह देने की व्यवस्था की गई ।

लोकोपयोगी सेवाएँ—इनमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं —

- (क) रेल, सड़क, नदी, समुद्र और वायु के रास्ते परिवहन सेवाएँ ।
- (ख) डाक, गार और टेलीफोन प्रणाली ।
- (ग) बिजली, गैस और पानी का समरण ।

लोकोपयोगी सेवाओं के लाभ—(१) परिवहन सेवाएँ तथा तार टेलीफोन आदि संचार के तेज साधन लोगों के जीवन को अधिक आरामदेह बना देते हैं । दूर-दूर जाने में होने वाली भौतिक कष्टान, रेलों, बसों, ट्रामों और विमानों से यात्रा में गहरी होती । यात्रा अधिक सुरक्षित हो जाती है । डाक और तार नाममात्र पैसा लेकर एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी सफर पहुँचा देने हैं । मुझ प्रति लोगों को बहुत से रोगों से बचाना है । पैठ की जगह बिजली का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अधिक अच्छा है । रेडियो के मंत्रांतरक कार्यक्रम पारिवारिक जीवन को सुभी बनाने हैं ।

(२) परिवहन के इन साधनों का होना देश को आर्थिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है । इनके द्वारा कौमला, लोहा और अनाज जैसी भारी और बड़ी वस्तुएँ दूर-दूर स्थानों पर ले जाई जा सकती हैं । विमान अपना मान सबसे अधिक आवश्यकता की जगह सेजकर अच्छी से अच्छी कामना शामिल कर सकता है । परिवहन के दृष्ट साधनों के कारण जकाल कम बिनाकारी हो गए हैं, क्योंकि अब अधिकता वाले क्षेत्रों में अनाज जमानों से अकाल-प्रसन्न प्रकृति में ले जाया जा सकता है । पैकरी मालिक काल्पा सामान नियमित रूप से मिलने रहने और निमित्त वस्तुएँ जल्दी सुधर-उधर पहुँचा दिये जाने के कारण अपनी धनियों छाटू रख सकता है । परिवहन के तेज साधनों के कारण ही बिनी देशों को एक ही प्रकार का उत्पादन कर रहने की मुक्ति हो गई है । परिवहन के अच्छे साधन न हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान और एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार असम्भव हो जाएगा । सब तो यह है कि संचार के तेज साधनों

ने सारे मसार को एक बाजार बना दिया है।

(३) लोकसेवायुक्ति मेवाआ का मस्कुतिव मत्व भी है। मचार और परिवहन के तेज साधना के परिणामस्वरूप एव देग के लागो म और मसार के जगो में एक दूसरे के साथ अधिक मिलना-जुटना हा सकता है। बसा, ट्रामा और रेलम में हमें अलग-अलग जगह के अलग अलग राष्ट्रो और मस्कुतिया के सब जगह के लोग मिलने है। मस्कुतिया के आदान प्रदान मे लोगो का जीवन सम्पन्न हुना है और उनमें अधिक मोहादं और शान्ति पैदा होनी है। इन प्रकार यह स्पष्ट है कि सब लक्ष्योपयोग मेवाए एक न एक दृष्टिकोण म परम आवश्यक है। अगला सवाल यह पैदा हुना है कि क्या ये मेवाए निजी उपक्रम के लिए छोड दी जानी चाहिए, या वे राज्य के स्वामित्व और प्रबन्ध म रहनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में इन मेवाआ के मत्व के कारण वे प्रायः राज्य के स्वामित्व और प्रबन्ध में ही होती है। पर जहा निजी उपक्रम का भी काम करने दिया जाता है, जैसे, बसो, ट्रामो, जल मभरण, और बिजली की जवम्मा में, वहा राज्य उनके दण मन्चालन के लिए नियम और धर्ने बना देना है। इन क्षेत्रों में प्रतिपादिता अयाछनीय समनी जाती है। और इन प्रकार, सब जगह किसी कम्पनी या निवाय को सरकार की मन्त देख-रेख के अधीन एवाधिकार दे दिया जाता है। इन सवालों में निजी उपक्रम के विरुद्ध ये मुक्तिवा है —

१ इन मेवाआ का मभरण नियमित और दण होना चाहिए। इन मामों में जरा सी भी बाधा पडने से सारे राष्ट्र को भारी हानि हो सकती है। परिणामत इन मेवाओ में निजी उपक्रम पूर्णतः होमसारक नहीं हा सकता। बार्द निजा मन्चालक या कम्पनी इन मेवाओ की मीमत बहुत अधिक बढ़ाकर गरीबो को इन मेवाआ के उपयाय म वचित रण सकती है।

२ रेल, टाक और तार तथा मडकों देगव्याप, मेवाए है। उनमें बहुत अधिक पया लगाना पडता है। इनके लिए, एक आदमी या कम्पनी के लिए उनका पान्न आपनदण पनर्ग। व्यवस्था करना बडा कठिन है।

३ मडक आदि में बड़ी मात्रा, पूनी ल्याकर भी, पौरन कुछ लाभ मिलन की सम्भावना नहा जाती। इसलिए बार्द निजी आदमी या कम्पनी उनका निर्माण करना पनाद नहीं करना।

४ रेल और मडकों आगत के समय पीनों को एक जगह म दूसरे जगह घेजने के लिए बर्द, महन्वपूर्ण है। इन कारण भी उक्त निजी उपक्रम और नियन्त्रण के अर्थन करना मुक्तिव नहा।

राज्य का लक्ष्य या प्रयोजन

राज्य के आवश्यक पूना उद्गम, प्रवृत्ति, और बायों पर विचार करने के बाद हमारा उक्त प्रश्न पैदा हुना है कि राज्य म किस लक्ष्य की पूर्ति के, आशा की जाती है। समय-समय पर अनेक लेखकों ने राज्य के लिए अनेक-अनेक लक्ष्य सुझाए हैं।

कानून और व्यवस्था बनाये रखना, अधिकतम, मर्यादा का अधिकतम मुख, सामाजिक सेवा, न्याय और प्रगति—ये सब राज्य के लिये उपायुक्त लक्ष्य मुद्राएँ हैं। मंटे तोर से कहें तो राज्य के लक्ष्य सम्बन्ध, विचारों को दो वर्गों में बाटा जा सकता है —

१ वे लोग जो राज्य को अपने आप में एक लक्ष्य समझते हैं।

२ वे लोग जो राज्य को एक लक्ष्य का प्राप्ति का साधन समझते हैं।

जो लोग राज्य को एक लक्ष्य का साधन समझते हैं, उन्हें फिर दो भागों में बाटा जा सकता है —

(क) कुछ लोग राज्य को वैयक्तिक या सामाजिक कल्याण की सिद्धि का बुरा साधन समझते हैं।

(ख) दूसरे लोग राज्य को व्यक्ति और समाज दोनों की भलाई करने के लिए एकमात्र उपायुक्त साधन समझते हैं।

राज्य एक लक्ष्य के रूप में—प्राचीन ग्रंथों के लोगों के लिए राज्य अपने-आप में एक माध्य या लक्ष्य था। चीन के नगद-राज्य नागरिक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को अपने अधीन रखते थे। आदर्श, समाज के लिये ही जीता और मरता था। इन्हीं विचारों को १९वीं सदी में जर्मन आदर्शवादियों ने फिर मानने रखा। उनके अनुसार, राज्य अलग-अलग नागरिक के सर्वोत्तम अर्थ का प्रतिनिधि है। इसलिए आदर्शों का, अधिकतम भलाई इमी बात में है कि वह पूरी तरह राज्य की आज्ञा माने, उसे हमेशा अपने अर्थ को राज्य के अर्थ के लक्ष्य तक उठाने का यत्न करना चाहिए। राज्य व्यक्ति के लिए आदर्श है। यह व्यक्ति के जीवन का माध्य है। इस प्रकार आदर्शवादियों के अनुसार, राज्य की कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं करता। उसे तो अपने व्यक्तियों के कार्यों का मार्ग प्रदर्शन, नियंत्रण और विनियमन करना है जिससे इसका अपना अधिक से अधिक भला हो।

राज्य लक्ष्य-सिद्धि का बुरा साधन है—व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, और साम्यवाद, यानी कम्युनिस्ट आदर्शों या समाज की हित सिद्धि के लिए राज्य को बुरा साधन समझते हैं। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। वे इसे खत्म नहीं करना चाहते। वे राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और बाहरी दुश्मनों से इसकी रक्षा के लिए हैं, इसे बनाए रखते हैं। दूसरी ओर अराजकतावादी के लिए राज्य का कोई उपयोग नहीं है। उनके अनुसार, राज्य बल को निरूपित करता है और इसलिए यह कोई भलाई नहीं कर सकता। नैतिक जीवन बल से नहीं बनाया जा सकता। साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स ने राज्य को गरीबों के संघर्ष के लिए धर्मियों का शृंखला बताया है।

राज्य लक्ष्य-सिद्धि का अच्छा साधन है—अरस्तू का विद्वान या कि अच्छा जीवन राज्य में ही सम्भव है। योखिम राज्य की एक मगरमध्य पद्धति समझता था। उसने विद्वान-वादी राज्य की अधिकतम व्यक्तियों के लिये अधिकतम मुख प्राप्त करने का साधन समझते थे। समाजवादी राज्य को समाज की सब तरह की भलाई के लिए सबसे अधिक उपायुक्त साधन समझते हैं।

राज्य का अगली लक्ष्य—इस प्रकार पता चलता है कि अकेली व्यष्टि का मुख्य सारे समाज का मंगल और स्वयं राज्य का मंगल, घारी-बारी, राज्य के लक्ष्य बताय गये हैं। पर हमें याद रखना चाहिए कि न तो अकेली व्यष्टि का लाभ, न अनेक सामाजिक कल्याण और न अकेला राज्य का भला ही राज्य के हान का लक्ष्य या प्रयोजन हो सकता है। राज्य माधन भी है और साध्य भी। यह एक ऐसा माधन है जिसके द्वारा व्यष्टि का अधिकतम विकास और समाज का अधिकतम भला हो सकता है। राज्य वही तब अपने आप में एक लक्ष्य है, जहाँ तब यह अपने नागरिकों की भावी परिस्थिति के कल्याण पर भी विचार करता है।

मानव ने राज्य के तीन लक्ष्य मुझाए हैं, जो बहुत ठीक मुझाए गए हैं —

(१) प्रथम तो, राज्य को व्यष्टि के अच्छे से अच्छे विकास के लिए उचित व्यवस्थाएँ पेश करने उम्मीद सहायता करने चाहिए।

(२) दूसरे, इसे समाज और राज्य के लक्ष्यों के रूप में व्यष्टियों के जो सामूहिक हित है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।

(३) तीसरे, इस अपनी गतिविधियों और अपने नागरिकों की गति-विधियों को ऐसे चलाना चाहिए कि सारी मानव जाति गति और प्रगति की ओर बढ़े।

सारांश

राज्य के कार्य—राज्य के कार्यों के बारे में दो चरम विचार ये हैं —

(१) व्यष्टिवादी विचार—राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसलिए इसे कम से कम काम, अर्थात् भीतरी अराजकता और बाहरी हमले रोकना, ही दिया जाना चाहिए, और अन्य बातों में आदमी अपने कल्याण की प्राप्ति के लिए बिल्कुल आजाद रहना चाहिए। राज्य व्यष्टि के लिए कोई विषयवस्तु मलाई नहीं कर सकता।

व्यष्टिवादी भीमंत व्यष्टि की योग्यता के बारे में अत्यधिक आभावादी है। वास्तव में व्यष्टि को भाग्य प्रदर्सन की आवश्यकता है और मंगलकारी राज्य से अच्छा मित्र, सलाहकार, सेवक और रहनुमा कोई नहीं हो सकता। व्यापार और उद्योग में किसी तरह की दखलबाजी न होने से जनता के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को हानि होने की संभावना है।

(२) समाजवादी विचार—(१) राज्य आदमी का सबसे अच्छा मित्र है। वह निश्चित रूप से मलाई करता है। इसे अधिक से अधिक कार्य देने चाहिए। (२) समाजवाद का लक्ष्य सारे समाज का अधिकतम लाभ है। (३) समाजवाद उत्पादन के साधनों के वैयक्तिक स्वामित्व का विरोधी और राष्ट्रीयकरण का समर्थक है। (४) समाजवाद सम्पत्ति का समान वितरण करता है। इसलिए यह अधिक शक्तिशाली और न्यायमय है।

पर समाजवाद सिद्धान्तरूप में जितना आवश्यक है, उतना व्यवहार में नहीं। व्यवहार की दृष्टि से, इसमें कुछ कमजोरियाँ हैं —

(१) राज्य को बहुत से बाध गोंप देने से सब कामों में कमी जाने की संभावना है ।

(२) राष्ट्रीयकरण होने पर अन्धी और गली वस्तुएँ नहीं बनाई जा सकतीं ।

(३) कहा जाता है कि समाजवाद आदमों की स्वयं आपे रहने की भावना को और नियंत्रण की स्वाधीनता को नष्ट कर देता ।

राज्य के कार्य

(क) अनिवार्य काम :

(१) भीतरी कानून व्यवस्था बनाने रचना ।

(२) बाहरी आक्रमण से रक्षा ।

(ख) ऐच्छिक कार्य :

(१) कृषि उत्पादन और उद्योग, व्यापार, बैंकिंग और बीमे को बढ़ावा देकर आर्थिक उन्नयन करना ।

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, और शिक्षा को व्यवस्था करना ।

(३) शिक्षा देना ।

(४) रेल और सड़क, डाक, तार और टेलीफोन, बिजली, गैस और पानी आदि सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य करना ।

(५) मत्ती प्रथा, बाल हत्या, बाल विवाह, दहेज, छुआछूत, वैचार, दामना, पराब और जुए आदि कुछ अनैतिक और अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करके सामाजिक जीवन में सुधार करना ।

(६) लोगों को रोग, बुढ़ापे और बेरोजगारी से निरिचलित करने के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाना ।

राज्य का लक्ष्य या प्रयोजन—राज्य के लक्ष्य के सम्बन्ध में जो विचार हैं, उन्हें छोटे छोटे से दो वर्गों में बांटा जा सकता है :—

(१) वे लोग जो राज्य को अपने आप में एक लक्ष्य या साध्य समझते हैं ।

(२) वे लोग जो राज्य को एव साध्य का साधन समझते हैं ।

राज्य एक साध्य है—प्राचीन ग्रीक लोगों और आधुनिक काल में जर्मन आदर्शवादियों के अनुसार, आदमों को राज्य के लिए ही जीना और मरना चाहिए क्योंकि राज्य अपने आप में एक लक्ष्य है । इसलिए व्यक्ति का काम इसी में है कि वह पूरे तरह से राज्य की आज्ञा का पालन करे ।

राज्य एक लक्ष्य का अच्छा साधन है—उपयोगितावादी राज्य का अधिकतम लोगो के लिए अधिकतम सुख का साधन समझने है। समाजवादी समाज को सब तरह को प्रगति करने के लिए सबसे अच्छा साधन मानते हैं।

सच्चा लक्ष्य—गान्धे के अनुसार, राज्य के तीन लक्ष्य होने चाहिए

- १ व्यक्ति का कल्याण।
- २ सारे समाज का कल्याण।
- ३ सारी मानव जाति का कल्याण।

प्रश्न

QUESTIONS

- १ सरकार के कार्यों के धारे में व्यक्तिवादी और समाजवादी विचार लिखिए।
(५० वि० सितम्बर, १९५२)
- 1 State the views of the Individualistic and Socialist schools relating to the functions of government (P U Sep., 1952)
- २ किसी आधुनिक राज्य के मुख्य कार्य क्या हैं? किस प्रकार का राज्य उन्हें अधिकतम दक्षता से कर सकता है।
- 2 What are the main functions of a modern state? What kind of state can perform them most efficiently?
- ३ राज्य के सामाजिक सेवा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
- 3 Give a brief account of the social service functions of the State
- ४ लोक-उपयोगी सेवाओं से आप क्या समझते हैं? ये राज्य के प्रथम और नियंत्रण में क्यों रहनी चाहिए?
- 4 What do you understand by public utility services? Why should they be managed or controlled by the state?
- ५ सामाजिक सुधार के प्रसंग में राज्य के कर्तव्य को विवेचन कीजिए। क्या मनुष्य को नैतिक बनाना राज्य का कर्तव्य है?
- 5 Examine the role of the state in relation to social reform? Is it the duty of the state to make man moral?
- ६ सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? क्या गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना राज्य का कर्तव्य है?
- 6 What do you understand by 'social security'? Is it the duty of the state to remove poverty, unemployment and disease?
- ७ आधुनिक काल में राज्य के कर्तव्यों को देखते हुए यह सिद्ध कीजिए कि आज का राज्य भगल राज्य है, पुलिस राज्य नहीं।
- 7 In the light of functions of the state in modern times prove that the state of today is a welfare and not a police state.

- ८ राज्य के लक्ष्य के बारे में विभिन्न विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए ।
 8 Examine briefly the views regarding the end of the state
 ९ आपको राज्य में राज्य का सच्चा लक्ष्य क्या है ?
 9 What in your opinion is the true end of the state ?
 १० राज्य के लक्ष्य क्या हैं ? (पं० वि० सितम्बर, १९५१)
 10 What are the ends of the state ? (P. U. Sep, 1951)

शिक्षा

शिक्षा कितने कहते हैं—शिक्षा शब्द की बहुत सी परिभाषाएँ की गई हैं। सार्टर अंतिसफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इसकी यह परिभाषा है कि "जीवन के काम की तय्यारी में छोटे बच्चा को (और ब्यान्ति द्वारा बड़े को) बी जाने वाली व्यवस्थित सिपलाई, अध्यापन या प्रशिक्षण।" वेबस्टर के शब्दकोश में शिक्षा की यह परिभाषा है, "व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक परिवर्द्धन कराने वाली मील और प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त जानकारी और गुण का समुच्चय।"

उपर्युक्त दो तथा अन्य बहुत भी परिभाषाओं से निम्नलिखित बाने स्पष्ट हो जाती हैं —

१ शिक्षा मनुष्य के स्वाभाविक विकास के पत्राय उमे एक विमर्शित (deliberate) निर्देशन और प्रशिक्षण है।

२ यह विमर्शित निर्देशन और प्रशिक्षण हमेशा किसी दस मानव समाज के आदर्शों के प्रसंग में होता है। मानव समाज के बड़े सदस्य अपने छोटी को अपने जीवनादर्शों के अनुसार ही प्रशिक्षित करते हैं।

३ शिक्षा में आदमी का सर्वतोमुखी विकास अभिप्रेत है। इसका अर्थ सिर्फ बुद्धि का प्रशिक्षण नहीं है। बौद्धिक विकास के अलावा शिक्षा का लक्ष्य भौतिक और नैतिक विकास भी है।

४ शिक्षा जीवन भर चलने वाला उपक्रम है जिसमें आदमी एव ही समय कई चीजें सीखना है और कई चीजें भूलना है। शिक्षा बचपन के साथ समाप्त नहीं हो जाती। बूढ़े हो जाने पर भी शिक्षा का मिलनिल चलता रहता है।

शिक्षा के लक्ष्य—शिक्षा के लक्ष्यो के बारे में बड़ा विवाद है, और यह बहुत समय से चलता रहा है। कुछ लोग उदार शिक्षा के पक्षपाती हैं, और कुछ लोग व्यावसायिक या शून्ये की शिक्षा या प्रशिक्षण के पक्षपाती हैं। उदार शिक्षा के पक्षपातियों का लक्ष्य है लोगो के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास द्वारा पूर्ण व्यक्ति पैदा करना। व्यावसायिक शिक्षा के समर्थकों का मुख्य लक्ष्य किसी राजगार, कल या दस्तकारी में लोगो को प्रशिक्षित करके उन्हे उपयोगी बनाना है। पर आज की दुनिया में हर आदमी नागरिक भी अवश्य होना है इसलिए अच्छी शिक्षा प्रचाली के ये तीन लक्ष्य होने चाहिए —

१ प्रथम, शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की प्रकृति की गुप्त क्षमियों और योग्यताओं का विकास करना होना चाहिए। दूसरा अर्थ होगा आदमी का पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक

ओर नैतिक विकास । इस प्रकार शिक्षा सर्वथा उदार होनी चाहिए ।

२ दूसरे, शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए, इसमें हर लड़का या लड़की अपनी जीविका कमाने योग्य हो जाना चाहिए ।

३ तीसरे, आधुनिक सौतन्त्र्यीय युग में शिक्षा का लक्ष्य नागरिकता का प्रतिपादन देना भी होना चाहिए । व्यावसायिक शिक्षा नागरिक को उपयोगी बनाने में सिर्फ एक पटल होगी । आदमी उपयोगी नागरिक या अच्छा नागरिक तभी बहलाएगा जब उसमें कुछ नागरिक गुण होंगे ।

शिक्षा की मजिद—बच्चे के जीवन को छोटे नीर से तीन मुख्य अवस्थाओं में बाटा जा सकता है —

(१) बाल्यकाल—५ या ६ वर्ष की आयु तक ।

(२) किशोरावस्था—१० से १४ वर्ष तक की आयु तक ।

(३) तरुणावस्था—१४ से १८ वर्ष तक की आयु तक ।

बालकों की शिक्षा—बाल्यावस्था में बच्चा घरों और नर्सरी स्कूलों में उचित शिक्षा पा सकता है । इस अवस्था में बच्चे को ठीक स्वास्थ्य बनाए रखने के अलावा, अच्छा चरित्र निर्माण करने की आवश्यकता होती है । उसकी आदतें, शिष्टाचार और कथिया दस समय बनाई जाती हैं । छोटे बच्चों के लिए बूढ़ि के प्रतिक्षण का महत्व शीघ्र है पर उसकी जानबारी का दायरा अधिक से अधिक विस्तृत हो सकता है ।

बालकों की शिक्षा में घर का स्थान—आदमों पर बच्चे के लिए सर्वोत्तम विशाल-लय है । बच्चा प्रेम से अधिक गोबलता है और बच्चे से उनके अपने माता पिता के जन्मा कोई और आदमी अधिक प्रेम से व्यवहार नहीं कर सकता । पर प्रेम के साथ-साथ बच्चे की प्रकृति को ठीक ठीक समझना चाहिए और उचित प्रकार का अनुशासन रहना चाहिए बिना अनुशासन का बहुत अधिक अनुराग बच्चे की विगाह देगा । इसी प्रकार बहुत अधिक अनुशासन बच्चे में स्वयं कर्तृत्व और मूर्खत्वना की बूढ़ि को रोक देता है । यह बड़े महत्व की बात है कि माता पिता को अपने बच्चों पर भावे से ब हर न हो जाना चाहिए । बच्चे में अनुकरण की बहुत प्रवृत्ति होती है । माता-पिता को उन सब कामों में भी बचना चाहिए जिनसे उनके बच्चों पर बलत असर पड सकता है । इस प्रकार बच्चों का प्रतिक्षण बटा नठिन काम है । उनकी प्रकृति को ठीक से समझना भी आसान काम नहीं । इसलिए बच्चे की उचित शिक्षा के लिए हीनियारी में काम करने की जरूरत है । माता-पिता माता पिता का व्यस्त जीवन उन्हें अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देने देता । इसीलिए बच्चों की शिक्षा मातो या नम में कम कुछ हद तक, नर्सरी स्कूलों में होनी चाहिए ।

नर्सरी स्कूल—नर्सरी स्कूलों के निलाक एक यही बात नहीं जा सकती है कि उनकी शिक्षा बड़ी खर्चीली है और उनमें माता पिता जेगा अनुशासन नहीं हो सकता । अन्यथा, नर्सरी स्कूलों की पद्धति राष्ट्र के लिए बड़ी लाभदायक है । बच्चों की कुछ आवश्यकताएँ घर की अपेक्षा स्कूल में बहुत अच्छी तरह पूरी हो सकती हैं । खेलने के लिए खुली हवा और उचित तथा अनुचित चुराव स्कूल में बहुत अच्छी तरह मिल

सकती है। शोर करने की आजादी बच्चों के लिए बड़ी आवश्यक है। घरों में शोर करने वाले बच्चों को बड़े आदमी बड़ी गुमीबत समझते हैं। बच्चों की पूर्ण वृद्धि के लिए लगभग उसी उम्र के बच्चों का साथ भी परम आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति धनी माता-पिता भी नहीं कर सकते। अन्तिम बात यह है कि बच्चों के मीसने और मनोरञ्जन के लिए उचित वातावरण नर्सरी स्कूलों में बनाया जा सकता है। इस प्रकार घर की शिक्षा की पूर्ति नर्सरी स्कूलों में शिक्षा देकर करनी चाहिए।

दूसरी मजिल—स्कूलों में शिक्षा—बट्टेण्ड रमल के अनुसार, ६ वर्ष की आयु तक चरित्र का निर्माण अधिबन्धन पूरा हो जाता है। उसके बाद बच्चों का बुरे वातावरण से बचाने की ही जरूरत रहती है। बुरे वातावरण मनुष्य के चरित्र को उसके जीवन की जिंती भी मजिल में प्रभावित कर सकते हैं। स्कूल की शिक्षा के तीन मुख्य पहलू हैं, अर्थात् बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक।

बौद्धिक—दूसरी मजिल में पहले तो बौद्धिक प्रगति पर जोर देना चाहिए। छात्रों को सब तरह का ज्ञान पाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रेन विषयों का ज्ञान भी उनसे छिपाना नहीं चाहिए। कुछ गुण, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं, छात्रों में पैदा करने चाहिए। उदाहरणार्थ धैर्य, उद्योग, एकाग्रता, यथायथा और खुले भस्मिक से विचार करना। गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, आरम्भिक अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र या हाईजीन और आरम्भिक विज्ञान की शिक्षा इस उम्र में सब छात्रों के लिए आवश्यक समझी जाती है।

शारीरिक—बुद्धि का प्रतिक्षण तब तक अपूरा रहेगा, जब तक साथ ही शरीर को भी प्रतिक्षण न किया जाए। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। कोई भी अच्छी शिक्षा प्रणाली कमरत और खेल बूद के महत्व को कम नहीं समझ सकती। खेल और बूद से जहां स्वास्थ्य अच्छा रहना है, वहां छात्रों में कई नागरिक गुण भी पैदा होते हैं। अनुशासन, नेतृत्व, महयोग और खिलाड़ीपन आदि गुण खेल के मैदान में ही अच्छी तरह गीले जाते हैं। प्राचीन ग्रीस में जिमनास्टिक और मैनिक्स प्रतिक्षण शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग होते थे। आज के जमाने में भी मैनिक्स प्रतिक्षण का महत्व अधिकाधिक समझा जा रहा है। विरवविद्यालय मैनिक्स प्रतिक्षण दल और राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल फिर सामने आ रहे हैं।

नैतिक—नैतिक शिक्षा शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा से निकट सम्बन्ध रखती है। इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। छात्रों को अपने साधियों के साथ व्यवहार करते हुए जात्म नियंत्रण, ईमानदारी, सहिष्णुता, न्याय, सम्मान, और दया की शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार, किसी शिक्षा प्रणाली से सिर्फ बित्तावी कीडे न पैदा होने चाहिए। निरी बौद्धिक शिक्षा छात्र के और पहलुओं को दबाकर सिर्फ एक पहलू को विकसित करती है। दूसरे पक्षों में, शिक्षा उदार होनी चाहिए, जिसका लक्ष्य छात्र के सब पहलुओं का विकास करना हो।

ध्यापसाधिक शिक्षा—सामाजिक जीवन में आर्थिक बातों का महत्व बढ़ जाने

के कारण भव देशों में लोकमत व्यावसायिक शिक्षा ने अधिक पक्ष में होना जाता है । यह कहा जाता है कि निरी रितायी शिक्षा अधिकतर छात्रों के लिए गुप्त और अरबिकर होती है । यह आदमी को जीवन में किसी व्यवसाय के लिए भी तैयार नहीं करती और इस तरह सैकरी और शरीरी बटाने वाली बनाई जाती है । इसलिए, बहुत से लोग यह कहते हैं कि पढ़ाई किसी बुनियादी दम्तकारी के साथ-साथ चलनी चाहिए । अनुभव में जो यह सिद्ध हुआ है कि अधिकतर छात्रों के लिए रितायी पढ़ाई अरबिकर होती है और इस तरह राष्ट्रीय उद्योगों की बड़ी बरबादी होती है । यदि विभिन्न धर्मों, दम्तकारियों या पेशों के लिए छात्रों की रचि का पना लगाने का यत्न किया जाए तो बहा अच्छा हो । यह मय है कि १५ वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को रितायी शिक्षा मिलनी चाहिए, पर इस अवस्था में छात्र की रचि का पना लगा लेना चाहिए और रितायी पढ़ाई के साथ-साथ उसे किसी काम दस्तकारी, व्यापार या पेशे में, जो उसकी रचि और योग्यता के अनुसार हो, दाल देना चाहिए । किनो काम विषय का विशेष प्रशिक्षण बाद में, उस प्रयोजन के लिए बनाए गए विशेष शिक्षा केंद्रों में दिया जा सकता है । किन छात्रों में रितायी शिक्षा की रचि दिखाई दे, उन्हें विश्वविद्यालय में भी उनी में चलने देना चाहिए । हर मूल में शिक्षा का नाम १८ या २० वर्ष की आयु तक पूरा हो गया कहा जा सकता है ।

व्यावसायिक या शिल्पिक शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण में ही आवश्यक नहीं, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी परम आवश्यक है । बड़े पैमाने के उद्योग मुख्यतः कुशल धमिक निर्दिष्ट रूप में मिलने रहने पर निर्भर होते हैं । वैकनितिक शिक्षा में वाणिज्यिक और वृत्ति की शिक्षा भी शामिल है ।

तीसरी मजिल उच्च शिक्षा—विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा निर्ध उन्हे दी जानी चाहिए जो इसके उपयुक्त हो । बरूँठ रमल के अनुसार विश्वविद्यालयों को दो प्रयोजन होने चाहिए—

१. कानून, निवित्ता आदि कुछ पेशों के लिए पुण्यों और शिक्षियों को प्रशिक्षित करना ।

२. मातालिक उपयोगिता का बिना विचार नये ज्ञान और गपेपभा के मार्ग पर जाने जाना ।

इस प्रकार विश्वविद्यालय कुछ छोटे में चुने हुए छात्रों के लिए उपयोगी होंगे । कुछ लोग उच्च शिक्षा की बुराई करते हैं और इसे जिलकुल बेकार कहते हैं । पर हमें याद रखना चाहिए कि उच्च शिक्षा का अपना ही मूल्य है । यह हमारे दृष्टिकोण और मन को विस्तृत करती है, आत्मा को गम्भिर करती है और मन को मालिज देती है । बिना उच्च शिक्षा के विश्व के गम्भिर हमारे लिए रहल्य ही बने रहेंगे । विज्ञान, कला और दर्शन की कोई तकलीफ हो सकती है । हमने बिना आदमी प्रकृति का स्वामी होने के बजाय दास होना ।

नागरिकता के लिए शिक्षा—स्कूट, कालेज और विश्वविद्यालय के जीवन का

एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक और नागरिक प्रशिक्षण के लिए सबका प्रयत्न करना होना चाहिए। विनायी शिक्षा के अलावा या नागरिकों के सर्क और आलोचना के गुणों का विकास करती है, नागरिकता के प्रशिक्षण में पाठ्येतर कार्यों (extracurricular activities) के महत्व का भुगतान नहीं चाहिए। १२ वर्ष की आयु तक बागवानी, छात्र-नृत्य, अभिनय गेज, वगैरह यात्रा और शोक की चीजों सबसे अधिक उपयुक्त हैं। इनके बाद की उम्र में स्वार्जटण, वाद विवाद, नाटक, महकरी मोनाइटिया, ग्राम मुधार सोगाइटिया और ऐसी ही अन्य सामाइटिया बनाने की शिक्षा छात्रों को मिलनी चाहिए। पाठ्येतर कार्यों में छात्रों का छात्री समय में लाभ का काम मिल जाता है। लाभ इस अर्थ में होता है कि इनमें आदमी का व्यक्तित्व में वृद्धि होती है। छात्रों की परिपक्व और विधान मभाग छात्रों को स्वयंसेवा का प्रशिक्षण देती है। उन्हें नेतृत्व के प्रशिक्षण के अलावा, आत्म निपटण, महयाग और स्वयं-सर्वस्व की शिक्षा मिलती है। पत्रिकाएँ और वाद-विवाद मभाग गिनत और बाल्य में आत्मा-मिद्वक्ति का विकास करती है। यात्राओं में शरीर बनना है, ज्ञान की वृद्धि होती है और अनुभव का निवारण होता है। शब्द और ममात्र मगतन और प्रबंध का पयान गिरा देता है। उनमें स्वयं-सर्वस्व, मिन्नकारी, महयाग और कानून के गिन सम्मान का भी विकास होता है। हमने पट्टे बनाया है कि नागरिकता के लिए हान वाले प्रशिक्षण में से-अद्वैत का क्या महत्व है। सामाजिक मवा-मगतन, निस्वार्थ मवा और मानव बन्धुता का पाठ पढ़ाने है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई नागरिक गुण पैदा होत हैं और नागरिकता की उत्तम शिक्षा मिलती है।

प्रौढ़ शिक्षा—प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक मवस्य का एक और उपयोगी नागरिक बनाना है। प्रौढ़ों को शिक्षित करने की आवश्यकता एकरतन्त्रीय राज्य में और भी अधिक है, क्योंकि इसकी मफयता और दणता इसके लोग का ज्ञान पर निर्भर है। शिक्षा लोग के दृष्टिकोण को बढ़ा करके उनकी बुद्धि तथा तपमक्ति का तेज करके उन्हें उपयोगी नागरिक बनाने है। इसके मगवा प्रौढ़ों का शिक्षित करने का लक्ष्य उन्हें गिरा माधर बना देना नहीं होना चाहिए। उनकी शिक्षा शिवात्मक भी हानी चाहिए। यह उन्हें अपनी सामाजिक और आर्थिक ममरवाभा को हल करने के योग्य बनाने वाली होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा में चित्र, मैजिक संटन, मिनमा, शमोफान और रटियों आदि दुस्य और धान्त्रिक साधन बढ़े सहायक मिले हो सकते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा नई पीढ़ी की शिक्षा के लिए भी सहायक होती है। अनगड़ माना-पिता अपने बच्चों की शिक्षा का महत्व नहीं समझ सकते। वे प्रायः जन-बुशकर उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जब वे स्वयं शिक्षा पाने हैं, तब ही उन्हें अपने बच्चों के लिए इसकी उपयोगिता का पता चलता है।

राज्य और शिक्षा—१९वीं सदी के शुरुआत शिक्षा को विष्णुल निजी मामला समझा जाता था। अपनी शिक्षा के लिए हर आदमी खुद जिम्मेदार था। राज्य अपने नागरिकों को शिक्षित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं समझता था। उन दिना शिक्षा का

प्रबन्ध या तो धार्मिक संस्थाओं अर्थात् चर्चों, मठों, मसजिदों, और मंदिरों या कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा, जो धर्मार्थ विद्यालय खोलते थे, दिया जाता था। आज के जमाने में शिक्षा पाने का अधिकार आदमी का महत्वपूर्ण अधिकार है। मंगलकारी राज्य होने के नाते राज्य को अपने नागरिकों को शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसी विचार के कारण आजका प्रायः सब उन्नत देशों में मुफ्त और अनिवार्य बारम्बार शिक्षा दी जाती है।

लोकतन्त्र में नागरिकों की शिक्षा राज्य के दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण है। कोई लोकतन्त्रीय राज्य, जिसके नागरिक शिक्षित और प्रबुद्ध नहीं, दक्षतापूर्वक नहीं चल सकता। निम्नलिखित कारणों से शिक्षा राज्य को जिम्मेवारी बननी चाहिए है —

१ जैसा कि ऊपर बताया गया है, लोकतन्त्रीय राज्य की दक्षता के लिए छोटे-बड़े, गरीब-अमीर, नव नागरिकों की शिक्षा आवश्यक है। इन राज्य उनकी शिक्षा किन्हीं व्यक्तियों पर या निजी मस्याओं पर नहीं छोड़ सकता। यदि इनमें निजी मस्याओं पर छोड़ दिया जाए तो शिक्षा के भारी खर्च के कारण गरीब नागरिकों को अपने बच्चों को शिक्षित करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ अनपढ़ माता-पिता शिक्षा का महत्व मानद कभी भी न समझें। ऐसे लोगों को भी अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए मजबूर करना होगा।

२ दूसरी बात यह है कि देश भर में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने का खर्च इतना अधिक है कि कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं जुटा सकता।

इन कारणों ने आज के जमाने में शिक्षा का बोझ राज्य उठाना है। आजकल राज्य या तो अपने रुपये में स्वयं स्कूल और कॉलेज खोलकर अथवा निजी तौर से बटाई जा रही शिक्षा मस्याओं को सहायता देकर शिक्षा को बढ़ावा देता है।

शिक्षा का महत्व—शिक्षा व्यक्ति के विकास और समाज को तरक्की के लिये सबसे पहले जरूरी है। सश्रेय में शिक्षा के बिना अच्छा जीवन असंभव है। व्यक्ति के लिए अच्छे जीवन का अर्थ है, उसके ऊंचे या युक्तियुक्त जीवन का विकास। शिक्षा मनुष्य को अपने पागबिल भावों को तर्क द्वारा दवाने में सहायता देती है। यह उसका ज्ञान बढ़ाती है, उसका दृष्टिकोण विस्तृत करती है, उसकी बुद्धि तीव्र करती है, और उसकी सोचने और नर्क करने की शक्ति बढ़ाती है। शरीर सम्बन्धी शिक्षा से मनुष्य अच्छा स्वास्थ्य बना सकता है। नैतिक और सामाजिक शिक्षा चरित्र को ठीक रूप देती है। शिक्षा के बिना मानविक मानि और आत्मिक सुख मिलना असंभव है।

शिक्षा गरीबी, रोग और बेकारी को हटाने में भी मदद करती है। यह बुद्धि, उद्योग, व्यापार और पाणिज्य की तरक्की करती है। इनसे नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही ज्ञान होता है, और इन प्रकार वह अपने सामाजिक और राजनैतिक जीवन को सुधारता है। विज्ञान, कला, दर्शन, और साहित्य की महान रचनाएँ शिक्षा के

बिना कभी नहीं बन सकती थी। इस प्रकार, शिक्षा मस्तिष्क और सम्यता, दोनों, की तरक्की के लिए आवश्यक है। सशेष में यह मनुष्य जाति की प्रगति, समृद्धि और सुख की कुजी है।

सारांश

शिक्षा किसे कहते हैं—व्यक्ति की शिक्षा सीखने और भूलने की जीवन भर की प्रक्रिया है। इसमें ये तीन बातें आती हैं (१) उसके स्वाभाविक विकास के बजाए विमर्शित प्रशिक्षण। (२) अपने समाज के आदर्शों का प्रशिक्षण। (३) न केवल उसके बौद्धिक गुणा का, बल्कि उसके शारीरिक और नैतिक गुणा का भी विकास।

शिक्षा के लक्ष्य—(१) यह बिल्कुल उदार होनी चाहिए और इसका लक्ष्य व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास होना चाहिए। (२) साध-साध, इसका व्यावसायिक आधार भी होना चाहिए। (३) आज के जमाने में शिक्षा का लक्ष्य नागरिकता की शिक्षा देना भी होना चाहिए।

शिक्षा की मजिलें—(१) ५ या ६ साल की उम्र तक शिक्षा का लक्ष्य ठीक स्वास्थ्य और चरित्र का निर्माण तथा बच्चे की जानकारी का दायरा बढ़ाना चाहिए। इस अवस्था में बौद्धिक प्रशिक्षण का गौण महत्व है। बच्चों की उचित शिक्षा में घर और नर्सरी स्कूल दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है।

(२) ६ और १४ वर्ष की आयु के बीच स्कूलों की शिक्षा बिल्कुल उदार होनी चाहिए। छात्रों को सब तरह का ज्ञान शामिल करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, पर वे निररे किताबी कौटे ही न बन जाएं; कसरत और खेलकूद भी शिक्षा के बंधे ही महत्वपूर्ण भाग हैं। इसके अलावा चरित्र के उचित प्रशिक्षण के बिना शिक्षा बधुरी रहती।

पर इन बिना उदार शिक्षा बिल्कुल नापाकी समझी जाती है। यह व्यावसायिक शिक्षा के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा पूरी होने के बाद आदमी आसानी से जीविका बना सके। इसके अलावा, किताबी शिक्षा हर विद्यार्थी के लिए उपयुक्त नहीं। ही सकता है कि यदि उसे कोई दस्तकारी सीखने का मौका दिया जाए तो वह चमक जाए। आधुनिक औद्योगिक समाजों में व्यावसायिक या शिल्प सम्बन्धी शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है।

(३) विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा, विज्ञान, कला और दर्शन की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है। पर यह सिर्फ उनको लिए होनी चाहिए जिनकी इसमें रुचि हो।

नागरिकता की शिक्षा—लोकतन्त्र के युग में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में, पढाई के अलावा, किये जाने वाले काम नागरिकता की शिक्षा देने हैं। इन कामों में सहयोग, मिलनसारता, सहिष्णुता, अनुशासन, स्वयं कर्तव्य, नेतृत्व, प्रशामन, स्वशासन, मार्गजनिक् भाषण कला, और सामाजिक सेवा की शिक्षा मिलनी है।



राज्य और शिक्षा—विषी समय शिक्षा को व्यक्ति का निजी मामला समझा जाता था । पर अब यह राज्य की जिम्मेदारी है क्योंकि आजकल राज्य लोकतन्त्रीय और मजदूरी राज्य है । लोकतन्त्रीय राज्य जनता का सेवक है । इसे अपने स्वामियों को शिक्षित करना पड़ता है । राज्य की दक्षता के लिए भी आवश्यक है कि इसके नागरिक शिक्षित हों । हो सकता है कि कोई आदमी इतना गरीब हो कि वह शिक्षा पर खर्च न कर सके । इसलिए राज्य को उसे शिक्षित करना चाहिए । इसके अलावा शिक्षा के आवश्यक व्यय भी राज्य ही अधिक अच्छी तरह कर सकता है ।

शिक्षा का महत्व—यह मनुष्य की पंगुवृत्ति को रोखती है और उसके बौद्धिक अंग का विकास करती है । सामाजिक जीवन में शिक्षा गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद देती है । यह आर्थिक उन्नति में भी सहायता देती है । सामाजिक और राजनीतिक जीवन को यह अधिक सौहार्दपूर्ण बनाती है । संशोधन में शिक्षा मानव जाति की उन्नति और सुख की कुञ्जी है ।

प्रश्न

QUESTIONS

- १ शिक्षा कितने कहते हैं ? इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए ?
1. What is 'education'? What should be its aim ?
२. शिक्षा में माता-पिता का क्या स्थान है ?
2. What is the role of parents in education ?
३. शिशुओं और बड़े उम्र के बच्चों को किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता होती है ?
3. What type of education do infants and children of schoolgoing age require ?
४. व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में युक्तियाँ दीजिए ।
4. Make out a case for vocational education
५. लोकतन्त्र के नागरिक के लिए शिक्षा का क्या महत्व है ?
5. What is the importance of education for a citizen of democracy ?
६. आज के नागरिक को किस प्रकार की शिक्षा चाहिए ?
6. What type of education does a citizen of today require ?
७. भारत में स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के पक्ष में युक्तियाँ दीजिए ?
7. Make out a case for female and adult education in India
८. शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए ?
8. Why should education be a responsibility of the state ?



पर ही किसी दावे को समाज द्वारा अधिकार माना जाएगा—

Handwritten mark

१. यह युक्ति-युक्त दावा होना चाहिए ।

२ दावा ऐसा होना चाहिए कि उसे नैतिक दृष्टि में उचित ठहराया जा सकता हो । चोरी करने, घराब पीने, गाली देने और हत्या या आत्महत्या करने के दावों को नैतिक दृष्टि में उचित नहीं ठहराया जा सकता । दूगरो और, आदमी जीने का, शिक्षा पाने का, और काम करने का दावा नैतिक रूप में कर सकता है ।

३ दावा स्वार्थपूर्ण न होना चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए कि इसकी पूर्ति से व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ हो । यह समाज द्वारा सामाजिक रूप में स्वीकृत होना चाहिए । उदाहरण के लिए, किसी आदमी की आत्महत्या करने का दावा स्वार्थपूर्ण दावा है । आत्महत्या आदमी को सब चिन्ताओं और परेशानियों से छुटकारा दे सकती है । पर यह समाज को उन लाभों से वंचित कर देगी, जो उसे इसके जीवन से मिलने । इसी प्रकार, भिक्ष मागने का अधिकार किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि भिखारी समाज पर बोझ है और वह सामाजिक जीवन में कुछ भी योगदान नहीं करता ।

४ उपर्युक्त विवेचन में यह परिणाम निश्चलता है कि वह दावा जो अपने में सबहित कर्तव्य को नहीं स्वीकार करता, अधिकार नहीं माना जा सकता । यह खालसा दावा होगा ।

५ जो दावा अधिकार माना जाना है वह सब जगह लागू हो सकता चाहिए । समाज के लिए यह अगम्य है कि वह अलग-अलग जादमियों की अवस्था में अलग-अलग दावों को मानते । लोगों के कुछ सामान्य दावों को भी अधिकार माना जा सकता है । अधिकारों का उपयोग सब नागरिकों द्वारा समान रूप में किया जाना चाहिए ।

क्या किसी अधिकार के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक है?—अधिकारों के लिए राज्य की स्वीकृति परम आवश्यक नहीं है । वे भी अधिकार हीं मकन है जिन्हें नैतिक दृष्टि में उचित ठहराया जा सकता है और जिन्हें समाज स्वीकार करता है । मान हो, यदि राज्य भी उन्हें मान ले और अपने कानूनों को हिस्सा बना ले तो अधिकारों का बल बड़ जाएगा । उस अवस्था में लोग अपने अधिकारों का उपयोग अधिक पक्के तौर से कर सकेंगे ।

अधिकारों का वर्गीकरण—अधिकारों को मोटे तौर से नैतिक और वैधिक (legal) अधिकारों में बाटा जाता है ।

नैतिक अधिकार—यदि किसी आदमी के दावे नैतिकता के आधार पर हैं और वे सिर्फ समाज द्वारा माने जाते हैं तो वे नैतिक अधिकार कहलाएंगे । नैतिक अधिकारों के पीछे जो अनुगति या बल है, वह लोकमत है, राज्य का प्राधिकार नहीं । नैतिक अधिकार स्थितिज अधिकार (potential rights) भी कहलाते हैं । उनमें अपने को राज्य से भी स्वीकार कराने की शक्ति नहीं होती । जो राज्य जनता का मित्र और गुभाकासी होने का दावा करता है वह उनके उन दावों की उपेक्षा नहीं कर सकता जो नैतिकता और लोकमत के आधार पर हैं । इसलिए सब नैतिक अधिकारों में

बाद में वैश्विक अधिकार बनने की प्रवृत्ति होती है। भारत में शिक्षा प्राप्ति का अधिकार अभी नैतिक अधिकार है। पर अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस आदि अन्य राज्यों में यह वैश्विक अधिकार है। भारत में भी कुछ समय बाद यह वैश्विक अधिकार बन जाएगा।

वैश्विक अधिकार—वैश्विक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य द्वारा अभि-स्वीकृत और प्रवर्तित किये जाते हैं। उनके पीछे राज्य का बल होता है। राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकार इसके कानूनों का अंग बन जाते हैं। उनका अतिक्रमण करने पर वेमा हों दंड दिया जाता है अर्थात् कानून का अतिक्रमण करने पर। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि सब वैश्विक अधिकार नैतिक दृष्टि में उचित ठहराये जा सकें हों। उदाहरण के लिए, यह सुविध्य है कि जात्रकाल अर्थात् वैश्विक सम्पत्ति का अधिकार नैतिक दृष्टि में उचित ठहराया जा सकता है। नागरिक शासन में हमें अधिकतर वैश्विक अधिकारों पर विचार करना है।

वैश्विक अधिकारों को फिर जानपद और राजनैतिक अधिकारों में बांटा जा सकता है।

जानपद अधिकार—जानपद अधिकारों का सम्बन्ध लोगों के जीवन और सम्पत्ति में है। वे सामाजिक जीवन की आरम्भिक शर्तों की पूर्ति की व्यवस्था करने हैं। उनके बिना मनुष्य जीवन सम्भव नहीं। उनमें जीवन और सम्पत्ति का अधिकार, मविदा करने का अधिकार, पुत्रा मोर मर्ग का अधिकार, बोलने का, मन रखने का मोर इच्छा होने का अधिकार, आदि आते हैं।

राजनैतिक अधिकार—राजनैतिक अधिकार जानपद अधिकारों में पृथक् होते हैं। प्रत्येक राज्य में अन्यदेशियों को राजनैतिक अधिकार निषिद्ध होते हैं। पर वह उन्हें जानपद अधिकार दे सकता है। इन अधिकारों का उपयोग सिर्फ नागरिकों द्वारा किया जाता है, और ये अधिकार नागरिकों को राज्य में अन्य मनुष्य मनुष्यों में पृथक् करते हैं। राजनैतिक अधिकार नागरिक को अपने राज्य के मामलों में हिस्सा लेने और उन्हें विनियमित करने के योग्य बनाते हैं। पर इन अधिकारों का पूरा और सामाजिक उपयोग सरकार के लोकायुक्तन आवे में ही सम्भव है। राजनैतिक अधिकारों में ये अधिकार शामिल हैं —

- (क) नागरिकता प्राप्त कर लाने के लिए शान्तिपूर्वक इच्छा होने का अधिकार।
- (ख) सरकार से अपने कर्तों को हूर करने के लिये अलग-अलग या सामूहिक रूप में प्रार्थना करने का अधिकार।
- (ग) मन देने का अधिकार।
- (घ) चुनाव के लिए मते होने का अधिकार।
- (ङ) कोई मरदारों पर धारण करने का अधिकार।

क्या नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज होती है ?

पहले यह कहा जाता था कि कुछ अधिकार मनुष्य को निरर्पित प्राप्त हैं। मनुष्य उन्हें लेकर ही पैदा हुआ था, और व उसी प्रकृति का वैसे ही हिस्सा है जैसे उसकी त्वचा का रंग। इन अधिकारियों को समाज और राज्य से भी अधिक प्रबल कहा जाता था। राज्य या समाज भी आदमी को उससे नैसर्गिक अधिकारों से न्यायन वंचित नहीं कर सकता। इन अधिकारों को तब तक कम भी नहीं दिया जा सकता जब तक व्यक्ति स्वयं राज्य को बना कराने का अधिकार न दे। इन नैसर्गिक और अन्याय्य अधिकारों का संक्षेप में 'जीवन, स्वार्थनता और सम्पत्ति' कहते थे।

नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धान्त १७ वीं और १८वीं शताब्दी में बहुत प्रचलित था। समाज विद्वान् सिद्धान्त के लेखकान इस बात प्रिय बनाया। पर आजकल यह सिद्धान्त नहीं माना जाता। जैसे कि हम परबल देव शुरुत आज आदमी को समाज से स्वतन्त्र कोई अधिकार नहीं है। इससे अलावा कुछ अधिकार नैसर्गिक रूप में परस्पर विरोधी हैं। उदाहरण के लिए, स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार। इनके अलावा, नैसर्गिक अधिकारों का कोई पूर्ण सूची भी नहीं जिन पर सब सहमत हो।

मूल अधिकारों का अर्थ—कुछ अधिकार प्रत्येक नागरिक के विनाम के लिए मौलिक महत्त्व के माने जाते हैं। आधुनिक लोकतन्त्रवाय राज्यों में इन अधिकारों को कभी-कभी संविधान का हिस्सा बना लिया जाता है और मूल अधिकारों का नाम दिया जाता है।

प्रायः संविधान में, जो देश का सर्वोच्च कानून होता है परिवर्तन के लिए लचीली-चोटी और विभेद प्रक्रिया अपनाती पड़ती है। जब अधिकार इनका हिस्सा बन जाते हैं, तब सरकार के लिए उन्हें वास्तुतः के सामान्य तरिके से कम करता या छीनना कठिन हो जाता है। बहुमत पक्षान्तरण होने पर अल्पमत का उनसे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। इस प्रकार, संविधान का हिस्सा बन जाने पर इन अधिकारों का बल बढ़ जाता है पर मूल शब्द का यह अर्थ न समझना चाहिए कि यह अधिकार अननिक्रम्य (inviolate) या निरुन्तर्ध (absolute) हो जाते हैं।

अधिकारों के साथ कर्तव्य अपने आप आ जाते हैं—इस मतमें यह प्रवृत्ति है कि हम अपने अधिकारों पर जोर देने हैं और अपने कर्तव्यों की परवाह नहीं करते। पर हम याद रखना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य एक साथ रहते हैं। कोई अधिकार बिना कर्तव्य के नहीं हो सकता। प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ जाता है। अधिकार और कर्तव्य एक निष्कल व दा पास्वों की तरह हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि मूल कोई चीज पालन का अधिकार है, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं दूसरों का भी वह अधिकार स्वीकार करूँ। यह सामाजिक व्यवहार का सरल लेकिन पटला नियम है। दूसरों से वह व्यवहार करा, जो तुम अपने से कराना चाहते हो।

सुदान पैदा करने की आजादी है। यह अविराट मानव वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है।

स्वतन्त्रता का अधिकार—स्वतन्त्रता का अधिकार जीवन के अधिकार का एक आवश्यक भाग है। बिना स्वतन्त्रता के जीवन अर्थहीन हो जाता है। स्वतन्त्रता का अधिकार बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण अधिकार है। इसके अन्तर्गत, अन्य कई अधिकार आते हैं, जैसे उपासना की स्वतन्त्रता-चलने-फिरने और साहचर्य, की स्वतन्त्रता, विचार और भाषण की स्वतन्त्रता वगैरे की स्वतन्त्रता। हम इन पर एक-एक करके विचार करेंगे।

उपासना की स्वतन्त्रता—यह एक आधुनिक अधिकार है। आधुनिक राज्य लौकिक या धर्म निरपेक्ष (secular) राज्य है। यह किसी भी धर्म से अपने आप को नहीं जोड़ता। उपासना के अधिकार में सब नागरिकों का अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने की आजादी ध्वनित होती है। यदि धार्मिक आचरण के साथ कोई आर्थिक या राजनैतिक गतिविधि भी सम्बन्धित है, तो इन गतिविधियों को विनियमित और अवरुद्ध करना राज्य के लिए पूर्णतया उचित होगा।

अवाध संचालन का अधिकार—इस अधिकार के अनुसार नागरिक को राज्य के क्षेत्र में कहीं भी आने-जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इसमें यह बात भी आ जाती है कि कोई व्यक्ति दोषपूर्णतया गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यह अधिकार भी अपरिच्छिन्न नहीं है। सरकार युद्ध के दिनों में या राष्ट्रीय आपात के समय नागरिकों के घूमने-फिरने की आजादी पर बहुत सी पाबन्दियाँ लगा सकती है।

सविदा करने का अधिकार—इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक को दूसरे नागरिक के साथ सविदा करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सविदा बार-बार और सामाजिक संगठन को दृढ़ करती है, और इसलिए समाज की प्रवृत्ति के लिए बहुत आवश्यक है। पर राज्य कुछ प्रकार की सविदाएँ करने की इजाजत नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, अपने आपको बेचकर दास बनाने की, या दासों का व्यापार करने की, या ऐसी सविदाएँ करने की इजाजत नहीं दे सकता, जिसमें रिश्तत देनी होती है। न राज्य ऐसी सविदाएँ करने दे सकता है, जिनमें उसकी सुरक्षा को खतरा हो।

साहचर्य का अधिकार—हम देख चुके हैं कि आदमियों को अपनी अनेक तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहचर्यों की आवश्यकता होती है। साहचर्य बनाना मनुष्य की महान प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम है। यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और हितों के अनुसार साहचर्य बनाने के लिए स्वतन्त्र न हो तो उसका पूर्ण विकास संभव नहीं। निस्सन्देह, ऐसे किसी साहचर्य को नहीं रहने दिया जा सकता जिसका लक्ष्य राज्य का तन्त्रा पलटना हो।

बोलने, छापने और इच्छा होने का अधिकार—बोलने के अधिकार का अर्थ यह है कि हर आदमी को सरकारी दखल से आजाद रहते हुए सोचने की और सार्वजनिक रूप में अपनी राय जाहिर करने की आजादी है। सरकार की नीतियों और कार्यों की

आलोचना भी इसमें आ जाती है। फिर, वोटों के द्वारा ही हम दूसरों को राय और अनुभव में लाम उठाते हैं। इस प्रकार, स्वतन्त्र भाषण का अधिकार नमाज की स्वस्थ प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर सामाजिक व्यवस्था के हित की दृष्टि में इस अधिकार पर भी राज्य के कानून ऐसी बात कहने पर दब देने हैं, जिनमें गतिशील नैतिकता दूषित होती हो, या लोगों को बदनाम किया जाता हो, या लोगों को अपराध के लिए मजबूत किया जाता हो, या राज्य के विरुद्ध झोठ फैलाया जाता हो। पर, ऐसी पाबन्धियों का अभिप्राय वैयक्तिक स्वतन्त्रता को कम करना नहीं है। वे पाबन्धियाँ हमसे को स्वतन्त्रता मृत्तिस्त्रित करने के लिए और राज्य की स्वायत्तता को रक्षा के लिए लागू की जाती हैं।

प्रेस या समाचार-पत्र के अधिकार का अर्थ यह है कि जो बात मनुष्य विक्षिप्तता को न बनना है, उसे प्रकाशित करने का उसे अधिकार। यह अधिकार बोलने के अधिकार में से ही निकलता है। प्रबुद्ध लोकमत बनाने में प्रेस बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। बोलने के अधिकार पर जो परिमोमाएँ हैं, वे छापने के अधिकार पर भी लागू होती हैं।

सम्पत्ति का अधिकार—सम्पत्ति का अधिकार आदमी का बहुत पुराना अधिकार है। तथ्य तो यह है कि राज्य का निर्माण ही लोगों को सम्पत्ति की रक्षा के लिए किया गया था। आगे धन्यों का सबसे उपयोग और उपभोग भी इस अधिकार के अन्तर्गत आता है। इसका यह भी अर्थ है कि आदमी उपहार या विनिमय द्वारा अपनी सम्पत्ति देने के लिए स्वतन्त्र है। कुछ वैयक्तिक सम्पत्ति नागरिक के व्यक्तित्व के स्वतन्त्र और पूर्ण विकास के लिए निरान्न आवश्यक है। पर वैयक्तिक सम्पत्ति के असीमित मन्त्र के अधिकार पर आवश्यक समाजवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण आगति उठानी आ रही है।

संरक्षित और भाषा का अधिकार—यह अधिकार किसी देश के अल्पसंख्यकों के लिए विशेष महत्व का है। प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को लोकतन्त्रीय देश में अपनी भाषा और संस्कृति के विकास के लिए स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

शिक्षा पाने का अधिकार—यह एक जापुनिक अधिकार है। १५० वर्ष पहले शिक्षा का एक वैयक्तिक मामला समझा जाता था। आजकल अपने नागरिकों की शिक्षा की सुविधाएँ देने के लिए राज्य को जिम्मेदार माना जाता है। लोकतन्त्र के नागरिकों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। यह उनकी समझने की शक्ति को बढ़ाती है और उनकी दृष्टिकोण विस्तृत करती है।

काम करने का अधिकार—यह भी एक जापुनिक अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक को बेरोजगारी में बचाया जाए। यह राज्य की जिम्मेदारी मानी जाती है कि वह हर नागरिक के लिए काम की व्यवस्था करे। इस अधिकार में यह बात भी ध्यान रखनी है कि हर मजदूर की निर्वह-मजदूरी निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। उसकी मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि वह अपने खन-खन का खर न्याय-संगत रूप में सुविधाजनक रख सके।

कानून के सामने बराबरी का अधिकार—इस अधिकार के अनुसार कानून हर नागरिक के लिए बराबर होना चाहिए और उसे जन्म, धन, रंग, मूलवश, धर्म या लिंग का कोई ध्यान न करना चाहिए।

मत देने का अधिकार—मत देने का अधिकार लोकतन्त्र का फल है। लोकतन्त्रीय राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार के चुनने में हिस्सा लेने का मौका होना चाहिए। इसी कारण राज्य को हर वयस्क मनुष्य को मत देने का अधिकार दिया जाता है। इस अधिकार के उपभोग के आजकल एकमात्र अपवाद अवयक्त, दिवानिए, अपराधी और अन्यदेशीय हैं।

सरकारी पद धारण करने का अधिकार—जिन नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उन मनुष्यों जन्म, धन, रंग, मूलवश, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना, राज्य के अधीन पदधारण करने का भी अधिकार है।

याचिका देने का अधिकार—जिसी राज्य के सब मनुष्यों का एक विशेष अधिकार है अपने शत्रुओं के निवारण के लिए सरकार को याचिका देना।

भारतीय नागरिकों के अधिकार—उपरोक्त सब अधिकार सब लोकतन्त्रीय राज्यों में नागरिकों को मिल जाने आवश्यक नहीं। भारत में अब तक शिक्षा पान का अधिकार और रोजगार पाने का अधिकार राज्य द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं। इसका कारण यह है कि हमारे राज्य के वित्तीय मसाधन अभी बड़े सीमित हैं। अब तब सरकार के लिए यह सम्भव नहीं कि वह भारत की विशाल आबादी के लिए आवश्यक मस्या में स्थूल कोल सके। वह हमारा राज्य, जिसकी अधिक अवस्था पिछड़ी हुई है, सब नागरिकों को रोजगार की ही गारंटी दे सकता है। तो भी ब्रिटिश शासन के दिनों की तुलना में औपल भारतवासी का आजकल बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। ब्रिटिश शासन में मत देने का अधिकार जनता के सिर्फ थोड़े से हिस्से को दिया गया था। बोलने की, मातृचय बनाने की, सम्मेलन की, और प्रेम की आजादी भी बहुत सीमित थी। राज्य के कुछ ऊंचे और महत्त्वपूर्ण पद भारतवासियों के लिए बिल्कुल बंद थे। अन्य पदों में भी राममाहों आदि के और धनी आश्रमियों के लड़कों को पहले लिया जाता था। स्वतन्त्र भारत में सब नागरिकों को समान रूप में ये अधिकार हैं। गरीब से गरीब नागरिक को भी राज्य के ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुँचने में कोई म्बाध नहीं है।

नागरिकता के कर्तव्य—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कर्तव्य अधिकारों के साथ अनस्य जुड़े रहते हैं। यदि कोई आदमी अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानता वह अच्छा नागरिक नहीं कहला सकता। अधिकार का आराम से उपभोग करना, यह ध्यान और भी आवश्यक कर देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

अधिकारों की तरह कर्तव्य भी वैधिक और नैतिक होने हैं। नैतिक कर्तव्य हमारी नैतिक शक्त के धारण हमारे पर आते हैं। उदाहरण के लिए हमारे ऊपर यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने सतों का ईमानदारी से प्रयोग करें। जब कोई कर्तव्य

लिए सदा तैयार रहना चाहिए। संक्षेप में, जिन आदमी को उसको महत्ता की आवश्यकता हो, और जो उसका पात्र हो, उसे महत्ता देना उसका कर्तव्य है।

माराश

— अधिकार किसे कहते हैं—लास्की ने अधिकारों की यह परिभाषा की है कि “सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएँ जिनके बिना कोई भी आदमी अपना अधिकतम विकास नहीं कर सकता।” इसका अर्थ यह है कि समाज को आदमी के व्यक्तिगत व पूर्ण विकास के लिए कुछ सुविधाओं का गारण्टी देनी होगी। ऐसी अवस्थाओं और सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं।

इस प्रकार अधिकार सामाजिक जीवन का एक परिणाम है। कोई भी स्वार्थ-पूर्ण, अपुस्तियुक्त और अनैतिक दावा अधिकार नहीं बन सकता। हर एक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा रहता है।

कोई दावा अधिकार तभी बन सकता है जब समाज ने उसका अनुमोदन कर दिया हो। हम समाज से स्वतन्त्र अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। राज्य द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं, यद्यपि कानून की शक्ति अधिकारों का बल बढ़ा देती है।

(१) नैतिक अधिकार—यदि किसी आदमी का दावा नैतिकता के आधार पर है और वह सिर्फ राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो उसे नैतिक अधिकार कहा जाएगा। उनके पीछे एवमात्र तारक लोकमत है। लोकमत का बल नैतिक अधिकारों को वैधिक अधिकारों में बदलवाने की प्रवृत्ति रखता है।

(२) वैधिक अधिकार—वैधिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य स्वीकार और परिवर्तित करता है। उनके अतिरिक्त पर राज्य दड देता है।

वैधिक अधिकारों को जानपद और राजनैतिक अधिकारों में बाटा जा सकता है। जानपद अधिकारों में जीवन, सम्पत्ति, सार्वजनिक, मविदा और उपासना आदि के अधिकार शामिल हैं। राजनैतिक अधिकारों में स्वतन्त्र रूप में भाषण और विचार प्रकाशन, सम्मेलन, याचिका, मतदान और राज्य के अधीन पदधारण के अधिकार शामिल हैं।

नैतिक या प्राकृतिक अधिकार या जन्मजात अधिकार कोई चीज नहीं होती। 'सारे समाज के हित की दृष्टि से किसी भी अधिकार को भीमित किया जा सकता है।

जो अधिकार सविधान का हिस्सा बना दिये जाते हैं, उन्हें और भी अधिक बल प्राप्त हो जाता है और वे मूल अधिकार कहलाने लवते हैं।

अधिकार कर्तव्यों की प्रवृत्ति करते हैं—कोई अधिकार ऐसा नहीं जिसके साथ कर्तव्य न जुड़ा हो। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पार्श्वों की तरह हैं, जो हमेशा साथ रहने हैं। यदि क का एक अधिकार है तो म का एक कर्तव्य है कि वह उस अधिकार का सम्मान करे। फिर क का अधिकार क का कर्तव्य भी है। यदि क को एक अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्तव्य है कि वह ल के वैश ही अधिकार का आदर करे। क का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग ईमानदारी से और समाज तथा राज्य के सर्वोत्तम हित की दृष्टि से करे। अन्तिम बात यह है कि राज्य के

प्रति, जो हमारे अधिकारों को पाएँगी देना है और रखा करता है, हम में से हरेक कुछ कर्तव्य है।

नागरिक के विविध अधिकार—प्राथमिक आधुनिक राज्य के नागरिक के निम्नलिखित जातपद और राजनैतिक अधिकार होते हैं।

जीवन का अधिकार, जिसमें आत्म-रक्षा और मजान वीर्य करने का अधिकार भी शामिल है, स्वतन्त्रता का अधिकार, इच्छानुसार उपामना का अधिकार, निर्वाण धूमने-फिरने का अधिकार, मविदा करने का अधिकार, बोल्ने का अधिकार, माह्वन बनाने का अधिकार, प्रेम की स्वतन्त्रता का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, मस्वृति और भाषा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, चानुन के मानने बराबरी का अधिकार, मन देने का अधिकार, सरकारी नौकर होने का अधिकार, और पाषिका देने का अधिकार।

नागरिकता के कर्तव्य—कर्तव्य भी वैधिक और नैतिक होते हैं। नैतिक कर्तव्य हमारी नैतिक ममत्त द्वारा हमारे ऊपर डाले जाते हैं। जब कर्तव्य चानुन द्वारा लिखित हो जाते हैं, तब वे नैतिक कर्तव्य बन जाते हैं। नागरिक के वैधिक कर्तव्य यह हैं. (१) राज्य के प्रति निष्ठा, (२) राज्य के चानुनों का पाठन, (३) राज्य को कर देना, (४) जुरी के रण में कार्य करना और (५) अपने बच्चों को शिक्षा देना।

नैतिक कर्तव्य ये हैं. (१) मन का ईमानदारी में प्रयोग करना, (२) सरकारी पद पर रहने हुए ईमानदारी और (३) गामात्रिक सेवा।

प्रश्न

QUESTIONS

- १ अधिकार किसे कहते हैं? किसी दावे के अधिकार बनने के लिए कौन-कौन सी शर्त आवश्यक है?
- 1 What is a 'Right'? What conditions are necessary for a claim to become a right?
- २ वैधिक और नैतिक कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से भेद कीजिए। क्या किसी अधिकार के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक है?
- 2 Distinguish clearly between legal and moral rights. Is state recognition necessary for a right?
- ३ "अधिकार कर्तव्यों को ध्वजित करने हैं" इसकी व्याख्या और विवेचना करो।
(५० वि० अर्सेल, १९४८, ५०)
- 3 "Rights imply duties" Explain and discuss. (P U April. 4S & 50)
- ४ 'अधिकार' और 'कर्तव्य' शब्दों की व्याख्या कीजिए। किसी आधुनिक राज्य के नागरिकों को प्राप्त कुछ अधिकारों का उल्लेख कीजिए।
(५० वि० अर्सेल, १९४९)

या

आधुनिक राज्य में किसी नागरिक के महत्त्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य कौन से हैं?
(५० वि० नवम्बर, १९५१)

4. Explain the terms 'Rights' and 'Duties' Mention some of the rights enjoyed by citizens of a modern state
(P U. April, 1949)

Or

What are the important rights and duties of a citizen in a modern state ?
(P U Sept, 1950)

५. अधिकार की परिभाषा कीजिए। प्रारम्भिक राज्य में प्राधुनिक राज्य को किन अधिकारों की गारण्टी देनी चाहिए ? (प० वि० नितम्बर, १९५१)
5. Give definition of 'right'. What rights in your opinion should be guaranteed by the state
(P U Sept, 1951)
६. अधिकारों की परिभाषा करो ? जनसद अधिकारों, राजनैतिक अधिकारों और नैतिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं ?
(प० वि० अप्रैल, १९५२)
6. Define 'Rights' What do you understand by Civil Rights, Political Rights and Natural Rights ?
(P.U April, 1952)
७. राज्य के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं ? (प० वि० अप्रैल, १९५३)
7. What are the obligations of the citizens towards the state ?
(P U April, 1953)
८. अधिकारों की परिभाषा करो ? क्या आत्मी को राज्य के ऊपर कोई अधिकार प्राप्त हो सकता है ? (प० वि० अप्रैल, १९५४)
8. Give a definition of Rights Can a man possess rights against the state ?
(P U April, 1954)

विधि, स्वाधीनता और समता—अपराध और दण्ड विधि या कानून

विधि का अर्थ और प्रकृति—'विधि' शब्द उन नियमों का निर्देश करता है जो मानवीय क्रियाओं के पथ प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य की सामाजिक प्रकृति यह चाहती है कि वह अपने अन्य प्राणी मनुष्यों के गण्य में बचने के कारणों आचरण के कुछ नियमों पर चले। यदि इन नियमों का सम्बन्ध मनुष्य की आंतरिक प्रेरक भावनाओं में है और वे उसके धन वरण की चीज हैं, तो वे नियम नैतिक नियम मन्गते हैं। यदि वे निकट उनकी बाह्य क्रियाओं में सम्बन्ध रखते हैं तो वे सामाजिक या राजनैतिक नियम होते हैं।

राजनैतिक नियमों और सामाजिक नियमों में अन्तर है। यदि कोई आदमी सामाजिक नियम को न माने तो उसके काम को समाज बुरा कहता है, पर इसके परिणामस्वरूप उसे कोई शारीरिक दण्ड नहीं मिलता। पर राजनैतिक नियम का अतिप्रमाण करने पर दण्ड मिलता है। इन राजनैतिक नियमों को ही विधि या कानून कहते हैं। राजनैतिक नियम या विधियाँ राज्य द्वारा बनायी जाती हैं और उनके पीछे समता प्राधिकार होता है। हार्लेड ने राजनैतिक नियम या विधि की यह परिभाषा की है कि 'बाहरी मानवीय क्रिया का व्यापक नियम, जो सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता द्वारा लागू किया जाता है।' नागरिक शासन के विद्यार्थी के रूप में हमारा समता इसी प्रकार के नियम, अर्थात् विधि, में है। राजनैतिक नियमों, अर्थात् विधियों, के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए —

(१) विधि राज्य का एक आदेश है, जो इसकी सर्वोच्च सत्ता से समाहित होता है। इस अर्थ में विधि कस्टम (custom) में भिन्न है। कस्टम के पीछे मित्र लोकमत का बल होता है। राज्य के क्षेत्र में मौजूद सब आदमियों, पशुओं और शाहसकों को इसके आदेशों का पालन करना चाहिए। उनको और से आज्ञा का पालन न किए जाने पर राज्य दण्ड देता है।

(२) राज्य के अत्याचार और कोई प्राधिकरण विधि जारी नहीं कर सकता। विधि सर्वोच्चता का फल है और सर्वोच्चता मित्र राज्य को प्राप्त है।

(३) कोई विधि स्वयं राज्य पर उपनकारी नहीं होती। राज्य किसी भी

समय किन्ना विधि को मसौदा या निरस्त (repeal) कर गता है ।

(४) विधि मनुष्यों की निरंकुश शक्ति के विनियमित करती है और साधारणतया शक्ति के प्रेरक भावों पर विचार नहीं करती ।

विधि के स्रोत—राज्य की ही तरह विधि भी इतिहास की ही उपज है । यह विकास की अनेक मजिलों में से गुजरी है और कई बारकों ने इसके विकास में योग दिया है । ये सब कारक विधि के स्रोत कहलाने हैं । पर यह याद रखना चाहिए कि बाहरी मानवीय आचरण के नियमों का स्रोत चाहे कुछ भी हो, पर यदि उन नियमों को सर्वोच्च प्रभु की मजूरी प्राप्ता न हो तो उन्हें विधि का बल नहीं मिल सकता । विधि के स्रोत निम्नलिखित बताए जा सकते हैं ।—

रूढ़ि—रूढ़ि विधि के सबसे पुराने स्रोतों में से एक है । रूढ़ि । आचरण के ये नियम हैं जो किसी समाज में आदा के कारण या किसी उपयोगिता की दृष्टि में स्थापक रूप में स्वीकार कर लिए जाने हैं । राज्य इन नियमों को बनाने में कोई हिम्मा नहीं लेता । वे आम प्रयोग और स्वीकृति के कारण बढने हैं और समाज में फँसे हैं । पहले के राज्यों में रूढ़िया ही एक मात्र विधिया थी । आज भी प्रत्येक राज्य में उसकी विधि प्रणाली का बहुत बड़ा हिस्सा रूढ़ि पर आधारित है । पर प्रत्येक रूढ़ि विधि प्रणाली को अन्तर्गत नहीं आती । राज्य निरंकुश शक्तियों को स्वीकृत करता है जो समाज के जीवन के लिए उपयोगी और सुविधाजनक पाई जाती हैं ।

धर्म—पहले के अधिनिर्गत समाजों में जीवन के गद नियमों के पीछे धर्म का आदेश होता था और रूढ़ि तथा धर्म को एक दूसरे से मिला दिया जाता था । मुस्लिम राज्यों की विधिया कुरान से निकली हैं । ईसाई विधि और हिन्दू विधि भी बहुत दूर तक अपने धर्म ग्रंथों से निकली हैं ।

न्यायिक निरुद्ध—संघटन के अनुसार, राज्य का जन्म विधि के सृष्टा के रूप में नहीं हुआ, बल्कि रूढ़ि के निर्वाचन वर्ता और लागू करने वाले के रूप में हुआ । समाज की परिस्थितिया बदल जाने पर कोई रूढ़ि प्रायः कुछ स्थितियों और अवस्थाओं की दृष्टि से पुष्टिपूर्ण पाई गई । ऐसी परिस्थितियों में न्यायाधीशों की मौजूदा रूढ़ि का निरुद्धन दृग तरह करके कि कोई नया मापला उनके अन्तर्गत आजाय, सभी सभी अपने विनिश्चयों के द्वारा नई विधिया पैदा कर देने से । जहाँ कोई रूढ़ि नहीं थी, वहाँ न्याय और साम्य (Equity) के सिद्धान्त लागू किये जाते थे । इंग्लैंड में सारी की सारी रूढ़ि विधि इसी प्रकार पैदा हुई ।

सामाजिक भाव्य—वृद्ध के देशों में महान विधि सारणी हुए हैं । उनसे धर्मों में महान विधि सम्बन्धी सिद्धान्त और अभिमत (opinions) हैं । इन अभिमतों का समय समय पर बदलाव और न्यायाधीशों पर बड़ा असर पडा है । इन प्रकार उन्होंने विधि प्रणाली को एक रूप दिया है ।

विधान (Legislation)—आधुनिक काल में विधिया मुद्दयन विधान

मण्डली द्वारा अधिनियमित की जाती है। तब्य तो यह है कि आज विधानमण्डल विधि के एक मात्र स्रोत बनते जाते हैं। सदियों की भी सुनिदिष्ट लिखित विधियों का रूप दिया जा रहा है।

विधि के प्रकार—मंडल के अनुसार विधि को निम्नलिखित वर्गों में बाटा जा सकता है—

१. वैयक्तिक विधि (Private law) जो एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के सम्बन्धों को विनियमित करता है।

२. लोकविधि, जो राज्य के साथ व्यक्ति के सम्बन्धों को विनियमित करती है।

३. अन्तर्राष्ट्रीय विधि, जो एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के सम्बन्धों को विनियमित करती है।

१. वैयक्तिक विधि—वैयक्तिक विधि के अधीन किसी मामले में, निजी व्यक्ति पक्ष होते हैं। राज्य सिर्फ निर्णायक के रूप में कार्य करता है। राज्य व्यक्ति तयों के सब सम्बन्धों को विनियमित नहीं करता। यह सिर्फ उन सम्बन्धों को विनियमित करता है जो सार्वजनिक महत्व के हैं। सारे की सारी व्यवहार विधि (Civil law) इस वर्ग के अन्तर्गत आती है।

२. लोक विधि—लोक विधि के अधीन मूकदमों में एक पक्ष राज्य होता है। यह विधि एक तो राज्य के सगठन और नायों के सम्बन्ध में होती है, और दूसरे यह राज्य और उसके नागरिकों के सम्बन्ध विनियमित करती है।

लोक विधि के फिर ये उपविभाग किए जा सकते हैं—

(क) संवैधानिक विधि (Constitutional law)—संवैधानिक विधि सामान्यविधि से सर्वथा भिन्न होती है। यह सरकार की संरचना, परिचालन, कार्यों और शक्तियों की परिभाषा करती है। विधानमण्डल, जो सामान्य विधि बनाता है, स्वयं संवैधानिक विधि में पैदा होता है।

(ख) प्रशासनिक विधि—लोक विधि का यह भाग विधि को लागू करने वाले शरीरों के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। यह आदर्शों को यह भी बताता है कि यदि कार्यपालिका द्वारा उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया जाए तो उसके पास क्या उपचार हैं।

(ग) दण्ड विधि—यह लोक विधि की एक शाखा है जो व्यक्ति या व्यक्तियों के उन कार्यों को निर्दिष्ट करती है, जो राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। अपराध राज्य के विरुद्ध जुर्म है। राज्य दण्डविधि के अनुसार अपराधों पर अपराध के लिए मुकद्दमा चलाता है।

३. अन्तर्राष्ट्रीय विधि—यह एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के सम्बन्धों को विनियमित करती है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि न तो अधिनियमित की जाती है, और न किसी सर्वोच्च न्यायिककरण द्वारा प्रवर्तित की जाती है। इसके पीछे विभिन्न राज्यों

में मौजूद लोकमत ही होता है। यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि या पालन करने से इनकार करदे तो उसे दण्ड नहीं मिलेगा।

विधि और नैतिकता का सम्बन्ध

विधि और नैतिकता का एक दूसरे से निकट सम्बन्ध है, दोनों में बहुत सी बातों में भेद भी है। पहले हम विधि और नैतिकता में भेद करने वाली बातों पर विचार करेंगे।

भेद करने वाली बातें—विधि और नैतिकता अन्तर्वस्तु, पृष्ठबल और सुनिश्चितता (contents, sanction and definiteness) में एक दूसरे से भिन्न हैं। जहाँ तक अन्तर्वस्तु और अभिक्षेत्र (scope) का सम्बन्ध है, विधि मनुष्य के गिर्फ बाहरी कार्यों से सम्बन्ध रखती है और इसे उसके विचारों, प्रेरक भावों और आशयों से कोई वास्ता नहीं। विधि विचारों और प्रेरक भावों पर तब ही विचार करती है, जब वे क्रियाओं में दिखाई देते हैं। झूठ बोलना नैतिक दृष्टि से बुरा है, पर विधि में यह तब ही बुरा है जब न्यायालय में शपथ लेकर बोला जाए। ग़ुस्सा करना अनैतिक है, पर विधि में यह तभी बुरा है, जब मैं गुस्से में किसी को चोट पहुँचाऊँ। नैतिकता के अनुसार धोरी की बात सोचना भी गलत है, पर विधि किसी आदमी को तभी दण्डित करेगी, जब यह वास्तव में धोरी करे।

जहाँ तक पृष्ठबल (sanction) में भेद का सम्बन्ध है, विधि सरकार द्वारा लागू की जाती है और इसके अपालन पर दण्ड दिया जाता है। इसके पीछे बल की सत्ता है। नैतिकता के नियम का अतिभ्रमण करने पर सार्वभौमिक दण्ड या जुर्माना नहीं होता। अनैतिक कार्य पर समाज अधिक से अधिक, आलोचना कर सकता है। नैतिकता के पीछे सिर्फ लोकमत की शक्ति है।

तीसरे, विधि स्वरूप में सुनिश्चित और सावधिक होती है। विधि एक समान सब पर लागू होती है। दूसरी ओर, नैतिकता स्वरूप में अनिश्चित और व्यक्तिगत होती है। यह अलग-अलग व्यक्ति के माप जलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, एक आदमी रिश्वत लेने को सर्वथा अनैतिक मान सकता है, और दूसरा इसे स्वीकार करने को सर्वथा उचित समझ सकता है।

चौथे, नैतिक विधियाँ या नियम सही और गलत, न्याय तथा अन्याय, के निरपेक्ष मानदण्ड बनाने हैं, पर विधि सामाजिक औचित्य (expediency) के मानदण्ड पर चलती है। जिस काम का विधि निषेध करती है, हो सकता है कि वह अनैतिक कार्य न हो, पर वह जनता के मंगल और क्षेम के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, तेज मोटर चलाना अनैतिक नहीं है, पर वह विधि द्वारा निषिद्ध है।

विधि और नैतिकता का सम्बन्ध—विधि और नैतिकता इन दोनों का उद्गम एक था। प्राचीन काल के समाजों में नैतिक नियमों और सामाजिक

धास्यता के नियमों में कोई भेद नहीं किया जाता था। धर्म-धीरे उनमें भेद किया जाने लगा। अनेक भेदों के होने हुए भी इन दोनों का सम्बन्ध आज भी बड़ा घनिष्ठ बना हुआ है। राज्य की विधियों के लिए आवश्यक है कि वे नैतिक नियमों के विपरीत न हों। उनके न्यायानुसंगत पालन के लिए यह आवश्यक है कि वे लोगों में मौजूद नैतिकता के मानदण्ड के विरुद्ध न हों। उदाहरण के लिए, शराब पीने के विरुद्ध बार्डर् गैर विधि का उन क्षेत्रों में पालन होना कठिन है जिनमें शराब पीने की आदत लोगों में बहुत आम है, पर विविधा नैतिकता का अनेकित मानदण्ड बनाने में भी बड़ा कार्य करनी है। टिमो जमाने में सती प्रथा और बाल विवाह बहुत आम चीज थी। कानून बन जाने पर ही ये प्रथाएँ रहीं।

स्वतन्त्रता या स्वाधीनता

स्वतन्त्रता किसे कहते हैं—स्वतन्त्रता या स्वाधीनता है जो कुछ आदमी चाहे वह करने की आजादी, पर ऐसी स्वतन्त्रता अगम्य है। हम कुछ नियमों के बिना इच्छा नहीं रह सकते और नियमों का मतलब है हमारे कार्यों पर श्रावणें। इस प्रकार नातिकुल्य साम्राज्य जीवन तभी सम्भव है, यदि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निर्दिष्ट स्वतन्त्रता हो। दूसरी ओर, यदि हर आदमी अपनी इच्छानुसार काम करना चाहे, तो लोगों में लडाइयाँ भी होनी हैं। इसलिए स्वतन्त्रता का अर्थ है जब कुछ करने की आजादी बनने कि इनके दूगने की आजादी को हानि न पहुँचे।

स्वाधीनता के प्रकार—स्वाधीनता शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है इसलिए इनके अर्थ को साफ तौर से समझने के लिए हमें इनके अनेक अर्थों में भेद करना चाहिए।

प्राकृतिक या नैसर्गिक स्वाधीनता—अवरोध या नियन्त्रण से आजादी को नैसर्गिक स्वाधीनता कहते हैं। यह मनुष्य के अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के असली अधिकार को बताती है पर ऐसी स्वाधीनता सिद्ध जगली पशुओं में है। कहा जाता है कि यह अवस्था समाज सुविधा विद्वान की काल्पनिक निर्धारणों में मनुष्यों में भी मौजूद थी। यह स्वाधीनता समाज में रहते हुए मनुष्यों में कभी नहीं हो सकती। नैसर्गिक स्वाधीनता का विचार मुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, पर व्यवहार में यह कभी भी नहीं जा सकता। यदि इसे व्यवहार में लाया जाय तो सबसे पहले आदमी को ही ऐसी स्वाधीनता मिल सकती है। अन्य लोग इस एक आदमी के गुलाम मात्र होंगे, और उन्हें कोई स्वाधीनता नहीं होगी। फिर सबसे पहले आदमी को भी नैसर्गिक स्वाधीनता स्यायी रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। यह उमे तब तक ही मिल सकती है, जब तक कोई अधिक बलवान आदमी उमे न मिले। इस प्रकार नैसर्गिक स्वाधीनता सब के लिए नहीं हो सकती।

नागरिक स्वाधीनता—नैसर्गिक स्वाधीनता से विपरीत नागरिक स्वाधीनता वह स्वाधीनता है जो मनुष्य को समाज में मिलती है। यह स्वाधीनता माना में

सीमित हो सकती है, पर यह वास्तविक, स्थायी, और समाज के सब सदस्यों के लिए समान होती है। यह सब के लिए वास्तविक, स्थायी, और समान हम वारण होती है क्योंकि इसका उपभोग विधि के संरक्षण में किया जाता है। इन प्रकार नागरिक स्वाधीनता राज्य द्वारा जनित और रक्षित होती है।

नागरिक स्वाधीनता राज्य द्वारा स्वीकृत और प्रवर्तित अधिकारों के कुल योग को कहते हैं। जीवन और सम्पत्ति का अधिकार नागरिक स्वाधीनता के उदाहरण हैं।

राजनैतिक स्वाधीनता—राजनैतिक स्वाधीनता का अर्थ है नागरिकों को सरकार के चुनाव और परिचालन में हिस्सा लेने की आजादी। इसमें मत देने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, मन्त्री पद धारण करने का अधिकार, और सरकार की नीति पर आजादी से विचार करने और उसकी आलोचना करना शामिल है।

सांविधानिक स्वाधीनता—यदि स्वाधीनता की, संविधान द्वारा, सरकार को दखलदाजी से भी रक्षा की जाती है तो इसे सांविधानिक स्वाधीनता कहते हैं।

आर्थिक स्वाधीनता—आर्थिक स्वाधीनता का अर्थ है अभाव के छुटकारा। आर्थिक स्वाधीनता के बिना, और सब प्रकार की स्वाधीनता निरर्थक हो जाती है। आजादी तब तक वास्तविक नहीं हो सकती जब तक आदमी को जीवन धारण की आवश्यकताएँ मिलनी सुनिश्चित न हों। हर आदमी को वरोजगारी में यचना चाहिए। उसे निर्वाह मजदूरी भी सुनिश्चित रूप में मिलनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्वाधीनता—यह एक राष्ट्रियता में आरंभ लोगों के लिए आजाद, अनाश्रित और सर्वोच्च राज्य को सूचित करती है। राष्ट्रीय स्वाधीनता अन्य सब प्रकार की स्वाधीनता से अतिरिक्त और पूर्ण उपयोग के लिए परम आवश्यक है। यह नागरिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वाधीनता का मूल है।

विधि और स्वाधीनता का सम्बन्ध—जब से राज्य का जन्म हुआ है, तब से ही विधि और स्वाधीनता की समस्या एक महत्वपूर्ण विषय रही है। व्यक्तिवादी, अराजकनावादी, सिडिकेलिस्ट और बहुत से अन्य मतधारियों का यह कहना है कि स्वाधीनता और विधि में सामंजस्य नहीं हो सकता। ऊपरी दृष्टि में देखने वाले को भी विधि और स्वाधीनता शब्द एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होंगे, क्योंकि विधि का मतलब है अवरोध लगाना, और स्वाधीनता का अर्थ है अवरोधों का न होना। पर यदि हम स्वाधीनता का अर्थ नागरिक स्वाधीनता लेंगे तो विरोध शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। यदि विधि और स्वाधीनता एक दूसरे के विरोधी होंगे तो राज्य कभी का खत्म हो गया होता। यह तथ्य ही कि यह इतने समय तक कायम रहा है और अब भी कायम है, प्रदर्शन करता है कि दोनों में कोई विरोध नहीं है।

विधि और स्वाधीनता परस्पर विरोधी तो हैं ही नहीं। ये अमल में महत्वपूर्ण हैं। तथ्यतः नागरिक स्वाधीनता विधि द्वारा रक्षा की गई है। विधि ही नैतिक

स्वाधीनता की शुरु है। हम पढ़ते ही देख चुके हैं कि नैसर्गिक स्वाधीनता कोई स्वाधीनता नहीं, बसोकि यह अपिकतर कालान्तर और अस्थायी है। यह सिद्धे घोड़े से लोगो के लिए है। जो चीज वास्तविक, स्थायी और पक्की है वह नागरिक स्वाधीनता है। विधि ही नागरिक स्वाधीनता को वास्तविक और स्थायी बनाती है। नागरिक स्वाधीनता मीमित प्रकार की स्वाधीनता हो सकती है और इसके अनन्त वह मर आजादी है, जो मनुष्य और समाज के पूर्ण और अनुमंसी विकास के लिए वाछनीय है। आदमी समाज और राज्य के सदस्य के रूप में जिन अनेक अधिकारों का उपयोग करता है, वे विधि की देन हैं। ये अधिकार आदमी को दूसरे लोगो के व्यक्तित्व के विकास में बिना बाधा डाले अपने व्यक्तित्व का विकास करने की पूरी स्वाधीनता देते हैं। विधि न हो तो आदमी के व्यक्तित्व का विकास तो हो ही नहीं सकता, अपने जीवन को भी हंगामा खतरा बना रहेगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विधि स्वाधीनता की मित्र है।

पर इसमें हमें यह न भ्रम लेना चाहिए कि विधि सदा स्वाधीनता की मित्र होती है। जहां सरकार और समाज का गठन सधमुच लोकतंत्रीय होता है, वहां यह निश्चित रूप से स्वाधीनता की मित्र होती है, पर जिन देशों में सरकार बन्ध-देशीय होती है, उनमें विधि स्वाधीनता की मित्र नहीं होती। विधि और स्वाधीनता का उन समाजों में भी मेल नहीं बैठता जहां सामान एक या कुछ घोड़े से व्यक्तियों के हाथों में होता है।

विधि और स्वाधीनता के संबंध के प्रथम में दो बातें और याद रखनी चाहिए, प्रथम तो विधि द्वारा नागरिकों पर लगाए गए अवरोध सब आदमियों के लिए समान होने चाहिए और पूर्ण निष्पक्षता से लागू किए जाने चाहिए। दूसरी बात यह कि वे अवरोध युक्तियुक्त होने चाहिए और समाज को उनके औचित्य का विश्वास होना चाहिए। वे बातें न होने पर विधि और स्वाधीनता में मेल नहीं रह सकता। उन अवस्था में लोग विधि को बार बार चुनौती देंगे।

समता

समता एक और शब्द है जिसे प्रायः लोग गलत रूप में समझते हैं। यह बहना तो ठीक है कि सब मनुष्यों को जन्म से गान इन्द्रिया मिलती है। उनमें शारीरिक बल, इच्छाएं बागनाएं और मानसिक योग्यताएं भी एक-सो ही मालूम होती हैं। इसलिए इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सब आदमियों के साथ एक-सा व्यवहार होना चाहिए। पर समता का यह विचार अनिर्जित विचार है और इसका तर्कों से मेल नहीं बैठता। समार में कोई दो वस्तुएं एक-सी नहीं होती। मनुष्य भी अपने शारीरिक और मानसिक गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस प्रकार, हम यह कह सकते हैं कि मनुष्यों में एक प्रकार की नैसर्गिक विषमता है। इन नैसर्गिक विषमताओं को दूर कर देना मनुष्य की शक्ति के बाहर है, चाहे वह अपने लिए

कितना भी यत्न करे। पर नैसर्गिक विषमताओं के अलावा मनुष्यकृत विषमताएँ भी हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा हटाया जा सकता है। जन्म, धन-दौलत, मूलवश, (race), धर्म, रंग, जाति या वर्ग, और लिंग के भेद भाव पर आधारित विषमताएँ मनुष्यकृत विषमताएँ हैं।

इस प्रकार नागरिक शास्त्र में जब हम समता की बात कहते हैं तब इतने हमारा अभिप्राय मनुष्यकृत विषमताओं को खत्म करना ही होता है। नागरिक शास्त्र में हमारी समता की अवधारणा यह मानकर चलनी है कि प्रकृति द्वारा जनित विषमताएँ सदा बनी रहेंगी। समता शब्द को जिस रूप में अब हम समझते हैं, उसमें इसका अर्थ होगा :—

(१) विधि के समक्ष समता।

(२) एक-ही अहंताओं वाले सब आदमियों को और किसी बात का विचार किए बिना समान अवसर देना।

यह निस्संदेह सच है कि समान अवसर दिए जाने के बाद कुछ लोग अपनी नैसर्गिक योग्यता द्वारा औरो से बहुत आगे बढ़ जाएँगे। समान अवसर का अर्थ एक ही व्यवहार नहीं है।

स्वाधीनता और समता में सम्बन्ध

यदि स्वाधीनता का अर्थ नैसर्गिक स्वाधीनता हो और समता का अर्थ व्यवहार, कार्य और पुरस्कार की अभिन्नता हो, तो स्वाधीनता और समता एक दूसरे के विरोधी होंगे। नैसर्गिक स्वाधीनता समता की विरोधी है क्योंकि यह सबके लिए समान नहीं हो सकती। इसी प्रकार सब व्यक्तियों की योग्यता अहंता पर बिना विचार किए सीधी समानता का अर्थ वास्तव में योग्य व्यक्तियों को स्वाधीनता से वंचित करना होगा क्योंकि उस अवस्था में मूर्ख और बुद्धिमान को समान पुरस्कार मिलेगा पर जिन अर्थों में स्वाधीनता और समता शब्दों को नागरिक शास्त्र में प्रयुक्त किया जाता है, उन अर्थों में ये एक दूसरे की विरोधी नहीं। जन्म, धन-दौलत, मूलवश, धर्म, जाति या वर्ग, रंग और लिंग पर आधारित मनुष्यकृत विषमताओं को हटाना और इन बातों का बिना विचार किए सब आदमियों को समान अवसर देना लोगों की स्वाधीनता में वृद्धि करता है। फिर, नागरिक शास्त्र में समता का जो अवधारण है उसका लक्ष्य उन लोगों को समान करना नहीं है जो निस्संशय असमान हैं या जिनमें अलग-अलग अहंताएँ और योग्यताएँ हैं। इसलिए हमका लक्ष्य वस्तुतः समर्थ लोगों की स्वाधीनता को कम करना नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता और समता एक दूसरे की विरोधी नहीं हैं।

अपराध और दण्ड

अपराध और इनके दण्ड की समस्या सब युगों और सब देशों में रही है, चाहे वह काल या देश कितना ही अच्छा रहा हो। इसकी कारण यह सत्य है कि मनुष्य

स्वाधीनता की शुरु है। हम पहले ही देख चुके हैं कि नैसर्गिक स्वाधीनता कोई स्वाधीनता नहीं, क्योंकि यह अधिकतर काल्पनिक और अस्थायी है। यह सिद्ध हो चुके से लोगों के लिए है। जो चीज वास्तविक, स्थायी और पक्की है वह नागरिक स्वाधीनता है। विधि ही नागरिक स्वाधीनता को वास्तविक और स्थायी बनाती है। नागरिक स्वाधीनता सीमित प्रकार की स्वाधीनता हो सकती है और इसके अंतर्गत वह सब आजादी है, जो मनुष्य और समाज के पूर्ण और चतुर्मुखी विकास के लिए वाञ्छनीय है। आदमी समाज और राज्य के सदस्य के रूप में जिन अनेक अधिकारों का उपभोग करता है, वे विधि की देन हैं। ये अधिकार आदमी को दूसरे लोगों के व्यक्तित्व के विकास में बिना बाधा डाले अपने व्यक्तित्व का विकास करने की पूरी स्वाधीनता देते हैं। विधि न हो तो आदमी के व्यक्तित्व का विकास तो हो ही नहीं सकता, उसके जीवन को भी हमना खराब बना रहेगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विधि स्वाधीनता की मित्र है।

पर हमसे हमें यह न समझ लेना चाहिए कि विधि सदा स्वाधीनता की मित्र होती है। जहाँ सरकार और समाज का गठन मनुष्य लोकतंत्रीय होता है, वहाँ यह निश्चित रूप से स्वाधीनता की मित्र होती है, पर जिन देशों में सरकार अल्प-देशीय होती है, उनमें विधि स्वाधीनता की मित्र नहीं होती। विधि और स्वाधीनता का उन समाजों में भी मेल नहीं बैठता जहाँ शासन एक या कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में होता है।

विधि और स्वाधीनता के मूल के प्रयोग में दो बातें और याद रखनी चाहिए; प्रथम तो विधि द्वारा नागरिकों पर लगाए गए अवरोध सब आदमियों के लिए समान होने चाहिए और पूर्ण निष्पक्षता में लागू किए जाने चाहिए। दूसरी बात यह कि ये अवरोध युक्तिपूर्ण होने चाहिए और समाज को उनके जीवन का विरुद्ध होना चाहिए। वे बातें न होने पर विधि और स्वाधीनता में मेल नहीं रह सकता। उन अवस्था में लोग विधि को बार बार चुनौती देंगे।

समता

समता एक और शब्द है जिन प्रायः लोग मूल रूप में समझते हैं। यह महत्त्व तो ठीक है कि सब मनुष्यों को जन्म से सब इतिहास मिलती है। उनमें धार्मिक अंग, इच्छाएँ, सामान्य और मानसिक योग्यताएँ भी एक-सी ही मालूम होती हैं। इसलिए इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सब आदमियों के साथ एक-सा व्यवहार होना चाहिए। पर समता का यह विचार अनिश्चित विचार है और इसका तर्कों से मेल नहीं बैठता। मरार में कोई दो मनुष्य एक-सी नहीं होतीं। मनुष्य भी अपने शारीरिक और मानसिक गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस प्रकार, हम यह कह सकते हैं कि मनुष्यों में एक प्रकार की नैसर्गिक विषमता है। इन नैसर्गिक विषमताओं को दूर कर देना मनुष्य की क्षमता के बाहर है, यह वह इनके लिए

कितना भी पल करे। पर नैसर्गिक विषमताओं के अलावा मनुष्यकृत विषमताएँ भी हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा हटाया जा सकता है। जन्म, धन-दौलत, मूलवश, (race), धर्म, रंग, जाति या वर्ग, और लिंग के भेद भाव पर आधारित विषमताएँ मनुष्यकृत विषमताएँ हैं।

इस प्रकार नागरिक शासन में जब हम समता की बात कहते हैं तब इसमें हमारा अभिप्राय मनुष्यकृत विषमताओं को खत्म करना ही होता है। नागरिक शासन में हमारी गणना की अवधारणा यह मानकर बनती है कि प्रकृति द्वारा जनित विषमताएँ सदा बनी रहेंगी। समता शब्द को जिस रूप में अब हम समझते हैं, उसमें इसका अर्थ होगा—

(१) विधि के समान समता।

(२) एन-जी अहंताओं वाले सब आदमियों को और निजी धन का विचार किए बिना समान अवसर देना।

यह निस्संदेह सच है कि समान अवसर दिए जाने के बाद कुछ लोग अपनी नैसर्गिक योग्यता द्वारा औरों से बहुत आगे बढ़ जाएँगे। समान अवसर का अर्थ एक ही व्यवहार नहीं है।

स्वाधीनता और समता में सम्बन्ध

यदि स्वाधीनता का अर्थ नैसर्गिक स्वाधीनता हो और समता का अर्थ व्यवहार काय और पुरस्कार की अभिन्नता हो, तो स्वाधीनता और समता एक दूसरे के विरोधी होंगे। नैसर्गिक स्वाधीनता समता की विरोधी है क्योंकि यह सबके लिए समान नहीं हो सकती। इसी प्रकार सब व्यक्तियों की योग्यता अहंता पर बिना विचार किए सीधी समानता का अर्थ वास्तव में योग्य व्यक्तियों की स्वाधीनता से वंचित करना होगा क्योंकि उस अवस्था में मूर्ख और बुद्धिमान को समान पुरस्कार मिलेगा पर जिन अर्थों में स्वाधीनता और समता शब्दों का नागरिक शासन में प्रयुक्त किया जाता है, उन अर्थों में वे एक दूसरे की विरोधी नहीं। जन्म, धन-दौलत, मूलवश, धर्म, जाति या वर्ग, रंग और लिंग पर आधारित मनुष्यकृत विषमताओं को हटाना और इन बातों का बिना विचार किए सब आदमियों को समान अवसर देना लोगों की स्वाधीनता में वृद्धि करता है। फिर, नागरिक शासन में समता का जो अवधारण है उसका लक्ष्य उन लोगों को समान करना नहीं है जो नितर्गत असमान हैं या जिनमें जलग-जलग अहंताएँ और योग्यताएँ हैं। इसलिए इसका लक्ष्य वस्तुतः समान लोगों की स्वाधीनता को कम करना नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता और समता एक दूसरे की विरोधी नहीं हैं।

अपराध और दण्ड

अपराध और हमारे दण्ड की समस्या सब युगों और सब देशों में रही है, चाहे वह बाल या देश कितना ही अच्छा रहा हो। इसका कारण यह सत्य है कि मलती

करना मनुष्य का स्वभाव है। कभी-कभी अच्छे चरित्र और आशयो वाला आदमी भी अपराध कर देता है इसका कारण यह है कि अमन आदमी के लिए कानून के बारे में सब कुछ जानना कठिन है। पर कानून का अज्ञान कोई दलील नहीं। इसलिए जो आदमी भी अपराध करता है, चाहे वह जानते हुए करे या अनजाने हुए, उसे दण्डित होना पड़ेगा।

अपराध की समस्या से राज्य, समाज और व्यक्ति, सबका गहरा सम्बन्ध है। अपराध के बार-बार होने से राज्य के शौरव, समाज की शान्ति और व्यक्ति की स्वाधीनता को हानि पहुँचती है। इसके अलावा, अपराध की अधिकता इन तीनों पर बलब है। यह कहा जा सकता है कि अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी राज्य की है। पर हमें यह याद रखना चाहिए कि यदि समाज और व्यक्ति राज्य की सहायता न करें तो अकेला राज्य अपराध को नहीं रोक सकता।

असत्य किसे कहते हैं—राज्य की विधि का या सर्वोच्च प्रभु के आदेश (command) का अतिक्रमण अपराध कहलाता है। राज्य सर्वोच्च प्रभु के रूप में अपने सदस्यों की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ आदेश देता है। नियत सीमा से परे व्यक्ति का कोई भी कार्य निश्चित रूप से अपराध माना जाएगा।

पाप किसे कहते हैं—अपराध और पाप में अन्तर है। इन दोनों में तीन भेद हैं।

(१) अपराध किसी विधि का अतिक्रमण है और पाप किसी नैतिक उपदेश का अतिक्रमण है।

(२) अपराध का परिणाम राज्य द्वारा शारीरिक दण्ड या जुर्माना होता है। अपराध करने पर इसी दण्ड में आदमी को दण्ड मिलता है। दूसरी ओर, यदि कोई पाप साध ही कोई अपराध भी न हो तो उसका कोई शारीरिक दण्ड नहीं मिलता। पाप का दण्ड परलोक में सम्बन्ध रखता है।

(३) यद्यपि अधिकतर अपराध पाप भी होते हैं, तो भी दोनों एक ही बात नहीं हैं। सेज मोटर चलाना अपराध हो सकता है, पर यह पाप नहीं।

अपराधों के कारण—सब अपराधों का मूल अनुवसिक्ता (heredity) या वातावरण या दोनों के प्रभाव में दूँडा जा सकता है। कुछ लोग जन्म से अपराध कर्ता होते हैं। उन्हें अपने माता-पिता में अपराध की प्रवृत्ति सूत्र में ही मिलती है। कुछ तो जन्म से अपराध करने वाले नहीं होते, पर बुरे वातावरण के प्रभाव में अपराधी बन जाते हैं। उनका पालन पोषण बुरा हो सकता है, या वे बुरी संगत या परिस्थितियों में पड़ गए हो सकते हैं। कुछ अपराधियों में दोनो प्रभाव काम कर रहे हो सकते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अपराध अपराधी की प्रवृत्ति के कारण ही होता है। दूसरी ओर, अपराधों के अनेक कारणों का वातावरण से विरक्षण करने से हमें पता चलेगा कि वातावरण का प्रभाव अनुवसिक्ता से

भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अधिकतर अपराधी अपने वातावरण के शिकार हो जाते हैं।

आनुवंशिकता—आनुवंशिकता अपराधियों के बंशजों में ही अपराध का कारण होती है। बच्चे में अपने अपराधी माता पिता से कुछ मानसिक और शारीरिक असामान्यताएँ आती हैं। इन असामान्यताओं में बच्चे में भी अपराध की आदतों का विकास होने में सुविधा होती है। पर यह कहना सही नहीं कि अपराधी का पुत्र हमेशा अपराधी ही होगा। अच्छे वातावरण में रहने में आनुवंशिक प्रभाव दबे रह सकते हैं।

वातावरण—वातावरण आदमी के जीवन में बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक बहुत महत्वपूर्ण अंश डालते हैं। प्रथम तो परिवारों में बच्चों के पालन-पोषण पर बहुत ध्यान निर्भर है। ठाढ़ प्यार करने वाले माता पिता प्रायः अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बच्चे पर बाहरी प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति भी बहुत होती है। वह अपने माता-पिता की सब आदतें और कियाएँ सीख लेता है। यही कारण है कि अपराधी माता पिता के बच्चे मुश्किल में ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

दूसरे, वातावरण में वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी शामिल हैं जो समाज व्यक्ति पर डालता है। सामाजिक रुढ़ियाँ का अन्त, नवी गरीब वर्तियों का जीवन, गरीबी और बेरोजगारी इन सबका परिणाम अपराध होता है। विधवा विवाह पर रोक, दहेज प्रथा और जात पाति के बन्धन सामाजिक अत्याचार के उदाहरण हैं। जब किसी आदमी को गरीबी भूख और उदात्त परिणामस्वरूप मौत का सामना करना पड़ता है, तब ही वह कोई भी अपराध कर सकता है। शराब पीने और जुवा खेलने की बुरी आदतें भी अपराध को बढ़ावा देती हैं। अन्तिम बात यह है कि किसी अन्यदेशीय सरकार की राजनीतिक अधीनता अच्छे से अच्छे लोगों से भी कानून भंग करती है।

दण्ड और उसके सिद्धान्त—राज्य समाज में शांति रक्षाने के लिये विधि के अतिश्रमण पर दण्ड देता है। यदि अपराधियों को दण्ड न दिया जाय तो व्यष्टियों के अधिार और स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रह सकने। फिर यदि अपराधों पर दण्ड न दिया जाय तो दूमरे लोगों को अपराध करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। हमें याद रखना चाहिए कि अपराध की प्रवृत्ति हम सब में है पर हम दण्ड के भय से अपराध नहीं करते। यदि ऐसा भय न हो तो कोई भी अपराध करने में सहज नहीं करेगा। सब लोग राज्य की शक्ति का निगदर करने लगे और इसमें गौरव को बड़ी हानि पहुँचेगी। इसलिए, विधि के अतिश्रमण पर दण्ड देना विस्तृत आवश्यक है। अतः प्रथम यह पैदा होना है कि दण्ड की प्रवृत्ति कौसी होनी चाहिए।

दण्ड की प्रवृत्ति और प्रयोजन के बारे में तीन प्रमुख दृष्टिकोण या सिद्धान्त हैं —

(१) प्रतिशोधार्थ दण्ड का सिद्धान्त।

(२) प्रतिशोधक दण्ड का सिद्धान्त ।

(३) मुषापरमक दण्ड का सिद्धान्त ।

प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त—दण्ड के बारे में यह सबसे पुराना सिद्धान्त है । प्रतिशोध का अर्थ है बदला । इस प्रकार उस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड देने के पीछे प्रयोजन यह था कि अपराधी द्वारा किए गये अपराध के लिए दूम्ने बदला लिया जाय । आँसू के बदले आँसू, दाँत के बदले दाँत, का मूल इस सिद्धान्त के प्रयोजन को वही अच्छी तरह स्पष्ट करता है । पहले जमाने में, जब राज्य अपनी शैशव अवस्था में ही था, अपराध एक व्यक्ति के द्वारा दूम्ने व्यक्ति के विरुद्ध किया गया दोष माना जाता था और पीड़ित व्यक्ति को दूम्ने ने बदला लेने की आशा ही थी । संसमन कानून इंग्लैंड में ह्यूगो को फुतक के आश्रितों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी । धीरे-धीरे अपराध राज्य के विरुद्ध किया गया दोष भी माना जाने लगा । राज्य अपराधी को दण्ड देने लगा और पीड़ित व्यक्ति का कोई हान न रहा । राज्य के दण्ड के पीछे भी बदले का ही विचार था, क्योंकि अपराध को राज्य का अपमान माना जाता था । अपराधी को दण्ड देकर राज्य के लिए अपनी मर्यादा बनाए रखना जरूरी था ।

प्रतिशोध वाला विचार राज्य द्वारा दिए गए दण्ड में आज भी मौजूद है । पर यह तथ्य देखते हुए कि आज राज्य मण्डकारी राज्य है, यह विचार प्रतिष्ठा नहीं पा सकता । अराजकियों ने बदला लेना राज्य को शोभा नहीं देता । बदला लेना अतिविक्रम है । राज्य सुवका सुमन्वसी है, इस नाने से अपराधियों के कल्याण पर ही विचार करना चाहिए । प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त अपराधी के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं देता ।

प्रतिशोधक सिद्धान्त—उस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का लक्ष्य, बने पहले, अपराधी को वैसा अपराध या मुनाह करने से रोकना होना चाहिए । दूम्ने, अपराधी को दिया गया दण्ड ऐसा होना चाहिए जो समाज के अन्य सदस्यों के दिल में भय पैदा करे, या दूम्ने मज्दों में, अपराधी को दिया गया दण्ड उदाहरण रूप होना चाहिए जिससे दूम्ने लोग वह अपराध करने से डरें । पिछले जमाने में निर्निष या अपराधी को पत्थर आदि से मार कर मृत्यु कर डालने और सूली पर चढ़ाने जैसे दण्डों के पीछे और आजकल फाँसी की मर्जा के पीछे यह प्रतिशोधक सिद्धान्त ही काम करता है । प्राचीन और मध्य कालीन युगों में अनेक प्रकार के अमानवीय दण्ड दिये जाते थे । सूली पर चढ़ाने और फाँसी से मार डालने के अलावा कान, नाक, हाथ और पैर काट डालना, आँधे निकाल लेना, अपराधी को शही के पैरों से कुचलना देना, आदि पाण्डितिक दण्ड दिये जाते थे, जो मनुष्य के लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए निकाले थे । ऐसे अधिभार अमानवीय दण्ड मात्र ने जमाने में नहीं है क्योंकि आज के जमाने में इन्हें सब जगह बुरा समझा जाता है ।

प्रतिरोधक दण्ड के सिद्धान्त में ये पगिया हैं

१. इसके तर्क के अनुसार, यह होना चाहिए कि कोई अपराध जितनी अधिक बार होता हो उसकी सजा उतनी ही अधिक होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि चोरिया हत्याओं को अपेक्षा अधिक होने हैं तो हत्याओं की अपेक्षा चोरियों के लिए अधिक दण्ड मिलना चाहिए। यह बात स्पष्ट तौर से बहूदा है। हमें किसी अपराध की गम्भीरता में जिस अधिकार का अतिप्रमण किया गया है, उसके महत्त्व के अनुसार नापनी चाहिए। जीवन का अधिकार सम्पत्ति के अधिकार की अपेक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिए हत्या के लिए बड़ी सजा होनी चाहिए।

२. इस प्रकार, यह सिद्धान्त यह मान कर चलता है कि यदि एक बार कोई अपराध होता है तो और लोग भी वह अपराध करेंगे। पर ऐसा मान लेना अनारण्य है। कुछ अनिश्चित भयों से बचने मात्र के लिए अपराधी को भारी दण्ड देना न्याय विरुद्ध है।

३. प्रतिरोधक सिद्धान्त अपराध के लिए अपराध का सारा दोष अपराधी पर डालता है। यह अपराध में वातावरण के प्रभाव की अपेक्षा करता है।

४. यह सिद्धान्त एक अपराधी को एक साध्य का साधन बनाता है और वह साध्य है दूसरों के सामने उदाहरण पेश करना। पर अपराधी को अपने आप में एक साध्य मानना चाहिए, किसी साध्य का साधन नहीं।

५. प्रतिरोधक दण्ड से अपराधी के ओर पक्का हो जाने की सम्भावना रहती है।

सुधारात्मक सिद्धान्त—अन्य दो सिद्धान्तों के मुकाबिले में यह सिद्धान्त मानव प्रवृत्ति के विषय में अधिक आशावादी विचार रखता है। उससे अनुसार अधिकतर अपराधी प्रवृत्ति में बुरे नहीं होने, बल्कि परिस्थितियों और वातावरण के कारण बुरे हो जाते हैं। इस सिद्धान्त के समर्थक अपराधी के कल्याण पर बल देते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार, यदि कोई अपराधी बार-बार अपराध कार्य करते अन्यथा सिद्ध न कर दे तो उसे समाज के हाथ से निकल गया नहीं मानना चाहिए। यह कष्ट देने की बुराई करता है और अपराधी के लिए सहानुभूति रखने को बहता है। अपराधी को समाज के लिए फिर दान्तिपूर्ण नागरिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सिद्धान्त अपराध को एक रोग मानता है और मरीज की तरह अपराधी का इलाज होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जेलों की जगह हस्पताल और सुधारालय होने चाहिए। इस सिद्धान्त में तर्कगत विश्वास था यह अर्थ भी हुआ कि एक अपराध का दण्ड दो अपराधियों के लिए एक होना आवश्यक नहीं। जिनसे पहली बार अपराध किया है उससे, अल्पतम अपराधी की अपेक्षा, अधिक नरमी से बतवि होना चाहिए।

प्रतिरोधात्मक और प्रतिरोधक सिद्धान्तों की प्रतिक्रिया के रूप में सुधारात्मक सिद्धान्त बड़ा स्वागत योग्य है। जेलों की अवस्थाओं में मामूलबूल परिवर्तन

(२) प्रतिशोधक दण्ड का सिद्धान्त ।

(३) सुपारारत्मक दण्ड का सिद्धान्त ।

प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त—दण्ड के चारों में यह सबसे पुराना सिद्धान्त है। प्रतिशोध का अर्थ है बदला। इस प्रकार उस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड देने के पीछे प्रयोजन यह था कि अपराधी द्वारा किए गये अपराध के लिए इमगे बदला लिया जाय। आँसू के बदले आँसू, दाँत के बदले दाँत, का सूत्र इस सिद्धान्त के प्रयोजन को बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट करता है। पहले जमाने में, जब राज्य अभी संशय अवस्था में ही था, अपराध एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया दोष माना जाता था और पीड़ित व्यक्ति को दूसरे में बदला लेने की आजादी थी। संकमन कालीन इंग्लैंड में हत्यारे को मृतक के आश्रितों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। धीरे-धीरे अपराध राज्य के विरुद्ध किया गया दोष भी माना जाने लगा। राज्य अपराधी को दण्ड देने लगा और पीड़ित व्यक्ति का कोई हाथ न रहा। राज्य के दण्ड के पीछे भी बदले का ही विचार था, क्योंकि अपराध को राज्य का अपमान माना जाता था। अपराधी को दण्ड देकर राज्य के लिए अपनी मर्यादा बनाए रखना जरूरी था।

प्रतिशोध वाला विचार राज्य द्वारा दिए गए दण्ड में आज भी मौजूद है। पर यह तथ्य देखते हुए कि आज राज्य मंगलकारी राज्य है, यह विचार प्रतिष्ठा नहीं था सकता। अपराधियों के बदला लेना राज्य को शोभा नहीं देता। बदला लेना अनैतिक है। राज्य सबका सुभारक्षी है, इस नाते उसे अपराधियों के बल्याण पर भी विचार करना चाहिए। प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त अपराधी के बल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं देता।

प्रतिशोधक सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का लक्ष्य, उसे पहले, अपराधी को वैसा अपराध या गुनाह करने में रोकना होना चाहिए। दूसरे, अपराधी को रिना गया दंड ऐसा होना चाहिए जो समाज के अन्य सदस्यों के दिल में भय पैदा करदे, या दूसरे शब्दों में, अपराधी को दिया गया दण्ड उदाहरण रूप होना चाहिए जिससे दूसरे लोग वह अपराध करने में डरें। पिछले जमाने में लूटिग या अपराधी को पत्थर आदि से मार कर मृत कर डालने और मूली पर चढ़ाने जैसे दण्डों के पीछे और आजकल फाँसी की मर्दा के पीछे यह प्रतिशोधक सिद्धान्त ही काम करता है। प्राचीन और मध्य कालीन युगी में अनेक प्रकार के अमानवीय दण्ड दिये जाते थे। मूली पर चढ़ाने और पत्थरों से मार डालने के अलावा कान, नाक, हाथ और पैर काट डालना, आँसू निकाल देना, अपराधी को हाथी के पैरों ठोके कुचलवा देना, आदि पारंपरिक दण्ड दिये जाते थे, जो मनुष्य के लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए निकाले थे। ऐसे अपमानर अमानवीय दण्ड आज के जमाने में नहीं हैं क्योंकि आज के जमाने में उन्हें सब जगह बुरा समझा जाता है।

प्रतिरोधक दण्ड के सिद्धान्त में ये समिया है

१. इससे तर्क के अनुसार, यह होता चाहिए कि कोई अपराध त्रिनयी अधिन बार होता हो उसकी मात्रा उतनी ही अधिक होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि चोरिया हत्याओं की अपेक्षा अधिक होनी हैं तो हत्याओं की अपेक्षा चोरियों के लिए अधिक दण्ड मिलना चाहिए। यह बात स्पष्ट तौर से बहूदा है। हमें किसी अपराध की गम्भीरता में त्रिन अधिकार का अतिव्रमण किया गया है, उसके महत्त्व के अनुसार मापनी चाहिए। जीवन का अधिकार सम्पत्ति के अधिकार की अपेक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिए हत्या के लिए घड़ी मात्रा होगी चाहिए।

२. इस प्रकार, यह सिद्धान्त यह मान कर चलता है कि यदि एक बार कोई अपराध होता है तो और लोग भी वह अपराध करेंगे। परंतु मान्यता अवारण है। कुछ अनिश्चित भयों के बचने मात्र के लिए अपराधी को भारी दण्ड देना न्याय विरुद्ध है।

३. प्रतिरोधक सिद्धान्त अपराध के लिए अपराध का तारा रोग अपराधी पर डालता है। यह अपराध में वातावरण के प्रभाव की अपेक्षा करता है।

४. यह सिद्धान्त एक अपराधी को एक माध्यम का मापन बनाता है और वह माध्यम है नृगरी के सामने उदाहरण पेश करना। पर अपराधी को अपने आप में एक साध्य मानना चाहिए, किसी माध्यम का साधन नहीं।

५. प्रतिरोधक दण्ड के अपराधी के और परता हो जाने की सम्भावना रहती है।

सुधारामक सिद्धान्त—अन्य दो सिद्धान्तों के मुकाबिले में यह सिद्धान्त मानव प्रकृति के विषय में अधिक आशावादी विचार रखता है। उसने अनुसार अधिकतर अपराधी प्रकृति में घुने नहीं होने, बल्कि परिस्थितियों और वातावरण के कारण घुने हो जाते हैं। इस सिद्धान्त के समर्थक अपराधी के कल्याण पर बल देते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई अपराधी बार बार अपराध कार्य करते अन्यथा सिद्ध न कर दे तो उन समाज के हाथ से निकल गया नहीं मानना चाहिए। यह दण्ड देने की बुराई करता है और अपराधी के लिए सहानुभूति रखने को कहता है। अपराधी को समाज के लिए फिर सान्निध्यपूर्ण नागरिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सिद्धान्त अपराध को एक रोग मानता है और मरीज की तरह अपराधी का इलाज होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जेजों की जगह हस्पताल और सुधारालय होने चाहिए। इस सिद्धान्त में तर्कमय विरवाद का यह अर्थ भी होगा कि एक अपराध का दण्ड दो अपराधियों के लिए एक होना आवश्यक नहीं। त्रिनने पहली बार अपराध किया है उससे, अन्यस्त अपराधी की अपेक्षा, अधिक नरमी में दर्शाई होना चाहिए।

प्रतिरोधात्मक और प्रतिरोधक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठिता के रूप में सुधारामक सिद्धान्त बड़ा स्वागत योग्य है। जेज की अवस्थाओं में बामूल्युक्त परिवर्तन

होना चाहिए और उन्हें अधिक अच्छा बनाया जाना चाहिए। अपराधी को उसके अकेले अतिरिक्त में उचित प्रतिशोध द्वारा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। पर गुनरात्मक मिद्वान्त भी कमियों में रहित नहीं है।

१. सुधार निम्नदेश दण्ड देने में एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए, पर सुधार पर ही साग जोर डालना समाज के हितों की अपेक्षा करता है। अपराधी अपने गैर-अभिप्रेत व्यवहार के लिए समाज के प्रति भी उत्तरदायी है।

२. यह भी याद रखना चाहिए कि यदि अपराधी में अपने को सुधारने की इच्छा न हो तो सुधार के प्रयत्नों में कोई नैतिक विफल नहीं हो सकता।

३. यह विश्वास कि पातक्यकरण या समाज अपराध के लिए अधिक दोषी है, आसो में रहित नहीं। इसका विरोधी विश्वास कि अपराध अधिकतर अपराधी की विद्वल प्रवृत्ति और अनुमानहीनता का परिणाम है, उतना ही प्रबल है।

४ उभी अपराध के लिए अल्प-अल्प दण्ड देना व्यवहार्य नहीं। कानून सब के लिए एक होना चाहिए। सब जगह को अत्यधिक विवेकाधिकार देना पड़ेगा और वे प्रलोभनों में अधिक फसने की स्थिति में होंगे।

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि दण्ड के तीनों मिद्वान्तों में सजाई का कुछ-कुछ अर्थ है। दण्ड के मजबूत मिद्वान्तों में तीनों मिद्वान्तों का उचित मिश्रण होना चाहिए। दण्ड के निम्नलिखित लक्ष्य उचित होंगे

१. दण्ड प्रथम तो, अपराध का निवारक होना चाहिए, पर वह अमानवीय न होना चाहिए। अनावश्यक रूप से कठोर दण्ड अधिक पाने अपराधी पेश करने लगते हैं। दण्ड किन्तु अपने अपराध के अनुपात में होना चाहिए। यह अनिर्णयित किए गये अधिकार के महत्व के अनुसार होना चाहिए।

२. दण्ड को एक साम्य का गायन मानना चाहिए। जो साम्य सिद्ध करना अभीष्ट है, उसमें अपराधी का सम्पूर्ण और मार्भैतिक शान्ति बनाए रखना भी शामिल होना चाहिए। अपराधी का सुधार वैसा ही महत्वपूर्ण है, जैसा विधि व्यवस्था को बनाए रखना।

सारांश

विधि

विधि का अर्थ और प्रकृति—हार्नेण्ड ने राजनैतिक विधि की यह परिभाषा की है "बाहरी मानवीय विद्या का वह व्यापक नियम, जो सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता द्वारा लागू किया जाता है।" इस प्रकार विधि राज्य का एक आदेश है जो उसकी सर्वोच्च सत्ता द्वारा नसबित होता है। विधि के अतिरिक्त पर राज्य दण्ड देता है। राज्य के अन्तर्गत और कोई सत्ता विधि जारी नहीं कर सकती। स्वयं राज्य अपनी विधि में बद नहीं होता।

विधि के स्रोत—इति विधि के सबसे पुराने स्रोतों में से है। बहुत सी सभियाँ

आजकल के जमाने में हटि वन गई । हिन्दुओं मुसलमानों और ईसाइयों की विधियाँ उनकी धार्मिक पुस्तकों में निरूपी थीं । आज के जमाने में विधि की अप्रसिद्ध बातों पर न्यायालयों के विनिश्चय और विधान मण्डलों द्वारा अधिनियमित (enacted) सविधियाँ (statutes) विधि के मुख्य स्रोत हैं ।

विधि के प्रकार विधियों का पहले इस प्रकार विभाजन किया जा सकता है —

१. व्यक्तिगत विधि, जो एक आदमी और दूसरे आदमी के सम्बन्धों को विनियमित करती है ।

२. लोक विधि, जो व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों को विनियमित करती है ।

३. अन्तर्राष्ट्रीय विधि, जो एक राज्य और दूसरे राज्य के सम्बन्धों को विनियमित करती है ।

लोक विधि का फिर यह वर्गीकरण किया जा सकता है

(१) सर्वधार्मिक विधि, (२) प्रशासनीय विधि, (३) दण्ड विधि ।

विधि और नैतिकता का सम्बन्ध, दोनों में भेद करने वाली बातें—(१) विधि निरंक बाहरी कार्यों में सम्बन्ध रखती है । नैतिकता प्रेरक भावों और आशयों को भी देखती है ।

(२) विधि के अतिवृत्त का परिणाम शारीरिक दण्ड या जुर्माना होता है ।

निसी अनैतिक कार्यों को समाज द्वारा आलोचना भर की जा सकती है । (३) विधि मुनिविद्यन और स्वरूप में सार्वजनिक होती है । नैतिकता अप्रसिद्ध और व्यक्तिगत होती है । (४) विधि सामयिक औचित्य के मानदण्ड के अनुसार चलती है । नैतिकता मूल्य और सही के निरपेक्ष मानदण्ड बनाती है ।

सम्बन्ध बताने वाली बातें—(१) विधि और नैतिकता दोनों का उद्गम एक था ।

(२) राजनैतिक विधियों की स्थापना उनके नैतिक होने पर भी निर्भर है ।

(३) विधियाँ भी प्रायः नैतिकता को लागू करती हैं ।

स्वाधीनता स्वाधीनता कितने कहते हैं—नागरिक साम्य में स्वाधीनता से हमारा मतलब है सब कुछ करने की आजादी वजत कि यह दूसरों की आजादी को हानि न पहुँचाये । इसका अर्थ अवरोध का अभाव नहीं है ।

स्वाधीनता के प्रकार—(१) नैसर्गिक स्वाधीनता—अवरोध मुक्ति के अर्थ में जो स्वाधीनता होती है, यह नैसर्गिक स्वाधीनता कहलाती है । ऐसी स्वाधीनता समाज में सम्भव नहीं यह काल्पनिक, अव्यावहारिक और अस्थायी होती है । (२) नागरिक स्वाधीनता—यह वह स्वाधीनता है जो समाज में मनुष्य को प्राप्त होती है । यह चारतन्त्र, स्थायी और सबके लिए समान होती है, क्योंकि यह विधि द्वारा रक्षित होती है । (३) राजनैतिक स्वाधीनता—इसका अर्थ है सरकार चुनने और चलाने में हिस्सा लेने की आजादी (४) सार्वधार्मिक स्वाधीनता । (५) आर्थिक स्वाधीनता—

इसका अर्थ ? अभाव में सुदृढता । (६) राजकीय स्वाधीनता ।

विधि और स्वाधीनता का सम्बन्ध—अपने साम्प्रदायिक अर्थ की दृष्टि में ये परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं । स्पष्टिकारी, अनासक्तवादी और गिगलहॉल्ट यह मानते हैं कि स्वाधीनता और विधि में सम्बन्ध नहीं किया जा सकता । पर वास्तव में विधि स्वाधीनता की विधि है । विधि नैतिक स्वाधीनता की दायी है पर यह अधिकारों के अर्थ में नागरिक स्वाधीनता की गारंटी और रक्षा करती है । दूतरी और, डिप्लोमेटिक और साम्राज्यवादी राज्य की विधि स्वाधीनता की दायी होती है । विधि का स्वाधीनता में सम्बन्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि लोग विधि को मुक्तिमूलक समझें हों और इसे पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए ।

समता—नागरिक शासन में समता शब्द के ये अर्थ हैं —

(१) विधि के समत समता । (२) एक-ही अर्हता के सब लोगों को एक धन-योग्य, मूल्यवान्, धर्म, रण, जाति या धर्म और लिंग पर बिना विचार किए समान अवसर देना ।

निम्नोक्त समान अवसर दिये जाने के बाद कुछ लोग अर्हता नैतिक योग्यता द्वारा औरों में आगे बढ़ जायेंगे । समान का अर्थ एक व्यवहार नहीं ।

स्वाधीनता और समता का सम्बन्ध—साम्प्रदायिक अर्थ की दृष्टि में ये दोनों परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं । पर समता के ऊपर दायें सब अर्थ को देने में हुए समता और नागरिक स्वाधीनता में कोई विरोध नहीं दिखाई देगा । सम्भव तो यह है कि समता का उपाय अन्वयण उन बहुत अधिक लोगों के लिए स्वाधीनता को अर्थ देता है, जो धन, जन्म, लिंग, मूल्यवान् भादि की विशेषताओं भोगों में । दूसरी ओर, समता का हमारा अन्वयण उन लोगों को स्वाधीनता में वंचित नहीं करता जिन्हें प्राप्ति में अधिक अच्छी स्थिति में रखा है ।

अपराध और दंड—राज्य, समाज और स्पष्ट इन तीनों का अपराध की सम्बन्धना में गहरा सम्बन्ध है । अपराध की अधिकता इन तीनों पर बलक है ।

अपराध कैसे बढ़ते हैं—राज्य की विधि के बिना अनियमन की अपराध बढ़ जाता है । यद्यपि अधिकतर अपराध पाप भी होते हैं, तो भी दोनों बातें अभिन्न नहीं । पाप बिना नैतिक उपदेश के अनियमन को बढ़ते हैं । अपराध करने पर राज्य द्वारा दण्ड दुनिया में शारीरिक दण्ड दिया जाता है या जुर्माना किया जाता है । पाप का कोई शारीरिक दण्ड नहीं मिलता और इसका दण्ड परलोक में मिलता है ।

अपराध के कारण—सब अपराधों का मूल आनुवंशिकता का या वातावरण का या दोनों का उभाव होता है । आनुवंशिकता अपराधियों के वंशजों की अदरवा में ही अपराध का कारण होती है । अधिकतर अपराधी अपने वातावरण के कारण अपराधी बनते हैं । बुद्धि सामाजिक स्थिति, सराव आदतें, परीची और संश्लेषकारी

लोगों को अपराध करने के लिए मजबूर करती है।

दण्ड और उसके सिद्धान्त—लोगों के अधिकारों और स्वाधीनता को सुरक्षित करने के लिए अपराध का दण्ड आवश्यक दिया जाना चाहिए। दण्ड के तीन प्रमुख सिद्धान्त ये हैं —

१. प्रतिशोधत्मक दण्ड का सिद्धान्त—'आम के बढ़ने आस और दान के बढ़ने दात' के मूल में इसका प्रयोजन अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है।

२. प्रतिरोधक सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड न केवल ऐसा होना चाहिए कि वह अपराधी को फिर वैसा ही अपराध करने से रोके बल्कि समाज के अन्य सदस्यों के मन में आतंक पैदा करने वाला भी होना चाहिए।

३. सुधाररत्मक सिद्धान्त यह सिद्धान्त अपराध को रोग मानता है। भोर रोगी की तरह इसका भी इलाज होना चाहिए और जेलों की जगह हस्पताल और सुधारालय होने चाहिए।

इन सिद्धान्तों में से कोई भी अकेला काफी नहीं। इन सबमें मध्य का कुछ अंश है। उचित दण्ड ऐसा होना चाहिए कि वह अमानवीय न हो, पर अपराध को रोक दे। दण्ड का लक्ष्य अपराधी का कल्याण और सार्वजनिक शान्ति बनाए रखना, ये दोनों ही होने चाहिए।

प्रश्न

QUESTIONS

१. विधि की परिभाषा करो। इसके स्रोत और प्रकार कौन कौन से हैं ?
(५० वि० १९५२)
- 1 Define 'Law' What are its sources and kinds ?
(P U 1952)
२. विधि की परिभाषा करो। किसी नागरिक को अच्छी विधियाँ बनवाने और बुरी विधियाँ खत्म कराने के लिए कौनसे साधन अपनाने चाहिए।
(५० वि० सितम्बर, १९५१)
- 2 Define 'Law' What means should a citizen adopt, to get good laws made and bad laws modified ? (P U Sep 1951)
३. विधि और नैतिकता में क्या सम्बन्ध है ?
- 3 What is the relation between law and morality
४. स्वाधीनता शब्द से आप क्या समझते हैं ? विधि और स्वाधीनता में क्या सम्बन्ध है ?
(५० वि० १९५१)
- 4 What do you understand by the term 'Liberty' ? What is the relation between 'Law and Liberty' ? (P U April 1951)
५. स्वाधीनता की परिभाषा करो। इसके कौन-कौन से प्रकार हैं ?
- 5 Define 'Liberty'. What are its various kinds ?
६. समता शब्द से आप क्या समझते हैं ? समता और स्वाधीनता में क्या सम्बन्ध है ?

सरकार—विधानांग, कार्याङ्ग, न्यायांग

सरकार किते कहते हैं—राज्य अमूर्त होना है और वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इसे अपने काम कराने के लिए किसी मूर्त अभिकर्ता की जरूरत होती है। सरकार राज्य का वह अभिकर्ता है जिसके जरिये इसकी सत्ता का प्रकाशन होता है, और इसका प्रयोजन पूरा होता है। सरकार क विविध ढंग इस काम में राज्य की सहायता करते हैं। राज्य की इच्छा विधानांग में रूप ग्रहण करती और अभिव्यक्त होती है। यह कार्यांग द्वारा अमल में लाई जाती है और न्यायांग द्वारा प्रवर्धित (enforced) कराई जाती है।

सरकार के अंग—आधुनिक सरकार के कार्य प्रायः तीन भागों में बंटे हुए हैं अर्थात् विधायक, कार्यात्मक और न्यायिक। इन तीन कार्यों के करने के लिए तीन ही अंग हैं। वे हैं विधानांग, कार्यांग और न्यायांग। जैसा ऊपर कहा गया है, विधानांग सरकार का वह अंग है जिसके जरिये राज्य की इच्छा रूप ग्रहण करती और अभिव्यक्त होती है। यह विधियां बनाता है। कार्यांग इन विधियों को लोगों पर लागू करने के लिए है। न्यायांग यह मुनिविचन करने के लिए है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति इन विधियों का ठीक-ठीक पालन करे।

विभिन्न अंगों का आपेक्षिक महत्त्व—तीनों अंग अपने-अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें क प्रत्येक शासन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। इसके बावजूद शासन के विभिन्न रूपों में किसी एक अंग को सामान्यतः औरों से ऊंची स्थिति प्राप्त होती है। निरंकुश राजतंत्रों और तानाशाही शासनो में कार्यांग (राजा और तानाशाह) सर्वोच्च होते हैं। संधान (Federation) के अतिरिक्त अन्य लोकतंत्रों में विधानांग को ऊंची स्थिति प्राप्त होती है। संधानों में न्यायिक उच्चतम न्यायालय का सिद्धान्त चलता है, यद्यपि स्विट्जरलैंड इस नियम का अपवाद है।

विधानांग—विधानांग के कार्य

विधान—विधानांग का करने महत्त्वपूर्ण काम विधियां बनाना है। नई विधियां बनाने के अलावा विधानांग मौजूदा विधियों का सशोधन और निरस्तन (repeal) भी करता है। कार्यांग और न्यायांग विधानांग द्वारा बनाई गयी विधियों

को लागू करते हैं और उनका निर्वचन (Interpret) करते हैं। इस अर्थ में ही विधानमण्डल सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि विधियाँ बनायीं न जाएं तो उन्हें लागू और प्रवर्तित कैसे किया जा सकता है। कुछ विधान मंडलों को, जैसे ब्रिटिश संसद, सार्वभौमिक विधि बनाने और सशोधित करने की भी शक्तियाँ हैं।

वित्त का नियंत्रण—आधुनिक काल में विधानमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण काम राज्य के वित्तों का नियंत्रण करना है। लोकोत्तम के युग में यह स्वाभाविक धारण है कि विधानमंडल में लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी आगाज न केवल विधियाँ बनाने में, बल्कि वित्त में भी अंतिम होनी चाहिए। उन्हें ही यह निश्चय करना चाहिए कि वे कौन से कर देंगे और उनसे होने वाली आमदनी कैसे खर्च की जाएगी। इस प्रकार, सरकार के वार्षिक बजट पर विधान-मंडल विचार करता है और उनका अनुमोदन करता है। इसे नये कर लगाने और पुराने कर बदलने या सख्त करने की शक्ति होती है। कार्यांग के विविध विभागों के खर्च की मजूरी भी यह देता है। इस प्रकार विधानमंडल का सरकार के खर्चे पर पूरा नियंत्रण होता है।

कार्यांग पर नियंत्रण—लोकतंत्रों में कार्यांग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ताम्र के राष्ट्रपतीय रूप में, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में है, यह जिम्मेदारी प्रत्यक्ष है, पर शासन के सगदीय रूप में, जैसा कि भारत और इंग्लैंड में है, यह जिम्मेदारी विधानमंडलों में, जनता के प्रतिनिधियों की माध्यम, परोक्ष है। विधान-मंडल मंत्रियों और उनके अधीन विभागों पर सख्त नियंत्रण रखता है। इनके सदस्यों को किसी भी मंत्री के विभाग के मामलों में आवश्यक पूछनाछ करने के लिए उसने प्रश्न करने का अधिकार है। विधान मंडल मंत्रियों के आचरण की निंदा करके उनकी स्थापनाओं को अस्वीकार करके और उनके विरुद्ध तीव्र अविश्वास का प्रस्ताव पास करने उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर कर सकता है।

अन्य कार्य—विधानमंडल कुछ अन्य कार्य भी करता है, जयान् निर्वाचन सचची, न्यायिक और कार्यवाही (Executive)। विधान मंडल अपने कार्य सचचादन और कार्यवाही के लिए स्वयं अपने नियम बनाते हैं। वे अपने सदस्यों की धर्तुवा निर्धारित करते हैं, और चुनावी सचची विवादों का फैसला भी करते हैं। विधान मंडलों को मंत्रियों पर महाभियोग लगाने (impeaching) और उनकी अन्वीक्षा करने (trying) की शक्ति होती है और उन न्यायाधीशों की बर्खास्त करने की भी शक्ति होती है जो भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाएँ। यूनाइटेड स्टेट्स में नियुक्तियों के मामले में और मंत्रियों पर हस्ताक्षर करने में राष्ट्रपति के साथ-साथ संसद की भी शक्ति है। कुछ राज्यों में राज्य का सम्पत्ति भी विधान मण्डल द्वारा निर्वाचन होता है।

विधान मण्डल का गठन—विधान मण्डल एकसदनी या एकपरे और द्विसदनीय या दोपरे (unicameral or bicameral) होने है, अर्थात् उनमें एक

सदन या दो सदन होने हैं। आजकल अधिकतर विधान मण्डलों में दो सदन होते हैं, अर्थात् प्रथम सदन या छोटा सभा और द्वितीय सदन या राज्य सभा।

द्वितीय सदन—द्वितीय सदन या तो आनुवन्धित या नामजद या निर्वाचित या अथवा नामजद और अथवा निर्वाचित होने हैं। इंग्लैण्ड की लार्ड सभा दुनिया का एकमात्र आनुवन्धित द्वितीय सदन है। विभिन्न देशों के दूसरे अधिकतर द्वितीय सदन अथवा परोक्ष निर्वाचन और अथवा नामजदगी में बने हुए हैं।

आनुवन्धित, नामजद और परोक्षत निर्वाचित द्वितीय सदनों को प्रथम सदनों की अपेक्षा, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होते हैं, कम शक्तियां होती हैं। मनाइस्टेड स्टेट्स की सैनेट, जो द्वितीय सदन है, ऐसा एकमात्र द्वितीय सदन है, जिसे प्रथम सदन में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसका कारण यह है कि सैनेट प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधान है, और वहाँ सरकार विधान मण्डल के प्रति उत्तर दायी नहीं।

द्वितीय सदनों के भय प्रहण सामान्यतया स्थायी निकाय हैं। वे जहाँ नामजद और निर्वाचित हैं, वहाँ भी उनके मारे सदस्य कभी नुबं नहीं होते। प्रत्येक दो या तीन वर्षों बाद उनके एक तिहाई सदस्य धारी-धारी निकृत होते हैं और उनका स्थान पर नये सदस्य आ जाते हैं।

सब जगह द्वितीय सदन अधिक उम्र के लोगों का सदन भी है। द्वितीय सदन की सदस्यता के लिए अर्हता की आयु सामान्यतया प्रथम सदन वाली आयु की अपेक्षा ऊँची होती है।

प्रथम सदन—प्रथम सदन सब जगह एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विभिन्न देशों में प्रचलित चुनाव की विभिन्न रीतियों के अनुसार एक या अधिक सदस्य चुनता है। चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। २५ वर्ष की या ऐसी ही आयु के सब नागरिकों को चुनाव में सड़े होने का अधिकार होता है। प्रथम सदनों की अवधि सामान्यतया ४ से ५ वर्ष तक होती है। उनके आधार भी अलग-अलग होते हैं पर सदन बहुत बड़ा न होना चाहिए। प्रथम सदन में किसी भी अवस्था में ५०० से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए।

प्रथम सदन जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। इस नाते उसे द्वितीय सदन की अपेक्षा साधारणतया अधिक शक्तियां होती हैं। इन धन संबंधी मामलों में प्रायः अनन्य (exclusive) नियंत्रण प्राप्त होता है। जहाँ सामन में मंत्रिमण्डल प्रणाली प्रचलित है, वहाँ प्रधान मंत्री प्रथम सदन का सदस्य होता है। मंत्रिमण्डल दूसरे सदन की आस्था इस सदन की इच्छाओं की अधिन परवाह करता है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधि सदन है और मंत्रि परिषद इसके प्रति उत्तरदायी है।

इस पृष्ठभूमि में अरहम विधान मण्डल की एकसदनी और द्विसदनी प्रणालियों के गुण-दोषों पर विचार करेंगे।

बचाती है। यदि गिरफ्त एग सदन हो तो सम्भव है कि यह शक्ति के मद में भर जाए। तब हो सकता है कि यह डिस्ट्रेक्टर की तरह व्यवहार करें। इस प्रकार, यदि विधायक शक्ति को दो सदनों में बाँट दिया जाए तो जनता को अधिक स्वाधीनता प्राप्त होगी।

निहित स्वार्थों के प्रतिनिधान के लिए आवश्यक—कुलीन तब या अल्पतब से जब लोकतंत्र में परिवर्तन होता है, तब कुछ निहित स्वार्थों को प्रतिनिधान देने के लिए द्वितीय सदन की आवश्यकता होगी है। बड़े-बड़े जमींदारों और उद्योग पतियों को, जिनके निहित स्वार्थ हैं कानून बनाने में जनता के प्रतिनिधियों के साथ साम्य बना लेना चाहिए। इंग्लैंड में लार्ड महा इसी तरह बनी।

पेशों के आधार पर प्रतिनिधान के लिए आवश्यक है—प्रथम सदन में प्रतिनिधान क्षेत्रीय आधार पर होना है पर प्रतिनिधान की यह विधि पेशेवार प्रतिनिधान के प्रतिपादन को तनुष्ट नहीं करती। इस प्रकार, द्वितीय सदन का विभिन्न पेशों, यथा किसानों, जमींदारों, पूँजीपतियों और मजदूरों, को प्रतिनिधान देने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अल्पसङ्ख्यकों के प्रतिनिधान के लिए आवश्यक—उस अल्पसङ्ख्यका को, जिन्हें आम चुनावों में प्रथम सदन में स्थान पाने का कोई मौका नहीं है, विशेष प्रतिनिधान दिया जा सकता है।

द्वितीय सदनों के विषय में धुक्कियाँ—द्विसदनी प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया बढ़ती जाती है। कहा जाता है कि द्वितीय सदन के लाभ गिरफ्त ऊपरी और अवास्तविक हैं। द्वितीय सदन के विपक्ष में ये धुक्कियाँ हैं—

वे प्रतिक्रियावादी निरर्थक हैं—कहा जाता है कि द्वितीय सदन प्रतिक्रियावादी निरर्थक होते हैं। उनमें साधारणतया रूढ़िवादी दृष्टिकोण के बड़ी उम्र के लोग या निहित स्वार्थों के प्रतिनिधि होते हैं। वे दोनों सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन का विरोध करते हैं और इस प्रकार प्रगति के मार्ग में बाधा बन जाते हैं।

दो सदन होने से एकता नष्ट हो जाती है—द्विसदनी विधान मण्डल उस पर व समान है जिसमें फूट पड़ी हुई हो। कहा जाता है कि दो सदन होने से बार-बार अनिरोध होने हैं। विधायक कार्यवाही असम्भव हो जाती है, और प्रगति रुक जाती है। लोगों के लिए अपनी इच्छा को एक रूप देना और उसे अभिव्यक्त करना भी कठिन हो जाता है।

अल्पसङ्ख्यकों के प्रतिनिधान के लिए आवश्यक नहीं—यदि अधिकार पत्र (Bill of rights) के रूप में अल्पसङ्ख्यकों के हितों की संविधान में उचित रीति से रक्षा की गई हो तो उक्त द्वितीय सदन में प्रतिनिधान की जरूरत नहीं रहेगी।

द्वितीय सदन व्यर्थ होते हैं—अन्य बात यह है कि कहा जाता है कि द्वितीय

गदन विस्तृत अनावश्यक होते हैं। उनकी प्रत्यक्षता में विधान बनाने में बचने के लिए भी आवश्यकता नहीं। विधेयक को विधि बनाने में पढ़ने अनेक मंत्रियों में से चुनना पड़ता है और इन प्रकार पाग होने में उमे बहुत समय लगता है। इसी कई पढ़न (reading) होने है और इस पर पूरी तरह चर्चा होती है। इसके अतिरिक्त, आजकल लोकमत विधान मण्डलों के ऊपर काफी नियमन रमता है। एक सदन के जल्म का मय भी इसी कारण नहीं होना चाहिए।

नियमकर्म—द्वितीय सदनों के पत्र में चाहे जो कुछ कहा जाए, पर अविश्वर राज्यों में द्वितीय विधान मण्डल है। अब तक किसी राज्य में जतने द्वितीय सदन को तत्न करने का सम्भोदता में विचार नहीं किया। इससे निश्चि होता है कि द्वितीय सदन अक्षय कुछ उपयोगी कार्य कर रहे हैं। अब मय यह मानने है कि आदर्श द्वितीय सदन में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए—

(१) द्वितीय सदन न तो मारा आनुवधिक होना चाहिए और न मारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। यह थोड़ा परोक्ष निर्वाचित और थोड़ा नामजद होना चाहिए। परोक्ष निर्वाचन इसे प्रथम सदन की अपेक्षा कमजोर बनाए रखेगा। नामजदगी में कुछ अत्याचारों का प्रतिनिधान मुनिश्चित हो जाएगा और योग्य व्यक्तियों की मद्रापना मित मरेगी।

(२) इसी मविजयी प्रथम सदन की शक्तियों के समान नहीं होनी चाहिए। यह मुख्यत मत्रणादाना और पुनरीक्षण (Revising) निभाव होना चाहिए।

(३) इसमें दर्दा उम्र के और अनुभवी लोग होने चाहिए।

सब विधान मण्डलों की कुछ सामान्य विशेषताएँ किसी विधान मण्डल की बैठक मारे माल नहीं होनी। विधान मण्डलों के मत्र वर्ष में दो बार होने हैं। माधारणतया विधान मण्डल का आह्वान (Summoning), मत्रारमान (Prorogation) और विघटन राज्य के अक्षरक्ष द्वारा किया जाता है। पर युनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटिश इम्पैरि में, मविधान-द्वारा निश्चिन विधियों पर उनकी बैठक होती है और वे अपने आपसे विघटित कर लेते हैं। विधान मण्डल के प्रत्येक सदन में कार्यमन्त्रालय एक मन्त्रागि या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो माधारणतया स्वयं सदन द्वारा निर्वाचित होता है। सदन के मत्र सदस्य बोलने के लिए उनकी इजाजत लेते हैं, और वे अपने भाषण और प्रश्न उमे ही मन्त्रोचित करने हैं। तथ्य तो यह है कि सदन में कोई भी बात उमरी उजाजत के बिना नहीं की जा सकती।

सदन के कार्यमन्त्रालय के नियम माधारणतया सदन द्वारा ही बनाए जाते हैं। विधान मण्डल का प्रत्येक सदन अपने जाय का ममिधियों के रूप में बाट लेता है। जो चानून सदन के समझ विचार के लिए जाते हैं वे जरीबी के जाय करने के लिए इन ममिधियों को बेजे करते हैं। इन ममिधियों के सदन के मय दर्दों को प्रतिनिधान मिलता है, पर ममिधि का मन्त्रागि माधारणतया दर्दमन्त्रक दल का होता है। सदन के विचार के लिए विधेयक कार्यमन्त्रालय द्वारा (यहाँ मायन की मविम इन्वी

प्रणाली है वही) या इसके किमी मसय टाग पुर न्धापित विण जा सकते हैं । सब विधेयको के साधारणतया तीन पठन होने हैं । विधेयको पर मनदाग दलीय आधार पर होता है । यदि कोई विधेयक तीसर पञ्ज में पाग हो जाता है, तो यदि दूसरा सदस है, तो यह उमे भेजा जाता है । अन्यथा यह मीधे ही राज्य के अध्यक्ष के पास हस्ताधार के लिए जाता है । उसके हस्ताधार के बाद कोई विधेयक अन्तिम रूप से विधि बन जाता है । विधान मण्डलों के सदस्यों को भाषण की स्वतन्त्रता और गिरफ्तारी में स्वतन्त्रता आदि के रूप में कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होने हैं ।

कार्याग या कार्यपालिका

कार्याग या कार्यपालिका की रचना—मोटे तौर से कहा जाए तो कार्याग या कार्यपालिका में न्यायाग और विधानाग के अफसरों को छोड़ कर राज्य के और सब अफसर शामिल हैं । इस अर्थ में सरकार की प्रशासन शाखा के सब कर्मचारी—राजा या राष्ट्रपति से लेकर चपरसीतक सब के सब—कार्याग या कार्यपालिका के अग हैं । पर नागरिक शास्त्र में कार्याग या कार्यपालिका शब्द राज्य के अध्यक्ष और उमने मन्त्रियों पर लागू होता है ।

कार्याग के प्ररूप—विविध राज्यों के कार्यागों को निम्नलिखित रीति से वर्णयद्ध किया जा सकता है ।

राजनैतिक और स्थायी—यह भेद सब राज्यों में कार्याग के दो भागों पर लागू होता है । राज्य के अध्यक्ष या और उमने मन्त्री राजनैतिक कार्याग हैं । वे राजनैतिक कहे जाने हैं क्योंकि वे अधिकतर चुनाव के द्वारा ही पद ग्रहण करते हैं, और हर चुनाव पर बदलते रहते हैं । राज्य की नीतियाँ कार्याग का यही भाग बनाता है ।

स्थायी कार्याग में विभिन्न कार्यपालक विभागों के स्थायी कर्मचारी होने हैं । कार्याग के इस भाग को जानपद सेवा (Civil Service) भी कहते हैं । इसमें सचिव, अधीक्षक, सहायक और लिपिक या क्लर्क शामिल हैं । राजनैतिक कार्याग द्वारा निर्धारित नीति को स्थायी कार्यपालिका व्यवहार में लाती हैं ।

आनुवशिक, निर्वाचन और नामजद—कार्यपालिकाओं में यह विभेद राज्य के अध्यक्ष को नियुक्त करने की विधियों पर आधारित है । यदि वह राजा है तो कार्यपालिका आनुवशिक कटलाएगी । इगलैण्ड में राजा आनुवशिक होता है । यदि राज्य का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्षत निर्वाचित होता है तो कार्यपालिका निर्वाचित होगी । जिस राज्य में कार्यपालिका का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, वह गणराज्य कहलाता है । भागत एक गणराज्य है । राज्य का अध्यक्ष नामजद भी हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए कनाडा का गवर्नर जनरल । अंग्रेजों के जमाने में भारत का गवर्नरजनरल भी नामजद होता था ।

वास्तविक और नाममात्र—यह प्रभेद नाम के मसदाय रूप की कार्यपालिका पर ही लागू होता है । इसमें राज्य का अध्यक्ष नाममात्र कार्यपालिका

होना है और मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होना है। राज्य का अल्पतः, चाहे वह राजा ही या राष्ट्रपति, मित्र भाग्यी शक्तियों रमना है। शासन उसके नाम पर किया जाता है पर कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। इसलिए इस शासन प्रणाली में वास्तविक कर्ता-कर्ता उत्तरदायी मन्त्री होते हैं। राज्य के अल्पतः कोई वास्तविक अधिकार नहीं होता। यह मित्र नाममात्र होता है।

मन्त्रीय और प्रजातीय या राष्ट्रपतीय—यह प्रभेद कार्यपालिका और विधानिका के सम्बन्ध की प्रकृति पर आधारित है। यदि कार्यपालिका विधान मण्डल में से चुनी जाती है और अपने मन्त्रियों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है तो वह साम्प्रदायिक कार्यपालिका कहलाती है। जहाँ शासन गणतन्त्रीय हो और कार्यपालिका विधान मण्डल के नियन्त्रण में आजाद हो, वहाँ यह प्रजातीय या राष्ट्रपतीय कार्यपालिका कहलाती है।

एक शक्ति और बहुशक्ति—यदि कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग की शक्ति जिम्मेदारी एक शक्ति पर हो तो वह एकशक्ति कार्यपालिका कहलाएगी। पर वास्तविक व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग कई व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में मन्त्रिमण्डल की कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग की शक्ति जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है, पर वास्तविक व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के मन्त्री करते हैं। जहाँ कार्यपालिका की शक्तियों की अन्तिम जिम्मेदारी व्यक्तियों के किसी निवास पर होती है, वहाँ कार्यपालिका बहुशक्ति कार्यपालिका कहलाएगी। स्विट्जरलैंड में मन्त्रीय परिषद, यानी फेडरल कौन्सिल, जिसमें सात आदमी होते हैं, बहुशक्ति कार्यपालिका का एक उदाहरण है।

कार्यपालिका के शक्ति—एक राज्य और दूसरे राज्य के कार्यपालिका कार्यों में कोई एकत्वता नहीं होती। मोटे तौर से कहा जाय तो कार्यपालिका निम्नलिखित कार्य करती है—

प्रशासन—कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधियों को अमल में लाना है। इस प्रयोजन के लिए कार्यपालिका कई विभागों में बाँटी जाती है, और इनमें से प्रत्येक विभाग प्रशासन की एक शाखा के लिए जिम्मेदार होता है। कार्यपालिका पर यह देखने की भी जिम्मेदारी है कि कोई आदेशी विधि का अतिक्रमण न करे। पुलिस, जिनका काम विधि-व्यवस्था कायम रखना है, कार्यपालिका का एक हिस्सा है। पुलिस अवधारणों को पकड़ती है, उनका चालान करती है और उन्हें उपयुक्त दण्ड के लिए न्यायपालिका के सामने उपस्थित करती है।

कार्यपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य भीनरी तथा बाहरी मामलों में राज्य की नीति निर्धारित करना है।

कार्यपालिका अपने विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति,

वरलास्तगी और दैनिक आचरण के नियम भी बनाती हैं ।

प्रतिरक्षा—कार्यपालिका का एक और महत्वपूर्ण कार्य राज्य के क्षेत्र और आबादी की विदेशी आक्रमणों की से रक्षा करना है । जो विभाग देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करता है, वह प्रतिरक्षा और युद्ध विभाग कहलाता है । यह विभाग जेनाओं की सन्धि और सगठन का निश्चय करता है, और जनरल तथा कमाण्डर नियुक्त करता है ।

विदेशी संबंध—विदेशी मामलों में सम्बन्ध रखने वाले कार्य राजनयिक कार्य कहलाते हैं । इनके अन्तर्गत युद्ध की घोषणा और राजनैतिक तथा वाणिज्यिक दोनों प्रकार की संधियों पर हस्ताक्षर करना भी शामिल है । अन्य राज्यों के साथ संबंधों का सम्बन्ध बनाए रखने के लिए कार्यपालिका उनके साथ राजदूतों का नियुक्त करती है । ऐसे मामलों में सम्बन्ध रखने वाले विभाग को परराष्ट्र विभाग कहते हैं ।

विनीत कार्य—यस सम्बन्ध अपने बहुत तरह के कार्यों की पूर्ति के लिए प्रति वर्ष बड़ा-बड़ी धनराशिवा संचय करती है । यह धन उन कार्यों में जाता है जो कार्यपालिका द्वारा विधान मण्डल की समूची सन्धि से जाने हैं । कार्यपालिका का यह विभाग, जो धन सम्बन्धी कार्यों की सभायता है, वित्त विभाग कहलाता है । यह विभाग न केवल विभिन्न विभागों को धन बाँटना है, बल्कि जेना-परीक्षा (audit) द्वारा उनके व्यय को भी विनियमित और नियंत्रित करता है ।

विधान कार्य—विधान मण्डल का आह्वान, सभासभान और विघटन कार्यपालिका के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । सामान्य की प्रतिमण्डलीय प्रणाली में विधियों के सम्बन्ध कार्यपालिका के विभिन्न विभागों द्वारा बनाये दिये जाते हैं और विधान मण्डल उनका निरूपण या निरसुमोदन (disapproval) कर देता है । कोई भी विधेयक विधि नहीं बन सकता यदि उस पर राज्य के अध्यक्ष के हस्ताक्षर न हो । इसके अलावा, जब विधान मण्डल का सत्र न चल रहा हो, तब विधि बनाने की शक्ति राज्य के अध्यक्ष के हाथ में होती है । कार्यपालिका द्वारा इन तरह बनाई गई विधियों अप्यादेश कहलाती हैं ।

न्यायिक कार्य—न्यायाधीन कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । सब जगह राज्य के अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह न्यायालयों द्वारा सपा-विधि दंडित गए अपराधियों की क्षमा प्रदान कर सके । यह एक अर्थ में न्यायिक शक्ति है क्योंकि राज्य का अध्यक्ष क्षमा प्रदान करने में अपराधी पर दया दिखाना है, और मामलों पर कानूनी आधार पर विचार नहीं करता ।

अच्छी कार्यपालिका के लिए आवश्यक गुण

१. कार्यपालिका में इच्छा की एकता होनी चाहिए और उसके फंक्शने दृढ़ होने चाहिए ।

२. इसका कार्य स्वतंत्र होना चाहिए ।

होता है और मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होता है। राज्य का बन्धन, चाहे वह राजा ही या राष्ट्रपति, किन्तु वास्तविक शक्तियाँ रखता है। सामन उसके नाम पर किया जाता है पर कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। इसलिए इस सामन प्रणाली में वास्तविक कर्ता-वर्ता उत्तरदायी नहीं होते हैं। राज्य के अन्धश को कोई वास्तविक अधिकार नहीं होता। यह सिर्फ नाममात्र होता है।

सम ही और प्रणालीय या राष्ट्रपतीय—यह प्रभेद कार्यपालिका और विधानिका के सम्बन्ध की प्रकृति पर आधारित है। यदि कार्यपालिका विधान मण्डल में से चुनी जाती है और अपने सब कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है तो वह मण्डीय कार्यपालिका कहलाती है। जहाँ सामन गणतन्त्रीय ही और कार्यपालिका विधान मण्डल के नियन्त्रण में आजाद हो, वहाँ यह प्रधानीय या राष्ट्रपतीय कार्यपालिका कहलाती है।

एक-शक्ति और बहुशक्ति—यदि कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग की शक्ति त्रिभेदांगी एक प्रादमी पर ही तो वह एकशक्ति कार्यपालिका कहलाएगी। पर वास्तविक व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग कई व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में सभ संस्कार की कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग की शक्ति त्रिभेदांगी राष्ट्रपति की है, पर वास्तविक व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय सरकार के मंत्री करते हैं। जहाँ कार्यपालिका की शक्तियों की अन्तिम त्रिभेदांगी व्यक्तियों के किसी निष्पाय पर होती है, वहाँ कार्यपालिका बहुशक्ति कार्यपालिका कहलाएगी। स्विट्जरलैंड में मन्त्रीय परिषद, यानी कंसल वौमिल, त्रिसमें सार आदी होते हैं, बहुशक्ति कार्यपालिका का एक उदाहरण है।

कार्यपालिका के शक्ति—एक राज्य और दूसरे राज्य के वायव्यव्य कार्यों में कोई एकस्पता नहीं होती। छोटे क्षेत्र में कहा जाय तो कार्यपालिका निम्नलिखित कार्य करती है—

प्रशासन—कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई शक्तियों की प्रकृति में जाना है। इस प्रयोजन के लिए कार्यपालिका कई विभागों में बाँटी जाती है, और इनमें में प्रत्येक विभाग प्रशासन की एक शाखा के लिए जिम्मेदार होता है। कार्यपालिका पर यह दृष्टिकोण की भी जिम्मेदारी है कि कोई आदमी विधि का अनिष्कमण न करे। पुलिस, त्रिमका काम विधि व्यवस्था कायम रखना है, कार्यपालिका का एक हिस्सा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, उनका चालान करती है और उन्हें उपयुक्त दण्ड के लिए न्यायपालिका के सामने उपस्थित करती है।

कार्यपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य भीतरों तथा बाहरी मामलों में राज्य की नीति निर्धारित करना है।

कार्यपालिका अपने विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति,

परमोच्चतम और दैनिक आचरण के नियम भी बनानी हैं।

प्रतिरक्षा—कार्यपालिका का एक और महत्वपूर्ण कार्य राज्य के क्षेत्र और आबादी की विदेशी आक्रमणों की रक्षा करना है। जो विभाग देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करता है, वह प्रतिरक्षा और युद्ध विभाग कहलाता है। यह विभाग ज्वाभों के मर्या और मरहम का निक्षण करता है, और जनरल तथा कमाण्डर नियुक्त करता है।

विदेशी सम्बंध—विदेशी मामलों में सम्बन्ध रखने वाले कार्य राजनयिक कार्य कहलाते हैं। इनके अन्तर्गत युद्ध की घोषणा और राजनयिक तथा वाणिज्यिक दोनों प्रकार की संधियों पर हस्ताक्षर करना भी शामिल है। अन्य राज्यों के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाए रखने के लिए कार्यपालिका उच्च माय राजदूतों का नियुक्ति करती है। ऐसे मामलों में सम्बन्ध रखने वाले विभाग को परराष्ट्र विभाग कहते हैं।

द्वितीय कार्य—महत्त्वपूर्ण अर्थात् बड़ा तर्क का कार्य की पूर्ति के लिए प्रति वर्ष बड़ी-बड़ी धनराशियाएँ व्यय करती हैं। यह धन उतारना मुश्किल है जो कार्यपालिका द्वारा विधान मण्डल की मजूरी से लगाये जाते हैं। कार्यपालिका का यह विभाग, जो धन सम्बन्धी कार्य को सम्भालता है, वित्त विभाग कहलाता है। यह विभाग न केवल विभिन्न विभागों को धन सौंपता है, बल्कि सरकारी-परिषद (audit) द्वारा उनके व्यय को भी विनियमित और नियंत्रित करता है।

विधायक कार्य—विधान मण्डल का आह्वान, गणानुमान और विघटन कार्य पालिका के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। धाना की सविमण्डलीय प्रणाली में विधियों के सरासिरे कार्यपालिका के विभिन्न विभागों द्वारा बना दिए जाते हैं और विधान मण्डल उनका निकट अनुमोदन या निरनुमोदन (disapproval) कर देता है। कोई भी विशेष विधि नहीं बना सकता यदि उस पर राज्य के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर न हो। इसका अलावा, जब विधान मण्डल का मन न चल रहा हो, तब विधि बनाने की शक्ति राज्य के अध्यक्ष के हाथ में होती है। कार्यपालिका द्वारा इस तरह बनाई गई विधियाँ अध्यादेश कहलाती हैं।

श्राविक कार्य—न्यायाधीश कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। यह उच्च राज्य के अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह न्यायालयों द्वारा सजा-विधि दंडित हुए अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सके। यह एक अर्थ में श्राविक शक्ति है क्योंकि राज्य का अध्यक्ष क्षमा प्रदान करने में अपराधी पर दया दिखाना है, और मामले पर कानूनी आधार पर विचार नहीं करता।

अच्छी कार्यपालिका के लिए आवश्यक गुण

१. कार्यपालिका में इच्छा की एकरता होनी चाहिए और उसके पंक्तों दृढ़ होने चाहिए।

२. इसका कार्य त्वरित होना चाहिए।

३. इसे अपने विनिश्चयों और बीच-गन्तव्य के बारे में पूर्ण गोलगोला समझनी चाहिए। वे लोगों को मध्य में पट्टे बना न चटने चाहिए।

४. कार्यपालिका को बहुत सी विवेकशील शक्तियाँ न देनी चाहिए। अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा।

५. इसकी अवधि इतनी काफी लम्बी होनी चाहिए कि यह अपने काम में ज्वलन दिखाने लगे।

६. अच्छी कार्यपालिका का मतलब महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह विधियों को लागू करने में विनम्र ईमानदार और निष्पक्ष होनी चाहिए। कार्यपालिका को घुग न लेनी चाहिए या पक्षपात न करना चाहिए।

न्यायपालिका या न्यायालय

जब न्याय कार्य एक मात्र राज्य का कार्य है। पर यह हमेशा ऐसा नहीं रहा। शुरू में राज्य के न्यायालय आदि के रूप में कोई न्यायिक अंग नहीं होते थे, और न्याय कार्य इनके कार्यों में नहीं माना जाता था। हानि उठाने वाला हानि करने वाले से मुद्दा बढ़ता जाता था। धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि कोई दोष राज्य के विरुद्ध भी अपराध माना जाने लगा। इस प्रकार धीरे-धीरे न्याय राज्य के एकाधिकार में आ गया।

न्यायपालिका का महत्व—हम ऐसे समाज को बनाना कर सकते हैं जिनमें विधि बनाने वाले अंग न हों। वास्तविकता तो यह है कि पूर्णतया परिवर्धित विधान मण्डल अंशदा हानि ही में पैदा हुए हैं। वे ५०० या ६०० वर्षों में अर्ध पुराने नहीं। विधान मण्डल की अनुपस्थिति में न्यायालय दण्डों या धार्मिक पुस्तकों के नियम लागू करते थे। इस प्रकार विधान मण्डल इनके महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि न्यायालय। हम ऐसे सम्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते, जिनमें न्यायालय न हो, क्योंकि हम उनका जगह किंग और मनोपन्नक चीज की कल्पना नहीं कर सकते। लाहें शक्ति के काल में न्यायपालिका का महत्व अनुभव हो जायगा। उसके अनुसार, किमी शासन की श्रेष्ठता की मांगे अच्छी नसोटी इसकी न्यायिक प्रणाली की दृष्टि ही है क्योंकि कोई और चीज जीवन नागरिक के कल्याण और सुरक्षा से इतना निकट सम्बन्ध नहीं रखती जितना निकट सम्बन्ध यह भावना रखती है कि वह सुनिश्चित और स्वरित न्याय पर भरोसा कर सकता है।

न्यायपालिका के कार्य

अवधारणों को दण्डित करती है और विधियों को सशक्त करती है—न्यायपालिका का पहला कार्य यह देखना है कि कोई व्यक्ति विधि का अतिक्रमण न करे। यह मौजूदा कानून को अपराध के अलग-अलग मामलों पर लागू करती है और सब कानून तोड़ने वालों को दण्ड देती है, पर किमी कानून को लागू करने में यह फँसला करना न्यायधीन का काम नहीं कि कोई कानून अच्छा है या बुरा, सभ्य है या वरम।

उगे तो उमी रूप में कानून को मानता है, जिस रूप में वह है ।

जनता के अधिकारों की रक्षा करती है—दूसरे यह देखना भी न्यायालयों का कर्तव्य है कि कार्यपालिका विधि को प्रवर्तित कराने में विधि की सीमाओं में परे न चली जाए। यदि वह उससे परे जाती है तो इसका अर्थ हुआ जनता की स्वाधीनता में हस्तक्षेप । न्यायपालिका का कर्तव्य है कि कार्यपालिका की ज्यादतियों से जनता के अधिकारों और स्वाधीनता को रक्षा करे ।

नई विधियाँ बनानी हैं—विधि का विवेचन करते हुए न्यायपालिका प्रायः नई विधि बना देती है। कभी-कभी किसी मामले की कोई खाम अवस्था किसी कानून के मौजूदा उपबन्धों में किसी में नहीं आती। ऐसी परिस्थितियों में निकटतम उपबन्ध का निर्वचन इस तरह किया जाता है और उसे इस तरह विस्तृत कर दिया जाता है कि वह उस स्थिति पर लागू हो सके। न्यायाधीश-निर्मित विधि प्रत्येक राज्य की विधि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

न्यायपालिका सविधान की पहरेदार है—जहाँ शासन का मर्यादीय रूप है, वहाँ न्यायपालिका सविधान के पहरेदार के रूप में कार्य करती है। सघनीय और राज्य सरकारों की वे सब विधियाँ, जो सविधान के प्रतिफल जाती हैं न्यायपालिका द्वारा शून्य और अप्रवृत्त घोषित कर दी जाती हैं।

न्यायिक के अलावा अन्य कार्य—बहुत बार न्यायालय कई-ऐसे कार्य करते हैं, जो असल में न्यायिक नहीं होते। वे अनुमतिदाता देते हैं, अभिभावक और न्यायो नियुक्त करते हैं, वसीयतें लेते हैं, तलाक़ मंजूर करते हैं, विवाह प्रमाणित करते हैं, और मृत व्यक्तियों की सम्पदाओं का उनके अवयवों के निमित्त प्रबन्ध करते हैं।

मद्रणा देने सम्बन्धी कार्य—कार्यपालिका विधि सम्बन्धी विंगी प्रश्न पर न्यायपालिका से परामर्श कर सकती है। ऐसी अवस्था में न्यायालय अन्वीक्षा (trial) की औपचारिकताओं में बिना गये विधि का अर्थ और अपेक्षाएँ घोषित करते हैं। पर ऐसी राय या मद्रणा खुली अदालत में देनी होगी, गुप्त रूप में नहीं। भारत का उच्चतम न्यायालय मद्रणा देने का कार्य करता है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता—हम यह देख चुके हैं कि न्यायपालिका विधि और व्यवस्था कायम रखने में तथा जनता की स्वाधीनता कायम रखने में महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है। बहुत आवश्यक है कि न्याय जल्दी, दक्षता से और निष्पक्षता से हो। लार्ड ब्राइस ने बहुत ठीक कहा है कि "यदि न्याय-कार्य बेईमानी में किया जाय तो नमक का नमकीनपन ही जाता रहा। यदि उसे कमजोरी या सनस से लागू किया जाए तो मारुति या व्यवस्था बेकार हो जाती है, क्योंकि अपराधियों को दण्ड की कठोरता से उत्तना नहीं दयाया जाता जितना उसकी निद्रिचतता से। यदि अधरे में दोषक मुक्त जाए तो किन्ना अधिक अधरे हो जाएगा।" इस प्रकार न्याय को मौघ और निष्पक्ष करने के लिए न्यायाधीश कार्यपालिका और विधान मण्डल से स्वतन्त्र

३. इसे अपने विनिश्चयो और जाँच-पड़ताल के बारे में पूर्ण गोपनीयता रखनी चाहिए। वे लोगों को गन्ध में पड़ने तथा न चलने चाहिए।

४. कार्यपालिका को बहुत सी विवेकशील प्रतिनियाँ न देनी चाहिए। अन्यथा इसका परिणाम जून होना।

५. इसकी अधि इतनी काफी लम्बी होनी चाहिए कि यह अपने काम में उचित दिखसती के सरे।

६. अच्छी कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह विधियों को लागू करने में विन्दुल ईमानदार और निष्पक्ष होनी चाहिए। कार्यपालिका को धूम न लेनी चाहिए या पक्षपात न करना चाहिए।

न्यायपालिका या न्यायांग

अब न्याय कार्य एक मात्र राज्य का कार्य है। पर यह हमेशा ऐसा नहीं रहा। शुरू में राज्य के न्यायालय आदि के रूप में कोई न्यायिक अंग नहीं होते थे, और न्याय कार्य इनके कार्यों में नहीं माना जाता था। हानि उठाने वाला हानि करने वाले में खुद बदला लेता था। धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि कोई दोष राज्य के विरुद्ध भी अपराध माना जाने लगा। इस प्रकार धीरे-धीरे न्याय राज्य के एकाधिकार में आ गया।

न्यायपालिका का महत्व—हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिनमें विधि बनाये जाते अथ न हों। वास्तविकता तो यह है कि पूणतया परिवर्तित विधान मण्डल अधिकांश हाल ही में पैदा हुए हैं। वे ५०० या ६०० वर्षों में अधिक पुराने नहीं। विधान मण्डलों की अनुपस्थिति में न्यायालय अधिकारी या धार्मिक पुत्रको के नियम लागू करते थे। इस प्रकार विधान मण्डल इनके महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने न्यायालय। हम ऐसे सम्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते, जिनमें न्यायालय न हों, क्योंकि हम उनकी जगह किसी और सतोपजना चीज की कल्पना नहीं कर सकते। लार्ड श्यान् के कथन में न्यायपालिका का महत्व अनुभव हो जायगा। उसके अनुसार, ‘विधियों कायम की श्रेष्ठता को सबसे अच्छी बनौती, इसकी न्यायिक प्रणाली की दृढ़ता ही है क्योंकि कोई और चीज जितना नागरिक के कल्याण और सुरक्षा से इनका निकट सम्बन्ध नहीं रखती जितना निकट सम्बन्ध यह भावना रखती है कि वह मुनिदिव्य और स्वर्ग न्याय पर भरोसा कर सकता है।’

न्यायपालिका के कार्य

अपराधियों को दण्डित करती है और विधियों को मर्यादित करती है—न्यायपालिका का पहला कार्य यह देखना है कि कोई व्यक्ति विधि का अनिश्चय न करे। यह मौजूदा कानून को अपराध के जलन-जलग भावों पर लागू करती है और सब कानून तोड़ने वालों को दण्ड देती है, पर किसी कानून को लागू करने में यह फर्मला करता न्यायधीन का काम नहीं कि कोई कानून अच्छा है या बुरा, मजबूत है या नरम।

जंग तो उसी रूप में कानून को मानना है, जिम रूप में वह है ।

जनता के अधिकारों की रक्षा करनी है—दूसरे यह देखना भी न्यायालया का कर्तव्य है कि कार्यपालिका विधि को प्रवर्तित कराने में विधि की सीमाओं से परे न चली जाय । यदि वह उससे परे जाती है तो शरणा अर्पण हुआ जनता की स्वाधीनता में हस्तक्षेप । न्यायपालिका का कर्तव्य है कि कार्यपालिका की ज्यादातियों से जनता के अधिकारों और स्वाधीनता को रक्षा करे ।

नई विधियाँ बनानी हैं—विधि का त्रिवेचन करते हुए न्यायपालिका प्रायः नई विधि बना देती है । कभी-कभी किसी मामले की वार्ड खाम अवस्था किसी कानून के भीरूदा उदाहणों में किसी में नहीं आती । ऐसी परिस्थितियों में निकटतम उपबन्ध का निर्वचन इस तरह किया जाता है और उसे इस तरह विस्तृत कर दिया जाता है कि वह उस स्थिति पर लागू हो सके । न्यायाधीश-निर्मित विधि प्रायः राज्य की विधि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ।

राज्यपालिका सचिवालय को पहरेदार है—जहाँ शासन का सघनीय रूप है, वहाँ न्यायपालिका सचिवालय के पहरेदार के रूप में कार्य करती है । सघनीय और राज्य सरकारों की वे सब विधियाँ, जो सचिवालय के प्रतिकूल जाती हैं न्यायपालिका द्वारा सून्य और अप्रवृत्त घोषित कर दी जाती हैं ।

न्यायिक क प्रलाप अन्व कार्य—सहुत बार न्यायालय कई-दो कार्य करते हैं, जो अकल में न्यायिक नहीं होते । वे अनुज्ञप्तिपत्र देते हैं, अभिभावक और न्यायी नियुक्त करते हैं वसीयतें लते हैं, तलाक मंजूर करते हैं, विवाह प्रमाणित करते हैं, और मृत परिशयो की सम्पदाओं का उनके अवयवों के निमित्त प्रबन्ध करते हैं ।

मन्त्रणा देने सम्बन्धी कार्य—न्यायपालिका विधि सम्बन्धी विगी प्रश्न पर न्यायपालिका स परामर्श कर सकती है । ऐसी अवस्था में न्यायालय अन्वीक्षा (trial) की औरबारिकताओं में बिना सपे विधि का अर्थ और अपेक्षाएँ घोषित करते हैं । पर ऐसी राय या मन्त्रणा सुली अदालत में देनी होगी, गुप्त रूप में नहीं । भारत का उच्चतम न्यायालय मन्त्रणा देने का कार्य करता है ।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता—हम यह देख चुके हैं कि न्यायपालिका विधि और व्यवस्था कायम रखने में तथा जनता की स्वाधीनता कायम रखने में महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है । सहुत आवश्यक है कि न्याय अल्दी, दक्षता में और निष्पक्षता में हो । लार्ड वाइम ने बहुत ठीक कहा है कि 'यदि न्याय-कार्य बेईमानी में किया जाय तो सभ्यता का नमकीनपन हो जाता रहा । यदि उसे कमजोरी या सनक से लागू किया जाए तो सार्वभ्यता या व्यवस्था बेभार हो जाती है, क्योंकि अपराधियों को दण्ड की सज़ा से उतना नहीं दवाया जाना जितना उनकी निरिच्छता में । यदि अधरे में धीरे-धीरे दण्ड नष्ट हो किन्तु अधिक अधरे हो जाएगा ।' इस प्रकार न्याय को धीरे-धीरे और निष्पक्ष बनाने के लिए न्यायाधीश कार्यपालिका और विधान मण्डल से स्वतन्त्र

इस सिद्धान्त का सूत्र—मौनवेत्स्यू का यह कहना सही है कि दो या तीन शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देना जाना की स्वाभौतना के लिए अहितकर है। दूसरे, आत्र के जमाने में शासन कार्य को सब शाखाओं में विभेदीकृत जाना ही जरूरत होती है। इस प्रकार शक्तियों और बाधों का पृथक्करण शासन की दक्षता के लिए भी आवश्यक है।

पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जब हम शक्तियों के पृथक्करण की बात कहते हैं, तब हमारा आशय बहुत अधिक पृथक्करण से नहीं होना, अल्पमध्यम पृथक्करण से होना है। मध्यम पृथक्करण का मतलब यह है कि सरकार की तीनों शाखाओं में, जहाँ तक दक्षता के लिए आवश्यक है वहाँ तक, सहयोग रहे। अन्य मामलों में, जहाँ उनमें पृथक्करण वाञ्छनीय है, तीनों अथवा एक दूसरे पर रोफ़ के रूप में कार्य कर सकते हैं।

ध्यानोचना—शक्तियों के अत्यधिक पृथक्करण के सिद्धान्त की अनेक प्रकार से आलोचना हुई है और आत्र के जमाने में इसे समझ नहीं लिया जा सकता। इस सिद्धान्त पर निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाई जाती हैं—

अत्यधिक पृथक्करण वाञ्छनीय नहीं—मौनवेत्स्यू ने तीनों शक्तियों का जमा पृथक्करण किया है, वंशासकार के दक्ष सचिवान्त की दृष्टि से वाञ्छनीय नहीं। कुछ पृथक्करण तो दक्षता बढ़ाना है, पर पूर्ण पृथक्करण का परिणाम इसके विपरीत होता है। यह शासन मन को टर कर देता है।

अत्यधिक पृथक्करण असम्भव है—अत्यधिक पृथक्करण न केवल अवाञ्छनीय है बल्कि यह असम्भव भी है। सरकार एक इकाई है और इसके कार्यों को एक दूसरे से विलुप्त पृथक् भागों में बाँट देना असम्भव है।

अत्यधिक विभाजन कहीं नहीं है—वास्तविक व्यवहार में शासन के तीनों अंगों में पूर्ण पृथक्ता नहीं है। आधुनिक काल में अधिकतर देशों में शासन की मंत्रिमण्डलीय प्रणाली है और इस प्रणाली में कार्यांग और विधानांग निकट सहयोग से काम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ही एकमात्र महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ शासन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित कहा जा सकता है। पर यूनाइटेड स्टेट्स में कार्यांग और विधानांग में पूर्ण पृथक्करण नहीं है। तब तो यह है कि मौनवेत्स्यू ने स्वयं अपने दूरदर्शन-निवास में इंग्लिश मंत्रिमण्डल की गन्त रूप में पढ़ा। वहाँ उसके समय भी मंत्रिमण्डलीय प्रणाली प्रचलित थी और मंत्रिमण्डलीय प्रणाली मौनवेत्स्यू द्वारा सोचे गए शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त का निरोध है।

तीनों अंगों में समता नहीं—शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त इस कल्पना पर आधारित है कि शासन के तीनों अंग प्रविष्टा और शक्ति में समान हैं, पर उनकी समानता सिद्धान्त रूप में ही है। साधारणतया व्यवहार में आत्रकाल विधानांग की अन्य दोनों अंगों से ऊँचा स्थान प्राप्त है।

यह सिद्धान्त पुराना पड़ गया—सबिन्सो ने वृषस्वरण का सिद्धान्त पुराना पड़ चुका है। यह आजकल के सविधानशास्त्रियों को पसंद नहीं। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाएगी कि पिछले १०० वर्षों में बहुत अधिक सविधान मन्त्रिमंडलीय शासन के नमूने पर बनाए गये हैं। दूसरी बात यह कि शासन के किसी अंग द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग करने पर प्रबुद्ध लोकमत मौननेस्वयू द्वारा मुचाई गई रोकों की अपेक्षा अपितु अच्छी रोक लगा सकता है।

सारांश

सरकार कितने कहते हैं—सरकार राज्य की वह अभिवर्ता है जिसके द्वारा इसके प्राधिकार का प्रयोग होता है और इसका प्रयोजन पूरा किया जाता है।

सरकार के अंग—आज के जमाने में प्रत्येक सरकार के तीन अंग होने हैं (१) विधायिका या विधानांग वह अंग है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा रूप ग्रहण करती है और विधियों के रूप में अभिव्यक्त होती है। (२) कार्योक्त या कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करती है। (३) न्यायांग या न्यायपालिका यह देखती है कि प्रत्येक व्यक्ति इन विधियों का ठीक-ठीक पालन करे। अपने-अपने स्थान में ये तीनों अंग महत्त्वपूर्ण हैं, पर लोकतंत्रों में (कुछ संघानों को छोड़ कर) विधायिका को ऊँची स्थिति प्राप्त है। संघानों में प्रायः न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धान्त लागू किया जाता है।

विधायिका

विधायिका के कार्य—(१) नई विधियाँ बनाना और प्रचलित विधियों को संशोधित या निरस्त करना। (२) राज्य के वित्तों का नियंत्रण करना। (३) शासन के संसदीय रूप में कार्यपालिका का नियंत्रण करना। (४) अपने कार्य-संचालन और कार्य-याही के लिए नियम बनाना। (५) अपने सदस्यों की अहंताएँ निर्धारित करना। (६) राजद्रोह के अपराधी मंत्रियों और अन्य अधिकारियों पर महाभियोग लगाना। (७) भ्रष्ट न्यायाधीशों की बर्खास्तगी का समर्थन करना।

विधानमंडल का गठन—आजकल अधिकतर विधानमंडल दो सदनों वाले होते हैं। द्वितीय सदन और प्रथम सदन। द्वितीय सदन आनुवंशिक या नामजद या निर्वाचित या अर्धत नामजद और अर्धत निर्वाचित होते हैं। जो विधानमंडल प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, उन्हें छोड़कर दूसरे द्वितीय सदनों को साधारणतया प्रथम सदन या लोकसभा की अपेक्षा कम शक्तिवाली होती हैं। प्रथम सदन या लोकसभाएँ सब जगह जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होती हैं। यदि मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है तो वे प्रथम सदन के प्रति ही अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हैं। प्रथम सदनों को साधारणतया घन सवधी मामलों में अत्यन्त नियंत्रण होता है।

द्वितीय सदनों की उत्पत्ति—द्वितीय सदनों की उपयोगिता पर प्रायः

न्यायपालिका या न्यायाग

जनताधारण की दृष्टि से न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। औनत व्यक्ति सरकार की धोखता का फंसला इसकी न्यायपालिका से करता है।

न्यायपालिका के कार्य—(१) अपराधियों को दण्ड देकर यह जनता से कानूनों का आदर कराती है। (२) यह कार्यपालिका के अनुचित हस्तक्षेप से जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। (३) अस्पष्ट विधियाँ के नियंत्रण द्वारा यह नई विधियों को जन्म देती है, जो न्यायाधीश-निर्मित विधि कहलानी है। (४) सघानों में न्यायपालिका सविधान के पहरेदार या रक्षक के रूप में काम करती है। (५) विधि सम्बन्धी मामलों में कार्यपालिका के सलाह माँगने पर न्यायपालिका उसे सलाह देती है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता—न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए निम्नलिखित बातें करनी आवश्यक हैं— (१) न्यायाधीश बकीलों में से छांटने चाहिए। (२) वे नामजद होने चाहिए, निर्वाचन नहीं। (३) वे सदाचरण-पर्यन्त अपने पदों पर रहने चाहिए और उनकी बर्खास्तगी अकेली कार्यपालिका या विधायिका के हाथ में नहीं होनी चाहिए। (४) उन्हें अच्छा वेतन मिलना चाहिए, और उनके पदधारण काल में उनका वेतन घटाया नहीं जाना चाहिए।

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के साथ एक फ्रेंच दार्शनिक मोन्तेस्क्यू का नाम जुड़ा हुआ है। इस सिद्धान्त के अनुसार, शासन की तीनों शक्तियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाने से जुलूम आता है और उनके पृथक्करण से स्वाधीनता आती है। जनता की स्वाधीनता उस अवस्था में अधिक होगी, यदि प्रत्येक अंग अन्य अंगों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहता हुआ अपने लिए निर्धारित क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रयोग करे।

सिद्धान्त का मूल्य—मोन्तेस्क्यू का यह कहनाय ही है कि दो या तीन शक्तियों का इकट्ठा हो जाना जनता की स्वाधीनता के लिए अहितकर है। आजकल शासन की दक्षता के लिए यह भी आवश्यक है कि शक्तियों और कार्यों का पृथक्करण हो। पर हमारा आशय सिर्फ मध्यम दर्जे के पृथक्करण से है, पूर्ण पृथक्करण से नहीं। मध्यम दर्जे के पृथक्करण में यह बात या जानी है कि दक्षता के लिए जहाँ तक आवश्यक है वहाँ तक तीनों शाखाओं में सहयोग हो।

प्रान्तेचना—(१) अत्यधिक पृथक्करण वाछनीय नहीं। (२) अन्यधिक पृथक्करण असंभव है। (३) अत्यधिक पृथक्करण कही नहीं है। (४) तीनों अंगों में कोई शक्ति नहीं है। (५) यह सिद्धान्त अतः पुराना पद था है।

प्रश्न

१. शासन के मुख्य अंग कौन से हैं ? उनके अपने-अपने कार्य बताइए।

(५० वि०धर्म, १९४८ और अप्रैल, १९५३)

1. What are the chief organs of Government? Describe their respective functions (P U. April 1948 and April 1953)
२. सरकार के विभिन्न अंग कौन-कौन से हैं? उनमें क्या-क्या सम्बन्ध है?
(पं० वि० नवम्बर, १९५१)
2. What are the different organs of Government? What is the relationship between them? (P U. Sept. 1951)
३. द्विसदनी विधानमण्डल के पक्ष और विपक्ष में क्या-क्या युक्तियाँ हैं?
3. What are the arguments for and against a bicameral system of legislature?
४. कार्यपालिका के कार्य और प्रकार क्या-क्या हैं?
4. What are the functions and kinds of executive?
५. लोकतन्त्रीय राज्य में न्यायपालिका के क्या-क्या कार्य हैं? न्यायपालिका का मण्डल कैसे होना चाहिए? इसकी शक्तियाँ क्या होनी चाहिए?
(पं० वि० सितम्बर, १९५३)
5. Describe the functions of the Judiciary in a democratic state? How should the judiciary be constituted? What should be its powers? (P U. Sept. 1953)
६. शक्तियों के पृथक्करण का क्या अर्थ है? किन्हीं सम्बन्धित राज्यों में स्वतन्त्र न्यायपालिका का होना क्यों आवश्यक है? (पं० वि० अप्रैल, १९५३)
6. What is meant by 'Separation of Powers'? Why is an independent judiciary necessary in a civilised state?
(P U. April, 1952)
७. शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की प्रालोचना कीजिए।
7. Critically examine the theory of separation of powers
८. न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका से क्या सम्बन्ध होना चाहिए?
8. What should be the relations of the judiciary with the executive and legislature?
९. लोकतन्त्रीय राज्य में कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या हैं? विधान मण्डल के साथ इसके क्या सम्बन्ध हैं?
9. What are the main functions of the executive in a democratic state? Describe its relations with the legislature.

सरकार के रूप—राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र, लोकतन्त्र, और अधिनायकतन्त्र

पुराना वर्गीकरण—राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तू ने सरकारों का वर्गीकरण उन व्यक्तियों की संख्या के अनुसार किया था जिनमें राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति निहित होती थी।

इस मिश्रण के अनुसार सरकारों का वर्गीकरण निर्मालक्षित रीति में किया गया था—

(१) राजतन्त्र—सर्वोच्च अधिकार एक व्यक्ति में निहित होता था।

(२) कुलीनतन्त्र—सर्वोच्च सत्ता कई (सर्वोत्तम) व्यक्तियों में निहित होती थी।

(३) बहुतन्त्र (Polity)—सर्वोच्च सत्ता बहुत से व्यक्तियों में निहित होती थी।

अरस्तू के अनुसार उपरोक्त तीन रूप शासन के शुद्ध या सामान्य रूप थे, क्योंकि उनमें एक, कई या बहुत से व्यक्ति सर्वहित की दृष्टि से शासन करते थे। पर इन तीनों में प्रत्येक रूप का एक भ्रष्ट या विवृत रूप भी था। जब शासन सत्ताधिकारियों के अपने शुद्ध स्वार्थों के लाभ के लिए बतलाया जाता था, तब राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और बहुतन्त्र विषड कर अत्याचारी शासन अल्पतन्त्र और लोकतन्त्र का रूप ले लेता था। इस प्रकार अरस्तू के अनुसार तीन शुद्ध या सामान्य रूप और तीन भ्रष्ट या विवृत रूप हैं।

शुद्ध रूप

- (१) राजतन्त्र
- (२) कुलीनतन्त्र
- (३) बहुतन्त्र

विवृत रूप

- (१) अत्याचारी शासन
- (२) अल्पतन्त्र
- (३) लोकतन्त्र

अरस्तू का यह वर्गीकरण आधुनिक दशाओं के साथ मेल नहीं खाता। आज-कल लोकतन्त्र शासन का सबसे अच्छा और सबसे अधिक यत्न किया जाने वाला रूप समझा जाता है। पर अरस्तू ने इसे एक विवृत रूप बतलाया था। इसका अर्थ यह हुआ कि अरस्तू की दृष्टि में न तो इंग्लैंड में मौजूदा शासन अच्छा माना जाएगा

भारत अमरीका में। आजकल के किसी भी सम्य देश में सर्वोच्चता किसी एक व्यक्ति या छोटे से वर्ग में निहित नहीं। इंग्लैन्ड में रानी है, पर इन तथ्य से अस्तु के वास्तविक वर्गीकरण का कोई निर्देश नहीं मिलता और यह आज की सरकारों पर लागू नहीं किया जा सकता।

वर्गीकरण—आज के जमाने में हम सरकारों के दो भोटे भाग कर सकते हैं—

(१) लोकतंत्र

(२) अधिनायक तंत्र

चू कि अधिकतर राज्यों में शासन का लोकतंत्रीय रूप है और चू कि वे गठन में एक दूसरे से भिन्न हैं इसलिए लोकतंत्रों को भी आगे तीन शीर्षकों में रखा जा सकता है—

(१) यह सार्वभौमिक राजतंत्र है या गणतंत्र ?

(२) यह शासन का समद्रीय रूप है अथवा प्रधानीय या राष्ट्रपतीय रूप है ?

(३) यह एकीय (Unitary) रूप है या सविधानीय रूप है।

पर यह याद रखना चाहिए कि कोई सरकार समद्रीय और एकीय होनी हुई भी सार्वभौमिक राजतंत्र हो सकती है। इंग्लैड में राज्य की अध्यक्ष रानी है, पर उनमें सार्वभौमिकता समद्रीय है और शासन एकीय है। दूसरी ओर, कोई सरकार एक ही समय लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र नहीं हो सकती। इसी तरह यह एक ही समय प्रधानीय या राष्ट्रपतीय और समद्रीय दोनों नहीं हो सकती।

अब हम पुराने वर्गीकरण में से शिफा राजतंत्र और कूलीनतंत्र पर तथा नए वर्गीकरण के सब रूपों पर विचार करेंगे।

राजतंत्र—राजतंत्र से अरम्भ का आशय राज्य के लोगों के आम हित की दृष्टि से किए जाने वाले एक व्यक्ति के निरंकुश शासन से था। राजतंत्र आनुवंशिक या निर्वाचित या इन दोनों का मेल हो सकता है, पर अधिकतर राजतंत्र आनुवंशिक ही हुए हैं।

राजतंत्रों में एक और भेद यह हो गया है कि वे निरंकुश राजतंत्र हो सकते हैं या सार्वभौमिक राजतंत्र हो सकते हैं। पूर्ण राजतंत्र का राजा राज्य के पूर्ण अधिकार का प्रयोग करता है। उनकी इच्छा ही विधि है। भारत में चन्द्रगुप्त, अशोक और अकबर वे सब निरंकुश राजा हुए हैं। इसके विपरीत, सार्वभौमिक राजा वह है जिसका प्राधिकार सीमित और विधि प्रदा, परम्परा और रुडि द्वारा नियत है। इंग्लैड की रानी आज सार्वभौमिक राजा की एक उदाहरण है।

पूर्ण और हितकर राजतंत्र के बहुत से लाभ बताए जाते हैं। प्राय यह कहा जाता है कि राज्य की शक्ति और ससाधन एक व्यक्ति के हाथ में इकट्ठे हो जाने से निरंकुश राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत थोड़े समय में जीवन की आशय अक-स्थाए पैदा कर सकता है। इस व्यक्ति के समर्थन में इतिहास से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अशोक, अकबर, एलिजाबेथ, पीटर महान, ये सब ऐसे ही शासक थे।

उनके शासनकाल में लोगों का जीवन बड़ा मुसीबत था, पर पूर्ण राजतंत्र के समयक यह भूल जाते हैं कि वस्तुतः अच्छे राजाओं के उदाहरण इतिहास में दुर्लभ हैं। दूसरी ओर, इतिहास क्रूर और दुष्ट राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी शक्ति, लिप्सा, शक्त और विलास के लिए अपनी प्रजा के जीवनों को बरबाद कर दिया। आजकल व्यक्ति स्वाधीनता के प्रेमियों को हिनकर राजतंत्र पर भी भावति होगी।

कुलीनतंत्र—कुलीनतंत्र की परिभाषा यह की जा सकती है कि वह शासनतंत्र जिसमें राज्य के अफसरों को चुनने और राज्य की नीतियां के निर्धारण में अपेक्षा की हो सके नागरिकों की भावाज होती है। यीक लोग इसे सर्वोत्तम व्यक्तिओं द्वारा शासन मानते थे। पर यह बात स्पष्ट नहीं है, कि सर्वोत्तम शब्द का अर्थ ज्ञान, शिक्षा, अनुभव, और नैतिक चरित्र की दृष्टि से सर्वोत्तम या पावन, जन्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से सर्वोत्तम था। सर्वोत्तम शब्द का चाहे जो अर्थ हो पर कुलीनतंत्र शासन का वह रूप है, जिसमें मात्रा या सभ्यता के बजाय श्रेष्ठता को महत्व दिया जाता है। कुलीनतंत्र के प्रेमी लोकतंत्र को अज्ञान का शासन कहते हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र के समर्थक कुलीनतंत्र की बुराई करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से आदमी अपने स्वार्थ के लिए बहुतों का शोषण करते हैं। कुलीनतंत्र का अर्थ कुछ अच्छे शिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों का शासन है, जो भी इसमें शीघ्र ही विगड़ कर अल्पतंत्र के रूप में अर्थात् कुछ घनी व्यक्तियों के शासन में बदल जाने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा, यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि सर्वोत्तम कौन हैं, और उनके लिए क्या बमोटी है।

लोकतंत्र

लोकतंत्र का अर्थ—हम लोकतंत्र के युग में रहते हैं। लोकतंत्र शासन, राज्य और समाज का एक रूप है।

शासन का रूप—अधिकांश सभ्य राज्यों में शासन का प्रचलित रूप लोकतंत्र है। शासन के एक रूप के तौर पर लोकतंत्र की अनेक तरह परिभाषा की गई है। प्राचीन ग्रीक लोग इसे बहुता द्वारा शासन के रूप में परिभाषित करते थे। प्रोफेसर सीली ने इसे ऐसा शासन बताया है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा होना है। लार्ड वाइस ने इसे शासन का ऐसा रूप बताया है जिसमें प्रत्येक राज्य की शासन शक्ति किसी खास वर्ग या वर्गों में निहित न होकर समस्त सारे समुदाय के सदस्यों में निहित होती है। एक और परिभाषा जो बहुत बार उद्धृत की जाती है अब्राहम लिंकन द्वारा की गई परिभाषा है। उसने 'इसे जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए किया जाने वाला शासन' बताया है। इस प्रकार, लोकतंत्र में राज्य की सर्वोच्च सत्ता सारी जनता में निहित होती है। सब लोगों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन में हिस्सा होना है। शासन का यही एक रूप है, जिसमें शासक और शासित में कोई भेद नहीं होता।

राज्य के रूप में—लोकतन्त्र शासन का ही रूप नहीं है। यह राज्य का और समाज का भी एक रूप है। प्रायः लोकतन्त्र इन तीनों का मेल होता है। शासन के लोकतंत्रीय रूप से लोकतंत्रीय राज्य ध्वनित होता है, पर किमी लोकतंत्रीय राज्य में यह आवश्यक नहीं कि सरकार लोकतंत्रीय ही हो। लोकतंत्रीय राज्य वह है जिस में सारा समुदाय सर्वोच्च और नियन्त्रणकारी सत्ता होता है। लोकतंत्रीय राज्य का शासन राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र या लोचनत्र हो सकता है।

समाज के रूप में—राज्य के और प्रकार के रूप के अलावा, लोकतन्त्र समाज की व्यवस्था का नाम भी है। समाज की व्यवस्था के रूप में लोकतन्त्र अपने सब सदस्यों में समता और बंधुता की भावना ध्वनित करता है। पर हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि लोकतंत्रीय समाज, राज्य और सरकार एक साथ ही होंगे। मुसलमानों में समाज लोकतंत्रीय था, पर उनकी सरकार निरबुद्ध राजतन्त्र थी। आजकल हम में लोकतंत्रीय समाज तो है, पर शासन का लोकतंत्रीय रूप नहीं है। हिन्दुओं का समाज लोकतंत्रीय नहीं था, पर प्राचीन हिन्दू भारत में लोकतंत्रीय राज्य भी थे और सरकारें भी।

लोकतन्त्र के प्रकार—लोकतन्त्र का वर्गीकरण इस तरह किया जा सकता है—

(क) प्रत्यक्ष या सीधा लोकतन्त्र।

(ख) परोक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र—प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में सब नागरिक सभा के रूप में बैठने हैं, और राज्य की इच्छा को रूप देते और अभिव्यक्त करते हैं। वे अपनी ओर से काम करने के लिए प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि नहीं चुनते। जैसा कि इनकी प्रकृति से स्पष्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सिर्फ उन राज्यों में संभव है, जिनकी आबादी बहुत छोटी है और जिनकी समस्याएँ बहुत थोड़ी तथा सरल हैं। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की प्रणाली आधुनिक काल के बड़े और सङ्घल राज्यों के लिए ठीक नहीं। जहाँ एक राज्य की आबादी करोड़ों में है, वहाँ सब नागरिकों को एक सभा में इकट्ठा करना संभव नहीं। प्राचीन ग्रीस और रोम में, जहाँ राज्य नगर-राज्य होता था, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र चल सकता था। आजकल प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के एवमात्र उदाहरण स्विट्जरलैंड के चार कैंटन या जिले हैं। स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटनों में, जहाँ प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र है, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की हानि को पूरा करने के लिए रीपरेण्डम या परिपुण्ड (Referendum) का और उपक्रमण या प्रारम्भण (Initiative) का प्रयोग किया जाता है। हम इन उपायों के अर्थ और प्रयोजन पर एक बाद के अध्याय में विचार करेंगे।

परोक्ष लोकतन्त्र—आजकल लोकतन्त्र का यही रूप प्रचलित है। परोक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र में राज्य की इच्छा जनता द्वारा अपने उन प्रत्यायुक्तों या प्रतिनिधियों की माफ़त अभिव्यक्त की जाती है, जो आम चुनाव में निश्चित अवधि के लिए उनके द्वारा चुने जाते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र में भी प्राधिकार का प्रथम

सौत जनता ही है, पर यह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र से इस बात में भिन्न है कि प्रतिनि-
ध्यात्मक लोकतन्त्र इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जनता स्वयं उम प्राधिकार का
प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से और सनोपजनक रीति से नहीं कर सकती।

लोकतन्त्र के पक्ष और विपक्ष में युक्तियाँ

लोकतन्त्र के गुण

✓समता पर आधारित है—लोकतन्त्र ही शासन का एक रूप है जो समता के
सिद्धान्त पर आधारित है। प्रथमतः, यह जन्म धन, ज्ञान या वर्ण, रंग, धर्म
और लिंग का बिना विचार किए, सब आदमियों के परिवर्धन और सुधार को
बराबर महत्व देता है। दूसरे, सब नागरिकों को, चाहे वे बड़े हों या छोटे, धनी
हों या गरीब, राज्य के मामलों में बराबर अधिकार होता है। राज्य की विधि
सबमें एक सा व्यवहार करती है। सब नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य
बराबर हैं। संक्षेप में, लोकतन्त्र हम धारणा पर आधारित है कि राज्य सब नागरिकों
का है और कि इसके मामले हर विषय की चिन्ता का विषय है। इस प्रकार, यह
मनुष्य को उठा कर सबके बराबर कर देता है और किसी से हीन नहीं रहने देता।

✓आधिकतम स्वाधीनता देना है—दूसरे, लोकतन्त्र शासन का एकमात्र रूप है
जिसमें आदमी को अधिकतम स्वाधीनता मिल सकती है। राज्य की सुरक्षा का
ध्यान रखने हुए यह विचार, भाषण, सभरण, और साहचर्य की पूर्ण स्वाधीनता
देता है। इनकी अधिक स्वाधीनता शासन के किमी और रूप में समभव नहीं।

✓सम्मति द्वारा शासन—लोकतन्त्र की एक और अच्छी विशेषता यह है कि
यह सम्मति द्वारा शासन है। लोग शासन के लिए अनुपयुक्त सरकार के नीचे कष्ट
पाने के लिए बाधित नहीं होते। लोकतन्त्र में लोग बिना हिंसा का प्रयोग किए अपनी
सरकार बदल सकते हैं। शासन के अन्य किमी रूप में यह सुविधा नहीं। फिर, यह
शासन का ऐसा एकमात्र रूप है जिसमें नागरिक और शासन में कोई भेद नहीं और
शासन शासन भी है तथा शासन शासन भी है।

✓यह शिक्षा है—लोकतन्त्र का शिक्षात्मक महत्व भी बड़ा है। राज्य के
सापने आने वाले और शासन के संचालन सम्बन्धी बहुत सी समस्याओं के बारे में
लोगों को लोकतन्त्र प्रणाली में जितना ज्ञान होता है, उतना शासन के किमी अन्य
रूप में नहीं होता। आम चुनाव लोगों में अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक
मामलों में लोगों की दिलचस्पी ही नहीं पैदा करते, बल्कि उन्हें इनके बारे में सोचने
और तर्क करने के लिए मजबूर करते हैं।

✓चरित्र-निर्माण करता है—लोकतन्त्र का जनता के चरित्र पर ऊँचा उठाने
वाला प्रभाव होता है। यह अपने नागरिकों में स्वावलम्बन, स्वयंसेवकत्व, सहयोग,
सहिष्णुता और जिम्मेदारी के गुण पैदा करता है। तथ्यतः, लोकतन्त्रीय शासन
और समाज आदमी के चरित्रों का विकास में सहायक होते हैं।

/ देशभक्ति को बढ़ाता है—लोकतन्त्र आदमी के मन में देशभक्ति या अपने देश का प्रेम बढ़ता है। इसका कारण यह तथ्य है कि लोकतन्त्र में राज्य और सरकार जनता की होती है।

यह स्वार्थी होता है—यदि किसी राज्य में शासन का रूप लोकतन्त्रीय है तो शक्ति का घनत्व बहुत कम हो जाता है। जब लोग आम चुनावों में शांतिपूर्ण तरीके से शासन को बदल सकते हैं तब उन्हें हिंसक और शक्तिवारी विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जनता का उन विधियों को अतिशय घृणा जो उन्होंने अपने लिए बनाया है, नैतिक दृष्टि में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, लोकतन्त्र शासन का एक स्वार्थी रूप है।

लोकतन्त्र के दोष

लोकतन्त्र की बहुत आलोचना की गई है। इस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ उठायी जाती हैं —

(१) लोकतन्त्र के प्रेमी लोकतन्त्र को अज्ञानियों का शासन बताते हैं। उनकी मान्यता यह है कि शासन कार्य के लिए विशेष ज्ञान और विशेष प्रशिक्षण चाहिए जो मन्त्रियों तथा जनता के प्रतिनिधियों को प्राप्त नहीं हो सकता। उनके अनुसार, लोकतन्त्र मात्र या मजबूती को अनुचित महत्त्व देता है और श्रेष्ठता की उपेक्षा करता है। लोकतन्त्र बहुमत का शासन होता है। इसलिए हमें सोचने से बर्हिमान मनुष्यों की अपेक्षा १०० मूर्खों की बात उदादा चलेगी।

(२) दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि अधिकतर लोग राज्य के मामलों में निराल्प दिलचस्पी नहीं लेते। इस कारण लोकतन्त्र में भी शक्ति का प्रयोग सामान्य में सोचने से व्यक्तिगतों द्वारा ही किया जाता है और इस प्रकार अपने सामयिक मसालों में यह अलान्त्र में अगुआ नहीं।

(३) उपरोक्त कारणों से यह भी कहा जाता है कि लोकतन्त्र में शक्ति श्याभीमता और समता का दावा किया जाता है वे मिडान्त मात्र हैं, व्यवहार में नहीं आता।

(४) यह भी कहा जाता है कि लोकतन्त्रीय देशों में राजनैतिक दल अपने दल प्रचार, मिडान्तवारी और भ्रष्टाचार से जनता को लाभ की अपेक्षा शक्ति अधिक पसुंधते हैं। राजनैतिक नेता लोगों की भावनाएँ प्रकट कर उनके मत प्राप्त कर लेते हैं और जूने जाने के बाद से अपनी दक्षिण का प्रयोग अपनी स्वार्थ-मिडि के लिए करते हैं। ऐसी अवस्था में जनता का शिक्षण और चरित्र-निर्माण नहीं हो सकता। मंत्रियों के साथ लोगों का सीधा सम्पर्क होने के कारण अनुशासन सिधिल हो जाता है। लोग मन्त्रियों से संघर्षित अनुग्रह की आशा करते हैं, और मन्त्री अपने मन्त्रियों और मित्रों का बड़ी-बड़ी नोकरीय प ने में मदद करते हैं। इसका परिणाम होता है पक्षपात और भ्रष्टाचार और उसने शासन में अक्षमता पैदा होती है।

(५) लोकतन्त्र शासन का अधिक खर्चीला रूप है। सरकार को चुनावों पर और विधान मंडल के सदस्यों के वेतनों और भत्तों पर बहुत बड़ी धनराशियाँ खर्च करनी पड़ती हैं।

लोकतन्त्र का मूल्यांकन—लोकतन्त्र पर किए गए उपर्युक्त प्रत्येक आरोप में कुछ न कुछ सचाई है, पर साथ ही वे आरोप बहुत अतिरिक्त हैं। शासन की कोई भी प्रणाली त्रुटिहीन नहीं पर शासन के अन्य रूपों की तुलना में लोकतन्त्र में कम बुराईयाँ हैं। इसके गुण इसके दोषों की अपेक्षा सुनिश्चित रूप से बहुत अधिक हैं।

हमें याद रखना चाहिए कि लोकतन्त्र शासन का एक कठिन रूप है। इसके दक्ष संचालन के लिए इने चलाने वाले लोगों में चरित्र और प्रशिक्षण का एक निश्चित स्तर होना चाहिए। लोकतन्त्र की सफलता के लिए कुछ बातों का होना परमावश्यक है। यदि वे बातें हो तो लोकतन्त्र में उन अनेक बुराईयों से नुबानाव होने की सम्भावना नहीं रहनी जो इसमें बटाई जाती हैं।

लोकतन्त्र की सफलता के लिए अत्यन्त शर्तें सबल और प्रबुद्ध लोकमत—सबल और प्रबुद्ध लोकमत लोकतन्त्र की सफलता के लिए पहली और सबसे अधिक आवश्यक शर्त है। यह विधानमण्डल के सदस्यों और अन्य सरकारी अफसरों को नियमित रखने के लिए आवश्यक है। ऐसा न होने पर वे जनताधारण के हितों की उद्देश्य करके स्वार्थ मिद्धि की दिशा में जाएंगे।

शिक्षा—यहाँ शिक्षा का अर्थ राजनीतिक शिक्षा है, पढाई-लिखाई नहीं, यद्यपि बड़ा पढाई-लिखाई ही तो और भी अच्छा है। शिक्षा में ही लोगों को जानकारी प्राप्त होनी है। उन्हें अपने सामने आनेवाले प्रश्नों और समस्याओं का पता लगना है। ऐसी परिस्थितियों में लोग अपने प्रतिनिधियों के कामों का अधिक अच्छी तरह फंमला कर सकते हैं। लोगों की शिक्षा होने पर स्वाधीनता और नमता की अतिरिक्त भावनाएँ पक्षपात, गलत प्रचार और अनुशासनहीनता, ये सब बुराईयाँ खत्म हो जाएँगी।

स्थानीय स्वशासन—पचायतों और नगरपालिकाओं में लोगों को स्वशासन की जो शिक्षा मिलनी है, वह नागरिकता के लिए उनकी राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण की दिशा में एक कदम होता है।

स्वतन्त्र प्रेस या संपादक—सबल लोकमत बनाने के लिए स्वतन्त्र प्रेस या संचारों का होना परम आवश्यक है।

आर्थिक सुख—लोकतन्त्र की सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लोगों को आर्थिक सुरक्षा अनुभव होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभाव में मूकित होनी चाहिए। अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वाह के लिए आर्थिक समृद्धि बहुत आवश्यक है। राज्य के कर्मचारियों आर्थिक दृष्टि से सुखी होने पर प्रलोभनों में कम पड़ेंगे और मतदाना अपने मत नहीं बेचेंगे। समृद्धि से नागरिकों को राज्य सम्बन्धी

सामग्री की ओर ध्यान देने के लिए बहुत खाली समय भी मिल जाएगा।

सच्छा चरित्र—लोकतन्त्र के नागरिक को अपने कर्तव्यों के निर्वाह में ईमानदार होना चाहिए। उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसमें देश-प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता की भावना रहनी चाहिए। उसे उत्तरदायी और अनुशासित रीति से व्यवहार करना चाहिए।

अधिनायकतंत्र या तानाशाही

लोकतन्त्र तो सम्मति द्वारा शासन है और एक व्यक्ति या एक दल के मनमाने शासन को अधिनायकतन्त्र या तानाशाही का नाम दिया जाता है। एक व्यक्ति के शासन की दृष्टि में अधिनायकतन्त्र में राजतन्त्र से यह भेद है कि अधिनायक मुकुट नहीं पहनता, या सिद्दासन पर नहीं बैठा। अधिनायक का पद राजा के पद की तरह आनुवंशिक भी नहीं होता। अधिनायक जनशासन में से होता है और राजा की तरह उसमें कोई वृत्तीय रक्त नहीं होता। जहाँ तक सत्ता के साम्प्रतिक प्रयोग का प्रश्न है, अधिनायक और निरंकुश राजा में कोई अन्तर नहीं है।

पुरानी और नयी तानाशाही—तानाशाही, शासन का कोई नया रूप नहीं है। यह पुराने भी मौजूद थी। जूलियस और नैपोलियन के नाम हमें से अधिकतर लोग जानते हैं। प्राचीनकाल में तानाशाही मन्चे ज्योंमें एक आदमी का शासन होती थी। आजकल एक आदमी के हाथ में बाहर से ही अधिकार दिवारा देता है, पर वास्तव में वह व्यक्ति एक राजनैतिक दल के नेताओं के रूप में सत्ता का प्रयोग करता है। हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन आज हमें ज्ञान देने तानाशाह हुए हैं। वे सब हमें ज्ञान देते हैं कि वे सत्ताका दल के नेता थे। इस प्रकार मौजूदा दल व्यक्ति की तानाशाही के बजाय दल की तानाशाही का युग है। हमारे अलावा आज की तानाशाहीवादी लोकतन्त्रीय देश में रहती हैं, यद्यपि वास्तव में वे लोकतन्त्र से विन्दुल दूरी होती हैं।

लोकतंत्र बनाम तानाशाही

- (१) लोकतन्त्र सम्मति द्वारा शासन है। दूसरी ओर, तानाशाही का आधार बल है।
 - (२) लोकतन्त्र में विचार, भाषण, उचरण और साहचर्य की बहुत स्वाधीनता होती है। तानाशाही में सबसे पहले इन्हीं पर पाबन्दी लगायी है। लोगों को तानाशाह द्वारा नियंत्रित किया गया पेशा अमाने, बेश पहनने और शिक्षा लेने के लिए भी मजबूर किया जाता है।
 - (३) लोकतन्त्र में राजनैतिक दल बनाने की स्वाधीनता होती है। तानाशाही में एक राजनैतिक दल के अलावा अन्य सब राजनैतिक दलों पर पाबन्दी होती है।
- तानाशाही के पुरे**—कुछ देशों में १९१४-१८ के विश्वयुद्ध के बाद तानाशाहीका पैदा हुई। उन देशों में युद्ध ने अधिक अवस्थाएँ बहुत विगाड़ दी थी और

उन सरकारों को लोचनन्त्र के ऊपर डाला जाता था। लोकतन्त्र को शासन का अर्थ रखा गया था और इसलिए तानाशाही को एक मौजा दिया गया था। आज भी हमारे जैसे देशों में, जहाँ अधिकांश जनता अज्ञान है, और अनुशासन-हीनता, स्वार्थरति, धूमधारी और चोरमारारी आम चीज है, लोक कमी कमी लोकतन्त्र की जगह तानाशाही का पक्ष पोषण करते हैं। हम प्रकार, तानाशाही का मुख्य गण इमनी दक्षता बनाया जाता है। इन्हीं देशों की सब बुराइयों का एक ऋण गढ़ा जाता है। लोकतन्त्र मन्दगति है, पर तानाशाही जपधना चाहे तो समय में जीवन में शान्ति ला सकती है।

तानाशाही के दोष—तानाशाही के दोष हमने यूपी की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। इसकी सबसे बड़ी बुराई यह है कि यह व्यक्ति को बड़े स्वाधीनता नहीं मानने देती। समाज का जीवनयत्न खालि मा होने लगता है। आदमी की मौलिकता और स्वयं चतुस्व की विकसित नहीं होने दिया जाता। न विचार का स्वतन्त्र विस्तार हो सकता है। आतिरकार, आदमी तक के अनुसार चलने का आदमी है, और वह गिफें रोटी में जीवित नहीं रहता। विचार, भाषण, कारकिर्दी और साहस की स्वतन्त्रता उसके पूर्ण विकास के लिए बड़ा आवश्यक है। उसमें जलावा, तानाशाही न केवल देश की आन्तरिक नीति में बल्कि इसकी वैदेशिक नीति में भी बल प्रयोग पर जोर देती है। वैदेशिक मामलों में तानाशाह युद्ध की नीति पर चलते हैं, और इस प्रकार, अपने देशों को विनाश की ओर ले जाते हैं। बल पर आधारित हानि के कारण तानाशाही लोकतन्त्र की अपेक्षा कम स्थायी है।

सार्वभौमिक राजतन्त्र और गणराज्य—कोई लोकतन्त्र या तो सार्वभौमिक राजतन्त्र होता है और या गणराज्य होता है। सार्वभौमिक राजतन्त्र पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं। गणराज्य शासन का वह रूप है जिसमें राज्य का अध्यक्ष या इसका मुख्य न्यायपालक अधिकारी या तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में और या पराक्ष रूप में निर्वाचित होता है। यूनाइटेड स्टेट्स और भारत दोनों लोकतन्त्रीय गणराज्य हैं, पर गणराज्य का लोकतन्त्रीय होना आवश्यक नहीं। मोन्टेस्क्ये भी एक गणराज्य है पर वह लोकतन्त्रीय नहीं है।

सारांश

सरकार के रूप—अरस्तू का वर्गीकरण

१. राजतन्त्र—सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है।
२. बुलीनतन्त्र—सर्वोच्च सत्ता थोड़े से (सर्वोच्च) व्यक्तियों में निहित होती है।
३. धृष्टतन्त्र—सर्वोच्च सत्ता बहुत से व्यक्तियों में निहित होती है।

ऊपर बताए गये शुद्ध या सामान्य रूपों के साथ-साथ एक भ्रष्ट या विकृत रूप होता है अर्थात् अत्याचारी शासन, अल्पतन्त्र और लोकतन्त्र।

अरस्तू का यह वर्गीकरण आधुनिक युग की अवस्थाओं से मेल नहीं खाता।

अरस्तू लोकतन्त्र को एक विवृत रूप मानता था, पर आज यह शासन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। लोकतन्त्र आज सबसे अधिक प्रचलित रूप भी है।

साधनिक वर्गीकरण—(१) लोकतन्त्र, (२) तानाशाही या अधिनायकतन्त्र।

लोकतन्त्रो को फिर तीन शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है—

१. सार्वधानिक राजतन्त्र या गणराज्य।

२. एकीय या सघानीय।

३. समदीय या प्रधानीय (राष्ट्रपतीय)।

पर कोई शासन समदीय और एकीय होते हुए सार्वधानिक राजतन्त्र हो सकता है। पर कोई शासन एक ही समय में राजतन्त्र और गणराज्य या समदीय और प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) नहीं हो सकता।

राजतन्त्र—राजतन्त्र आनुवंशिक या निर्वाचित और निरकुश या सार्वधानिक हो सकता है। सार्वधानिक राजा वह है, जिसे सीमित अधिकार होंगे। निरकुश और हिनकारी राजतन्त्र के पक्ष में प्रायः यह युक्ति दी जाती है कि यह लोगों के लिए जीवन की आदर अन्वयाएँ पैदा कर सकता है। पर बहुत थोड़े निरकुश राजा अच्छे शासक हुए हैं। आज के जमाने में राजतन्त्र पसन्द नहीं किये जाने, और जहाँ कहा है भी, वह सार्वधानिक है।

कुलीनतन्त्र—कुलीनतन्त्र सर्वोत्तम व्यक्तियों द्वारा शासन कहा जाता है, पर सर्वोत्तम की परिभाषा करना कठिन है। यदि कुलीनतन्त्र का अर्थ कुछ अच्छे शिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों का शासन है, तो इसमें धीरे-धीरे थोड़े से सगे व्यक्तियों का रूप लेने की प्रवृत्ति हो जाती है।

लोकतन्त्र—हम लोकतन्त्र के युग में रहने हैं। लोकतन्त्र न केवल शासन का एक रूप है, बल्कि राज्य का और समाज का भी एक रूप है। शासन के रूप के तौर पर, इसे यह शासन कहा जा सकता है जिसमें हर कोई हिस्सा लेता है। लेकिन ने इसकी परिभाषा यह की थी कि 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन।' लोकतन्त्र में सर्वोच्चता जनता में निहित होती है और शासक तथा शासित में कोई भेद नहीं होता।

लोकतन्त्रीय राज्य वह होता है जिसमें सारा समुदाय सर्वोच्चता-सम्पन्न होता है। किसी लोकतन्त्रीय राज्य का शासन राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र या लोकतन्त्र हो सकता है।

लोकतन्त्रीय समाज इसके सदस्यों में समता और बराबरी की भावना को सूचित करता है। मुसलमानों का समाज लोकतन्त्रीय था, जबकि उनका शासन निरकुश राजतन्त्र था। हिंदुओं में समाज कभी लोकतन्त्रीय नहीं रहा, यद्यपि प्राचीन हिन्दू भारत में राज्य और शासन लोकतन्त्रीय थे।

लोकतन्त्र के प्रकार—(१) प्रत्यक्ष, (२) परोक्ष या प्रतिनिध्यात्मक। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में कानून बनाने के लिए सब नागरिक विधान सभा के रूप में बैठते हैं।

कोई प्रतिनिधि नहीं चुने जाते। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र बहुत छोटे राज्यों के लिए ही ठीक हो सकता है। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र आजकल प्रचलित लोकतन्त्र है। इसमें जनता की इच्छा विधानमण्डलों में उनके प्रतिनिधियों के द्वारा जलाई जाती है।

लोकतन्त्र के गुण—(१) शासन का एतन्मात्र यह रूप है, जो गणता के सिद्धान्त पर आधारित है। (२) अधिकतम स्वाधीनता लोकतन्त्र में ही हो सकती है। (३) निरंकुश लोकतन्त्र में ही शासक और शासित में भेद नहीं होना। (४) लोकतन्त्र ही ऐसा शासन है, जिसे रिता हिंसा के बदला जा सकता है। (५) यह सम्मति द्वारा शासन है। (६) लोकतन्त्र में साधारण निर्वाचनों का बड़ा शिक्षारामक महत्त्व है। (७) लोकतन्त्र जनता के चरित्र को ऊँचा उठाना है। (८) यह देशप्रेम बढ़ाता है। (९) यह शासन का सबसे स्थिर रूप है।

दोष—(१) मूल्यलक्षण के प्रेमी लोकतन्त्र को अज्ञानियों का शासन कहते हैं। यह मध्या के मूकबालों में गुण की उपेक्षा करता है। (२) जनता राज्य के मामलों में बहुत कम हिस्सेदारी लेती है। इंग्लैंड का र्क मन्त्रालय की दृष्टि में लोकतन्त्र अल्पतन्त्र (Oligarchy) में अधिक अच्छा नहीं है। (३) लोकतन्त्र में स्वाधीनता और समता सिद्धान्तरूप में ही अधिक होती है, व्यवहार में नहीं। (४) राजनैतिक दल शिक्षा देने की अपेक्षा निन्दा अधिक करते हैं। (५) लोकतन्त्र बड़ा खर्चीला होता है।

सूत्रोक्त—यद्यपि उरयुंक्व आशेषों में से प्रत्येक में कुछ सचाई है, पर उनमें दुराश्यों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है। लोकतन्त्र के दक्ष परिपालन के लिए जनता में चरित्र का एक निश्चित स्तर होना जरूरी है। यदि उचित अवस्थाएँ विद्यमान हों तो लोकतन्त्र में इनमें से कोई भी बुराई नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर लोकतन्त्र शासन का सर्वोत्तम रूप है।

लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक बातें—(१) मुक्ति और प्रबुद्ध लोकमत। (२) जनता की शिक्षा। (३) स्थानीय स्वशासन की शिक्षा। (४) स्वतन्त्र प्रेस या अवधार। (५) जनता की आर्थिक अवस्था अच्छी होनी चाहिए। (६) लोग ईमानदार, सहिष्णु, सत्ययोग्य, उत्तरदायी और अनुशासित होने चाहिए।

तानाशाही या अधिनायकतन्त्र

तानाशाही या अधिनायकतन्त्र एक आदमी या एक दल के मनमाने शासन को कहते हैं। यह दल द्वारा शासित है और इस रूप में लोकतन्त्र का विरुद्ध उलटा है। पुरानी तानाशाहियाँ एक एक आदमी की हुआ करती थीं, पर आधुनिक युग दल की तानाशाही का युग है।

गुण—तानाशाही का मुख्य गुण इसकी दक्षता को बनाया जाता है। कहा जाता है कि लोकतन्त्र बहुत धीरे चलता है और तानाशाही अपेक्षया थोड़े समय में जीवन को ऊपर से नीचे तक बदल सकती है।

शेष—तानाशाही में आजादी नहीं रहती । समाज का जीवन मशीन की तरह चलने लगता है । आदमी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का मौका नहीं होता । तानाशाह अपने देशों को युद्ध में झोक देने हैं । तानाशाही लोकतंत्र में कम स्थायी भी है ।

प्रश्न

१. 'लोकतंत्र' शब्द से आप क्या समझते हैं ? प्रत्यक्ष और परोक्ष लोकतंत्र में भेद बतारो ।

1. What do you understand by the term 'Democracy' ? Distinguish between direct and indirect democracy

२. शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में पुष्टियाँ दो ।

या

शासनपद्धति के रूप में लोकतंत्र के गुणों और दोषों की आलोचना करो ।

(१० वि० अप्रैल, १९५१)

2 Make out a case for and against democracy as a form of government

or

Explain the merits and demerits of democracy as a form of government. (P U April, 1951)

३ लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन-सी शर्तें आवश्यक हैं ?

(१० वि० सितम्बर, १९५१)

3 What are the necessary conditions for the success of democracy ? (P U Sept., 1951)

४ लोकतंत्र और तानाशाही के आर्थिक गुणों और दोषों की विवेचना करो ?

4 Examine the relative merits and demerits of democracy and dictatorship

५ प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के गुण और दोष बताओ । (१० वि० अप्रैल, १९५४)

5 Point out the merits and demerits of a representative democracy (P U April, 1954)

अध्याय : : १७

शासन के रूप (क्रमागत)

एकीय, स्थानीय-संसदीय और प्रधानीय या राष्ट्रपतीय शासन
का एकीय रूप

यदि किसी राज्य के सारे अधिकार का प्रयोग सामान्य रूप से एक ही सदन के अखिर होना हो जो केन्द्रीय सरकार कहती है तो सरकार एकीय है। शासन के इस रूप में प्रांतीय सरकारें होने पर भी उन्हें सिर्फ केन्द्रीय सरकार से दिया गया अधिकार ही प्राप्त होता है। उनका अधिकार केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी समय कम या अधिक किया जा सकता है, या रद्द करने के लिये जा सकता है। इस प्रकार शासन के एकीय रूप में सारा अधिकार एक जगह केन्द्रीय हो जाता है। इंग्लैंड में एकीय प्रणाली मरकर है।

गुण—शासन के एकीय रूप के निम्नलिखित गुण हैं —

(१) प्रशासन की एकरूपता—कहा जाता है कि अधिकार के एक जगह केन्द्रीय होने से सारे देश में विधि, नीति और प्रशासन की एकरूपता हो जाती है।

(२) एकता और एकता—सारे अधिकार का प्रयोग एक स्थान से होने से प्रशासन में अधिक दक्षता आ जाती है। विधि और प्रशासन की एकरूपता से देश की जनता में एकता की भावना बढ़ती है।

(३) आपातों के समय ताकत—सारी सत्ता एक स्थान पर होने के कारण एकीय रूप वाली सरकार युद्ध काल में और अन्य आपातों में अधिक ताकत और दक्षता देना सकती है।

(४) कम खर्चीला—सिर्फ एक सरकारी सदन होने से एकीय सरकार सभ्यता की तुलना में कम खर्चीली पड़ती है।

दोष—शासन के एकीय रूप के निम्नलिखित दोष हैं —

(१) स्थानीय स्वशासन नहीं रहता—एकीय प्रणाली में मुख्य दोष यह है कि इसके स्थानीय क्षेत्रों को उन मामलों में, जो अधिकतर सिर्फ उनसे ही सम्बन्ध रखते हैं, स्वशासन का अधिकार नहीं मिलता। कहा जाता है कि एक केन्द्रीय सरकार स्थानीय इलाकों से दूर होने के कारण उनकी सार आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकती। यह उन्हें सन्तुष्ट करने की अचूरी कोशिशें करती है। और वे भी यह

बहुत देर के बाद करती है। इसका कारण आपानी में ममत्त में आ जाता है। सरकार का सिर्फ एक संगठन होने के कारण, केन्द्रीय सरकार को पचासों तरह के काम करने होते हैं। इसपर काम का बहुत बोझ होता है। पहले सामान्य समस्याओं पर विचार किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों की अपनी-अपनी समस्याएँ हल होने में देर लग जाती है।

(२) नागरिकता की भेदना नहीं मिलनी—इसके अलावा लोगों की स्थानीय स्वशासन की शिक्षा देने की जरूरत होती है ताकि वे लोकतंत्र के उपयुक्त नागरिक बन सकें। पर शासन के एकीय रूप में नागरिकों में स्वयं चर्चा, सहयोग और जिम्मेदारी आदि नागरिक गुणों का विकास होने के कम मौके मिलते हैं।

(३) शासन का एकीय रूप साधारणतया उन छोटे-छोटे राज्यों के लिए ठीक होता है, जिनके क्षेत्र सब एक जगह हो और जिनकी आजादी छोटी और एकमात्र हो। यह उन देशों के लिये ठीक नहीं रहता जो बहुत लम्बे-चोड़े हो और जिनमें स्थानीय अवस्थाएँ बड़ी अलग-अलग हों और संस्कृति की विविधता हो। इन प्रकार, शासन के इस रूप में विविधता को एकरा और एकत्वना पर कुरबान करता पड़ता है।

संधान या शासन का संधानीय रूप

संधान कितने कहते हैं—जब कई छोटे-छोटे स्वतन्त्र सर्वोच्चना-सम्पन्न राज्य कुछ मामलों में अपना सर्वोच्च प्राधिकार एक साझी संध सरकार को देने के लिए आपस में सहमत होकर एक संध के रूप में इकट्ठे हो जाना स्वीकार करते हैं, पर साथ ही शेष मामलों में अपनी सर्वोच्चता और स्वतन्त्रता कायम रखते हैं। तब ऐसा संध संधान कहलाता है।

इस प्रकार संधान में सरकार की कुछ शक्तियाँ एक लिखित संधिद्वारा दो शासन संगठनों अर्थात् केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार में बाँट दी जाती हैं। प्रभारणा, विदेशी मामले, चरार्थ यानी बर्रेनी और विनिमय (Exchange), वाणिज्य और व्यापार आदि, संध के सामान्य हित के विषय केन्द्रीय सरकार को दे दिये जाते हैं और विधि और व्यवस्था, श्याम, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि स्थानीय महत्त्व के विषय संधान के राज्यों के अधीन रहते हैं।

संधान की आवश्यक विशेषताएँ

(१) संध है, ऐक्य नहीं—प्राकृतिक संधान में निम्नलिखित विशेषताएँ अवश्य होती हैं। संधान कुछ राज्यों का संध होता है, ऐक्य नहीं होता (Union and not a Unity)। ऐक्य शब्द का मतलब यह होता कि संधान बनाने वाले राज्यों का स्वतन्त्र अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा पर हम ऊपर देख चुके हैं कि राज्य अपनी सर्वोच्चता सिर्फ कुछ विषयों में संध सरकार को सौंपते हैं। शेष मामलों में उन्हें वैसी ही स्वतन्त्र सत्ता रहती है जैसी संध के निर्माण से पहले थी।

शासन के दो संगठन होते हैं—संधान में स्पष्ट तौर से शासन के दो संगठन

होते हैं—एक केन्द्र में, दूसरा सधान बनाने वाले राज्यों में से प्रत्येक में। विषयों की कम-से-कम दो और कभी-कभी तीन सूचियाँ होती हैं। धारण के प्रत्येक समूह को विषयों की अपनी सूची में परम प्राधिकार होता है। केन्द्र को प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय दे दिए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के लिए विषयों की जो सूची होती है उसे केन्द्रीय सूची या सध सूची कहते हैं। राज्यों के प्रशासन के विषय राज्य सूची में होते हैं। कुछ सधानों में ऐसे विषय भी होते हैं, जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए सामान्य होते हैं। ऐसे विषयों की सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। दोष विषय जो न केन्द्र को दिये गये हैं, न राज्यों को, और न दोनों के सामान्य हैं, अवशिष्ट विषय (Residuary Subjects) कहलाते हैं। कुछ राज्यों में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, अवशिष्ट विषय राज्यों के अधिकार में होते हैं और कुछ देशों, जैसे भारत में वे केन्द्र को दिये गये हैं। यह सब व्यवस्था सम्बन्धित देश व सविधान में साफ़ तौर से लिखी होती है।

(३) निश्चित सविधान—सधान का सविधान निश्चित होना चाहिए क्योंकि शासन के दोनों समूहों के अधिकारक्षेत्र स्पष्टतः निर्दिष्ट होने जरूरी है। सधान में सर्वोच्चता सविधान में होती है। केन्द्रीय सरकार या इकाइयों की सरकार को राज्य का सर्वोच्च प्राधिकार नहीं होता। दोनों का प्राधिकार सविधान से पैदा होना है। इस प्रकार किसी सधान की इकाइयों का प्राधिकार मौलिक होता है, और केन्द्रीय सरकार से लिया हुआ नहीं होता।

(४) सधानीय न्यायालय—सधान में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक या अधिक राज्यों तथा सध के बीच विवाद पैदा होने की सम्भावना रहती है। इसका कारण यह है कि शासन के दोनों समूहों के बीच विषयों का विभाजन विभा गया है, और सविधान को पढ़ने में मनभेद हो सकता है। इसलिए विवादों का फैसला करने और सविधान का अर्थ लगाने के लिए किसी निष्पक्ष प्राधिकरण की जरूरत है। यह काम एक न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसे उच्चतम या सधानीय न्यायालय कहते हैं। भारत में भी ऐसा न्यायालय है और यह भारत का उच्चतम न्यायालय कहलाता है। अमेरिका में भी ऐसा न्यायालय है जो यूनाइटेड स्टेट्स का उच्चतम न्यायालय कहलाता है। इसलिए सधान में उच्चतम न्यायालय होना जरूरी है।

सधानीय शासन के लाभ

एकता और स्वतन्त्रता दोनों धनी रहती है—शासन के स्थानीय रूप का सब से बड़ा लाभ यह बताया जाता है कि इसमें सध के सब लाभ मिल जाते हैं और ऐव्य की हानि कोई नहीं होती। शासन का यह रूप ऐव्य और स्वतन्त्रता के बीच उत्तम मध्य मार्ग पेश करता है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, संचार साधनों और मुद्रा आदि मामलों में, जिनमें ऐव्य वास्तवीय है, सधान बनाने वाले राज्यों को अमीयट लाभ मिल जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और कृषि

आदि मामलों में, जिनमें स्थानीय अवस्थाओं के भेद के कारण अलग-अलग नीतियाँ वांछनीय होती हैं, राज्यों को पूरी स्वायत्तता रहनी है। इस प्रकार संधान में स्थानीय क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन की आकांक्षाएँ एकता को बिना भंग किये आसानी से पूरी हो जाती हैं।

(२) वचन—संधानों में सच में वचन होना है। जब संधान बनाने वाले राज्य अलग-अलग और स्वतन्त्र थे तब प्रत्येक की अलग फौज, राजदूत और टकरालें आदि थीं। अब वे सच में आसने हैं और संधान बना लेते हैं तब सेना रखना, राजदूत भेजना और बिकड़े डाकना केन्द्रीय सरकार का काम हो जाता है। इस तरह, वह बहुत सा धन बच जाता है जो प्रत्येक राज्य पहले सच कर रहा था, क्योंकि उनसे साधन एक हो जाते हैं।

(३) बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त है—बहुत फँसे हुए और बहुत आवादी वाले राज्यों के लिए शासन का संधानात्मक रूप ही उपयुक्त होता है।

(४) दक्षता लाता है—शासन का काम सच सरकार और राज्य सरकारों में बंट जाने से अधिक दक्षता आ जाती है। एकीय प्रणाली में केन्द्रीय सरकार पर काम का बहुत बोझ रहता है।

(५) निरकुशता को रोकता है—क्योंकि न तो केन्द्रीय सरकार को पूरा अधिकार है और न राज्य सरकारों को, और दोनों एक दूसरे पर रोक का काम करती हैं, इसीलिए संधानात्मक शासन में निरकुशता का भय नहीं रहता।

(६) विद्वत राज्य के लिए समझा योग्य करता है—यदि विद्वत राज्य बनेंगे तो उनका रूप संधानात्मक ही होने की संभावना है।

(७) यह अधिकारिक पसन्द किया जा रहा है—आज की दुनिया में संधान को अधिकारिक पसन्द किया जा रहा है। इसके भी इसकी अष्टाई का पता चलता है।

संधान की हानियाँ

शासन के संधानात्मक रूप को ये हानियाँ बतलाई जाती हैं—

(१) असाधों के समय कमजोर—आसनों के समय सरकार की बहाला और लाकृत के लिए यह जरूरी होता है कि सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी हो। शक्तियों के बँटवारे के कारण संधान में जल्दी किए जाने वाले कामों में गड़बड़ी और देर लगने का खतरा रहता है।

(२) प्रशासन में एकरूपता का अभाव—शासन के संधानात्मक रूप में प्रशासन की एकरूपता संभव नहीं। संधान के राज्यों में विधियाँ और प्रशासन अलग-अलग होने की सम्भावना है। इस प्रकार उपर्युक्त कारण से लोगों में एकता की भावना भी कमजोर रहेगी।

(३) जिम्मेदारी का बँट जाना—शासन के संधानात्मक रूप में जिम्मेदारी बँटी रहती है। कभी-कभी बुरे शासन की जिम्मेदारी दोनों में से किसी एक पर

हालना बठिन हो जाता है ।

(४) अलग होने का भय—सधान में किसी राज्य या राज्यों के साथ से अलग हो जाने का भय हमेशा बना रहता है ।

(५) अधिक खर्चीला—शासन के दो संगठन होने के कारण सधानीय शासन एकीय शासन की अपेक्षा अधिक खर्चीला बँडता है । अनेक सत्थाएँ दोहरी बनानी पडती हैं । उदाहरण के लिए, हर एक राज्य में अपनी अलग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अवस्य होनी है ।

संसदीय और प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) सरकारें

सरकारों का संसदीय और प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) रूप में वर्गीकरण न्यायपालिका और न्यायपालिका के आपसी सम्बन्ध की प्रवृत्ति पर आधारित है ।

शासन के संसदीय रूप में कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) और विधायिका (संसद) एक दूसरे के साथ बहुत सहयोग करती हुई चलती हैं । शासन का यह प्ररूप इंग्लैण्ड की देन है, क्योंकि वहाँ ही मन्त्रिमण्डल और संसद की सरथाएँ सबसे पहले पैदा हुईं । शासन के संसदीय रूप को मन्त्रिमण्डलीय रूप या उत्तरदायी रूप भी कहते हैं क्योंकि इस में असली कार्यपालिका मन्त्रिमण्डल है और यह उत्तरदायी सरकार इस कारण है कि मन्त्रिमण्डल या असली कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है । इस प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष, राजा या राष्ट्रपति नाममात्र को कार्यपालिका है ।

दूसरी ओर शासन के प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) रूप में राज्य का अध्यक्ष असली कार्यपालिका है । मन्त्री वह स्वयं बनाता है और वे उसके अधिकार के अधीन ही होते हैं । संसदीय रूप के विपरीत प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) रूप में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतन्त्र रहकर कार्य करता है । राष्ट्रपति विधानमण्डल में से अपने मन्त्री नहीं चुनता और न व विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हैं । शासन के इस रूप को अपनाते वाला पहला राज्य यूनाइटेड स्टेट्स था और आज भी वही इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ।

संसदीय शासन की मुख्य विशेषताएँ

(१) शासन के संसदीय रूप में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग असल में मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है । कार्यपालिका का अध्यक्ष (राजा या राष्ट्रपति) राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है । वह अपने मन्त्रियों की सलाह पर कार्य करता हुआ माना जाता है । मन्त्रिमण्डल न केवल कार्यपालिका की सारी नीति तय करता है, बल्कि विधान और विन में विधान मण्डल का परप्रदर्शन भी करता है ।

(२) विधानमण्डल भी मन्त्रिमण्डल को नियमित करता है । शासन के संसदीय रूप में मन्त्रिमण्डल विधानमण्डल की एक समिति है । इसके सदस्य विधानमण्डल के बहुमत दल में से छाटे जाते हैं, और इस दल का नेता प्रधानमन्त्री बनता है ।

प्रधानमंत्री अन्य मंत्री छाटता है। वे भी सदन के सदस्य और उसके दल के आदमी होने चाहिए।

प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी अर्थात् मंत्रिमंडल अपने सब राजकीय कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे तब तक अपने पदों पर रहते हैं जब तक उन्हें विधानमंडल का विश्वास प्राप्त रहे। विधानमंडल अपने प्रति मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी को मंत्रियों में प्रश्न पूछकर, निंदा प्रस्ताव द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा लागू करता है।

गुण—शासन की संसदीय पद्धति के निम्नलिखित गुण हैं—

(१) कार्यपालिका और विधायिका में सहयोग—मंत्रिमंडलीय प्रणाली शासन की ऐसी एकमात्र प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका में मंत्रीपूर्ण सहयोग होना सुनिश्चित है। कानून बनाने वाले और कानून लागू करने वाले प्राधिकरणों में नजदीकी सहयोग से कानून व्यवस्थित ढंग का बनता है। इसी प्रकार, धन देने वाले और धन खर्च करने वाले अधिकारियों में सहयोग होने पर खर्च कम होता है और दक्षता आती है। शासन के इस रूप में फैसले और काम जल्दी होते हैं और कार्यपालिका और विधायिका में संघर्ष और गतिरोध की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है।

(२) कार्यपालिका की जिम्मेदारी निरंकुशता पर रोक लगानी है—शासन के संसदीय रूप में कार्यपालिका की जनता के प्रतिनिधियों के सामने सीधी जिम्मेदारी निरंकुशता पर रोक लगती है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ही ऐसी एकमात्र प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका की जिम्मेदारी की अच्छी व्यवस्था है। जो लोग शासन करते हैं, वे सदा उनके नियंत्रण में रहते हैं, जिनपर शासन होता है।

(३) मंत्रिमंडलीय प्रणाली नम्य और लचीली है—मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नम्यता और लचीलापन आपात और संकट के समय शक्तिदायक बन पाता है। मंत्रिमंडल एक ऐसी समिति है, जिसमें विधानमंडल को पूरा विश्वास है। इसका अपने पद पर रहना भी विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए आपात के समय मंत्रिमंडल को बेखटके विस्तृत शक्ति दी जा सकती है, और जब आपात खत्म हो जाए तब अग्रधारण शक्तियां ले ली जाती हैं।

मंत्रिमंडलीय प्रणाली के दोष—मंत्रिमंडलीय प्रणाली के आलोचक इसमें निम्नलिखित दोष बताते हैं—

(१) यह शक्तियों के पुनर्करण के सिद्धांत को भंग करता है—कहा जाता है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली शक्तियों के पुनर्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस प्रणाली में विधायक और कार्यपालक कार्य प्रायः एक ही व्यक्ति हो जाते हैं।

(२) यह अधिकतर दलीय सरकार की प्रणाली है—लार्ड ब्राइले ने संसदीय प्रणाली के बारे में कहा है कि इसने दलीय भावना को बढ़ाया है। दलों में सत्ता

गाने के लिए लगातार होठ रहती है। समारूढ़ दल और विरोधी दल के सघर्ष में बहुत-सा समय और शक्ति बर्बाद होने हैं और उससे समाज में भी सघर्ष पैदा होता है। विभिन्न दलों के लोग हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहते हैं।

(३) मन्त्रिमंडल की तानाशाही—मन्त्रिमंडलीय प्रणाली की एक और आलोचना यह है कि इस से विधानमंडल पर मन्त्रिमंडल की तानाशाही हो जाती है। यह आलोचना सामगौर ने इंग्लिश मन्त्रिमंडल प्रणाली के बारे में की जाती है कहा जाता है कि इस प्रणाली में विधानमंडल मन्त्रिमंडल द्वारा पहले ही कर लिए गए निम्नियों को दर्ज करने वाला अंग मान रह गया है।

(४) ढूढ़ काल में कमजोर—प्रोफ़ेसर डिस्सी के अनुसार, मन्त्रिमंडल प्रणाली में काम और जिम्मेदारी कई मन्त्रियों में बटी होती है। फंसले एक आदमी के बजाए कई आदमियों से चर्चा के बाद किए जाने हैं। इस कारण प्रोफ़ेसर डिस्सी इसे पुष्ट और गभीर राष्ट्रीय सभ्य के समय कमजोर ढंग की सरकार कहते हैं।

(५) इसकी अस्थिरता—यदि शासन की मन्त्रिमंडलीय प्रणाली बहुदल प्रणाली के अधीन चलाई जाए तो इसने कार्यपालिका अस्थिर हो जाती है। मन्त्रिमंडल में बार-बार परिवर्तन होने से सरकार अक्षम हो जाती है। मास में बहुत से बल हैं और वहाँ मरवार का जीवन बहुत थोड़े दिन चलता है। कभी-कभी वह सिर्फ एक दिन का होता है, पर मन्त्रिमंडल का औमत जीवन ६ मास में कुछ अधिक रहा है।

प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ—हम पहले ही कह चुके हैं कि शासन की प्रधानीय (राष्ट्रपतीय) प्रणाली में कार्यपालक और विधायक मालाएँ प्रायः पूरी तरह अलग हो जाती हैं। यह दोनों एक दूसरे से स्वतन्त्र रहकर कार्य करती हैं और दोनों एक दूसरे पर रोक का काम करती हैं। शासन के इस रूप में राज्य का अध्यक्ष असली कार्यपालक है, मंत्री नहीं। वह मन्त्रिमंडल द्वारा तय किए गए किसी निश्चित समय के बीच चुना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में यह अवधि चार साल है। उसकी शक्तियाँ भी सीधे मन्त्रिमंडल से उद्भूत होती हैं, और कार्यपालक क्षेत्र में वह सर्वोत्तम है। यह अपने मन्त्रिमंडल के मन्त्रियों को नियुक्त और बर्खास्त करता है। वह उससे प्रति ही उत्तरदायी है, और उसके ही निर्देशानुसार और नियंत्रण में अधीन है। इस प्रकार विधानमंडल वा मन्त्रिमंडल पर कोई नियंत्रण नहीं रहता।

इसी तरह, विधानमंडल भी कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतन्त्र होता है। इसका बैठक और विघटन मन्त्रिमंडल द्वारा तय की गई विधियों पर होता है। राज्य का अध्यक्ष न तो इसे आहूत करता है, और न विघटित करता है। मन्त्रिमंडल के सदस्य विधानमण्डल को उसके कामों में मार्ग दिखाने और नियंत्रित करने के लिए वहाँ नहीं बैठते। विशेषकर मन्त्रिमंडल के सदस्यों द्वारा नहीं बनाए जाते और

न पास कराए जाते हैं, जैसा कि संसदीय प्रणाली में होता है।

इसके गुण—शासन की संसदीय प्रणाली के ये गुण बताए जाते हैं—

(१) कार्यपालिका की अधिक स्थिरता—राष्ट्रपतीय प्रणाली में कार्यपालिका की स्थिरता सुनिश्चित हो जाती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। कार्यपालिका एक निश्चित और पूरी अवधि तक बनी रहती है और विधानमण्डल में प्रतिकूल मनदान द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता।

(२) नीति की निरंतरता कार्यपालिका की स्थिरता के कारण देश की कम से कम चार या पाँच वर्षों के लिए एक नीति रहने का निश्चय होता है।

(३) कार्यपालिका की शक्तियाँ एक आदमी में केन्द्रित होने के कारण कार्यपालिका आवाज के समय अधिक जोर-शोर में और तात्परता में काम कर सकती है।

(४) दलीय प्रणाली की बुराईयाँ कम होती हैं। शासन की इस प्रणाली में दलीय प्रणाली की बुराईयाँ कम होने की सम्भावना है। कोई राष्ट्रपति दलीय राजनीति से ऊपर उठ कर निष्पक्ष रूप में काम कर सकता है।

इसके दोष—शासन की राष्ट्रपतीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष बताए जाते हैं—

(१) यह एकतन्त्रीय होता है—यह प्रणाली एकांगीय, अनुत्तरदायी और सत्तरनाक बताई जाती है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका अधिकार एक व्यक्ति, अर्थात् राष्ट्रपति, के हाथ में रहता है। राष्ट्रपति अपने निर्वाचन के बाद जो कुछ चाहे कर कर सकता है। पर उसे यह सावधानी रखनी होगी कि उसे विधान के अधिकारों का दोषी न ठहराया जा सके।

(२) कार्यपालिका और विधायिका में सहयोग नहीं—कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग आज के जमाने में बड़ा आवश्यक माना जाता है। दूसरी ओर, सहयोग न होने से शासन की दोनों शाखाओं में बार-बार गतिरोध आते हैं। विधान और वित्त के कामों में कार्यपालिका का मंत्रत्व न होने से एक-एक बात कई-कई कानूनों में आ जाती है और जनता का धन बर्बाद होता है।

(३) शासन की मंद गति—बाइन के अनुसार राष्ट्रपतीय प्रणाली सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी, चाल की नहीं। मन्त्रियों के पृथक्करण से सरकारी काम में देर और गड़बड़ी होती है।

सारांश

एकीय सरकार—एकीय सरकार में सत्ता केन्द्रीय सरकार में निहित है और प्रशासन की इकाइयाँ सुविधा के लिए बनाई जाती हैं। इकाइयों की सत्ता

मौलिक नहीं होती यह ली हुई होती है और केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर बड़ाई घटाई या थापस ली जा सकती है। केन्द्रीय सरकार स्वामा होती है और इकाइयों की सरकारें इसकी वसुधार्थी।

ऐसी सरकार से मुख्य लाभ ये हैं —

१. विधि, नीति और प्रशासन में एकरूपता,
२. एकीकृत प्रशासन,
३. दृढ विदेश नीति, और
४. यह शासन प्रदेशों के अलग होने को रोकता है।

इसकी चुटियां ये हैं —

- १ प्रशासन न तो प्रभावी होता है और न दक्ष,
- २ केन्द्रीय सरकार स्थानीय समस्याओं को नहीं समझ सकती और उनका हल नहीं निकाल सकती,
- ३ स्थानीय क्षेत्र उन्नति नहीं कर सकते,
- ४ एकीय सरकार लोकप्रिय नहीं होती, और
- ५ इसमें केन्द्रीयकृत नौकरशाही हो जाती है।

संघान या फेडरेशन—संघान एक नया तरीका है जिसमें सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न राज्य मिलकर एक नया राज्य बना लेते हैं। यह संघ आर्थिक या राजनैतिक कारणों से बनाया जाता है।

यह आवश्यक है कि संघ के लिए इच्छा हो। संघ बनाने की इच्छा के लिए अनुकूल परिस्थितियां ये हैं —

१. संघान बनाने वाले राज्यों का पड़ोस
२. भाषा, धार्मिक प्रथाओं, संस्कृति और राजनैतिक परम्पराओं की समानता, पर ये सब बाने बिल्कुल अनिवार्य नहीं हैं।
३. सामान्य राष्ट्रीय भावना का होना,
४. जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक संघान बनाने वाली इकाइयों में समानता।

संघान की विशेषताएं ये हैं —

- (क) यह मिलने के परिणाम स्वरूप बनता है,
- (ख) इसका लिखित सविधान अवश्य होना चाहिए,
- (ग) सविधान बन्धन (Rigid) होना चाहिए,
- (घ) केन्द्रीय सरकार की और इकाइयों की शक्ति का सविधान में सुनिश्चित होनी चाहिए,
- (ङ) विधायक, कार्यपालक और न्यायिक विभाग स्पष्टतः अलग-अलग होने चाहिए,
- (च) न्यायपालिका सर्वोच्च होनी चाहिए, और
- (छ) दुहरी नागरिकता।

इसके ये गुण हैं—

(१) सधान में राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता दोनों के लाभ हो जाते हैं,

(२) यह केंद्रीकरण को रोकता है,

(३) यह स्थानीय विधान और प्रशासन के प्रयोग होने देता है,

(४) यह कम-खर्च होता है क्योंकि इनमें दुहरी कस्याएं नहीं होतीं,

(५) यह इस बात का सर्वोत्तम उपाय है कि राज्य अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे और विदेशी आक्रमण से बचे रहे,

(६) अनेक दुःकाइयों को एक साथ में लाकर यह अंतर्राष्ट्रीय प्रेम-भाव पैदा करना है;

(७) यह नए और विस्तृत देश को विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है जिनमें अलग-अलग दमिनियों को अपनी विशेष आवश्यकताओं का विकास, जिन तरह वे ठीक समझे उस तरह करने का अवसर मिलता है।

सधान की कमजोरियाँ—१. यह विदेशी नामलों के संचालन में दुर्बल होता है।

२. सत्ता दो सरकारों के बीच बंट जाने से भीतरी शासन निबंध हो जाता है।

३. सधान में इसके विपटन की संभावना हमेशा बनी रहती है।

४. प्रशासन और विधान की दुहरी पद्धति से अनावश्यक व्यय और विलम्ब होता है।

५. यह इनमें अधिक स्थानीय स्वार्थ पैदा कर देता है कि राष्ट्रीय सगठन को गम्भीर हानि पहुँचती है।

६. क्योंकि सधान अनन्य सविधान होता है इसलिए प्रशासनीय व्यवस्था को समय की बदली हुई आवश्यकताओं के लिए आसानी से अनुकूल नहीं बनाया जा सकता।

७. सधान में सक्रियकारी न्यायपालिका प्रगतिशील दलों के लिए बड़ी खतरा है क्योंकि यह सविधान के मर्मों पर चलता है जिसे कानून की उपरोक्तता पर नहीं।

समशील शासन—समशील शासन को उत्तरदायी या सक्रियकारी शासन भी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ ये हैं :—

(क) राज्य का अन्धध राजा या राष्ट्रपति नाममात्र को कार्यपालक होता है।

(ख) साम्प्रतिक कार्यकर्ता मंत्री होते हैं।

(ग) मंत्री विधानमण्डल के बहुमत दल के होते हैं।

(घ) वे अपने सब सरकारी कार्यों के लिए विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी

होते हैं और तब तक अपने पदों पर रहते हैं, जब तक (i) वह दल जिसके वह सदस्य हैं बहुमत में रहे, (ii) इसे विधानमण्डल का विश्वास प्राप्त रहे या (iii) विधानमण्डल को जीवन-पर्यन्त ।

(ड) मंत्री विधानमण्डल के सदस्य तथा अपने कार्यपालक विभागों के अध्यक्ष होते हैं ।

शासन की इस प्रणाली के ये लाभ हैं —

१. यह कार्यपालिका और विधायिका में मेल-मिलाप रखती है

२. यह प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र का सर्वोत्तम नमूना है ।

३. यह कुलीनतन्त्र और लोकतन्त्र का मिश्रण है ।

४. इसमें नम्यता (Flexibility) और लोच या प्रत्यास्यता का गुण है ।

५. इसका शिक्षात्मक दृष्टि से बड़ा महत्व है ।

६. यह आलोचना द्वारा शासन है ।

७. यह शासन के सारे तन्त्र को लोकतन्त्रीय रूप देने में सफल हुई है ।

इसकी हानियाँ—

१. यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को तोड़ती है ।

२. यह अस्थिर और उत्तार-चढ़ाव वाली शासन पद्धति है ।

३. मंत्रियों के पद की अनिश्चिन्ता रहनी है और यह दूरदर्शिता-पूर्ण नीति नहीं पैदा करती ।

४. विरोधी पक्ष सश विरोध करता रहता है ।

५. यह गैर पेशेवर लोगों द्वारा शासन है ।

६. मंत्री राजनीतिज्ञ लोग होते हैं और उन्हें बहुत से अन्य राजनीतिक कार्य रहते हैं इसलिए वे सरकारी काम में पूरा ध्यान नहीं दे सकते ।

७. यह दलीय सरकार होती है और इसमें राजनीतिक फायदा उठाया जाता है ।

८. यह पद्धति, विशेषकर घापालों में, निर्दल सिद्ध होती है ।

शासन का राष्ट्रपतीय या प्रधानीय रूप—यह शासन का प्रतिनिध्यात्मक रूप है पर उत्तरदायी रूप नहीं । कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती । राज्यों का मुख्य कार्यपालक अध्यक्ष जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रपति यास्तविक कार्यपालक होता है और उमका पद निश्चित काल तक चलता है । वह अपने मंत्री चुनता है जो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं । इस प्रकार कार्यपालिका और विधायिका में पूर्ण पृथक्ता रहती है ।

लाभ—१. यद्यपि यह शासन का प्रतिनिध्यात्मक रूप है तो भी यह विधानमण्डल की बदलती-बदलती इच्छा पर निर्भर नहीं होता ।

का मताधिकार पागल आदमी के हाथ में सत्कार देने के समान बताया जाता था ।

(२) सम्पत्ति-सम्बन्धी अर्हता—सम्पत्ति सम्बन्धी अर्हता के पक्ष में पहली दलील यह दी जाती है कि जिन लोगों के पास कोई सम्पत्ति है उनका ही उचित रूप में देश में कोई जोखिम माना जा सकता है, और उन्हें ही मताधिकार दिया जाना चाहिए । दूसरी ओर, जिन लोगों के पास कोई सम्पत्ति नहीं, उन्हें मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे अपने ही जैसे आदमियों को विधानमण्डल के लिए चुनेंगे । ऐसे व्यक्तियों में हमेशा उन लोगों को शोषित करने की प्रवृत्ति रहेगी जिनके पास सम्पत्ति है ।

दूसरे, यह दलील दी जाती है कि मताधिकार उन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो सरकार को कर देते हैं । जॉन स्टुअर्ट मिल सम्पत्ति सम्बन्धी अर्हता का भी प्रबल समर्थक था । वह यह मानता था कि जो लोग कर नहीं देते, वे कब से प्राप्त धन को वैसे ही बिना विचारे खर्च करेंगे क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता ।

(३) लिंग सम्बन्धी अर्हता—यहूँ काल तक मताधिकार सिर्फ पुरुषों को था, स्त्रियों को नहीं । जो लोग स्त्रियों के मताधिकार के विरोधी हैं वे इस बात पर बल देते हैं कि स्त्री घर की रानी हैं और मातृ कार्य ही उसका उचित कार्य है । प्रकृति ने उसे राजनीतिक जीवन के लिए नहीं बनाया । उसके राजनीति में हिस्सा लेने से परिवार के जीवन में निश्चित रूप से गड़बड़ पड़ेगी । तब बच्चों को कौन पालेगा और घर के कामों की देख-भाल कौन करेगा इसके अलावा राजनीति के रही काम में पड़ने से स्त्रियों को मिलने वाला सम्मान और प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएँगे ।

आम तर्क मताधिकार के पक्ष में व्यक्तिगत—लोकतन्त्र के बारे में आजकल जो हमारे विचार हैं, उन्हें देखने हुए ऊपर दी हुई दलीलों में से किसी में भी आज की दुनिया में कोई बल नहीं । आजकल सब वयस्कों को, शिक्षा, सम्पत्ति और लिंग सम्बन्धी अर्हताओं का बिना विचार किये, मताधिकार दिया जाता है । आम तर्क मताधिकार के पक्ष में ये प्रकिया है—

(१) समता का अर्थ है समान मताधिकार—समता लोकतन्त्र का परम आवश्यक तत्व है । राजनीतिक समता के बिना कोई समता नहीं हो सकती । राजनीतिक समता का मिलना तभी सुनिश्चित हो सकता है जब सब नागरिकों को मताधिकार हो ।

(२) शासन से सबका वास्ता है—जिन बातों से सबका वास्ता है, वह सबको ही करना चाहिए । सरकार, कानून और नीतियाँ सब लोगों से वास्ता रखने हैं । इस प्रकार, सब नागरिकों को कानून बनाने में और सरकार की नीतियाँ तय करने में हिस्सा लेने का मौका होना चाहिए । यह तभी हो सकता है जब सब नागरिकों को मताधिकार हो ।

(३) कितनी शिक्षा आवश्यक नहीं—यह याद रखना चाहिए कि मताधिकार के दक्ष प्रयोग के लिए राजनीतिक शिक्षा की आवश्यकता है, कितनी शिक्षा की

नहीं। राजनैतिक शिक्षा का अर्थ यह है कि आदमी का सामान्य ज्ञान के काम करने और देश के सामान्य मौजूद समस्याओं का पता होना चाहिए। यह ज्ञान तभी हो सकता है जब कोई नागरिक पढ़ना-लिखना जानता हो। यह ठीक है कि विभावी शिक्षा नागरिक को ठीक तरह का ज्ञान इकट्ठा करने में मदद देनी है, पर इसे मताधिकार देने की कोई धरन नहीं बनाया जा सकता। इसमें अलावा, शौचालय स्वयं लोगो को शिक्षित करता है। इस प्रकार यह कहना कि मताधिकार से पहले शिक्षा होनी चाहिए, दोनों चीजों को ऊँचे त्रय में रखना है।

(४) सब लोग कर देने हैं—हम हम दलील की सहाय मानते हैं कि जो लोग कर देते हैं उन्हें ही मताधिकार होना चाहिए। पर हम दलील का सम्बन्ध न धारण से कोई सम्बन्ध नहीं। मताधिकार सम्पत्तिशाली वर्गों तक ही सीमित करने से समुदाय के अन्य सब भागों और हिता से बड़ा अन्याय होगा। आज की दुनिया में कर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हम में से सब देने हैं; अगले सम्पत्तिशाली वर्ग ही नहीं देते। गरीब से गरीब आदमी भी दियागल्ट्री खरीदना है और हम प्रकार सरकार को उत्पादन शुल्क देता है। हम तरह जो लोग सरकार के लक्ष के लिए धन देते हैं, उनके पास यह देखने का उपाय अवश्य होना चाहिए कि वह धन कौन खर्च किया जा रहा है। यह वे तभी कर सकते हैं, यदि उन्हें मत देने का और अपने सामान्य कर्तव्यों के पत्राव में हिंसा सेने का अधिकार हो।

(५) समता में लिंग की समता भी है—लोचनत के बदने के साथ साथ लिंगों के मताधिकार की मांग भी बढ़ती रही है। शिक्षा-न क रूप में, लोचनत एक आदमी और दूसरे आदमी में कोई भेद-भाव नहीं करता। तो, इसी लिंग का भेद-भाव क्यों करना चाहिए? लिंगों शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हो सकती हैं पर और दृष्टियों से वे पुरुषों से किसी बात में पटिया नहीं हानी। तर्क करने और समझने की शक्तियाँ जो मत के उचित प्रयोग के लिए परमानन्द्य है दोनों लिंगों में समान होती हैं। शरीर से दुर्बल होने की कारण लिंगों को अपनी रक्षा के लिए विधि और समान की आदमी से अपित् आवश्यकता भी है। इस लिए विधियाँ बनाने में उन का ह्राय होना और भी जरूरी है।

दूसरे, लिंगों को मताधिकार न देने का मतलब है लिंगों को अच्छे नागरिक बनने की प्रवृत्ति से वंचित करना। हम पहले देख चुके हैं कि नागरिकता के लिये वचने को प्रशिक्षित करने में माना क्या हिंसा ले सकती है। यदि उन्हें नागरिक भावना से वंचित कर दिया जाये तो वे अपने वचनों को कुछ भी शिक्षा न दे सकेंगे।

सत्वातामो द्वारा प्रत्यक्ष विधान—आधुनिक शौचालय का रूप प्रतिनिध्यात्मक है। विधियाँ साधारणतया निर्वाचकमण्डल द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती हैं, पर प्रतिनिध्यात्मक लोचनत की यही आलोचना की गई है। कहा जाता है कि विधान मण्डल सारे देश के हिता की उपेक्षा करते हुए बलगत भावना से विधियाँ बनाते हैं। दूसरे, ही भवता है कि किसी स्थान समय किसी स्थान मानने-

स्पष्ट करने का अधिक अच्छा ढंग यह है कि यह आवश्यक रूप से सब लोगों की राय नहीं होगी, पर मुनिदिन्दर रूप से सब लोगों के लिए राय होनी है। दूसरे पक्षों में, यह वह राय है जिगवा लक्ष्य किमी काम बर्न के बढाय सारी जनता का कल्याण होना है। जिम राय का लक्ष्य किमी काम मनुशाय, बर्न या महानर्य का काम है, वह वर्गीय राय कहलाएगी।

आशयिक नहीं कि यह षडुभन की राय हो—आशयिक नहीं कि लोकमत बहुमत की राय हो यद्यपि यह अधिकतर लोगों का मत है तो अधिक अच्छा होगा पर कभी-कभी बहुमत की राय स्वार्थ-भरी या बगहिन देखने वाली हो सकती है और अल्पमत की राय जनसाधारण के हित पर विचार करने वाली हो सकती है। उस अवस्था में अल्पमत की राय लोकमत होगी। उदाहरण के लिए, १९४७ में भारत का विभाजन होने पर पर हिन्दुओं और सिखों को पाकिस्तान में खदेड दिया गया तब भारत में बहुमत पाकिस्तान में पृष्ठ के पक्ष में था। भारत में सीधे बहुमत लोग यह अनुभव करते थे कि ऐसा कार्य हमारी नई पायी हुई आजादी के लिए हानिकारक होगा। इस प्रकार इन मामलों में अल्पमत की राय ही लोकमत है।

लोकतन्त्र में लोकमत का महत्व—यद्यपि तो, लोकमत होने का मर्याद सिर्फ लोकतन्त्र में ही पैदा होता है। तानाशाही में कोई लोकमत नहीं हो सकता, क्योंकि यमें विचार और भाषण की आजादी नहीं होती। दूसरे, लोकमत को अन्य रायों से अलग करने की कठिनाई भी लोकतन्त्र में ही पैदा होती है। तानाशाही में अगर कोई अभिमत होता भी है, तो वह तिरफ एक होता है। वहाँ जनता की राय चही होती है जो सरकार की। सरकार की राय से भिन्न राय रखने वाले आदमी को देशद्रोही मना जाना है और देशद्रोही को कठोर दण्ड दिया जाता है।

लोकतन्त्र लोकमत द्वारा शासन है। लोकतन्त्र में लोकमत केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के कार्यसंचालन में विभिन्न स्तरों पर आता है। विधानमंडल और कार्यपालिका दोनों को लोकमत द्वारा की गई आशेचना और प्रणमा पर उचित विचार करना पडता है। लोकतन्त्र में सामाजिक जीवन के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी लोकमत बडा प्रभाव डालता है। सच तो यह है कि लोकतन्त्र की प्रगति ही प्रबुद्ध, प्रागिर्णाल और जागरूक लोकमत पर निर्भर है।

प्रबुद्ध लोकमत के बनने के लिए आवश्यक शर्तें—किमी देश में प्रबुद्ध लोकमत बन सके इसके लिए जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं का होना अनिवार्य है—

(१) विचार और सोचने की आजादी—योगों को सोचने और अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। यदि सोचने और बोलने की आजादी नहीं है तो लोकमत का निर्माण नहीं हो सकता और न वह प्रकट किया जा सकता है। इसलिए प्रबुद्ध

लोकमन के लिए यह बात आवश्यक है कि आपस में स्वतन्त्रतापूर्वक चर्चा और खालीपना हो। इसके लिए शासन लोकतन्त्रीय होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के शासन में ही मोचने, खोजने और अपनी बात प्रकट करने की आजादी को गारंटी रहती है।

(२) स्वतन्त्र अभिव्यक्ति—ज्योति अधिनियम लोग अक्सर और कम परिभाषा के मन को ही अपना मन बना लेते हैं, इसलिए मुद्दों लोकमन के लिए स्वतन्त्र ईमानदार और निष्पक्ष अवसरों का होना एक और आवश्यक शर्त है। प्रम या अव्यक्त विमोचन वगैरे या समुदाय के हित साधन के उत्तरदायक नहीं होने चाहिए, और न उनपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। अव्यक्त को जनता के सामने नहीं और कम पारदर्शित समाचार और विचार रखने चाहिए।

(३) शिक्षा—बुद्धि को तेज करने, ज्ञान को बढ़ाने, और दृष्टिकोण को बड़ा करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा जनता की तर्क और आलोचना करने की योग्यता बढ़ाती है और लोगों को स्वतन्त्र विचार की आदत पड़ती है। अनपढ़ और अज्ञानी आदमी मूल्य प्रचार में गुमराह हो सकता है। बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति ही अच्छी और स्वतन्त्र राय रख और प्रकट कर सकता है। इसलिए शिक्षा दृढ़ और प्रबुद्ध लोकमन बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षाप्रणाली साम्प्रदायिक दृष्टिकोण में रहित होनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में बने हुए विचार और मत स्थायी में होते हैं।

(४) मेल मिलान—गुस्विदर और प्रबुद्ध लोकमन मेल मिलान और सहभाषता के वातावरण में ही तरबरी करता है। जनता को आपस में पूर्ण विश्वास और समझ-बूझ होनी चाहिए और उनका जीवन गण्यगिनतापूर्ण होना चाहिए। आपसी दुर्घ्या और अनिश्चय अच्छे लोकमन के बड़े दुश्मन हैं। सामाजिक जीवन में साम्प्रदायिक दलों या मजदूरों और मालिकों के झगडा में उबर पृथक् न होनी चाहिए।

(५) अवस्था और क्षमता—आम लोग सामाजिक और राजनैतिक सामन्याओं पर अपने विचार प्रकट कर गये। इसके लिए उनके पास उन समस्याओं के अध्ययन के लिए काफी सही समय होना चाहिए। सही समय उन्हें सभी मिल सकता है, जब वह आर्थिक दृष्टि से लुप्तहाण है। और इस प्रकार, लोकमन के निर्माण के लिए सही समय और समुचित दिना जरूरी हैं।

(६) सामनैतिक दल—अवसरों की तरह राजनैतिक दल का भी लोगों को शिक्षित करने में बहुत बड़ा स्थान है। राजनैतिक दल अपने प्रचार द्वारा लोगों को देश की अनेक समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं और इस तरह उन्हें अपनी राय बनाने के योग्य बनाते हैं। पर यह बहुत आवश्यक है कि दल दृढ़ आर्थिक और राजनैतिक सिद्धांतों के आधार पर बनाए जाएं। वे धार्मिक आधार पर नहीं होने चाहिए।

लोकमन के निर्माण और अभिव्यक्ति के माध्यम—यूँ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि सब लोग अपनी राय गूँध नहीं बनाते । उनके पास अनेक समस्याओं के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए माध्यम भी नहीं होते और उनके बारे में स्वतन्त्र निर्णय और सम्मति बनाने की योग्यता भी नहीं होती । सब लोगों के पास न इतना समय ही होता है कि वह सार्वजनिक मामलों का अध्ययन और विचार कर सकें । इसलिए अधिकतर लोग किसी न किसी जगह बनी-बनाई राय अपना लेते हैं । सार्वजनिक मामलों में बहुत बड़े लोग सक्रिय दिग्दर्शनी लेते हैं । ये लोग पेशेवर राजनीतिज्ञ, राजनैतिक दलों के नेता, विपक्ष सम्राज्यों के सदस्य और पत्रकार होते हैं । इन लोगों का काम है विविध समस्याओं का स्वयं अध्ययन करना और उनके हृदयस्थान बनना । ये लोग अखबारों और समाजों द्वारा अपने विचारों का प्रचार भी करते हैं, जहाँ से लोग अपनी अपनी पसन्द के अनुसार विभिन्न विचार ग्रहण कर लेते हैं ।

जो लोग बनी बनाई राय अपना लेते हैं, वे दो तरह के होते हैं । पहली तरह के लोग तो बहुत बड़े होते हैं, अखबारों और समाजों में प्रकट की जाने वाली रायों को बहुत तर्क-वितर्क के बाद स्वीकार करते हैं । ये अपना दिमाग खूबा रखते हैं, और उन्हें किसी सास दृष्टिकोण के पक्ष या विपक्ष में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता । दूसरी तरह के लोग, जो देश की भावार्थों का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, कुछ नेताओं के व्यक्तित्व, भाषणों या तारों में बहुरे उनसे दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते हैं ।

लोकमन बनाने के काम में लगे हुए अभिवरण ये हैं—प्रेस या अखबार, समाज, राजनैतिक दल, सिनेमा, रेडियो, शिक्षा मन्त्रालय और विधानमंडल । अब हम लोकमन के बनाने और उसे प्रकट करने में इनमें से प्रत्येक के कार्य पर विचार करेंगे ।

(१) प्रेम या अखबार—नागरिक शास्त्र में प्रेम का मतलब दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक अखबार और घटनाचक्र सम्बन्धी पुस्तकें हैं । अखबारों में रोज़ सब तरह की खबरें छपाई हैं और उनका मुख्य अस्थायी है । पत्रिकाएँ और पुस्तकें कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर उन पर विचार करती हैं और इस रूप में उनका मूल्य अधिक स्थायी होता है ।

लोकमन में प्रेम का कार्य—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, लोकतन्त्र लोकमन द्वारा शासन है । अखबार लोकमन के निर्माण और अभिव्यक्ति के मुख्य माध्यम होने के नाते लोकमन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं । ये निम्नलिखित कार्य करते हैं ।

जानकारी देने का काम—अखबारों का पहला काम है लोगों को देश-विदेश की अनेक राजनैतिक, बाणिज्य और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी देते रहना । वृत्ति लोकतन्त्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, इसलिए

यह बहुत आवश्यक बात है कि लोगों को सरकार की नीतियों, निश्चयों और कार्यों के बारे में सब कुछ पना हो। अखबार लोगों को इन सब बातों की जानकारी देते हैं। जानकारी देने के कार्य द्वारा अखबार शासन के संचालन में लोगों की दिलचस्पी बनाये रखने हैं।

निर्माणात्मक कामें - अखबारों का काम सिर्फ जानकारी देने का ही नहीं है, बल्कि निर्माण का भी है। ये पढ़ते लोगों को जानकारी देते हैं, फिर उन्हें अपनी राय बताने में सहायता देते हैं। समाचार देने के अलावा, अखबार अपने सम्पादकीय लेखों और अप्रलेखों में कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय भी देते हैं। जनता, जो यनी-बनाई राय अपना लेती है, अखबारों द्वारा प्रकट की हुई राय को ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि अखबार लोकमत को डालता और संपठित करता है।

अखबार लोकमत प्रकट करने का माध्यम है—अखबार सरकारी नीतियों और निश्चयों पर जनता की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रकट करने का साधन भी है। इस प्रकार अखबार पहले तो लोकमत के निर्माता के रूप में, और फिर उसके प्रकाशक के रूप में जनता के हितों की रक्षा करते हैं। अखबार प्रचार का संचित-साली साधन है, और इसलिए उनका जनता पर बड़ा प्रभाव होता है। कोई लोक-सुधी सरकार इसके महत्त्व की उपेक्षा नहीं कर सकती।

अखबार सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता करता है—जनता और सरकार के बीच में होने में अखबार को दोनों का आदर और विश्वास प्राप्त होता है। इसलिए जनता और सरकार में विरोध होने पर यह सर्वोत्तम मध्यस्थ है। यह दोनों तरफ की भावनाओं को हटका करके बड़ा उत्तम काम कर सकता है। यह उन दोनों को तर्कसंगत होने में सहायता देता है। यह सरकार को अत्याचार से और जनता को कान्तिकारी होने से रोकता है। इसलिए अखबार वह मेल-मिलाप बनाए रखता है जो लोकतन्त्र की स्वतंत्रता के लिए बहुत आवश्यक है।

अच्छे प्रेस के गुण—अच्छा प्रेस यानी अखबार सच और निष्पक्ष होना चाहिए। जिसे कम महत्त्व की बातों को बड़े बड़े शीर्षक देकर अतिरिजित नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसे सनमनीदार खबरें देने और किसी चढ़ाने के लिए कतक बचाने से बचना चाहिए। यदि वह ऐसा न करेगा तो एक ओर तो सरकार और जनता के बीच और दूसरी ओर, लोगों में परस्पर खाई चौड़ी हो जाएगी।

इसी प्रकार, अखबार को अपनी छबियों और विचारों में ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। इसे सरकार या किसी दल की स्वार्थसिद्धि या किसी समुदाय विशेष का हित-साधन नहीं करना चाहिए। अगर अखबार पक्षपात करने वाला है तो जनता की स्वाधीनता और समाज की शान्ति खतरे में पड़ जाएगी। हमारे देश में विभाजन से पहले के दिनों में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कटुता बढाने की

प्रिम्मेदारों वृद्ध हृद तक अवधारों पर थी। इस प्रकार अच्छे प्रेस का काम लोगों में तनाव के बजाय मेल मित्राप पैदा करना होना चाहिए।

(२) सभामंच—नागरिक शास्त्र में सभामंच से मतलब उस जगह से है जहाँ से सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिये जाते हैं। मंच सरकार की नीतियों और कामों के विषय जनता की सिकायतों प्रचारित करने का एक साधन है। यह ऐसा स्थान भी है जहाँ सरकार के सदस्य अपने कामों और नीतियों की सफाई देते हैं। इसलिए सार्वजनिक सभाओं में लोगों को दोनों तरफ की बात सुनने का मौका मिलता है। वे अपनी इच्छानुसार निष्कर्ष निकाल सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं।

(३) राजनैतिक दल—किसी राजनैतिक दल का मुख्य काम सत्ता प्राप्त करना है। लोकमत में राजनैतिक सत्ता उनके हाथ में रहनी है, जो बहुमत में होनी है। इसलिए प्रत्येक राजनैतिक दल अपने लिए अधिक से अधिक अनुयायी हासिल करने का यत्न करता है। इन प्रयोजन के लिए, राजनैतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करते रहते हैं। चुनावों से पहले यह प्रचार तीव्र कर दिया जाता है क्योंकि अधिकतर लोग उस समय ही सार्वजनिक मामलों में दिलचस्पी दिखाने हैं। राजनैतिक दल चुनाव के मनीफेस्टो या आविष्टपत्र तैयार करते हैं, और सार्वजनिक सभाएँ करते हैं। उनमें वे प्रत्येक दल अपने कार्यक्रम और नीति के पक्ष में बोलता है। इसलिए राजनैतिक दल अपने-अपने कार्यक्रम के पक्ष में लोगों को शिक्षित करते हैं, और लोकमत संगठित करते हैं।

(४) सिनेमा—आधुनिक काल में सिनेमा भी लोकमत बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन हो गया है। कुछ दृष्टियों से फिल्म का काम अवधारों के काम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सब लोग अवधार नहीं पढ़ते, पढ़ने से अधिकतर लोग फिल्में देखते हैं। इसलिए सिनेमा घरों में दिखायी जाने वाली सभावार चित्रावली अधिक लोगों को लाभ पहुँचाती है। फिल्मों का रूप चित्रात्मक होने से लोगों को बहुत-सी बातें आसानी से समझाना सम्भव हो जाता है। जनता की चेतना को मजबूत किया जा सकता है और फिल्मों में हृदयस्पर्शी कहानियाँ पेश करके अनेक सामाजिक और आर्थिक बुराइयों के खिलाफ लोकमत को आसानी से संगठित किया जा सकता है।

(५) रेडियो—लोकमत के संगठनकर्ता के रूप में रेडियो, अवधार, सिनेमा और सभामंच इन तीनों के थोड़े-थोड़े लाभ का मयोग है। अवधार की तरह रेडियो भी खबरें प्रसारित करके और उनपर टीकाटिप्पणी करके लोकमत संगठित करता है। सार्वजनिक हित के अनेक विषयों पर वात्ताएँ और दानवीर की व्यवस्था करके रेडियो अत्यंत सभामंच का काम करता है। सिनेमा की तरह रेडियो मनोरंजन और शिक्षा एक साथ देता है। मनोरंजन के साथ शिक्षा देने के उदाहरण देहाती प्रोग्राम और स्त्रियों तथा बच्चों के प्रोग्राम हैं।

इसलिए रेडियो का स्थान प्रेम से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। अखबार तो निकल पड़े-लिने आदमी के लिए उपयोगी है, पर रेडियो अनपढ़ लोगों के लिए भी फायदेमंद है। भारत में अगिकतर लोगों के अनपढ़ होने के कारण यहाँ जनसाधारण को शिक्षित करने में रेडियो का उपयोग लाभदायक हो सकता है। इसका सहारा लेकर हम कई सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बुराइयों को हटा सकते हैं और जनता के बुद्धिबोध को अधिक प्रगतिशील बना सकते हैं। रेडियो का एक बड़ा लाभ यह है कि इसके जरिये एक साथ लाखों लोगों में अपनी बात कही जा सकती है। इस प्रकार रेडियो में घोड़ी-घी ढेर में लोकमत सुगठित करना आसान हो जाता है।

पर यह सावधान रहना चाहिए कि प्रेम की तरह रेडियो का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। अधिकतर देशों में रेडियो पर सरकार का एनाधिकार है। वहाँ इसका अच्छा या बुरा उपयोग करना सरकार के ही हाथ में है। यदि सरकार जनता का हित चाहती है तो वह रेडियो का सही उपयोग करेगी। पर अगर किसी देश की सरकार स्वार्थी लोगों के हाथ में है, तो रेडियो में जनता को गुमराह किया जाएगा। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में सरकार लोगों में भारत-विरोधी भावनाएँ फैलाने में इसका उपयोग कर रही है।

(६) शिक्षा समस्याएँ—स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि शिक्षा संस्थाएँ भविष्य के नागरिकों के प्रशिक्षण की जगह हैं। नवयुवकों के निर्माण काल में इन संस्थाओं में लिए हुए विचार और बनाई हुई राय बाद के जीवन में भी उनके भाग बनती रहती हैं।

(७) विधानमण्डल—किसी लोकतंत्रीय देश के विधानमण्डल में सब स्थितियों और विचारों के योग होते हैं। इसलिए इसमें होने वाले भाषण लोकमत को प्रकट भी करते हैं और बनाते भी हैं।

राजनैतिक दल

राजनैतिक दल किसे कहते हैं—कोई राजनैतिक दल उन नागरिकों का एक संगठित समूह है जिनके सार्वजनिक प्रश्नों पर एक से विचार होते हैं, और वे जिस नीति को मानते हैं, उसे लागू करने के लिए सरकार पर नियंत्रण हासिल करने के वास्ते एक राजनैतिक इकाई के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक राजनैतिक दल मानवीय स्वभाव की निम्न दो विशेषताओं पर आधारित है—

(१) लोगों की राय अलग-अलग होनी है।

(२) साथ ही वे, स्वभाव से सूचकारी या समूह बनाकर रहने वाले (Gregarious) होते हैं। अपने मतभेदों के बावजूद उन्हें कुछ मोटे तमूली पर एकमत होना ही पड़ता है और उन नीति को अमल में लाने के लिए काम करना ही पड़ता है।

किसी राजनैतिक दल का आवश्यक तत्व—किसी राजनैतिक दल को, सही

जाता है। इसलिये दल साधारणतया उम्मीदवारों के चुनाव में बहुत मायावादी रहते हैं।

(३) दल उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करता है—दल उम्मीदवार को न केवल सहाय करता है बल्कि उसके लिए जोर-शोर से समर्थन भी हासिल करता है। अपने-अपने के लिए खुद बोट हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। दल के लिए यह कुछ कठिन काम नहीं, क्योंकि इसकी साक्षात् मांग देश में होती है।

(४) दलीय प्रणाली गरीब आदमियों को भी चुनाव में लक्ष्य होने का मौका देती है—दलीय प्रणाली गरीब आदमियों को भी चुनाव में लक्ष्य होने का मौका देती है। हर चुनाव में प्रचार पर कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता है। गनी-गनी चुनाव का खर्च हजारों रुपये होता है। अगर उम्मीदवार गरीब आदमी हो तो दल उसकी ओर में खर्च करता है। अगर राजनीति दल न होते तो सिद्ध धनी आदमी चुनावों में लक्ष्य होने।

(५) दलीय प्रणाली शिक्षादायक है—राजनीति दल अपने चुनाव प्रचार द्वारा लोगों को शिक्षित करते हैं और लोकमत संगठित करते हैं।

(६) लोकतन्त्र होने पर दल अपने बचनों के अनुसार बानून बनाते हैं—चुनाव के बाद बहुमत दल को सामन का नियंत्रण मिलना है। तब दलवा मत्तव्य है कि लोगों को दिए हुए बचनों के अनुसार बानून बनाए। विगी दल के लिए जनता को दिए हुए बचन का भंग करना अच्छा नहीं।

(७) विरोधी दल का प्रतिपक्ष का कार्य—जिन दलों को विधानमंडल में बहुमत नहीं मिलना वे मिलकर एक प्रबल विरोधी दल के रूप में संगठित हो जाते हैं। लोकतन्त्र में विरोधी दल भी महत्वपूर्ण हिस्सा लेता है। इसका यह काम है कि मत-दानाओं को सरकार की क्षमिया के बारे में निरंतर जानकारी देता रहे और इस तरह सामन को दृष्टि बनाए। प्रबल विरोधी दल सरकार को अस्थाचारी होने से रोक्ता है, क्योंकि लोकतन्त्र में जरा गा भी परिवर्तन सत्तासूत्र सरकार की ओर से देना है, क्योंकि लोकतन्त्र में जरा गा भी परिवर्तन सत्तासूत्र सरकार की ओर से देना है, क्योंकि लोकतन्त्र में जरा गा भी परिवर्तन सत्तासूत्र सरकार की ओर से देना है। पर यह याद रखना चाहिए कि विरोधी दल को हासिलकारण आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसे सत्तासूत्र दल को स्वतन्त्रता मुक्तव देने चाहिए। विरोधी दल को राष्ट्रीय हित के नामों में सरकार से सहयोग करना चाहिए।

दलीय प्रणाली के लाभ—दलीय प्रणाली के मुख्य लाभ यह हैं—

(१) दलीय प्रणाली लोकतन्त्र को चलाने योग्य बनाती है। अगर दल न होते तो प्रतिनिधियों का चुनाव और सरकारों का निर्माण कठिन काम होता। हम ऊपर देख चुके हैं कि लोकतन्त्रीय सरकार के गठन में दलों का क्या स्थान है।

(२) दल अपने चुनाव आदेशों द्वारा लोगों को शिक्षित करते हैं। वे चुनाव पंक्तिस्टों विकसलने हैं और देश के सामन भीजुद समाजियों के बारे में लोगों

को जानकारी देने के लिए सार्वजनिक मनाए करने हैं। दल न केवल जनता को जानकारी देते हैं, बल्कि वे उन्हें अपनी राय बनाने में भी सहायता देते हैं।

(३) दलीय प्रणाली साक्षार के अत्याचारी व्यवहार में बचाती है। विना लोगों के हाथ में शासन की बागडोर रूढ़ी है, वे सदा दल के नियंत्रण में रहते हैं। वे जो चाहे नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी दल मतदानियों का विश्वास नहीं लाता। फिर, विरोधी पक्ष सरकार के कार्यों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। वे मतदानियों को जो मोहनत्रय में अमली मानिक है उसकी कमियाँ बताते रहते हैं।

(४) दलीय प्रणाली जनता और शासन के बीच में आवश्यक कड़ी होती है। यह शासक और शासित के बीच पृथक् का काम करती है।

(५) दलीय प्रणाली सुधानों के लिए साक्षार में उपयोगी है। अणुता में दलीय प्रणाली द्वारा सहयोग सम्भव हो जाता है।

(६) शासन की प्रभावी या राष्ट्रीय प्रणाली के लिए भी दलीय प्रणाली विशेष उपयोगी है। इन प्रणाली में दल ही कार्यपालिका और विधायिका को सहयोग में काम करने योग्य बनाता है।

दलीय प्रणाली की हानियाँ—दलीय प्रणाली के आगेचक दुमनें कुछ दोष बताते हैं—

(१) कहा जाता है कि दलीय प्रणाली राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। यह लोगो में अनाकाम्य और द्विधम भेदभाव पैदा करती है। लोग परस्पर-विरोधी समूहों में बंट जाते हैं, और एक दूसरे की अदना दुश्मन समझने लगते हैं। यह भेदभाव राष्ट्रीय प्रगति में बाधा डालता है।

(२) कहा जाता है कि दलीय प्रणाली किसी देश के जीवन की मर्याद जंमा घना देती है। विरोधी दल सरकार द्वारा पैदा किए गए नव कानूनों का विरोध करना अपना कर्तव्य समझता है। इसी प्रकार, सरकार विरोधी दल द्वारा कही जाने वाली नव बातों पर गम्भीरता में विचार नहीं करती।

(३) दलीय प्रणाली की एक और आलोचना यह है कि यह दल के सदस्यों की अस्पष्टता (Individuality) को नष्ट कर देती है। उन्हें दल के अनुशासन में रहना पड़ता है, और इसलिए वे किसी मामले पर दल की इच्छाओं के विरुद्ध स्वतन्त्र रूप नहीं अपना सकते। आत्मसम्मान की भावना को प्रायः दल का नियंत्रण अपने लिए अमहनीय मान्य होता है। इसलिए दलीय प्रणाली बहुत से अच्छे नागरिकों को सार्वजनिक जीवन में अना रखती है।

(४) दलीय प्रणाली के विरोधियों का कहना है कि यह प्रणाली समाज के नैतिक स्तर को कम करती है। दलीय प्रचार में झूठ और कलक कथनों का बोला-बाला होता है। दल मतदानियों को रिकवत भी देते हैं।

दो-दलीय और बहु-दलीय प्रणाली—दिल्ली राज्य में दो दल अधिक राजनीति करने लगे हैं। जब दल की संख्या दो होती है, तब यह दो-दलीय प्रणाली बन जाती है। जब दो से अधिक दल होते हैं, तब यह बहु-दलीय प्रणाली कहलाती है। इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड संसद में दो-दलीय प्रणाली है। इन दोनों संघों में राजनीति करने की प्रणाली मजबूत हो गयी है पर इनमें प्रत्यक्ष में चुनाव दल का है। यूरोप के बड़े गणराज्यों में, गणतन्त्र प्रणाली में बहुत से दल हैं जिनकी संख्या कई जगह १० या २० तक है। जहाँ बहुत से दल होते हैं, वहाँ यह दल प्रणाली ही रहती है। वे प्रणाली में राजनीति समूह होते हैं।

दो-दलीय प्रणाली के मुल-दो-दलीय प्रणाली का मुख्य लक्ष्य यह है कि इसमें अधिक स्थायी और स्थिर शासन का हुआ सुनिश्चित हो जाता है। विधानमण्डल में एक दल का विधान अनुमूलन करवा लेता है। इसलिए अधिकतर दलों को मजबूत बहुमत का समर्थन मिलने का निश्चय हो जाता है। यह सभी एक दल का ही होना ही जिनमें बहुमत का अधिकारी रहता है।

दूसरे, दो-दलीय प्रणाली में मजबूत प्रथम में प्रतिनिधित्व का सामान होता है एकमात्र दली प्रणाली में जिनमें मतदाता सरकार को गोप्य चुनते हैं। दोनों दलों के सुनिश्चित कार्यक्रम होते हैं और उपाय आधार पर विचारणा ग गोप्य प्रतीय की जाती है। निर्वाचन दोनो दल-प्रणाली में न एक धुंलकन है और यह प्रणाली करते हैं कि नीतिगत दल परामर्श हो।

तीसरे, दो-दलीय प्रणाली विशेषी दल की सरकार के साथ अल्पमत सरकारों में अधिक स्थिरता और जिम्मेदार बनती है। इन प्रणाली में सरकार को बनाने के लिए अधिक जिम्मेदारी न की जाती है।

दो-दलीय प्रणाली के दोष—दो-दलीय प्रणाली का विशेषी, का बचना है कि हमने अधिकतर में लाना-बाहरी संदा होती है। इन प्रणाली में अधिकतर को विधानमण्डल में दोनो बहुमत मिल जाता है। विधानमण्डल को दलीय अनुशासन के कारण न गण-बाहरी और निश्चयों का समर्थन करना पड़ता है। इसलिए, अधिकतर को विधानमण्डल से ऊँची स्थिति प्राप्त हो जाती है, और यह प्रायः विधानमण्डल को अपनी दायित्वपूर्ण बनाता है।

दूसरे, बहुमत दल अपनी स्थिति समूह होने के कारण स्थिति में अंधा हो जाता है। यह संभावना रहती है कि जब तक इसे बहुमत प्राप्त है तब तक यह अल्पमत के हितों की कुछ भी परवाह नहीं करेगा।

तीसरे, दो-दलीय प्रणाली में निर्वाचनों की एक या दूसरे दल के सारे कार्य-

परिपृच्छा—यह वह मापन है जिम्मे विभी लेने बानून पर, जिन पर विधान-मण्डल अपनी राय प्रकट कर चुका है, निर्वाचकों का संसदा भाग जाता है।

प्रारम्भण या उपक्रमण—यह वह मापन है जिम्मे निर्वाचकों की ओरं विधि निर्दिष्ट सरदा कोई धान बानून बनाने के लिए विधानमण्डल को आदेश दे सकनी है।

परिपृच्छा और प्रारम्भण या उपक्रमण के पक्ष में धृतिवर्ग —

(१) वे जनता की सर्वोच्चता का प्रमाण है।

(२) उनके द्वारा जनता की वास्तविक इच्छा का पता लगाया जा सकता है।

(३) वे राजनैतिक दलों के प्रभाव को कम करने हैं।

(४) इन विधियों में बनाये गये बानूनों का पालन अधिक आसानी से होता है।

(५) वे लोगों को शिक्षित करने हैं और उनमें देशभक्ति के भाव बढ़ाने हैं।

परिपृच्छा और प्रारम्भण या उपक्रमण के विपक्ष में धृतिवर्ग—(१) वे विधान मण्डल के प्रभाव को कम करने हैं, और विधानमण्डल स्मररबाहू होने लगता है। (२) इन उपायों में बानूनों के प्रारूप (Draft) में त्रुटि रहती है। (३) विधेयक या तो सबसे मानना पड़ता है या रद्द करना पड़ता है। (४) ये उपाय राजनैतिक दलों की बुराइयों को ही बढ़ाने हैं। (५) विज्ञा देने की दृष्टि में इनका कोई मूल्य नहीं।

लोकमत : लोकमत कितने बहते हैं—आइये लोकमत उमे कह सकते हैं जिनका लक्ष्य जनसाधारण की मलाई हो और जो बहुत से लोगों का हो। पर यह जरूरी नहीं कि यह राजका या बहुमत का विचार हो। कोई वर्ग-पक्षधारी विचार लोकमत नहीं सकता।

लोकमत लोकमत द्वारा प्राप्त होता है और इसकी प्रगति लोकमत के प्रयुक्त और सजग होने पर निर्भर होती है।

प्रयुक्त लोकमत के लिये आवश्यक शर्तें—

(१) विचार और भाषा की आजादी।

(२) स्वतन्त्र प्रेस।

(३) आम शिक्षा।

(४) लोगों की अवकाश और सुरक्षा का होना।

(५) आर्थिक और राजनैतिक सिद्धांतों के आधार पर अच्छी तरह संगठित राजनैतिक दल होने चाहिए।

लोकमत बनाने और प्रकट करने के साधन—अधिकतर लोग बनी-बनाई राय अपना लेते हैं। लोकमत बनाने के काम में लगे हुए साधन हैं प्रेस, समाजिक राजनैतिक दल, क्लिपिंग, रेडियो, शिक्षा मर्यादा और विधान-मण्डल।

प्रेम—प्रेस लोगों को देश-विदेश की अनेक राजनैतिक, जायिक और सामा-
जिक घटनाओं का परिचय देना है और मन्त्रालयों के अन्दर और अल्पेणो द्वारा उन्हें
अपनी राय बनाने में मदद देना है। प्रेम द्वारा सरकार की नीतियों और फैसलों पर
जनता की भावनाओं और प्रतिश्रियाओं का प्रचार भी किया जा सकता है। इस
प्रकार, यह सरकार को अत्याचारी होने में रोकना है। अच्छा प्रेस विचारशील,
निष्पक्ष और ईमानदार रहकर खबरें और विचार देने वाला होना चाहिए। तब ही
यह सरकार और जनता के बीच मन्त्रालयों का काम कर सकता है।

समाजवाद—समाजवाद जनता की निराशाओं लोगों के सामने लाने का माधम है
और यह सरकार के ऊँचे अधिकारियों को अपने कामों और नीतियों की सफाई देने
का मौका देता है।

राजनैतिक दल—राजनैतिक दल लोगों को शिक्षित करते हैं और अपने
युवाय प्रचार द्वारा लोकमत संगठित करते हैं। वे मनीफेस्टो तैयार करते हैं, और
सामाजिक सुधारों करते हैं।

मिमेमा—मिमेमा कुछ दृष्टियों में प्रेम में भी अधिक महत्वपूर्ण माधम है,
क्योंकि यह जनता पर भी असर डालता है। फिल्मों में आने वाली खबरें और दिल
को छूने वाली कहानियाँ बहुत जल्दी लोकमत संगठित करती हैं।

रेडियो—रेडियो में बख्तवार, मिमेमा और समाजवाद तीनों के गुण एकत्र हो
जाते हैं। मित्रों, बच्चों और देहातियों के विशेष कार्यक्रम मनोरंजन के साथ-साथ
दिखा देते हैं। रेडियो ही एकमात्र माधम है जिसके द्वारा लोकमत कम में कम समय
में संगठित किया जा सकता है। इसके द्वारा हम कई सामाजिक और जायिक बुरा-
यों को भी दूर कर सकते हैं।

शिक्षा मन्शर—स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भावी नागरिकों के प्रशि-
क्षण की जगह हैं। यहाँ यह किसे गए विचार और बनाई गई राय बहुत कुछ
स्थायी बन गी होती हैं।

विधानमण्डल—विधानमण्डल में होने वाले विवाद लोकमत को प्रकट भी
करते हैं और बनाने भी हैं।

राजनैतिक राजनैतिक दल किसे करते हैं—राजनैतिक दल उन नागरिकों
का संगठित समूह है जिनके सामाजिक सुधारों पर एकमे विचार हो और जो अपनी
नीति को लागू करने के लिए सरकार पर नियंत्रण हासिल करने के वास्ते एक राजनै-
तिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार किसी राजनैतिक दल में चार चीजें
शर्ती जरूरी हैं—

- (१) इनके सदस्यों का कुछ मूल सिद्धान्तों पर एक मत होना चाहिए। (२) यह
एक गठित समूह होना चाहिए। (३) इनके अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए वैधानिक
उपायों में काम लेना चाहिए। (४) इनके राष्ट्रीय हित के लिए काम करना चाहिए,

किसी पक्ष या वर्ग के हितों के लिए नहीं।

राजनैतिक दल के कार्य—प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र राजनैतिक दलों के बिना काम नहीं चला सकता। वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करते हैं—(१) वे चुनाव के लिए उम्मीदवार छांटने हैं। (२) प्रत्येक दल अपने उम्मीदवार के चरित्र और आचरण की गारण्टी होता है। (३) प्रत्येक दल अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करता है। (४) राजनैतिक दलों की सहायता से गरीब लोग भी चुनावों में लड़ ही सकते हैं। (५) दल लोगमन को शिक्षित और संगठित करते हैं। (६) विरोधी दल सरकार को दक्ष बनाये रखते हैं और लोगों को सरकार के भ्रष्टाचार से बचाने हैं।

दलीय प्रणाली के लाभ - राजनैतिक दलों के जो कार्य हैं, वे दलीय प्रणाली के लाभ भी हैं। उपर्युक्त बातों के अलावा, प्रधानीय या राष्ट्रपतीय और स्थानीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका को बीच तथा सभ सरकार और राज्य सरकार के बीच आवश्यकता सम्बन्ध दलीय प्रणाली के द्वारा ही होता है।

दलीय प्रणाली की हानियाँ—(१) दलीय प्रणाली राष्ट्रीयता के लिए अहितकर है। (२) यह देश के राजनैतिक जीवन को मशोम जैसा बना देती है। (३) यह दल के सदस्यों की व्याप्टना को दबा देती है। (४) यह समाज के 'निर्दिव' स्तर को नीचा करती है।

दो-दलीय प्रणाली के लाभ—(१) इसमें सरकार अधिक स्थायी और स्थिर रह पाती है। (२) यही एक प्रणाली है जिसमें सीधे मनश्चात सरकार को चुनाव है। (३) इसमें विरोधी दल सरकार के साथ अपने सम्बन्धों में अधिक व्यवस्थित और जिम्मेदार होता है।

दो-दलीय प्रणाली के दोष—(१) यह मधिमण्डल की तानाश हों को जन्म देती है। (२) बहुमत दल विधानमण्डल में अपनी ठोस ताकत के कारण शक्ति से अबा होने लगता है। (३) दो-दलीय प्रणाली में मतदान को किसी एक पक्ष का सारा कार्य 'भ्रम मानना या ठुकराना' होना है। कोई वीध का रास्ता नहीं हो सकता।

बहुदलीय प्रणाली के गुण और दोष—दो-दलीय प्रणाली के जो गुण हैं वे बहुदलीय प्रणाली में दोष बन जाते हैं, और उनके दोष इसके गुण बन जाते हैं।

प्रश्न

१. आम वयस्क मताधिकार से क्या क्या सम्भते हैं? इस प्रणाली पर कौन-कौन से मुख्य आक्षेप किये जाते हैं और आप उनका क्या जवाब देंगे?
2. What do you understand by the system of Universal Adult Franchise? What are the chief objections to this system and how will you meet them?
३. परिपुच्छा और प्रारम्भण या उपक्रमण से क्या क्या सम्भते हैं? उनके गुण और दोष क्या हैं?

2. What do you understand by 'Referendum' and 'Initiative' ? What are their merits and demerits ?
३. लोकमत का क्या अर्थ है ? लोकतन्त्रीय राज्य में इसका क्या महत्व है ?
(प० वि० अप्रैल, १९५०)
3. What is meant by 'Public Opinion' ? Estimate its importance in a democratic state. (P.U. April 1950)
४. लोकमत के निर्माण और प्रकट करने के प्रत्येक साधनों का संक्षेप में वर्णन करो।
(प० वि० अप्रैल, १९५२)
4. Describe briefly the various organs or agencies for the formation and expression of public opinion. (P.U. April, 1952)
५. लोकमत बनाने में प्रेस का क्या स्थान है ? (प० वि० अप्रैल, १९६६)
5. What part does the press play in moulding public opinion ? (P.U. April, 1949)
६. लोकमत बनाने में प्रेस और रेडियो द्वारा किये गए काम का उन्नेव करो।
(प० वि० सितम्बर, १९५० और अप्रैल १९४८)
6. Describe the part played by press and broadcasting in moulding public opinion. (P.U. Sept. 1950 and April 1948)
७. दलीय सरकार कितने कहते हैं ? उनके गुण और दोष लिखो।
(प० वि० सितम्बर, १९५०)
7. What is Party Government ? Mention its merits and demerits. (P.U. Sept. 1950)
८. राजनैतिक दल से अ.प. क्या सम्बन्ध है ? राजनैतिक दलों का राज्य के काम और नागरिकों की शिक्षा में क्या स्थान है ? प० वि० अप्रैल, १९५०)
8. What do you understand by 'Political Party' ? What part do political parties play in the work of the state and the education of the citizen ? (P.U. April, 1952)

Or

- किसी लोकतन्त्रीय राज्य में राजनैतिक दलों के कार्य का वर्णन करो।
Describe the role of political parties in a democratic state.
६. क्या दलीय प्रणाली लोकतन्त्र के लिए आवश्यक है ? दलीय प्रणाली की प्रशंसा करो।
(प० वि० अप्रैल, १९५४)
 9. Is party system necessary for democracy ? Give a criticism of the party system. (P.U. April, 1954)
 १०. दो-दलीय और बहु-दलीय प्रणालियों के गुण और दोषों की तुलना करो।
 10. Examine the relative merits and demerits of two-party and multi-party system.

संस्कृति और सभ्यता, अवकाश और मनोरंजन

संस्कृति और सभ्यता

नागरिक शास्त्र अच्छी नागरिकता का विज्ञान है और अच्छे नागरिक को सभ्य और सुमस्वृत आदमी होना चाहिए। इसलिए नागरिक शास्त्र का अध्ययन करते हुए हमारे लिए संस्कृति और सभ्यता के अर्थों को समझना जरूरी हो जाता है।

संस्कृति का अर्थ—संस्कृति की परिभाषा करना यदा कठिन है। इनके समकालीन पर अलग-अलग लोगो ने अलग-अलग अर्थ समझा है। पर हम इस अध्याय में संस्कृति शब्द के दो अर्थों का उल्लेख करेंगे—

१. व्यापक अर्थ में संस्कृति का मतलब।

२. सीमित या ठीक अर्थ में संस्कृति का मतलब।

संस्कृति का व्यापक अर्थ—मोटे तौर से कह तो संस्कृति शब्द का प्रयोग आदमी के बनाये हुए मारे वातावरण और आदर्शों के मारे भीखे हुए व्यवहार (Learnt behaviour) के लिए हो सकता है।

मनुष्य अपने कार्य में अपने प्राकृतिक वातावरण को, अपने बनाए हुए वातावरण में बदल देता है। मोटे तौर से कहा जाय तो आज तक मनुष्य ने जो कुछ किया है, यह सब मनुष्य निर्मित वातावरण के अन्तर्गत आ जाता है। इसमें मनुष्य की सब भौतिक और अर्भौतिक सफलताएँ आ जाती हैं। इस तरह मोटे अर्थ में, संस्कृति शब्द में कलाएँ, औजार और मशीनें आदि मारे भौतिक आविष्कार तथा दर्शन, कला, साहित्य और विज्ञान आदि, अर्भौतिक सफलताएँ भी आ जा जाएँगी।

मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार भी मोटे अर्थ में संस्कृति है। मनुष्य का अधिकतर व्यवहार सीखा हुआ या सुस्कार-जनित व्यवहार है। उदाहरण के लिए, चलना, बोलना, खाना और पीना—ये सब सीखे हुए व्यवहार हैं। योग के आसनो और डबकी लगाने में साग रोकने की अवस्था में सास लेना भी एक सीखा हुआ व्यवहार हो जाता है। सड़े होना और पैठना भी प्राकृतिक नहीं, बल्कि अनजाने में सीखे हुए व्यवहार हैं।

इस तरह मोटे अर्थ में संस्कृति शब्द में मनुष्यों के सब कार्य और सफलताएँ आ जाएँगी।

सही अर्थ में संस्कृति का मतलब—मनुष्य ने संस्कृति शब्द का प्रयोग

2. What do you understand by 'Referendum' and 'Initiative'? What are their merits and demerits?
३. लोकमत का क्या अर्थ है? लोकतन्त्रीय राज्य में इसका क्या महत्त्व है? (प० वि० अप्रैल, १९५०)
3. What is meant by 'Public Opinion'? Estimate its importance in a democratic state (P.U. April, 1950)
४. लोकमत के निर्माण और प्रकट करने के अनेक साधनों का मर्मप में वर्णन करो। (प० वि० अप्रैल, १९५२)
4. Describe briefly the various organs or agencies for the formation and expression of public opinion. (P.U. April, 1953)
५. लोकमत बनाने में प्रेस का क्या स्थान है? (प० वि० अप्रैल, १९६६)
5. What part does the press play in moulding public opinion? (P.U. April, 1949)
६. लोकमत बनाने में प्रेस और रेडियो द्वारा किये गए काम का उल्लेख करो। (प० वि० सितम्बर, १९५० और अप्रैल १९४८)
6. Describe the part played by press and broadcasting in moulding public opinion (P.U. Sept. 1950 and April 1948)
७. दलीय सरकार किसे कहते हैं? उसके गुण और दोष लिखो। (प० वि० सितम्बर, १९५०)
7. What is Party Government? Mention its merits and demerits. (P.U. Sept, 1950)
८. राजनैतिक दल से क्या समझते हैं? राजनैतिक दलों का राज्य के काम और नागरिकों की शिक्षा में क्या स्थान है? प० वि० अप्रैल, १९५२)
8. What do you understand by 'Political Party'? What part do political parties play in the work of the state and the education of the citizen? (P.U. April, 1952)

Or

निम्न लोकतन्त्रीय राज्य में राजनैतिक दलों के कार्य का वर्णन करो।

Describe the role of political parties in a democratic state

९. क्या दलीय प्रणाली लोकतन्त्र के लिए आवश्यक है? दलीय प्रणाली की आलोचना करो। (प० वि० अप्रैल, १९५४)
9. Is party system necessary for democracy? Give a criticism of the party system. (P.U. April, 1954)
१०. दो-दलीय और बहु-दलीय प्रणालियों के गुण और दोषों की तुलना करो।
10. Examine the relative merits and demerits of two party and multi-party system

अध्याय : १६

संस्कृति और सभ्यता, अवकाश और मनोरंजन

संस्कृति और सभ्यता

नागरिक शास्त्र अच्छी नागरिकता का विधान है और अच्छे नागरिक को सभ्य और सुगठित आदमी होता चाहिए। इसलिए नागरिक शास्त्र का अध्ययन करते हुए हमारे लिए संस्कृति और सभ्यता के अर्थों को समझना जरूरी हो जाता है।

संस्कृति का अर्थ—संस्कृति की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। हमने समय समय पर अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अर्थ समझा है। पर हम इस अध्याय में संस्कृति शब्द के दो अर्थों का उल्लेख करेंगे—

१. व्यापक अर्थ में संस्कृति का मतलब।

२. सीमित या ठीक अर्थ में संस्कृति का मतलब।

संस्कृति का व्यापक अर्थ—मोटे तौर से कह तो संस्कृति शब्द का प्रयोग आदमी के बनावे हुए गारे वातावरण और आदमियों के गारे सीखे हुए व्यवहार (Learnt behaviour) के लिए हो सकता है।

मनुष्य अपने कार्य में अपने प्राकृतिक वातावरण को, अपने बनावे हुए वातावरण में बदल देता है। मोटे तौर से कहा जाय तो आज तक मनुष्य ने जो कुछ किया है, वह सब मनुष्य निर्मित वातावरण के अन्दर आ जाता है। इसमें मनुष्य की सब भौतिक और अधीतिक सफलताएँ आ जाती हैं। हम सरल मोटे अर्थ में, संस्कृति शब्द में विचारों, औजार और मशीनों आदि सारे भौतिक आविष्कार तथा दान, कला, साहित्य और विज्ञान आदि, अधीतिक सफलताएँ भी आ जा जाएँगी।

मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार भी मोटे अर्थ में संस्कृति है। मनुष्य का अधिभार व्यवहार सीखा हुआ या संस्कार जनित्र व्यवहार है। उदाहरण के लिए, चटना, धोना, खाना और पीना—ये सब सीखे हुए व्यवहार हैं। योग के आसन और हठयोगी लगाने में सास रोकने की अवस्था में सास लेना भी एक सीखा हुआ व्यवहार हो जाता है। लड़े हाना और बँटना भी प्राकृतिक नहीं, बल्कि अज्ञान में सीखे हुए व्यवहार हैं।

इस तरह मोटे अर्थ में संस्कृति शब्द में मनुष्य के सब कार्य और सफलताएँ आ जाएँगी।

सही अर्थ में संस्कृति का मतलब—मैकाइवर ने संस्कृति शब्द का प्रयोग

भारत में प्रचार के उन साधनों के द्वारा भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित और प्रचारित करने के यत्न किये जा रहे हैं।

सभ्यता कितने कहते हैं—मैकाइवर के मतानुसार, मनुष्य के कुछ काम उसकी व्यापक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए होने हैं। इनका सम्बन्ध मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं से होता है। इनका अपना कोई भीतरी महत्त्व नहीं होता। उनका इसलिए महत्त्व है कि ये मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन हैं। फिर ये कार्य सांस्कृतिक कार्यों से इतनी बात में भिन्न हैं कि ये अनिवार्य ढंग के हैं। वे मनुष्य के अस्तित्व के लिए और शान्ति तथा आराम के लिए आवश्यक हैं। एक अच्छी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, औजार, मशीनें, खेती, उद्योग, पोशाक और मकान ये सब आदमियों के लिए जरूरी हैं। ये सब चीजें सभ्यता शब्द के अन्दर आजायेंगी। इन प्रकार सभ्यता शब्द का प्रयोग उन सारी भौतिक सफलताओं के लिए किया जा सकता है जो किसी समाज ने सुखी और आराम का जीवन बिताने की कोशिश में प्राप्त की है।

सभ्यता और संस्कृति में अंतर

सभ्यता और संस्कृति दो विन्तुल अलग शब्द हैं, और इनके बारे में किसी तरह का धम न होना चाहिए। उनमें भेद बताने वाली बातें नीचे दी जाती हैं —

संस्कृति आत्मपरक (Subjective) है और सभ्यता वस्तुपरक (Objective)—संस्कृति आदमी के भीतरी जीवन से सम्बन्ध रखती है और इसलिए आत्मपरक या आत्मा सम्बन्धी होती है। दूसरी ओर सभ्यता बाहरी जीवन से सम्बन्ध रखती है और इसलिए वस्तुपरक या भौतिक होती है।

संस्कृति व्यक्तिगत और व्यक्तिगत होती है तथा सभ्यता सामूहिक और सामूहिक—वस्तुपरक और भौतिक होने के कारण सभ्यता में किसी परिवार के एक सदस्य या किसी देश के या सारी दुनिया के सब लोग हिस्सेदार हो सकते हैं। इसलिए यह सामूहिक होती है, और इसका स्वामित्व सादा होता है। दूसरी ओर संस्कृति जो आत्मपरक या आत्मिक होती है, हमेशा व्यक्तिगत चीज होती है। यह एक ही परिवार में भी आदमी-आदमी में अलग-अलग होगी है। यह आवश्यक नहीं कि सुसंस्कृत आदमी का पुत्र भी सुसंस्कृत हो और न कोई सुसंस्कृत पिता अपनी अन्य बच्चों के साथ अपनी संस्कृति अपने पुत्रों को पहुँचा ही सकता है।

सभ्यता की तुलना की जा सकती है पर संस्कृति की नहीं—हम सभ्यता के बारे में अपना फँगला दे सकते हैं। एक सभ्यता को दूसरी से घटिया या बढ़िया कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, आज की रेलगाड़ी को पुराने जमाने की बैलागाड़ी से अच्छा बताया जा सकता है। इसलिए वर्तमान सभ्यता को पहले की सभ्यता से ऊँचा धरना जा सकता है। पर सांस्कृतिक वस्तुओं के बारे में फँगला देना कठिन है। उदाहरण के लिए, हम यह नहीं कह सकते कि भारतीय संगीत पश्चिमी संगीत से बढ़िया या घटिया है।

सम्पत्ता सदा तरफती करती है, सस्कृति नहीं—सम्पत्ता के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह सदा तरफती करती है। उदाहरण के लिए कुछ मशीनों की अपेक्षा आज संचार के साधन अधिक अच्छे और तेज हैं। दूसरी ओर, हमें कहना है कि सम्पत्ति में कोई प्रगति न हो। भारत में अनेक गताश्रितों में सम्पत्ति के लोभों में बाँध प्रगति नहीं हुई।

सम्पत्ता एक देश से दूसरे देश में ले जाई जा सकती है, पर सस्कृति नहीं—सम्पत्ता को आगामी से एक देश से दूसरे देश में ले जाया जा सकता है। यह इस बात में निश्चय होता है कि रैडियो, हवाई जहाज और सिनेमा सम्पत्ति के सब लोभों की साम्या सम्पत्ति है। सस्कृति को एक देश में उठाकर दूसरे देश में नहीं ले जाया जा सकता। इसका कारण यह है कि सम्पत्ता की अपेक्षा सम्पत्ति की नकल करना अधिक कठिन है। भारतीयों को परिचित सम्पत्ता बनाने में कुछ भी समय नहीं लगा। पर अपनी सम्पत्ति में वे बहुत दिनों तक अग्रणी मानते रहने के बाद भी भारतीय बने रहे। यह बात यह है कि सम्पत्ति की नकल नहीं की जा सकती, हमें आत्मसात् करना पड़ता है। इन प्रकार सस्कृति बनाने वाले को अधिक कोशिश करनी पड़ती है।

सस्कृति का क्षेत्र सीमित है—सस्कृति का क्षेत्र सम्पत्ता की अपेक्षा बहुत सीमित है। जिस तरह सब लोग विज्ञानी के पत्रों की हवा लेना पसंद करते हैं इसी तरह सब लोग रैडियो रखना चाहते हैं, पर हमने से सब लोग साम्प्रदायिक संगीत को पसंद नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि हमें ही हवा का आनन्द लेने के लिए आपको इसकी पत्र-व्यवस्था जानने की जरूरत नहीं है, पर साम्प्रदायिक संगीत समझने के लिए आपको स्वयं संगीत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

सस्कृति और सम्पत्ता में सम्बन्ध—दोनों भेद होते हुए भी सस्कृति और सम्पत्ता एक दूसरे से बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध रखती हैं। मन से आनाकरण को पृथक् नहीं किया जा सकता। सस्कृति मन को निर्मित करती है, और सम्पत्ता इसके आनाकरण को, इसलिए सस्कृति और सम्पत्ता को भी अलग-अलग नहीं किया जा सकता। वे एक-दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। वे दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, हम यह नहीं कह सकते कि परिवार स्वाभाविक इच्छा का परिणाम है या गिरने अपनी उपयोगिता के कारण बना हुआ है।

सम्पत्ता और सस्कृति एक-दूसरे पर प्रभाव भी डालती हैं। उदाहरण के लिए, आज का हमारा बहुत-सा ज्ञान अलेक्जान्देर के आविष्कार का परिणाम है। वैज्ञानिक आविष्कारों के लोगों के कार्यों विचारों और दृष्टिकोण में ऊपर से नीचे तक परिवर्तन कर दिया है। इसी प्रकार विचारों और रीतियों में सुधार से सम्पत्ता भी गति बढ़ जाती है।

अवकाश और मनोरंजन

अवकाश कितने कहते हैं—जवसे समाज बना है, तब से ही मनुष्य पसीना पहाकर अपनी रोजी पमाता रहा है। कुछ घोंडे से आदमियों को छोड़ दीजिए। अधिकतर लोगो को अपनी रोटी बमाने के लिए काम करना पड़ता है। पर कोई भी आदमी लगातार काम करता नहीं रह सकता, और लगातार काम करने पर शरीर और मन स्वस्थ नहीं रह सकता। आदमी की बात छोड़िए, पर मशीन भी बहुत दिनों तक, बिना विश्राम के, काम नहीं कर सकती। इसे भी सफाई और रेल करे जरूरत होती है। मशीन की तरह मनुष्य के शरीर को भी ताजगी हासिल करने के लिए आराम की जरूरत होती है। काम के समय के बीच जो यह आराम का समय होता है, उसे अवकाश या फुरगत कहते हैं।

अवकाश और निकम्मापन एक नहीं—अवकाश या फुरगत और निकम्मापन को एक नहीं समझ लेना चाहिए। इन दोनों में दो तरह से भेद है। प्रथम तो, अवकाश के लिए काम जरूरी है। निकम्मापन का मतलब है काम का अभाव। अवकाश का मतलब है काम के बाद आराम। निकम्मापन में आराम ही आराम होता है, काम नहीं होता। दूसरे, अवकाश स मुक्त मिलता है, यह शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है। दूसरी ओर, निकम्मापन असुखकर और धनाने वाला होता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अवकाश आदमी की शक्ति और दक्षता बढ़ाना है। निकम्मापन न केवल शक्ति और दक्षता को कम करता है, बल्कि यदि बहुत दिनों तक जारी रहे तो यह मनुष्य को किसी भी काम के योग्य नहीं रहने देता। इस प्रकार, अवकाश और निकम्मापन दो भिन्न पदार्थ हैं।

अवकाश मुस्ती पैदा करने वाले या पकानेवाले काम से दूर भागने को भी कहा पड़ते। अवकाश, जैसा कि पहले कहा गया है, काम के बाद आराम को कहते हैं। चाहे वह काम दिव्यरूप हो या सुष्क। असल में सब तरह के काम कुछ न कुछ थकानेवाले होने हैं और कुछ न कुछ समय बाद खड़े लगने लगने हैं, इसलिए, हर काम के बाद अवकाश की जरूरत होती है।

अवकाश पहले और अब—प्रायः कहा जाता है कि पुराने जमाने के सरल और गान्ध जीवन के मुकामिले में आधुनिक जीवन की दोष-भाग अवकाश नहीं मिलने देती। पर इस विरुद्ध का आधार पिछले जमाने का मूल्य अध्ययन है। पहले अवकाश बड़े विषम रूप में बँटा हुआ था। कुछ घोंडे से लोगो को अवकाश मिलना था और बाकी लोग उनका काम करते थे। प्राचीन ग्रीस और रोम में अवकाश पाने का अधिकार सिर्फ नागरिको को था, जो सारी जाबादी का बहुत थोड़ा हिस्सा होते थे। दासो और श्रमियो को, जो जाबादी का काफी बड़ा हिस्सा होते थे, अवकाश नहीं मिलता था। पुराने जमाने में अवकाश का मूल्य भी इतना नहीं

या, विद्वान् अथ । पुराने जमाने की मुद्रना में आजकल व्यवसाय के अनेक तरह के उपयोग के बारे में भी ज्ञान बढ़ गया है ।

आधुनिक काल में व्यवसाय का विस्तार

आधुनिक काल में व्यवसाय का आसता और विस्तार, दोनों बढ़ गए हैं । इस वृद्धि के कई कारण हैं और वे नीचे दिये जाते हैं—

१. विज्ञान—वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि ने अनेक समय बचाने के उपाय निकाल दिये हैं । मनुष्य मशीन की सहायता से आजकल बहुत कम समय में काम पूरा कर लेता है, इसलिए वह व्यवसाय का आनन्द बहुत अधिक ले सकता है । मशीन में काम करने पर उनकी परिस्थिति भी नहीं होती । इस प्रकार, इस व्यस्त दुनिया में अगर आदमी को विश्राम के लिए थोड़ा थोड़ा समय भी मिल जाय तो वह फिर ताजा हो सकता है । अतीत काल में शारीरिक मेहनत अधिक होती थी, जिसके कारण आराम का समय भी अधिक चाहिए था ।

२. शिक्षा—ध्यात शिक्षा आदमी की वृद्धि को पैदा कर देती है और टैली कल शिक्षा से उसे अपने काम का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है । शिक्षित और मुगल मजदूर अनिश्चित या अचुगल मजदूर की अपेक्षा बहुत जल्दी अपना काम खत्म कर लेगा ।

३. आदमी का महत्व बढ़ गया है—पहले आदमी का कोई महत्व नहीं था । दासता का होना ही इसका प्रमाण है । लोकतन्त्र के आने से ही आदमी का महत्व बढ़ा है । लोकतन्त्र में हर आदमी एक जैसा अच्छा माना जाता है । गरीब नागरिक की भलाई का भी उतना ही महत्व है, जितना धनी नागरिक की भलाई का ।

४. मजदूरी या हितकारी राज्य—आजकल राज्य मजदूरीय राज्य होना है । राज्य किसी को कमजोर और गरीब नागरिकों की मेहनत का नाजायज लाभ नहीं उठाने देता । फैक्टरी कानून काम करके राज्य मानिक को मजदूरों को सट्टलियने देने को मजबूर करता है । काम के घंटे निर्दिष्ट हो जाते हैं, और काम के घंटों के बीच में आराम का समय रखा जाता है ।

इस प्रकार उन्मुक्त बानों के कारण, ममात्र के गरीब और कमजोर नागरिकों को भी व्यवसाय मिलना सम्भव हो गया है ।

के योग्य कमाई करने में बहुत कठिनाई भी न होनी चाहिए ।

आदमी के लिए अवकाश का महत्त्व—हम देख चुके हैं कि अवकाश आदमी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । खेल, बाहर की सैर, पढ़ाई और बातचीत उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं । अनेक तरह के शौक और सांस्कृतिक काम, जैसे वागदानी, संगीत, कविता और पेंटिंग आत्मा का भोजन हैं । बिना अवकाश के इनमें से कोई काम नहीं किया जा सकता । अवकाश में ही आदमी ध्यान और आत्म निरीक्षण कर सकता है । इस प्रकार, अवकाश आदमी के शारीरिक, मानसिक और भौतिक अवकाश के लिए बहुत आवश्यक है ।

लोकतन्त्र के लिए अवकाश का महत्त्व—लोकतन्त्र और अवकाश का घनिष्ठ सम्बन्ध है । ये दोनों एक दूसरे की सहायता पर निर्भर हैं । हम देख चुके हैं कि लोकतन्त्र ने अवकाश का दायरा बढ़ा दिया है । अवकाश भी लोकतन्त्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है । लोकतन्त्र में दक्षता अभी आती है जब उसके नागरिक उसके कार्य संचालन में दिलचस्पी लें । उदाहरण के लिए, हर नागरिक को अपना मत देने से पहले, अनेक समस्याओं और प्रश्नों पर शावधानी से विचार करना चाहिए । उसे सरकार के रोजाना के कामों की जानकारी रखनी चाहिए । इसलिए लोकतन्त्र के हर नागरिक के लिए अवकाश बहुत आवश्यक है जिससे उसे अनेक सार्वजनिक समस्याओं को सोचने के लिए काफी समय मिल सके ।

संस्कृति और सभ्यता के लिए अवकाश का महत्त्व—सब देशों में सभ्यता और संस्कृति का काम अवकाश वाले लोगों ने ही किया है । समृद्धि, मिश्रण, ऊँचे दर्जे का विचार, जो सभ्यता और संस्कृति के लिए इतनी जरूरी चीजें हैं, अवकाश वाले लोगों में ही मिल सकती हैं । आविष्कार, बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ, दर्शन, साहित्य और कविता मजदूरी से नहीं पैदा हुईं । कारण यह है कि मजदूर अधिस्तरीय समय अपनी रोजी कमाने में लगाता है । काम के बाद उसे जो अवकाश मिलता है, वह इतना ही होता है कि उसने शरीर और मन को आराम मिल जाए । मजदूर को अपने व्यक्तित्व की जरूरतों की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिलता इसलिए आदमी को ऊँचे विम्व का विचार करने के लिए, सामूहिक कार्यों के लिए, खाली समय अधिक मिलना चाहिए ।

मनोरंजन कितने कहते हैं ?—मनोरंजन का अर्थ है, काम से आने वाली थकान और झुंझना को हटाने के लिए आनन्दपूर्ण कार्य । मनोरंजन से न केवल शरीर और मन की ताजगी हासिल होती है, बल्कि आदमी के व्यक्तित्व का विकास भी होता है । अवकाश मनोरंजन के लिए बहुत आवश्यक है । अवकाश का ठीक उपयोग करने से ही मनोरंजन होता है । यदि अवकाश का ठीक उपयोग न किया जाय तो उसका उलटा परिणाम होगा ।

अवकाश का ठीक उपयोग या मनोरंजन के रूप

अवकाश के ठीक उपयोग के बारे में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हैं। पर निम्नलिखित कामों को अवकाश का ठीक उपयोग माना जा सकता है —

१. खेल—गेड-गूड जैसे फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट, और टेनिस तथा बिकरा खेलना, बूटना, दौड़, तैरना, पुरुषकारी और पेंडुल बाग या हाइकिंग दिमागी काम करने वाले लोगों को विशेष रूप से उपयोगी है। बहुत देर तक पढ़ने या दफ्तर का काम करने के बाद लोगों में शरीर का व्यायाम हो जाता है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। ताम, टेबल-टेनिस, बिलियर्ड और बैज्म आदि खेलों में शारीरिक प्रदान नहीं होती। इनमें शारीरिक और दिमागी दोनों तरह के काम करने वालों का मनोरंजन होता है।

गेड-गूड किसी राष्ट्र का स्वान्त्र्य बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत में नागरिक गुण, जैसे महयोग, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, टीम की भावना, मित्रा-टीरस की भावना और नेतृत्व शैली के संदान में ही मिले जाते हैं। खिलाड़ियों को चाहे वह किसी ही अच्छा खेलना हो, स्वार्थपूर्ण खेल न खेलना चाहिए। किसी भीष का जीतने के लिए महयोग और टीम की भावना बहुत आवश्यक है। खिलाड़ियों को अपने कैप्टन के अनुशासन में रहना चाहिए। उन्हें रफ़ी के फौजदे मानने चाहिए। कैप्टन अच्छा नेता होना चाहिए। उसका अच्छा खिलाड़ी होना आवश्यक है। वह अच्छा प्रशंसक होता चाहिए, और हार के समय टीम के हीमके को बनाए रखने में समर्थ होना चाहिए। खिलाड़ीय हार और जीत दोनों में मजबूत बनाए रखने के गुण को कहते हैं।

२. शौकिया काम (hobby)—जो शौक शान्त स्वभाव के होते हैं, या शारीरिक मेहनत परमन्त नहीं करने, उनके लिए अवकाश का उपयोग करने का सबसे अच्छा साधन कुछ शौकिया काम हैं। वाद्ययंत्र, टिकट और निक्के जमा करना, पेंट्रिपी हल करना, फोटोग्राफी, पेंटिंग और संगीत कुछ बड़े मनोरंजक शौक हैं। शौकिया कामों में कई लाभ होते हैं। इनमें मन प्रमन्त होता है। ज्ञान और अनुभव बढ़ते हैं, इसके अलावा उनका सामूहिक महत्व भी है। कभी-कभी शौकिया कामों से आर्थिक लाभ भी हो जाता है।

कुछ लोग अपना खाली समय बित्तावें, पत्रिकाएँ और अखबार पढ़ने में लगाते हैं। उपन्यास, यात्रा-वर्णन और जीवन-चरित्र पढ़ने में हस्के होते हैं। जीवन-चरित्रों और यात्रा-वर्णनों में प्रेरणा और शिक्षा भी मिलती है। पत्रिकाएँ और अखबार सामूहिक घटनाओं का ज्ञान कराते हैं, और अपना मत बनाने, आदमी

रजन है। मनोरंजन का एक और साधन रेडियो है। रेडियो और सिनेमा मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा भी देते हैं।

४. सामाजिक सेवा—कुछ लोग, यद्यपि उनकी पिनती थोड़ी है, न तो खेती में दिग्दर्शी रखते हैं, और न किसी शौकिया काम में। ऐसे लोगों की खाली समय का उपयोग सामाजिक सेवा में करना चाहिए। अमल में तो हर नागरिक को अपने खाली समय का कुछ हिस्सा सामाजिक सेवा में लगाना चाहिए।

अवकाश का गलत उपयोग—अवकाश का गलत उपयोग भी किया जा सकता है। शराब पीने और जूआ खेलने में अवकाश का उपयोग करना लाभदायक तो है ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अच्छा नागरिक वह है जो अपने खाली समय का अच्छे से अच्छा चाहे वे भौतिक हो या उपयोग करता है।

सारांश

संस्कृति और सभ्यता—संस्कृति का अर्थ—मोटे तौर से कहा जाए तो संस्कृति शब्द का प्रयोग सारे मनुष्य-जनित वातावरण के लिए और मनुष्यों के सारे शीले हुए व्यवहारों के लिए किया जा सकता है। इनके अन्तर्गत, मनुष्यों के सब कार्य, चाहे वे भौतिक हों या अमौक्तिक हों, आजायेंगे।

सीमित अर्थ में संस्कृति शब्द मनुष्य के सिवा उन कामों पर लागू होगा जो उसने मत्तरात्मक की सन्तुष्टि के लिए किए जाते हैं। पेंटिंग, मूर्ति और मूर्ति निर्माण आदि सब बल्गाए, उपयोग, नाटक और रचना आदि सारा साहित्य, दर्शन और धर्म ऐसे ही कार्य हैं। इस प्रकार, संस्कृति का अर्थ है हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का उचित मन्तव्य। सुसंस्कृत आदमी यह है जिसका व्यवहार मद्र तथा बुद्धि और आचार परिष्कृत है और जो जीवन के सत्य शिख, सुन्दर को तीव्रता से अनुभव करता है।

संस्कृति आदमी और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह आदमी को प्रसन्न, मद्र, शान्ति प्रेमी और सफल बनाने वाली है। संस्कृति नागरिकता के लिए बहुत जरूरी है। नागरिक के रूप में सुसंस्कृत व्यक्ति अपने अधिकारों की अपेक्षा अपने कर्तव्यों पर अधिक ध्यान देता है।

संस्कृति फैलाने के साधन, परिवार, मित्र, स्कूल, बालिका विरजविद्यालय और अनेक मासुक्तिक माहधय हैं।

सभ्यता किसे कहते हैं—सभ्यता शब्द मनुष्य के कामों के उन परिणामों को सूचित करता है जो बाह्य आत्मा की जन्मती की पूर्ति करते हैं। आविष्कार, औजार, मशीनें, खेती, उद्योग, बपडे और मकान सभ्यता के अलग-अलग भाग हैं।

संस्कृति और सभ्यता में अंतर—(१) संस्कृति आत्मपरक होती है, और

सम्पत्ता वस्तुपरक, (२) ससृष्टि व्यष्टिगत और व्यक्तिगत होनी है, सम्पत्ता सामूहिक और साक्षी होती है। (३) सम्पत्ता को तुलना आसानी से हो सकती है, ससृष्टि की नहीं, (४) सम्पत्ता सदा तरलनी करती है, ससृष्टि नहीं, (५) सम्पत्ता एक देश से दूसरे में पहुँचाई जा सकती है, पर ससृष्टि नहीं; (६) ससृष्टि सम्पत्ता की अपेक्षा कम लोगो को प्रभावित करती है।

ससृष्टि और सम्पत्ता का सम्बन्ध—बहुत से भेदों के बावजूद इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन को धानावरण से अलग नहीं किया जा सकता। ससृष्टि मन को बनाती है और सम्पत्ता इसके वातावरण को। परस्पर सम्बन्धित होने के अलावा वे एक दूसरे पर अमर भी डालती हैं।

अवकाश और मनोरजन अवकाश किसे कहते हैं?—काम के घटो के बीच में जो आराम का समय होता है, उसे अवकाश कहते हैं। इस प्रकार अवकाश निवर्म्मपन से भिन्न वस्तु है। निवर्म्मपन का मतलब है, काम न होना। पर अवकाश का मतलब है काम के बाद विधाम। दूसरी बात यह कि अवकाश मुख्य देता है और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। निवर्म्मपन अमुम्बर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

पहले अवकाश कुछ ही लोगो को मिल पाता था और इसका अधिक मूल्य नहीं था। आजकल विज्ञान और शिक्षा के प्रभाव ने अवकाश का परिमाण और दापना बड़ा हो गया। आधुनिक राज्य मगल्लगरी राज्य है, और यह सब आदमियों को समान महत्त्व देता है। इस विचार ने कमजोर और गरीब लोगो के लिए भी अवकाश पाना मन्त्र वर दिया है। समय बचाने वाले माघनों, राज्य के मरक्षण और शिक्षा के अलावा, आर्थिक अभाव से छुटकारा, अवकाश के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक चीज है।

अवकाश का महत्त्व—अवकाश का सबसे अधिक महत्त्व व्यक्ति के लिए है। यह उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरे अवकाश लोचनन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। लोचनन की दक्षता उस अवकाश पर निर्भर है जो इसके नागरिको को समाज और राज्य की अनेक समस्याओं पर विचार करने के लिए मिलता है। तीसरे, अवकाश ससृष्टि और सम्पत्ता की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह इन तथ्य से निश्चित होता है कि आविष्कार, कला की महान् रचनाएँ, दर्शन, साहित्य और कविता का नूतन प्रगतिवत्तर अवकाश वाले लोगो ने ही किया है।

मनोरजन किसे कहते हैं?—मनोरजन का अर्थ है काम की थकान और नीरसता को दूर करने के लिए कोई आनन्दपूर्ण कार्य। अवकाश का उचित उपयोग करने से ही मनोरजन होता है।

अवकाश का उचित उपयोग या मनोरजन के प्रत्यक्ष—(१) खेल-कूद। (२), यागवानी, टिकट और सिक्के जमा करना, पहेलियाँ हल करना, फोटोग्राफी, पेंटिंग,

संगीत और पढ़ना आदि शौकिया काम । (३) मिनेमा, थियेटर और रेडियो आदि मनोरंजन । (४) समाज-सेवा ।

अवकाश का गलत उपयोग—दाराद पीना और जूआ खेलना अवकाश के गलत उपयोग के उदाहरण हैं

प्रश्न

QUESTIONS

१. संस्कृति और सभ्यता शब्दों की सत्यताओं से व्याख्या कीजिए ।
(प. वि अग्रेल, १९१०)
1. Explain carefully the terms 'culture' and 'civilization'
(P U April, 1930)
२. संस्कृति और सभ्यता शब्दों की परिभाषा दीजिए और इन दोनों में भेद बताइए ।
(प. वि. अग्रेल १९५३)
2. Carefully define and distinguish between 'culture' and 'civilization'
(P U April, 1933)
३. आदमी के जीवन में अवकाश का क्या महत्त्व है ? अवकाश का सभ्य से प्रबुद्धा उपयोग कैसे किया जाए ? (प. वि अग्रेल १९४९ और सितम्बर १९५०)
3. Estimate importance of leisure in the life of an individual
How should leisure be best utilized ?
(P U April 1949 and Sep 1950)
४. अवकाश के मूल्य और सही उपयोग पर एक निबन्ध लिखें ।
(प. वि० अग्रेल, १९२०)
4. Write an essay on the value and right use of Leisure ?
(P U April, 1931)
५. वित्तीय नागरिक के जीवन में मनोरंजन सम्बन्धी कार्यों का महत्त्व बताओ ।
(प. वि. अग्रेल, १९५०)
5. Estimate the importance of recreational activities in the life of a citizen
(P U April, 1950)
६. नागरिक के जीवन में खेल-कूद का क्या महत्त्व है ?
(प. वि. १९४८)
6. Discuss the importance of games and sports in the life of a citizen
(P U 1948)

राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद—संयुक्त राष्ट्र संघ

राष्ट्रवाद

कोई नागरिक सिद्ध करने राष्ट्र और राष्ट्र का ही सम्बन्ध नहीं है, बल्कि वह नारी मानव-विचारों का भी सम्बन्ध है। वही हमने निष्ठाओं को ठीक मान में रखने पर विचार किया था, वही हम वहाँ चुके हैं कि नागरिक को अपनी निष्ठाएँ ऐसे क्रम में रखनी चाहिये कि उनकी अपने राष्ट्र और राष्ट्र के प्रतिनिष्ठा संसार-व्यापी मानव विचारों के प्रति उनकी निष्ठा की विरोधी न हों। साथ ही, हमने यह भी बताया था कि मनुष्य में अपने प्रति प्रेम इतना प्रबल है कि अविचार लोगों के लिए अपनी निष्ठाओं को ठीक क्रम में रखना अचम्ब है। आदर्श राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही मानव जाति के प्रति अपनी निष्ठा को, जो अधिक बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण है, पहचानने को तैयार नहीं। अब की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वृत्त-मा तनाव इसी कारण है। इसलिए नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद की समस्याओं का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है। इन अध्याय में राष्ट्रवाद के शीर्षक के अन्तर्गत हम निम्नलिखित बाजों का अध्ययन करेंगे—

- (१) राष्ट्रियता, राष्ट्र और राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ।
- (२) राष्ट्रवाद जो जन्म देने वाले कारण और उनका जातिगत महत्व।
- (३) राष्ट्रवाद के गुण और दोष।

इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रवाद के शीर्षक के अन्तर्गत हम इन बाजों पर विचार करेंगे—

- (१) अन्तर्राष्ट्रवाद किन शक्तियों का परिधान है।
- (२) अन्तर्राष्ट्रवाद के लाभ।
- (३) अन्तर्राष्ट्रवाद के मार्ग की बाधाएँ।
- (४) हम संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य मवादन का भी वर्णन करेंगे।

राष्ट्रियता (Nationality)—राष्ट्रियता शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, जो एकता की भावना से सज्जित होते हैं। यह एकता की भावना आत्मपरक एकता या मानसिक एकता है, जिसका कारण, भूत्वशा और भाषा, एक धर्म, एक निवास-स्थान, एक इतिहास और परम्परा आदि कुछ वस्तुपरक कारक हैं। पर

राष्ट्रिकता के अस्तित्व के लिए यन्तुपरक या बाहरी एकता या सादृश्य जरूरी नहीं है। जो चीज जरूरी है वह यह है कि लोगों की भावनाएँ और विचार एक होने चाहिए। उनका बाह्य रूप एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनकी पूजा के देवता अलग अलग हो सकते हैं, और उनके वेप आदि अलग-अलग हो सकते हैं।

राष्ट्र—जब कोई राष्ट्रिकता अपने-आपको राजनैतिक विकास के रूप में संगठित कर लेती है, या जब वह बाहरी एकता भी हासिल कर लेती है, तब वह राष्ट्र कहलाने के योग्य हो जाती है। इसके अनुसार, जो राष्ट्रिकता स्वतंत्र या भक्त होने की इच्छा वाले राजनैतिक निराश के रूप में संगठित हो गई है, वह राष्ट्र कहलाती है। दूसरे शब्दों में वह तो राष्ट्रीयता और राज्य मिश्रित राष्ट्र कहलाने हैं।

राष्ट्रवाद—राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीय हित, एका और स्वतंत्रता का समर्थन, या राष्ट्रवाद उस भावना की वह स्रजन है जो किसी राष्ट्रिकता को संगठित होने और अपने लिए स्वाधीनता प्राप्त करने को प्रवृत्त करती है। संक्षेप में, राष्ट्रवाद का अर्थ है, अपने राष्ट्र से प्रेम और उसके हितों को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाना।

राष्ट्रवाद के कारण—राष्ट्रवाद की भावना में अनेक तनु हैं। यह एक मूलवश और भाषा, एक मातृदेवता, एक धर्म, साक्षी सांस्कृतिक धाती, साक्षी परम्पराओं और साक्षी राजनैतिक आकांक्षाओं जैसे कई कारकों का फल है। यह याद रखना चाहिए कि इस भाव को पैदा करने के लिए इनमें से कोई भी कारक परम आवश्यक नहीं, तो भी किसी जाति में इनमें से जितनी अधिक बातें होगी, राष्ट्रवाद की भावना उतनी ही प्रबल होगी। अब हम इन कारकों का महत्त्व और हिस्सा संक्षेप में नीचे बताएँगे।

साक्षी भाषा—भाषा के द्वारा विचारों की अदृश बदली होती है। साक्षी भाषा होने से लोग अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं और इस प्रकार उनमें एकापैदा होती है। भारत में अंग्रेजों के अंग्रेजी चलाने से इस देश में राष्ट्रवाद की वृद्धि में बड़ी सहायता मिली।

साक्षी मूलवश—पुरानी कहावत है कि 'अपना अपना, पराया-पराया'। एक ही मूलवश के लोगों में अनन्य निश्चयता अनुभव होगी। उनमें जीवन का प्रति एक से विचार और दृष्टिकोण हाने। पर मूलवशीय सुझता सत्तर में बड़ी पुनर्भोज है। पर मूलवशी के मामूली मिश्रण से राष्ट्रीय-भावना पैदा होने में कोई रुकावट नहीं आती।

साक्षी धर्म—इतिहास में धर्म एक महत्त्वपूर्ण तत्व जोड़ने वाला बल रहा है। आज भी यहूदी, जापानी और आयरिश राष्ट्रिकताओं में धर्म एका का प्रबल बंधन है। पर आजकल साधारणतया धर्म कोई परमावश्यक कारक नहीं रहता। आजकल के राष्ट्रीय राज्य अधिवत्तर सौविक राज्य हैं, जहाँ एक से अधिक धर्म साथ साथ रहते हैं।

साम्ना मानु-देश—एक ही धर्म पर निवाम निम्नदेह बड़ा शक्तिशाली बंधन है और यह न होने पर राष्ट्रीय भावना दबी रहती है। तो भी, यहूदियों का ऐसा उदाहरण है जिसमें कुछ समय पहले तक एक राष्ट्रियता थी, पर मानुदेश नहीं था।

साम्नी परम्परा और यानी—कला, दर्शन, साहित्य, भोजन, वेश, आचार, जीव प्रथाओं की साम्नी गान्धर्विण्ण वाली किसी जाति में एकता का प्रबल बंधन है। मूलबन्ध, भाषा और धर्म की उड़ी भिन्नताओं के बावजूद भारतीय लोगों की एक साम्नी गन्धर्विण्ण है, जिसने उनमें और अन्य जातियों में सदा अंतर किया है। परम्परा लोगों को उन महत्त्वपूर्ण बातों का ध्यान दिलाती रहती है, जिनमें से होकर राष्ट्र ने संस्कृति की है। महीनों और वीरों की स्मृतियाँ भी परम्परा द्वारा जीवित रहती हैं।

साम्ना हिन—साक्षात् आर्थिक हिन या साची प्रतिरक्षा समस्या भिन्न प्रकार के लोगों को भी एक राष्ट्रियता में गुणठिन कर देती है। इन कारकों ने यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की विभिन्न जातियों को राष्ट्रियताओं का रूप दे दिया है।

साम्ना कष्टसहन—एक ही दुश्मन के कारण कष्टसहन की स्मृतियाँ लोगों में एकता की भावना पैदा करने में सबसे अधिक काम करती हैं। भारतीय लोगों की अंग्रेजों के कारण जो कष्ट सहने पड़े उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की गति को बड़ाया।

राष्ट्रवाद के गुण—राष्ट्रवाद के निम्नलिखित गुण बताए जाते हैं—

(१) राष्ट्रप्रेम या राष्ट्रीय हिन, एकता और स्वतंत्रता का समर्थन के अर्थ में राष्ट्रवाद बिल्कुल ठीक है। यह गुलाम राष्ट्रों को आजादी पाने की प्रेरणा देता है।

(२) राष्ट्रवाद किसी देश को प्रगति की ओर ले जाता है। इस भावना में हर आदमी अपने देश को प्यार करता है और राष्ट्रीय प्रगति में अधिक से अधिक योग देने की कोशिश करता है।

(३) राष्ट्रवाद प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सृष्टि का विकास करने के योग्य बनाता है। राष्ट्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहनी है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे में अपने बढ़ने की कोशिश करता है। वे एक दूसरे के अनुभवों में भी सीखते हैं। इसने सारी मानव-जाति को उन्नति होयी है।

(४) स्वतंत्र समस्याएँ भी राष्ट्रीय राज्य में अधिक संस्कृति करती हैं।

(५) किसी राष्ट्रीय राज्य में ही राज्य की सर्वोच्चता का ध्येय की स्वाधीनता में सर्वोत्तम समन्वय होता है।

राष्ट्रवाद के दोष—राष्ट्रवाद तक तक अच्छा है, जब तक वह आक्रमक न हो जाए। यह तब तक अच्छा है, जब तक इसका ध्येय-वाक्य 'जियो और जीने दो' है। पर आजकल राष्ट्रवाद जिम्ह रूप में चलता है, उस रूप में इसमें बहुत-सी बदलाव हैं।

(१) नाज़ी जर्मनी के प्ररूप का राष्ट्रवाद लोगों में यह विद्वान पंदा कर देना है कि वे ईश्वर के चुने हुए लोग हैं। उनमें अहंकार हो जाता है और उनका अहंकार दूसरे राष्ट्रों के प्रति आक्रामक रूप ग्रहण कर लेता है। वे सोचते हैं कि वेवल उन्हें ही स्वयं होने का अधिकार है। इस प्रकार राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की ओर ले जाता है।

(२) सब राष्ट्रों के सापन बराबर नहीं। कुछ राष्ट्र आर्थिक दृष्टि में औरों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में हैं। इसमें राष्ट्रों में आपसी ईर्ष्या पैदा हो जाती है।

(३) ईर्ष्या की भावना संघर्ष को जन्म देती है। राष्ट्रों में संघर्ष होने पर पक्षपातन शब्दों किये जाते हैं और उनका उपयोग भी किया जाता है। युद्ध अनिवार्य हो जाता है। आजकल युद्ध भूमंडल-व्यापी होते हैं, और वे इतने विनाशकारी हो गये हैं कि तारी मानव-जाति का अस्तित्व संघर्ष ही जाने का वास्तविक संघर्ष है।

(४) निरंतर तनाव और संघर्ष की अवस्था प्रत्येक राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार रखती है। राष्ट्रीय आप का बहुत बड़ा हिस्सा विनाश गेता रखों पर खनं किया जाता है। परिणाम यह होता है कि राष्ट्र-निर्माण के कार्य पन की रमी से नहीं हो पाते, और राष्ट्रीय प्रगति रुक जाती है।

(५) आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण अनीत बाल में राष्ट्रों ने अपनी फाशू बस्तुएँ दूसरे राष्ट्रों के उपयोग में आने वने के बजाए उग्ट जग देना ठीक समझा।

(६) राष्ट्रवाद के कारण अनेक छोटे-छोटे और कमजोर राज्य वन गये हैं। न तो वे अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ ठीक तरह पूरी कर सकते हैं, और न वे प्रबल राज्यों के आक्रमण से अपनी रक्षा ही कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रवाद

अंतर्राष्ट्रवाद उस प्रणाली या व्यवस्थानों बनाता है जिसने अधीन अपना शासन आप करने वाले और आत्म-सम्मानों सब राष्ट्र सभता, सम्भावना और तर्क के बधनों द्वारा संयुक्त होकर शान्ति में रह सकते हैं। इसका लक्ष्य यह है कि राष्ट्रों के संघर्ष होने वाले विवादों को फंसला पनु-बल क बजाए तर्क से हो। राष्ट्रवाद में युद्ध का जन्म होता है। पर अंतर्राष्ट्रवाद युद्ध को संघर्षा क्षम कर देना चाहता है। अंतर्राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद का भी दुश्मन है।

पर राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को एक दूसरे का विरोधी नहीं समझना चाहिए, बल्कि राष्ट्रवाद श्दष्टि और मानवता के बीच एक आवश्यक बड़ी है। अंतर्राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय राज्यों की आंतरिक सर्वोच्चता फिर भी बनी रहेगी। ये अन्य राज्यों के साथ व्यवहार करने में ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था के फैसलों के अनुसार चलेंगे। यदि कभी विद्वर राज्य बना तो उसका ढांचा संपानीय ही होगा।

अंतर्राष्ट्रवाद को जन्म देने वाली शक्तियाँ—विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों में युद्ध की सम्भावना को कम करने के लिए सहयोग की आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव

की जानी रही है, पर १९वीं शताब्दी तक इन दिशा में किये गये सब काम तभी धारणो से अधूरे रहे :

१. युद्ध सीमित क्षेत्र में होते थे ।
२. आर्थिक दृष्टि से राज्य एक दूसरे पर कम निर्भर थे ।
३. अन्तर्राष्ट्रीय राज्य असंभव माना जाता था ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कोई संस्था बनाने का पहला कमीर प्रपन १९१४ के बाद किया गया । राष्ट्र सभ (League of Nations) की स्थापना की गई । दूसरे विश्वयुद्ध के बाद भी समुक्त राष्ट्र सभ की स्थापना की गई । अन्तर्राष्ट्रवाद अब कोई स्वप्न-भात्र नहीं रहा । यह प्रतिदिन एक वास्तविकता बनना जा रहा है । पिछले ५० वर्षों में परिस्थितियाँ बहुत बदल गईं । परिवहन और संचार के द्रुत साधनों ने समार को एक दर्जा बना दिया है । हवाई जहाज, घंटार, तार और समुद्री तार के वैज्ञानिक आविष्कारों ने स्थान, दूरी और समय संबंधी विचारों को परिवर्तित कर दिया है । आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया एक होनी जा रही है । कोई भी देश अपनी अर्थ-व्यवस्था में आत्मनिर्भर नहीं । न कोई देश सिकं अपने लिए उत्पादन करता है । आजकल बाजार विश्वव्यापी है । युद्ध अधिक विनाशकारी और विश्वव्यापी हो गये हैं । अब वे सीमित क्षेत्र में नहीं होते । हम बीसवीं शताब्दी में दो भयकर युद्धों का अनुभव ले चुके हैं और तीसरा विश्व युद्ध किसी भी समय हो सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रवाद के लाभ—(१) युद्धों का अन्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रवाद एकमात्र हल है । यह अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए बल के स्थान पर तर्क का उपयोग करने के लिए होता है । आजकल युद्ध बड़े विनाशकारी हो गये हैं, उनसे जन-धन की बड़ी हानि होती है, लाखों आदमी मारे जाते हैं, और इनमें भी अधिक गृह-हीन हो जाते हैं । आजकल युद्ध अनैतिक आवादी पर भी उनका ही असर डालते हैं । असल में तो फैक्टरी और मकान, हवाई बमधारी का पहला गिकार होने हैं । उनसे लाखों स्त्रियाँ विधवा हो जाती हैं, और बच्चे अनाथ हो जाते हैं । अन्तर्राष्ट्रवाद इन सब बुराइयों और भुसोवतों का इलाज है ।

(२) शास्त्रास्थो पर होने वाला मारा सखं धन की बर्बादी है । इसमें कोई उत्पादक कार्य नहीं होता । अन्तर्राष्ट्रवाद के होने पर यह सारा सखं राष्ट्र-निर्माण के कामों में लगाया जा सकता है । अगर शास्त्रास्थो पर कोई सखं न हो तो दुनिया के लोगों की सब सामाजिक और आर्थिक बुराइयाँ दूर हो जाएँ ।

(३) राष्ट्रवाद के जो लाभ बताये जाते हैं वे अन्तर्राष्ट्रवाद में मग्न नहीं हो जाएँगे । सघानीय ढाँचे वाले अन्तर्राष्ट्रीय राज्य के होने पर प्रत्येक राष्ट्र को अपने भीतरी मामलों पर पूरी आजादी रहेगी ।

(४) अन्तर्राष्ट्रवाद सब आर्थिक ईर्ष्याओं को खत्म कर देगा । सब राष्ट्र एक दूसरे के साधनों का लाभ उठा सकेंगे । जो राज्य जो बस्तुएँ बनाने के लिए सब से

अधिक उपयुक्त है, उसे उन वस्तुओं के बनाने में विशेष योग्यता हासिल करने का मौका मिलेगा।

(५) अन्तर्राष्ट्रवाद से राष्ट्रों में सस्कृतियों और विचारों का बाधाहीन विनिमय हो सकेगा। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सफलताओं का लाभ उठा सकेगा। इस प्रकार सारे मानव-समाज का जीवन अधिक सम्पन्न होगा। कुछ पिछड़े हुए राष्ट्र भी दूसरे आगे बढ़े हुए राष्ट्रों के सम्पर्क से तरक्की करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रवाद के मार्ग की रुकावट—(१) राज्यों की सर्वोच्चता या प्रभु सत्ता अन्तर्राष्ट्रवाद के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। राज्य अपनी सर्वोच्चता पर किसी भी तरह रोक लगाने को तैयार नहीं। अन्तर्राष्ट्रवाद में राज्यों की बाह्य सर्वोच्चता पर कुछ पाबन्दियाँ लगायी जा सकती हैं।

(२) अन्तर्राष्ट्रवाद में साम्राज्यवाद की कोई जगह नहीं। विश्व-राज्य का परीक्षण तब तक तकल नहीं हो सकता, जब तक हर तरह का साम्राज्यवाद खत्म न हो जाए। पर साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने उपनिवेशों को आजादी देने को तैयार नहीं।

(३) अन्तर्राष्ट्रवाद में एक और रुकावट मूल्यस्य या रंग की उच्चता है। विश्व राज्य में छोटे-बड़े सब राज्य और काले-गोरे सब लोग समान स्तर पर खड़े होंगे।

(४) अन्तर्राष्ट्रवाद की सफलता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के फंसलों को लागू करने के निमित्त एक प्रबल शक्ति का होना अनिवार्य है। पर अब तब ऐसी शक्ति बनाना सम्भव नहीं हुआ।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय सेना के अभाव में अन्तर्राष्ट्रवाद तभी सफल हो सकता है, जब मानव प्रकृति में आमूल परिवर्तन हो जाए। मनुष्य अपना स्वार्थ और लोभ छोड़ दे और तर्क के अनुसार चलने को तैयार हो। मनुष्य में अब भी पशु का अंश बड़ा प्रबल है।

संयुक्त राष्ट्र संधि

राष्ट्र संधि को १९१९-४५ के दूसरे विश्व युद्ध ने खत्म कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संधि, जो अब इसके स्थान पर है, अप्रैल १९४५ में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में पास किए गये संयुक्त राष्ट्र संधि घोषणापत्र से पैदा हुआ। राष्ट्र संधि की तरह संयुक्त राष्ट्र संधि भी संधि में शान्ति बनाए रखने के लिए बनाया गया है। लोग महगूष करते हैं कि दुनिया को कानून और निष्पन्न न्याय की छत्रछाया में लाया जा सकेगा है। अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा बातचीत और तर्क से होना चाहिए, बल प्रयोग से नहीं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य और प्रयोजन—संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में संयुक्तराष्ट्र संघ के ये लक्ष्य और प्रयोजन बताये गये हैं—

(१) संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला प्रयोजन अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना है। यह संघ शान्ति बरखाने वाले सदस्यों को रोकने या हटाने और जाक्रमण के कार्यों तथा अन्य शान्ति-भंगों को दबाने के लिए सब शान्तिपूर्ण साधन उपयोग में लाएगा और न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े निपटायेगा।

(२) संयुक्त राष्ट्र संघ को मूल मानवीय अधिकारों का आदर करना होगा।

(३) संयुक्त राष्ट्र संघ का सब राष्ट्रों के लोगों में दोस्तीना सम्बन्ध बनाने के उपाय करने चाहिए। इसका यह लक्ष्य भी है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय डंग की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में सब देशों का सहयोग स्थापित किया जाए।

(४) संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्य संयुक्त संगठन होने के नाते इन छानान्य सभ्यों की सिद्धि के लिए राष्ट्रीय कार्यों के समन्वय के केंद्र के रूप में काम करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में उसके सिद्धान्त और लक्ष्य बताए गये हैं, और दूसरे में इसके घटक का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के छ मुख्य अंग हैं और कई सहायक अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग ये हैं—

१. बृहत् सभा या जनरल असेम्बली।
२. सुरक्षा परिषद।
३. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय।
४. सचिवालय।
५. सामाजिक और आर्थिक परिषद।
६. ट्रस्टीशिप कौंसिल या न्यायिक परिषद।

सहायक अंग ये हैं—

१. अन्तर्राष्ट्रीय धन संगठन (I. L. O.)
२. खाद्य और कृषि संगठन (F. A. O.)
३. संयुक्त राष्ट्र शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति-संगठन (U.N.E.S.C.O.)
४. विश्व स्वास्थ्य-संगठन (W. H. O.)
५. निरस्त्रीकरण आयोग।
६. पुनर्निर्माण और विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (I. B. R.)
७. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि (I. M. F.)

बृहत्सभा या जनरल असेम्बली—यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सब से बड़ा अंग है। अब इसके कुल ८० सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य का एक मत होता है। पर उच्च

५ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस प्रकार सब सदस्य राज्यों को इस सस्था में समानता की स्थिति प्राप्त है। जनरल असेम्बली मुख्यत एक विचार करने वाली सस्था है और इसकी तुलना किसी राज्य के विधान मण्डल से की जा सकती है। यह घोषणा पत्र के अन्तर्गत हर बात पर विचार कर सकती है। असेम्बली का अध्यक्ष हर सत्र के लिए निर्वाचित होता है। असेम्बली दो तिहाई बहुमत से सुरक्षा-परिषद के छ अस्थायी सदस्य दो वर्ष के लिए चुनती है। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद को १८ सदस्य भी चुनती है। ट्रस्टीशिप कौंसिल के सदस्य और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के १५ जज भी असेम्बली द्वारा चुने जाते हैं। महासचिव, जो संयुक्त राष्ट्र सभ के सचिवालय का अध्यक्ष है, इसी सस्था द्वारा नियुक्त किया जाता है। असेम्बली नये सदस्य प्रविष्ट करने और किसी वर्तमान सदस्य को निकालने के बारे में भी फैसला करती है।

सुरक्षा परिषद—यह संयुक्त राष्ट्र सभ की कार्यपालिका है। सदस्य राज्यों ने विश्व शान्ति और सुरक्षा कायम रखने की जिम्मेवारी इसे सौंप दी है। प्रत्येक सदस्य राज्य ने अपने कर्तव्य मानने की प्रतिज्ञा की है। सुरक्षा परिषद में कुल ११ सदस्य हैं और ये दो प्रकार के हैं अस्थायी और स्थायी। ५ स्थायी सदस्य ये हैं—चीन, यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैंड), फ्रांस, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स। ६ अस्थायी सदस्य जनरल असेम्बली द्वारा दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

कार्यपालिका सस्था होने के कारण सुरक्षा परिषद पर दुनिया की हिकाजत करने और अगर आवश्यक हो तो बल प्रयोग में विश्व शान्ति कायम रखने का भार है। यह संयुक्त राष्ट्र सभ का सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय अंग है। इसका सत्र लगातार रहता है। सुरक्षा परिषद को सब महत्वपूर्ण फैसला के लिए सात मत होने आवश्यक हैं। आर्थिक अनुशास्तियों (Economic sanctions), विवादों के पत्र निर्णय और सैनिक बलप्रयोग सम्बन्धी सब मामले सात मतों द्वारा ही तय होते हैं। इन सात में से ५ मत स्थायी सदस्यों के होने अनिवार्य हैं। इस प्रकार, सुरक्षा परिषद के किसी कार्य पर ५ बड़ी शक्तियों में से कोई भी वीटो या अभिवेध का प्रयोग कर सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—यह संयुक्त राष्ट्र सभ का न्यायांग है। इसके सामने सदस्यों द्वारा भी मामले लाये जा सकते हैं और गैर सदस्यों द्वारा भी। पर यह न्यायालय मामलों की सुनवाई तभी कर सकता है, यदि विवाद के दोनों पक्ष इसके क्षेत्राधिकार को मानें। इस न्यायालय का स्थायी अधिष्ठान हालैंड में हैंगर में है। इसमें १५ सदस्य हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश सामान्यतया ९ वर्षों के लिए चुना जाता है।

सचिवालय—संयुक्त राष्ट्र सभ के सचिवालय में एक महासचिव और अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जनरल असेम्बली द्वारा नियुक्त किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति जनरल असेम्बली के विनि

यमों के अन्तर्गत महासचिव द्वारा की जाती है ।

सामाजिक और आर्थिक परिषद—यह एक महत्वपूर्ण निधाय है जो उन सब आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार करती है, जो संसार के देशों को परेशान करते हैं । इनका मुख्य प्रयोजन अनुसंधान और गवेषणा है । इसके १८ सदस्य हैं । वे जनरल असेम्बली द्वारा ९ साल के लिए चुने जाते हैं । प्रत्येक ३ वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य निवृत्त हो जाते हैं ।

दृष्टीगोच्य कौमिल—इस निधाय का काम उन क्षेत्रों पर जो इसके न्यास के अधीन दिये जाए प्रशासन करना है । दूसरे विश्व युद्ध के बाद धुरी शक्तियों ने जोने गये राज्य क्षेत्रों और पुराने राष्ट्र संघ के अधिदेशों का प्रशासन करना है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रियता—संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिकतर सक्रियता राजनैतिक क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में हुई है । अपने घरों से उखड़े हुए लोगों को फिर से बसाने में संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्वासि प्राधिकरण की, रोमों का मुकाबिला करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की, और दुनिया के अनाज को विनियमित करने में खाद्य और कृषि संगठन की सफलताएं उल्लेखनीय हैं । शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति संघ सामाजिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उपयोगी काम कर रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय धन संगठन को मजदूरों का, कम से कम जीवन स्तर लागू करने में सफलता हुई है । विश्व बैंक युद्ध से घबराए देशों को अपनी अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिए ऋण दे रहा है । राजनैतिक क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व युद्ध रोकने में अब तक सफल रहा है । इसने विश्व राजनीति की शिक्षा को बहुत व्यापक कर दिया है । यह एक महत्वपूर्ण लाभ है । आज अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग १० वर्ष पहले की अपेक्षा बहुत अधिक है । विश्व लोकमत का परिमाण और शक्ति पहले से अधिक तेजी से बढ़ रही है । अन्तर्राष्ट्रीय मेगा के अभाव में, कोमनवेल्थ संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसलों के पीछे प्रभावकारी बल है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता—संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता राजनैतिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट है । यह बात ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया को बहुत से संकटमय प्रश्नों पर युद्ध से बचाया है, पर फिर भी आमतौर से माना जाता है कि इसने शान्ति की आशा पूरी नहीं की । अब तक भी मय से छुटकारा नहीं हुआ । राजनैतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :—

१. जर्मनों के एकीकरण की समस्या अब तक हल नहीं हुई ।
२. हिन्दचीन के सवाल का अन्तिम निबटारा नहीं हुआ ।
३. कास्पीर के सवाल पर अब तक भविष्य दूर नहीं हुआ ।
४. दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र संघ एरिथ्रियों और अफ्रीकनो को बुनि-

यादी मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं करा सका ।

५. राष्ट्रीय राज्यों द्वारा सरकारों के सचय को संयुक्त राष्ट्र सघ नहीं रोक सका । यह परमाणु शक्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण नहीं कर सका ।

संयुक्त राष्ट्र सघ की श्रुतियाँ या इसकी विफलता के कारण—१. सदस्यों का शक्ति गुटों में विभाजन—संयुक्त राष्ट्र सघ की ४ प्रमुख श्रुतियाँ हैं । संयुक्त राष्ट्र सघ को प्रमुख शक्ति गुटों अर्थात् एंग्लो-अमरीकन और रूसी, कम्युनिस्ट गुट में बँटा हुआ है । उनमें आदर्शों का विरोध है । इस विरोध का परिणाम है शक्ति राजनीति । इस कारण संयुक्त राष्ट्र सघ में किसी समस्या पर निष्पक्ष विचार असम्भव हो गया ।

२. बीटो या अनियंत्रित शक्ति—सुरक्षा परिषद का गठन बहुत अधिक अनौकलनीय है । ५ स्थायी सदस्य इसका नियंत्रण करते हैं । प्रथिमा सन्धी मामलों को अलावा अन्य मामलों में कोई भी सदस्य परिषद के फंक्शन्स को बीटो कर सकता है चाहे शेष दसों सदस्य इसके पक्ष में हों । इसलिए बीटो राष्ट्र सघ की सफलता में बड़ी रुकावट है ।

३. अन्तर्राष्ट्रीय सेना का अभाव—संयुक्त राष्ट्र सघ के पास अपने फंक्शन्स लागू करने के लिए कोई सेना या पुलिस नहीं है । इसलिए सदस्य-राज्य संयुक्त राष्ट्र सघ के फंक्शन्स के अनुसार काम करने से पहले अपना हित और सुविधा देखते हैं ।

४. पुरी शक्तियों की सदस्यता पर रोक थी—राष्ट्र सघ की तरह संयुक्त राष्ट्रीय जनरल असेम्बली में भी शत्रु राज्यों के, और उन राज्यों के, जिनका इस विजेताओं के प्रति अनुकूल नहीं था, प्रवेश पर रोक थी । जर्मनी और जापान तक भी संयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य नहीं हैं । यह बान न्याय और औचित्य के तम निन्दितों के विरुद्ध है ।

संयुक्त राष्ट्र सघ की विफलता के मुख्य कारण उसकी ये श्रुतियाँ ही हैं । इसकी विफलता का एक कारण यह भी है कि अभी राष्ट्रवाद की भावना बड़ी प्रबल है । हम सब लोग अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता तो अनुभव करते हैं, पर हम विषय सरकार के लिए तैयार नहीं जालूम होते । साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भी अभी खत्म नहीं हुई । कुछ सीमा में शत्रु बल काम कर रहे हैं ।

संयुक्त राष्ट्र सघ का मूल्यांकन—संयुक्त राष्ट्र सघ की ऊपर बताई हुई विफलता पर विचार करने पर हमें यह दिखाई देने लगता है कि राष्ट्र सघ की तरह यह भी खत्म हो जाएगा । पर इस अनुमान को स्वीकार करना, अभी असम्भविक और आत्महत्या के समान है । असाधारण तो इसलिए है कि अभी सब कुछ सन्ध नहीं हुआ । यह आत्महत्या के समान इसलिए है । क्योंकि हम मानव के जीवित रहने के लिए बनाए गए एकमात्र साधन को खत्म कर रहे होंगे । यद्द मे मानव जाति के खत्म हो जाने का सतत हर समय बना हुआ है । यह भी सच है कि अमरीका और रूस के मौजूदा संबंध यद्द से कुछ कम नहीं हैं । तो भी आपने-सागने बँठकर

मानवीयता बरने से मतभेद दूर होने में प्रायः मदद मिलती है। मंगुला राष्ट्र सभ मानव जाति के इतिहास में एक बहुत महत्त्वपूर्ण और युगारम्भ करने वाली सभ्या है। इसके साथ गम्भ्यता की उच्चतम और भद्रतम आकाशाएँ जुड़ी हुई हैं। यह तूफानों भरी दुनिया में हो समने चाली सुरक्षा का एवभाव आश्रय है। अगर संयुक्त राष्ट्र सभ विफल होना है तो अगल में दुनिया के लोग ही विफल होने हैं।

शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति-सभ—मंगुला राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति सभ संयुक्त राष्ट्र सभ का एक सहायक अंग है। १९४६ में इसे शुरू करने का लक्ष्य संसार के राष्ट्रों की शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में निकट लाना था।

अंतर्राष्ट्रीय धर्म सभ—अंतर्राष्ट्रीय धर्म सभ का लक्ष्य सारी दुनिया के मजदूरों को काम की मानवीयता अवस्थाएँ और न्याय प्राप्त कराना है। यह सभ्या राष्ट्र सभ से ही संयुक्त राष्ट्र सभ को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सभ ने मजदूरों की दसा समालने के लिए बहुत कुछ किया है। इनमें मजदूरों को जीवन मजदूरी, काम के निश्चिन्त घटे और रोग, वृद्धि और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने की कोशिश की है।

सारांश

प्रत्येक नागरिक सारी मानव विरादरी का भी सदस्य है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र के विचारों की राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की समस्याओं का अध्ययन भी करना जरूरी है।

राष्ट्रिकता—राष्ट्रिकता शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग में आता है जो एकत्व की भावना से सगठित होने हैं। इस प्रकार राष्ट्रिकता के लिए परमावश्यक बात यह है कि लोगों में साझी भावनाएँ और विचार हों। वे बाहर से देखने में एक-दूसरे से भिन्न दिखाई दे सकते हैं। पर बाहरी साक्ष्य की कुछ बातों में एकत्व की भावना पैदा होने में मदद मिलती है, ये बातें राष्ट्रिकता की वारक बहलाती हैं, और वे हैं (१) भाषा मूलवंश, (२) साझी भाषा, (३) साझा धर्म, (४) साझा निवास, (५) साझा इतिहास, और (६) साझी संस्कृति। यद्यपि इनमें से कोई भी कारक राष्ट्रिकता की भावना पैदा करने के लिए परमावश्यक नहीं है तो भी किसी जाति में उनमें से जितने अधिक वारक होते हैं, एकत्व की भावना उतनी ही प्रबल होती है।

राष्ट्र—राष्ट्र वह राष्ट्रिकता है जिनमें अपने जात को एक स्वतंत्र या स्वतंत्र होने की इच्छा वाले राजनैतिक निकाय के रूप में सगठित कर लिया है, या राष्ट्र राष्ट्रिकता और राज्य का जोड़ है।

राष्ट्रवाद—राष्ट्रवाद राष्ट्रिय हित, एकता और स्वतंत्रता से अनुराग या उनके समर्थन को कहते हैं। अथवा राष्ट्रवाद उस भाव को कह सकते हैं जो किसी राष्ट्रिकता की एक होने और अपने लिए आजादी हासिल करने के लिए प्रेरणा देता है।

राष्ट्रवाद के गुण—(१) यह मुलाम राष्ट्रों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा देता है। (२) इस भावना के होने पर हर व्यक्ति राष्ट्रीय उन्नति में अपना अधिक से अधिक हिस्सा देता है। (३) इसमें राष्ट्रों में आने बढने के लिए स्वस्थ प्रति-योगिता पैदा होती है। इस प्रकार सारी मानव-जाति का जीवन समृद्ध होता है। (४) राष्ट्रीय राज्य में ही सर्वोच्चता और स्वाधीनता का सबसे अच्छा मेल मिलाप होता है।

दोष—(१) अत्यधिक राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को जन्म देता है। (२) राष्ट्रों के साधनों में अधिक अन्तर होने से आपसी ईर्ष्या और युद्ध पैदा होते हैं। (३) युद्धों में बड़ा विनाश होता है। (४) राष्ट्रवाद में अनेक छोटे छोटे और कमजोर राज्य बन जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रवाद—यह ऐसी प्रणाली या व्यवस्था है जिसमें अपना सामन आप करने वाले और आत्मसम्मानों सब राष्ट्र सगता, सदभावना और तर्कों के बन्धन से बंध कर दानि से जीरन विनाने के योग्य होने हैं। इसका लक्ष्य यह है कि राष्ट्रों में युद्ध की जगह तर्कों को प्रतिष्ठित किया जाए।

पर अन्तर्राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद एक दूसरे के विरोधी नहीं। बल्कि राष्ट्रवाद व्यक्ति और मानव-जाति के बीच एक कड़ी है। अन्तर्राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय राज्यों की स्थिति बड़ी होगी जो किसी नधान में राज्यों या प्रान्तों की होगी।

अन्तर्राष्ट्रवाद की जन्म देने वाली शक्ति—१९वीं शताब्दी तक कोई भी अन्तर्राष्ट्रवाद पर गंभीरता से विचार नहीं करता था। इस दिशा में पहला गंभीर प्रयत्न राष्ट्र सच था। दो विश्व युद्धों के भयानक अनुभव और वेतों की एक दूसरे पर आधिक निर्भरता में मजबूर होकर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों ने सारी दुनिया को एक इकाई बना दिया है।

अन्तर्राष्ट्रवाद के लाभ—(१) यह युद्ध घात करने का एकमात्र तरीका है। यह बल की जगह तर्कों के प्रयोग के लिए कहता है। (२) इसके होने पर राष्ट्रवादियों पर तर्क होने वाला घन राष्ट्र-निर्माण के कामों में लगाया जा सकता है। (३) अन्तर्राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद की कोई हानि नहीं होती। (४) अन्तर्राष्ट्रवाद सब आधिक ईर्ष्या-आ को खत्म कर देगा। (५) इसमें सहस्रतियों और विचारों का बाधाहीन आदान प्रदान हो सकेगा।

अन्तर्राष्ट्रवाद में बाधाएँ—राज्य बाहरी मामलों में अपनी सर्वोच्चता छोड़ने को तैयार नहीं। (२) साम्राज्यवादी राष्ट्र साम्राज्यवाद छोड़ने को तैयार नहीं। (३) मूलवर्गीय और रम सम्बन्धी उद्वृष्टता के विचार राष्ट्रों में अब भी मौजूद हैं। (४) मनुष्य में पशुता अब भी बहुत प्रबल है, और इसलिए अभी युद्धों से छुटकारा नहीं मिल सकता।

समुन्नत राष्ट्र सच—इसका जन्म अप्रैल १९४५ में सान फ्रांसिस्को में पास किए गए समुन्नत राष्ट्रीय घोषणा-पत्र द्वारा हुआ। इसके लक्ष्य और प्रयोजन ये हैं—

(१) युद्ध से बचने के शान्तिपूर्ण उपाय अपना कर अन्तर्गोष्ठिय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना । (२) मूल मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान कायम करना । (३) राष्ट्रों में धार्मिक, सामाजिक और सामूहिक मामलों में सहयोग करना ।

संयुक्तराष्ट्र संघ के अंग—इसमें ६ मुख्य अंग और कई महापक्ष अंग हैं । मुख्य अंग ये हैं—

(१) बृहत् सभा या जनरल असेम्बली—इसमें ८० सदस्य हैं, और प्रत्येक का एक मत है । यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विधानमण्डल है । इसने कार्य विचारारामक और निर्वाचन सम्बन्धी हैं ।

(२) सुरक्षा परिषद—यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है । इसमें ११ सदस्य हैं, जिनमें से पाँच स्थायी सदस्य हैं । स्थायी सदस्यों की वीटो या प्रतिवध की शक्ति भी है । इस पर जहाँ तक हो सके पंचनिष्ठता द्वारा और अन्यथा दल प्रयोग द्वारा विद्व शान्ति कायम रखने का गार है ।

(३) अन्तर्गोष्ठिय न्यायालय—इसमें १५ न्यायधीश हैं और यह हेग में है । यह अन्तर्गोष्ठिय विधि के अर्थात् मामलों में सुन संवत्ता है पर अर्थ यह है कि दोनों पक्ष इसके क्षेत्राधिकार की स्वीकार करें ।

(४) सचिवालय—इसमें एक महासचिव और बहुत से सहायक अधिकारी होते हैं ।

(५) सामाजिक और आर्थिक परिषद—इसमें १८ सदस्य हैं, और यह संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों पर विचार करती है ।

(६) ट्रस्टीशिप कौन्सिल—यह उन क्षेत्रों पर ध्यान करती है, जो इसके न्याय के अधीन होने हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता—संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता अधिकतर राजनीति से निम्न क्षेत्र में हुई है । राजनैतिक क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व युद्ध रोषने में सफल रहा है । इसने पहले की अपेक्षा बहुत अधिक लोगों को विश्व-राजनीति का परिचय करा दिया है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता और उसके कारण—इसकी विफलता राजनैतिक क्षेत्र में अधिक उल्लेखनीय रही है । अबतक दुनिया भय से मुक्त नहीं हो सकी । संयुक्त राष्ट्र संघ की चार प्रमुख त्रुटियों या विफलता के चार कारण हैं :—(१) सदस्यों का शक्ति गुटों में बंट जाना, (२) पाँच बड़ी शक्तियों की वीटो या प्रतिवध की शक्ति, (३) संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपने फैसलों को लागू करने के लिए कोई फौज या पुलिस नहीं है, (४) बुरी शक्तियों की उदरगत पर रोक लगा दी गई ।

यह सब होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व-इतिहास में सब से महत्वपूर्ण और सुसंयुक्त संस्था है । यह इस दुर्गम और तूफान भरे समार-काल में सुरक्षा का एकमात्र उपाय है ।

प्रश्न
QUESTIONS

१. राष्ट्रवाद शब्द से आप क्या समझते हैं ? इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?
(५ वि० गितावर, १९४३)
- 1 What do you understand by the term 'Nationalism'? What are its salient features? (P U Sep 1953)
२. राष्ट्रवाद को पैदा करने वाले कारक कौन-कौन हैं ?
- 2 What are the factors contributing to 'Nationalism'?
३. राष्ट्रवाद के गुणों और दोषों की परिभाषा करो ?
- 3 Examine the merits and demerits of nationalism
४. अन्तर्राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं ? इसे पैदा करने वाली शक्तिया कौन कौन सी हैं और इसके मार्ग में कौन कौन सी रुकावटें हैं ?
- 4 What do you understand by 'Internationalism'? What are the forces contributing to it and what are the hinderances in its way?
५. संयुक्त राष्ट्र संधि के उद्देश्य क्या हैं ? (५० वि० प्रश्न, १९५०)
- 5 What are the objects and aims of U N O? (P U April, 1950)
६. अन्तर्राष्ट्रीयता के क्या लाभ हैं ?
- 6 What are the advantages of Internationalism?
७. संयुक्त राष्ट्र संधि के बुनियादी सिद्धान्त और वे कौन-कौन से हैं ?
(५० वि० गितावर, १९५२)
- 7 What are the basic principles and organs of the United Nations Organisation (P U Sep 1952)
८. अन्तर्राष्ट्रीय शांति के अर्थ के रूप में संयुक्त राष्ट्र संधि की सफलता और विफलता पर एक छोटी टिप्पणी लिखो। इसकी कौन-कौन सी सुटियाँ हैं ?
- 8 Write a short note on the success and failure of the U N O as an organ for international peace. What are its defects?
९. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो —
(१) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
(२) संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान-संस्कृति संधि।
(३) सुरक्षा परिषद।
Write short notes on —
1 The International Labour Organisation
2 The U N E S C O
3 Security Council

